



रा  
ज  
स्था  
न

शिक्षण संस्थायें-

अनुदान नियम

GRANT-IN-AID RULES

३५५  
विविध

शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के लिये सहायताय अनुदान नियम

[ हिन्दी-अंग्रेजी • द्विभाषी ]

[ राज्य सरकार तथा शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित आदेशों  
एवं परिपत्रों का धनूठा संकलन ]

सम्पादक

श्रीकृष्ण दत्त शर्मा,

एम० ए०, एल० एल० बी०

[ भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत लेखक ]



कैलाश सुख डिपो

B-23, गोविन्दपुरी (पूर्व) नया रायगढ़ रोड

जयपुर-302002

## नम्र निवेदन

गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के अनुदान सम्बंधी नियम तथा परिपत्रों व आदेशों के सफल सम्बंधी पुस्तक कहीं उपलब्ध नहीं थी। अतः मित्रों के आग्रह पर यह सफल प्रकाशित किया जा रहा है। भाषा है, यह पुस्तक गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों, उनमें कार्यरत अभ्यासियों, प्रबंधक मण्डल तथा शिक्षा विभाग के कार्यालयों के लिये सदा पुस्तक के रूप में उपयोगी सिद्ध होगी।

यद्यपि सफल का सम्पादन पर्याप्त सावधानी से किया गया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि ध्यान में लाई जावेगी या सुझाव प्राप्त होगा, तो आपकी कृपा होगी और इनसे भविष्य में इसमें सुधार हो सकेगा।

सादर धन्यवाद,

—वत्त

\*\*\*\*\*

© S K DUTT 1980

मूल्य—तीस रुपये

☐ प्रकाशक कलाश बुक डिपो

बी-23, गोविंद पुरी (पूर्व)

नया रामगढ़ रोड, जयपुर-302002

☐ मुख्य वितरक ए वन ऐजेंसीज

ब्रह्म हीरा बिल्डिंग, एम० आई० रोड,

(लक्ष्मी पेट्रोल पम्प के पास)

जयपुर-302001

☐ मुद्रक भाग (1) विनीता प्रिंटर्स, जयपुर-1

भाग (2) राष्ट्र उद्योग प्रिंटर्स, जयपुर-1

# राजस्थान शिक्षण सस्थ अनुदान नियम विषय सूची

भाग (1)

अध्याय (1)

शैक्षणिक एय सास्कृतिक सस्थाओ के लिये सहायताथ अनुदान नियम 1963  
[मूल अ प्रे जी मय हिन्दी अनुवाद]

	अंग्रेजी	हिंदी
नियम 1 सक्षिप्त नाम	2	3
2 परिभाषाएँ	2	3
3 योग्यता	4	5
नियम 2 सस्थाओ का वर्गीकरण	35	7
नियम 3 अनुदान की शर्तें	6	7
नियम 4 समचारीकरण की सेवा की शर्तें	16	17
नियम 5 वार्षिक पुनरावृत अनुदान का निर्धारण	20	21
नियम 6 स्वीकृत खच	26	27
नियम 7 अनावतक अनुदान	34	35
नियम 8 काम दिवस	38	39
नियम 9 सहायता अनुदान के लिये प्राथनापत्र	38	39
नियम 10 अनुदान में कमी, वापसी, रोकना आदि	38	39
नियम 11 प्राथनापत्र को जाँचने के लिये समिति	40	41
नियम 12 स्वीकृति प्राधिकारी	40	41
नियम 13 सम्पत्ति का हस्तांतरण	42	43
नियम 14 रजिस्टर इत्यादि का परिरक्षण	42	43
नियम 15 निविदा द्वारा क्रय	42	43
नियम 16 अतिक्रमण	42	43
सलग्नो (Enclosers) की सूची	42	43
परिशिष्ट I प्रबंध मण्डलो का निर्माण	44	45
, II शिक्षण सस्थाओ के अनुशासन के नियम	46	47
, III सविदा (इकगरनामा) का प्रपत्र	48	49
, IV प्रधानो के एकरारनामे का प्राख्य	58	59
, V विभागीय अधिकारियों के अधिकारो की सूची	66	67

परिशिष्ट VI अनुमानित खर्च की अधिकतम सीमा का सशोधित मूल्यांकन	76	77
„ VII चतुर्थ धरोखी का विवरण ।	86	89
अध्याय (2) अनुदान नियम 1963 में सशोधन एवं आदेश-प्राप्तापत्र	96	112
„ (3) रेलवे शालाओं के सम्बन्ध में अनुदान सम्बन्धी नियम व आदेश	113	116
(4) परीक्षाओं की मायता सम्बन्धी आदेश एवं परिपत्र	116	125
„ (5) प्रबन्धकारिणी समिति का गठन, परिसम्पत्तियाँ, रजिस्ट्रेशन, मायता	126	134
(6) भवन विराये के सम्बन्ध में आदेश	134	136
„ (7) फीस (गुल्ब) सम्बन्धी आदेश एवं परिपत्र	137	144

भाग (2) पृष्ठ (1) से (88)

[कृपया ध्यान रह-भाग (2) की पृष्ठ संख्या अलग से दी गई है]

अध्याय (8) आयु एवं सेवा निवृत्ति सम्बन्धी आदेश एवं परिपत्र	1	11
(9) पदों के निर्धारण सम्बन्धी आदेश व परिपत्र	11	15
„ (10) “भविष्य निधि” (प्रोविडेंट फंड) सम्बन्धी आदेश/परिपत्र	16	45
„ (11) कर्मचारियों की नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया सम्बन्धी आदेश/परिपत्र	45	74
„ (12) कर्मचारियों की सेवामुक्ति के लिये प्रक्रिया (अनुशासनिक कार्यवाही) एवं अधीन सम्बन्धी आदेश/परिपत्र	75	79
„ (13) विविध-राज्य सरकार या विभाग द्वारा प्रसारित अर्थ आदेश व परिपत्र	80	83
„ (14) निजी सम्पत्तियों की मायता निरीक्षण एवं अनुदान सम्बन्धी आदेश परिपत्र	84	88

[कुल पृष्ठ सं० 144+88=232]

# Grant-in-aid Rules for Educational & Cultural Institutions in Rajasthan

## ❀ Notification

In supersession of all previous orders and rules governing the grant in aid to non Government educational and cultural institutions, the Governor has been pleased to make the enclosed revised rules to regulate payment of grant in aid to the non Government institutions functioning for the educational and cultural development and physical culture of the people in the State

These rules shall be enforced and be applicable to grants payable in 1963-64. The recurring grants payable in 1963-64 shall be on the expenditure in 1962-63

---

❀ Education Department (Cell VI) Notification No F 2 (24)  
Edu/Cell/VI/62 dated 19th January, 1963

## शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के लिये सहायता अनुदान (Grant-in-Aid)

### ❀ विज्ञप्ति

प्र. सरकारी (Non government) शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के सहायता अनुदान सम्बन्धी अनुशासित आदेशों एवं नियमों को निम्नभावित करते हुए राज्यपाल ने राजस्थान की जनता के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास एवं शारीरिक संवर्धन के लिये कार्य करती हुई प्र. सरकारी संस्थाओं के सहायता अनुदान को व्यवस्थित रूप से वितरण के लिये सलग्न नियम लागू किये हैं।

ये नियम 1963-64 के अनुदान वितरण से लागू होंगे। 1963-64 में आवर्ती (Recurring) अनुदान वितरण 1962-63 के खर्चों पर होगा।

---

शैक्षणिक विभाग (प्रकोष्ठ 6) विज्ञप्ति संख्या एक 2 (24) सिंगा/प्रकोष्ठ 6/62  
दिनांक 19 जनवरी, 1963। (प्रमाधिकृत हिंदी अनुवाद) राजस्थान।  
संहिता का अध्याय (17)।

# THE RULES FOR PAYMENT OF GRANT IN AID TO NON- GOVERNMENT EDUCATIONAL, CULTURAL & PHYSICAL EDUCATION INSTITUTIONS IN RAJASTHAN, 1963

1 Short title —These Rules may be called the Rajasthan Grant in aid to educational and cultural institutions Rules, 1963

2 Definitions —In these rules unless the context otherwise requires —

- (a) Director of Education in case of degree and Post graduate colleges means the Director of College Education, Rajasthan
- (b) Director of Education in case of schools and other institutions (other than degree and Post-graduate colleges and institutions of Sanskrit education) means the Director of Primary and Secondary Education  
 \* "Director of Education" includes "Additional Director/Joint Director"
- (c) Director of Education in case of institutions of Sanskrit Education means Director of Sanskrit Education
- (d) Director of Education in case of institutions of Sanskrit Education means Director of Technical Education
- (e) Government means the Government of the State of Rajasthan
- (f) University will include University of Rajasthan, Jodhpur University and such other universities as may by law be established in Rajasthan
- ×(g) 'Examiner' means the Examiner, Local Fund Audit Department Rajasthan Jaipur

---

\* Added vide No 2 (24) शि प्र/6/62 Date 8.4.68 applicable from 18.10.1964

× Vide No 10 (102) Edu/VI/78 dated 28-5-79 Applicable w.e.f 1-4-1979

## राजस्थान में अ-सरकारी शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं शारीरिक शिक्षण सस्थाओं को सहायता अनुदान वितरण करने के नियम —

1 संक्षिप्त नाम —इन नियमों को 'शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक सस्थाओं के लिये राजस्थान सहायता अनुदान नियम सन् 1963' के नाम से सम्बोधित किया जावेगा ।

परिभाषाएँ —इन नियमों में जब तक कि प्रसंग का अर्थ अथ अपेक्षित न हो—

(क) स्नातक ( Degree ) एवं स्नातकोत्तर (Post graduate) महाविद्यालयों के सम्बन्ध में शिक्षा-निदेशक से अभिप्राय, राजस्थान के महाविद्यालय (College) शिक्षा निदेशक से है ।

(ख) विद्यालयों एवं अन्य सस्थाओं (स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों एवं संस्कृत शिक्षण सस्थाओं के अलावा) के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक से अभिप्राय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के निदेशक से है ।

ॐ निदेशक शिक्षा' में 'अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक शामिल है ।

(ग) संस्कृत शिक्षण सस्थाओं से सम्बन्धित शिक्षण सस्थाओं से अभिप्राय, संस्कृत शिक्षा निदेशक से है ।

(घ) तकनीकी (Technical) शिक्षण सस्थाओं से सम्बन्धित शिक्षा निदेशक से अभिप्राय, तकनीकी शिक्षा निदेशक से है ।

(ङ) सरकार से अभिप्राय, राजस्थान राज्य सरकार से है ।

(च) राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय एवं राजस्थान में विधि द्वारा स्थापित किये जा सकने वाले ऐसे अन्य विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के अन्तर्गत होंगे ।

× (छ) "परीक्षक" से अभिप्राय 'परीक्षक' स्थानीय निधि अथ केंद्र विभाग, राजस्थान, जोधपुर से है ।

ॐ क्रमांक—एफ 2 (24) शिप्र० /6/62 दि० 8 4 68 द्वारा जोड़ा गया और दि 18 10 64 से प्रभावशील ।

× टिप्पणी पृष्ठ 2 पर ।



3 Eligibility —All institutions functioning in Rajasthan for the educational and cultural development and physical culture of the people are eligible for the following kinds of grants which may be paid at the direction of the sanctioning authority —

- (i) Recurring or maintenance grant
- (ii) Non recurring grant towards equipments/buildings etc , and
- (iii) Such other grants as may be sanctioned by the Government from time to time

Note 1 —The Government, in exceptional cases, may also sanction an ad hoc non recurring grant to any such institutions functioning outside Rajasthan on such terms and conditions as it may deem fit to impose, if such an institution is of an all India character and its project and activities have been approved by the Central or any State Government

Note 2 —Proprietary institutions (i.e institutions not registered under either the Society Registration Act, 1860 or Rajasthan Public Trust Act or any other Act etc that may be specified by the Government) will not be eligible for any kind of grant from public funds

Note 3 —Moneys annually granted from public funds for undertaking educational activity in the State are administered under the control of the Director of Education in accordance with the conditions set forth in these rules

Note 4 —The payment of grants to institutions will be subject to the proviso that the requisite budget grants are sanctioned by the State Legislature Notice of the probable reduction in any year will be given as soon as possible after the budget grants are passed and such reduction will continue in force until the notice is modified or cancelled

योग्यता — राजस्थान में जनता की शिक्षा एवं संस्कृति के विकासार्थ एवं शारीरिक संवर्धन के लिये कतव्यरत सम्पूर्ण संस्थाएँ, स्वीकृतिदाता प्राधिकारी (Sanctioning authority) की स्वेच्छा (discretion) पर निम्न प्रकार के अनुदान लेने योग्य हैं —

(i) अनावर्ती अनुदान ।

(ii) उपकरणों/भवनो इत्यादि के लिए अनावर्ती अनुदान ।

(iii) ऐसे अन्य अनुदान जो सरकार ने समर्थ स्वीकृत किये जा सकें ।

टिप्पणी—1 अपवादित (Exceptional) अवस्था में सरकार राजस्थान से बाहर किसी भी ऐसी संस्था को, ऐसी शर्तों पर जो वह लागू करने योग्य मानती हो अनुदान स्वीकृत कर सकेगी,

यदि ऐसी संस्था सम्पूर्ण भारत का स्तर रखती हो और इसकी परियोजना केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो ।

टिप्पणी—2 स्वामित्वपूर्ण संस्थाएँ—जैसे वे संस्थाएँ जो कि सन 1860 ई के सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट (Societies Registration Act) या राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट या किसी अन्य एक्ट आदि जो कि सरकार द्वारा उल्लिखित हो, के अन्तर्गत पंजीकृत (Registered) न हो, सावजनिक कोष (Public Fund) से किसी भी प्रकार के अनुदान के लिये योग्य (Eligible) न होगी ।

टिप्पणी—3 राज्य में शैक्षणिक कार्य के लिए सावजनिक कोष से वार्षिक अनुदान राशियाँ, इन नियमों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार निदेशक, शिक्षा के नियंत्रण में प्रवर्धित हैं ।

टिप्पणी—4 संस्थाओं के अनुदान का वितरण करने में शत यह होगी कि आवश्यक अनुदान बजट राज्य विधान सभा द्वारा स्वीकृत किया जावे । किसी भी वर्ष में समाविष्ट कमी की सूचना अनुदान बजट की स्वीकृति के बाद शीघ्रातिशीघ्र दी जायेगी और ऐसी कमी तब तक चालू रहेगी, जब तक कि वह सूचना संशोधित अथवा विलोपित न हो जाये ।

**Rule 2 Classification of institutions**—The institutions will be classified under two categories—

(a) **Educational institutions**—In this category shall be included all schools, colleges, technical institutions and other institutions imparting primary, secondary or post secondary (higher) education and following the curricular prescribed or approved by the Education Department of the Government of Rajasthan or the Ministry of Education, Government of India, Board of Secondary Education Rajasthan, Statutory Universities established or to be established in Rajasthan

(b) **Other institutions**—In this category will be included institutions dealing with other aspects of education such as Pre Primary Training Institutions, pre Primary Montessori and Kinder Garten Schools Research and Cultural Societies engaged in the advancement of knowledge or cultural institutions for the collection, preservation, editing and publication of old literature which are not attached to a recognised school or college provided that they do not take part in communal or subversive activities, (Sanskrit Pathshalas and Colleges) societies or special schools engaged in the teaching of Music and/or Dance and or Drama or Physical Education, Physical culture organisation and sports Associations or other Bodies conducting tournaments and competitions in games sports or cultural activities special schools for physically handicapped children, Arts, (Science or Commerce Colleges, Teachers Training Colleges or Schools, Engineering College/Vocational and Technical Schools) or Institutes including Art or Craft Schools, Rural Institutes Scouts/Guide Association Vocational Guidance Clinics which are attached to educational institutions institutions for adult and social education, public libraries Educational Camps and tours etc etc

**Rule 3 Conditions of grant**—No grant shall be made to an institution unless it agrees to comply with the conditions hereinafter laid down which are over and above the conditions prescribed by the University, the Board of Secondary Education,

नियम 2—संस्थाओं का वर्गीकरण —संस्थाएँ निम्न दो श्रेणियों में विभक्त होंगी—

(अ) शिक्षण संस्थाएँ —इस श्रेणी में समस्त शालाएँ महाविद्यालय, औद्योगिक संस्थाएँ या दूसरी संस्थाएँ जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षा देती हों और जो राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग या भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय या उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल राजस्थान या राजस्थान में स्थापित या स्थापना किये जाने वाले विधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित या स्वीकृति पाठ्यक्रम का अनुसरण करती हों, सम्मिलित होंगी ।

(ब) अन्य संस्थाएँ —इस श्रेणी में शिक्षा के अन्य पहलुओं का सम्पादन करने वाली संस्थाएँ जैसे पूर्व प्राथमिक (Pre primary) प्रशिक्षण संस्थाएँ, नर्सरी, माटेसरी एवं किंडरगार्टन शालाएँ, ज्ञानोन्नति के लिए शोध एवं सांस्कृतिक समितियाँ अथवा प्राचीन साहित्य संग्रह, संरक्षण, सम्पादन एवं प्रचार के लिए सांस्कृतिक संस्था, जो किसी भी मापदंड प्राप्त (Recognised) शाला अथवा महाविद्यालय से सलग्न न हों, बशर्ते कि वे साम्प्रदायिक अथवा विध्वंसकारी कार्यों में भाग न लेते हों, संगीत और/या नृत्य और/या नाटक (Drama) शिक्षण अथवा शारीरिक प्रशिक्षण के लिये कठोरतम समितियाँ अथवा वरिष्ठ शालाएँ (संस्कृत पाठशालाएँ एवं महाविद्यालय), सांस्कृतिक सवधन संगठन और क्रीडा (Sports) सभ अथवा खेल-कूद या सांस्कृतिक कार्यों के लिये प्रतियोगिताएँ और स्पर्धायें संचालन करने वाली दूसरी संस्थाएँ, विकांग बच्चों के लिए 'विशिष्ट शालाएँ', कला विज्ञान अथवा वाणिज्य महाविद्यालय, अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय अथवा शालाएँ यत्र शास्त्र महाविद्यालय, व्यवसायिक और शिल्प (Technical) शालाएँ अथवा कला या हस्तकला शालाएँ ग्रामीण संस्थाएँ, बालचर (Scouts) भाग प्रदर्शन समितियाँ, शिक्षण संस्थाओं से सम्बंधित व्यावसायिक भागदशक क्लिनिक (Clinics) प्रोड एवं सामाजिक शिक्षण संस्थाएँ, सावजनिक पुस्तकालय, शिक्षण शिविर आदि संस्थाएँ सम्मिलित होंगी ।

नियम 3 अनुदान के लिये शर्त —किसी संस्था को जब तक अनुदान प्राप्त नहीं होगा जब तक वह एतत्पश्चात् रखी गई शर्तों की पूर्ति के लिए सहमत न हो, जो कि विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मंडल, राजस्थान (Board of Secondary

Rajasthan and the State Department of Education and every institution which applies for grant in-aid shall be deemed to have accepted its obligation to comply with these conditions —

(1) The institution shall neither prepare nor send up candidates unless permitted by the Director of Education for an examination held in another State when an examination of the same nature is held in Rajasthan by the Education Department or the Board of Secondary Education or the University

(2) The records and accounts of the institution shall be open to inspection and audit by persons authorised by Government or the Education Department or the Accountant General

(3) Admissions and all facilities including free studentship, half free studentships provided by the institutions shall be available to every section of people without any distinction of caste or creed

(4) The institution shall not be run for the profit of any individual and its Governing Body/Council or Management is such as can be trusted to utilise its assets for the furtherance of the objects of the institution

(5) The institution shall, satisfy the requirements laid down under Appendix I regarding to constitution of the management or Governing Body Among other things the constitution of the said body shall ensure its secular character by specially laying down that not more than 2/3rd of its members shall belong to any particular caste, sects or creed Any change in the personnel of the Governing or Managing Body shall be reported early to the Department

(6) The institution shall supply to the Education Deptt a list of all its assets, that the income of which is utilised for its expenditure

(7) In the event of the Government being satisfied that a serious dispute exists in the Managing Committee or Governing Board of the institution which hampers the smooth running of the institution and/or the election of the members of the

Education Rajasthan) और राज्य शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के प्रतिरिक्त हो, और सहायता अनुदान के लिए आवेदन देने वाली हर एक संस्था निम्न शर्तों की पूर्ति के लिए इसके आधार पर स्वीकृत की हुई समझी जायेगी —

(1) संस्था किसी भी उम्मीदवार को, बिना शिक्षा निदेशक की अनुमति के दूसरे राज्यों द्वारा रखी गई परीक्षा के लिये न तो तैयार करेगी और न ही भेजेगी, जबकि उसी प्रकार की परीक्षाएँ राजस्थान में शिक्षा विभाग अथवा माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा विश्वविद्यालय संचालित करता है।

(2) संस्था अभिलेख (Records) तथा विवरणों (Accounts) का निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा (Audit) सरकार अथवा शिक्षा विभाग अथवा महा लेखाकार (Accountant General) द्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्तियों के लिये खुला रहेगा।

(3) संस्था द्वारा प्रदत्त (Provided) प्रवेश की तथा नि शुल्क विद्याध्ययन, प्रदत्त शुल्क विद्याध्ययन सहित समस्त सुविधाएँ, बिना किसी जाति अथवा पथ के भेदभाव के हर एक बग के लिये ग्राह्य होगी।

(4) संस्था किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिये नहीं चलाई जायेगी और उसका संचालन निकाय (Governing body) समिति या व्यवस्थापन पर इस बात के लिए विश्वास किया जा सके कि संस्था की पूँजी केवल उम संस्था के उद्देश्यों की प्रगति के लिये ही उपयोग में लाई जाती है।

(5) संस्था संचालक अथवा व्यवस्थापक समिति के सम्बन्ध में परिशिष्ट (1) में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

दूसरी बात कि उक्त समिति का विधान अपनी असांख्यिक विशेष निर्धारण द्वारा निश्चित करेगा कि इसके सदस्यों का दो तिहाई भाग किसी जाति, बग या पथ विशेष से सम्बन्धित नहीं होगा। व्यवस्थापिका अथवा प्रबंधिका समिति के किसी भी व्यक्तिगत परिवर्तन की सूचना शीघ्रातिशीघ्र विभाग को दी जावेगी।

(6) संस्था शिक्षा विभाग को अपनी सारी सम्पत्ति की सूची, जिसकी प्रायः व्यय के उपयोग में लाई जाती हो, देगी।

(7) सरकार के सतुष्ट हो जाने की दशा में, कि संस्था की प्रबंधक समिति या व्यवस्थापक में कोई गंभीर भ्रष्टाचार है, और संस्था के सुचारु रूप से चलने में बाधक है और या प्रबंध समिति के सदस्यों को चुनाव जान बूझकर 6 माह से अधिक विलम्बित किये हैं। सरकार उहे कारण बतलाने का सूचना पत्र देने के पश्चात्

Managing Committee is wilfully delayed for more than six months the Government after giving them a show cause notice may suspend the Governing Body/Council or the Managing Committee and appoint an Administrator to exercise control over the assets and to run the institution till a new Governing Body/Council or the Managing Committee is formed according to rules or the dispute is settled otherwise

(8) The institution shall not be closed down or down graded without atleast one full academic year's notice being given to the Department. Such notice shall contain (i) the reasons of the intended closure or down grading and (ii) the list of all the assets held by it

(9) The institution shall unless specially exempted by Government, invest its endowment in trust stock or place them in deposit in the State Bank of India, the Post Office Savings Bank or any Schedule Bank or one Bank recognised by the State Government. All money realised as fees from students, contributions endowment and donations received for the institutions, its reserved funds, sums earmarked for building operations or other capital purposes and grants in aid shall constitute the Institutional Fund, which shall be placed in the State Bank of India the Post Office Savings Bank or any other Scheduled Bank or State Recognised Bank. No money shall be kept out of the Institutional Fund. Withdrawals from the Institutional Fund shall be made only by a person who is duly authorised by the Governing Body or the Managing Committee to operate the Fund and only for the purpose of incurring expenditure for the maintenance or improvement of the institution

(10) The institution shall see that the number of pupils on roll and their average attendance or the number of persons deriving benefit from it, does not fall below the standard or

व्यवस्थापक सभा/समिति अथवा प्रबन्धक समिति को निलम्बित कर सकती है और तब तक के लिये सम्पत्ति नियंत्रण तथा सत्था को चलाने के लिए एक प्रबन्धक नियुक्त कर सकती है जब तक या तो एक नई व्यवस्थापक सभा/समिति अथवा प्रबन्धक समिति न बन जाय या भंगवा न सुलभ जाय ।

(8) विभाग को बिना एक पूरे वर्ष की सूचना के कोई भी सत्था बन्द नहीं होगी अथवा स्तरावनत (down guarding) नहीं होगी । ऐसे सूचना पत्र में निम्न बातें होगी —

(i) बन्द करने का अभिप्राय या स्तरावनति (down guarding) का कारण ।

(ii) समस्त रक्की हुई सम्पत्ति की सूची ।

(9) सत्था तब तक अपने धर्मस्व को 'ट्रस्ट स्टॉक' (Trust stock) में विनियोजन (Invest) करेगी अथवा स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank) में अथवा केन्द्रीय सरकार से मायता प्राप्त किसी बैंक में धरोहर के रूप में रखेगी, जब तक वह सरकार से विनोय रूप से मुक्त न हो, सत्था के लिए विद्याविद्या से गुल्ब के रूप में अथवा चन्दा (Contribution) धर्मस्व और दात के रूप में धमूल की गई समस्त राशि इसके सचित को धवन धरम्मत अथवा दूसर मूल कायों के लिये सुरक्षित राशि तथा महायक अनुदान आदि के रूप में समस्त राशि सम्पदा कोष (Institutional fund) में होगी, जो कि स्टेट बैंक आरु इडिया, पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक अथवा किसी अन्य अनुसूचित बैंक अथवा केन्द्र में मायता प्राप्त बैंक में रखी जायेगी । कोई भी राशि सत्था कोष से बाहर नहीं रखी जायेगी । सत्था कोष से राशि केवल वही व्यक्ति निकाल सकेगा जो कि कोष को धार्यावित करन का और वह भी केवल प्रबन्ध के चालू खर्चों के लिये (Incurring expenditure for the maintenance) अथवा सत्था के विकास के लिये व्यवस्थापिका सभा अथवा प्रबन्ध समिति से अधिकार प्राप्त किया हुआ हो ।

(10) सत्था देवेगी कि नामावली (On roll) में विद्याविद्या की मर्या और उनकी धीततन उपस्थिति अथवा इससे लाभ लेने वाले व्यक्तियों की मर्या



number mentioned below --

Section	Class	Average of student on roll	Average attendance
Lower Primary School	I to III	45	75%
Pry Section	I to V	75	75%
Middle Sec	VI to VIII	45	75%
Secondary School	IX to X	40	75%
Higher Secondary School	IX to XI	45	75%
Hostels		25	75%
Sanskrit institutions			
Institutions upto Preve hika		12	75%
Madhyama		6	75%
Sanstri & Acharya		2	75%

Note - Provided that the average minimum enrolment in girls institutions shall be atleast 75% of the enrolment in boys institutions mentioned above. The average attendance in girls institutions shall not be less than 60%.

(11) The institution shall promptly comply with all the instructions issued by the Department for the proper running of the institution.

12 The scale of tuition and other fees charged from the students shall not be lower than the scale laid down by the Government in this connection and shall not be changed without the previous approval of the Government.

13 No grant shall be admissible for the starting of a new course, class, section or subject, a project unless previous permission has been obtained from the Department.

If the management of an institution wishes to close down any course, class, section or subject, information of the same shall be given to the Department at least three months before such closures.

लिखे स्तर अथवा सख्या से कम तो नहीं है —

वर्ग	कक्षा	नामवली में श्रीसतन विद्यार्थी	श्रीसतन उपस्थिति
प्राथमिक शालाएँ	प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी	45	75 प्रतिशत
	प्रथम श्रेणी से षष्ठ्य श्रेणी	75	75 "
उच्च प्राथमिक	छठवीं श्रेणी से आठवीं श्रेणी	45	75 ,
माध्यमिक शाला	नवमी श्रेणी से दसवीं श्रेणी	40	75 ,
उच्च माध्यमिकशाला	नवमी श्रेणी से ग्यारहवीं श्रेणी	45	75 "
छात्रावास		25	75 ,
संस्कृत सस्थाएँ			"
प्रवेशिका सस्थाएँ		12	75 "
मध्यमा		6	75 "
शास्त्री तथा आचार्य		2	75 "

टिप्पणी — किंतु साथ ही छात्रागो की सस्थाभा में श्रीसतन कम से कम नामाकन (Enrolment) लडको की सस्था के उपरोक्त दखित नामाकन का 75 प्रतिशत होगा । छात्रागो की सस्था में श्रीसतन उपस्थिति 60 प्रतिशत से कम न होगी ।

(11) सस्था को उचित रूप से चलाने के लिये विभाग द्वारा प्रसारित समस्त निर्देशो (Instructions) का वह सस्था अविलम्ब पालन करगी ।

(12) विद्यार्थिया के लिये शिक्षण एव अर्थ शुल्क की दर, सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित दर (Scale) में कम न होगी और बिना सरकार की पूर्व अनुमति के ये परिवर्तित नहीं की जायेगी ।

(13) कोई सस्था तब तक के लिये नये पाठ्यक्रम की कक्षा, वर्ग अथवा विषय अथवा परियोजना चालू करने के लिये अनुदान के लिये ग्राह्य नहीं होगी, जब तक विभाग में पूर्व अनुमति प्राप्त न हो । यदि सस्था की प्रबन्धिका किसी पाठ्यक्रम, कक्षा, वर्ग अथवा विषय को बन्द करना चाहती है, तो विभाग को उसकी सूचना बन्द करने के कम से कम तीन माह पूर्व दी जानी होगी ।

(14) No untrained teacher shall be permanently appointed in a school or in a teacher training institution without the permission of the Director of Education, unless the teacher concerned has been exempted from the training qualifications by the Department or the Board of Secondary Education

Note — This rule will not apply to Higher Secondary Schools until the academic session 1965-66

(15) An institution shall not appoint staff on a temporary basis for more than two year without the permission of the Director of Education

(16) The age of superannuation for teachers shall not ordinarily exceed 58 and no extension/re employment in service shall be granted beyond the age of 60. In Special cases the Government may waive this condition for not more than 5 years particularly for teachers doing postgraduate teaching or research work

<sup>1</sup>[“The age of superannuation of employees holding posts equal to class III and Class IV employees of Governments shall not exceed 58 and 60 years respectively ”]

<sup>2</sup>[“No Government Servant retired on superannuation will be re employed by any Institution receiving grant under these Rules ”]

<sup>3</sup>[“Teacher who have received National and State Awards may be re employed by the aided institutions till such teachers complete 58 years. Such aided institution would receive the usual grant in aid on the expenditure incurred on such teachers also ”]

---

1 Added as new para vide No F 1 (164) Edu/Cell VI/68 dated 21-3 1969, Applicable from 1 7 1969

2 Added vide No F 1 (164) Cell/VII/68 dated 13-3 1970, applicable from 1 7 1970

3 Added vide No F 7 (10) Gr V/74 dated 19-7-1974

(14) अप्रशिक्षित (Untrained) अध्यापक, बिना निदेशक की अनुमति के तब तक के लिये किसी शाला अथवा अध्यापक प्रशिक्षण सस्था में स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जावगा, जब तक सम्बन्धित अध्यापक विभाग अथवा माध्यमिक शिक्षा मण्डल से प्रशिक्षण योग्यताओं के लिये विमुक्त (Exempted) न हो।

टिप्पणी — यह नियम उच्च माध्यमिक शालाओं के लिये शिक्षण सत्र 1965-66 तक लागू नहीं होगा।

(15) बिना शिक्षा निदेशक की अनुमति के, कोई भी सस्था कर्मचारी (Staff) की दो वष से अधिक समय के लिये अस्थाई नियुक्ति नहीं करेगी।

(16) साधारणतया अध्यापकों की अधिवाषिकी आयु (Superannuation age) 55 वर्ष से अधिक नहीं बढ़गी तथा सेवा में पदोन्नति/पुनः नियुक्ति (Re-employment) 60 वर्ष की आयु के पश्चात् स्वीकृत नहीं की जायगी। विशेष परिस्थिति में सरकार, विनियमिता स्नातकोत्तर अथवा अनुसंधान कार्य करने वाले अध्यापकों के लिये इस शत की 5 साल तक के लिये त्याग सकती है।

[सरकारी कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में समकक्ष पदों को धारण करने वाले कर्मचारियों की अधिवाषिकी आयु क्रमशः 58 और 60 वर्ष से अधिक नहीं होगी]<sup>1</sup>

[इन नियमों के अधीन सहायता प्राप्त कोई सस्थान किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी को जो अधिवाषिकी पर सेवा निवृत्त हुआ है, पुनर्नियोजित नहीं करेगा]<sup>2</sup>

[अध्यापकों जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हैं, उनको 58 वर्ष की आयु पूरी करने तक के लिये किसी सहायता प्राप्त सस्थान में पुनर्नियोजित किया जा सकेगा। ऐसे सहायता प्राप्त सस्थान ऐसे अध्यापकों पर खर्च किये व्यय पर भी सामान्य सहायता प्राप्त करेंगे]<sup>3</sup>

1 क स एफ 1 (164) शिक्षा/प्र 6/68 दि 21-3-69 द्वारा जोड़ा गया तथा दि 1-7-69 से लागू।

2 क स एफ 1 (164) शिक्षा/प्र 6/68 दि 13-3-1970 द्वारा जोड़ा गया तथा दि 1-7-1970 से लागू।

3 क स एफ 7 (10) अ 5/74 दि 1974 द्वारा जोड़ा गया।

(17) Grant in aid shall not be sanctioned to such of the institutions which have failed to comply with the conditions in the past

(18) The Grant in-aid shall be utilised for the same purpose for which the same is sanctioned

(19) The un-utilised balance shall be surrendered to the Department/Government before the close of the academic session

**Rule 4 Condition of Service of the staff** —(a) The conditions of service of every member of the teaching and ministerial staff appointed substantively shall be governed by an agreement executed by him and the Governing Body/Council or the Managing Committee, in the form given in Appendix III. Variations in minor details may be approved by the Director of Education. The agreement must be executed within one month of the appointment of the persons on probation.

(b) The scale of pay and allowances to the staff of the institutions shall not be less than those prescribed by the Government for the staff of similar category in Government institutions. In case of higher salary scales grant in aid shall ordinarily be admissible at the prescribed Government scales only. The Government may in special cases allow grant on higher scales.

(c) Rules governing private tuitions and appearing at public examinations for members of the staff of the institution shall not be more liberal than those prescribed for Government institutions of the same type and standard.

(d) Salaries to the staff shall be paid in full and regularly every month and no unauthorised cut shall be made therein. The Director of Education may, if he considers it necessary, direct the Governing Body/Council or the Management of any particular institution to discharge salaries by cheque.

(e) No persons on the staff of the institution shall be dismissed or removed or reduced in rank until he has been given

(17) सहायता-अनुदान उन संस्थाओं के लिये स्वीकृत नहीं किया जायेगा जो भूत काल में शर्तों की पूर्ति में असफल हो गई हो।

[18] सहायता अनुदान जिस कार्य के लिये स्वीकृत हुआ है उसी कार्य के उपयोग में लिया जायेगा।

(19) बिना प्रयोग में लाया गया शेष धन शिप्यण सत्र की समाप्ति के पूर्व विभाग/सरकार को समर्पित किया जायेगा।

#### नियम 4 --कर्मचारी गण (Staff) की सेवा की शर्तें --

(क) शिक्षक एवं प्रशासी वर्ग में हर एक सदस्य की सेवा शर्तें, उसके द्वारा तथा व्यवस्थापिका सभा/समिति प्रबंधिका समिति के द्वारा, परिशिष्ट 3 में दिये गये रूप में, लिखित सविदा से शासित होगी। इन में परिवर्तन शिक्षा निदेशक की अनुमति से हो सकते हैं। व्यक्ति की परीक्षा (Probation) पर नियुक्ति के एक माह के अंदर सविदा लिखी जानी चाहिये।

(ख) संस्था के कर्मचारीगण के वेतन व भत्ते की दर, सरकार द्वारा सरकारी संस्थाओं में उसी श्रेणी के कर्मचारीगण के लिये निर्धारित दर से कम नहीं होगी। उच्च वेतन श्रेणी के सम्बन्ध में साधारणतया, सहायता अनुदान केवल सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ग्राह्य होगा। विशिष्ट व्यवस्था में सरकार उच्च वेतन श्रेणी अनुदान स्वीकार कर सकती है।

(ग) संस्था के कर्मचारी वर्ग के सदस्यों के लिये, निजी उपशिक्षण (Private tuitions) तथा सावजनिक परीक्षाओं में बैठने के नियम उसी तरह की तथा उसी श्रेणी की सरकारी संस्थाओं में निर्धारित नियमों से अधिक उदार (Liberal) नहीं होंगे।

(घ) कर्मचारी गण को वेतन, पूरा तथा नियमित रूप से हर माह चुकाया जायेगा तथा उसमें कोई अनाधिकृत (Un authorised) कटौती नहीं की जायेगी। शिक्षा निदेशक यदि आवश्यक समझे, तो किसी भी संस्था की व्यवस्थापिका सभा/समिति अथवा प्रबंधिका को भुगतान पत्र (cheque) द्वारा वेतन वितरण के लिये निर्देशित कर सकता है।

(ङ) संस्था के कर्मचारी वर्ग का कोई भी व्यक्ति तब तक के लिये सेवामुक्त निष्कासित, पदावनत नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके बारे में की जाने वाली

a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him provided that this clause shall not apply —

- (i) Where a person is dismissed or removed or reduced in rank on the ground of conduct which led to his conviction on criminal charge, or
- (ii) Where it is not practicable to give that person an opportunity of showing cause and the Department's consent has been obtained before the action is taken

(f) An order imposing punishment of the kind referred to in clause (e) above shall contain the reasons thereof and a copy of it shall be given to the person concerned immediately and sent to the Deptt for information within a month

(g) An appeal shall lie to the authority mentioned in Appendix V from every order of the Governing Body/Council or the Managing Committee imposing punishment referred to in clause (e) above

(h) The management shall implement the order passed by the appellate authority mentioned in (g) above within three months of the receipt of the copy thereof unless such implementation is stayed by the orders of any court or any higher authority

(i) In case the management fails without sufficient reason to pay the amount if any, specified in the order of the appellate authority the Director may deduct it from the next grant in aid and, if necessary from subsequent grant in aid bills also and pay the person concerned on behalf of the management. This would be deemed to be a payment to the management of the institution itself

(j) P F Rules are to be followed by the institution as framed by the Department/Board of Secondary Education/University/Universities to be established

§[Provided that the institutions shall follow the directions issued by the Government of Rajasthan with regard to investment of past accumulations as well as current and future accretions to the G P F account and ancillary matters from time to time

---

§ Proviso added to Rule 4 (j) and Rule 4 (k) Substituted vide No F 10 (102) Edu/vi/78 dated 28.5.1979, w e f 1.4.1979

प्रस्तावित कायदाही के विरुद्ध कारण बतलाने के लिये, उसे यथोचित अवसर न दिया गया हो, वशर्ते कि निम्नलिखित परिस्थितियों में यह खण्ड लागू नहीं होगा —

- (1) जहां एक व्यक्ति आचरण के आधार पर पदच्युत अथवा निष्कासित अथवा पदावनत किया गया है, जिसे आपराधिक आरोप के आधार पर उसका दोष सिद्ध हो जाय अथवा
- (2) जहां उस व्यक्ति को कारण बतलाने का अवसर देना व्यवहारिक न हो तथा कायदाही करने से पूर्व विभाग की सम्मति प्राप्त कर ली गई हो।

(च) उप निर्दिष्ट खण्ड (ड) की तरह के दण्ड से आरोपित आदेशों में उसके कारण प्रामाणिकता होने और उसकी एक प्रति सम्बंधित व्यक्ति को शीघ्रता शीघ्र दी जायेगी तथा एक प्रति विभाग को सूचनाय एक माह के अन्दर भेजी जायेगी।

(छ) उप निर्दिष्ट खण्ड (ड) में दण्ड देने वाली व्यवस्थापिका सभा/समिति अथवा प्रबन्धिका समिति की हर एक आज्ञा से, परिशिष्ट 5 में वर्णित आदेशानुसार अपील होगी।

(ज) ऊपर खण्ड (घ) में वर्णित अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को प्रबन्धिका समिति उसकी प्रति की प्राप्ति के तीन माह के अन्दर कार्यावित करेगी जब तक कि ऐसे क्रिया-व्ययन को किसी न्यायालय अथवा किसी उच्च प्राधिकारी द्वारा स्थगित नहीं कर दिये गये हों।

(झ) अपील प्राधिकारी के आदेशों में उल्लिखित यदि कोई भी राशि जिसकी प्रबन्धिका समिति बिना पर्याप्त कारणों के चुकाने में भ्रष्टाचार करती हो, की प्रवृत्ति में निदेशक अगली सहायता अनुदान में से उस राशि की कटौती कर सकता है, तथा यदि आवश्यक हो तो बाद की सहायता अनुदान में से भी काट सकता है तथा प्रबन्धिका के निमित्त सम्बंधित व्यक्ति को चुका सकता है। यह राशि सत्या की प्रबन्धिका को वितरण (Payment) समझा जायगा।

(ञ) विभाग/माध्यमिक शिक्षा मंडल/विश्वविद्यालय/स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालयों द्वारा बनाये गये भविष्यनिधि (P F) नियम सत्या द्वारा अनुमोदित है।

॥ परंतु यह है कि सत्यायें पिछली सचित राशि तथा चालू व भविष्य के सामान्य भविष्य भविष्य निधि की एकत्रित राशि के विनियोग और तत्सम्बन्धी मामलों के बारे में समय समय पर राजस्थान सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेगी।



**Note —**The Department/Board of Secondary Education/University/Universities to be established shall make necessary amendments in the respective rules framed by them

- (k) (i) All accumulated, current and future accretions to the P F amount of the employees and contribution of the institution shall be deposited in the interest bearing personnel deposit account by the institution in Government Treasury in the manner and as per directions laid down by the State Govt from time to time
- (ii) The reserve funds and deposits etc of institutions shall also be invested in the State Govt securities or National Savings Securities viz Post office Savings Bank Account, National Defence Certificates or Defence Deposit Certificates only
- (iii) All the other recurring and non recurring grants which are not needed within a period of three months shall be deposited in the Post Office Saving Account

**Note —**Reserve Funds will be invested in the manner prescribed under (ii) above only if under the relevant rules the maintenance of such funds is a condition precedent for entitlement to grant in aid ]

**Rule 5 Assessment of annual recurring grant—(a)**[Annual recurring grant will be given on the basis of estimated expenditure of the current year and be subject to adjustment from the grant payable in the next year ]

(b) Approved expenditure shall be arrived at according to rules and such other instructions that may hereafter be issued from time to time by the Director of Education

---

\* Amended vide No F-1 (45) Edu /C/vi /67 dated 15th September 1970 Applicable from 1-4-1970 "Note (1) below Rule 5 was deleted—

**"Note (1) —**In special cases such as a when a new course or class is started or a new experiment or project undertaken or an institution has to face serious financial hardships grants may be sanctioned on the basis of the current year's budget estimates provided that if the whole amount of the grant is not spent during the year the saving shall be recovered from the institution or deducted from the next year's grant'

टिप्पणी—विभाग/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्व विद्यालय/स्थापित होने वाले विश्व विद्यालय उनसे द्वारा बनाये गये सम्बंधित नियमों में आवश्यक सशोधन करेंगे।

(ट)(1) समस्त एकत्रित, चालू व भविष्य में होने वाले कमचारियों के भविष्य निधि खातों की एकत्रित राशि और सस्था के भ्रष्टान को सस्था द्वारा सरकारी कोष में व्याज सहित व्यक्तिगत जमा खाते (P D Accounts) में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित निर्देशों व तरीके से जमा कराना होगा।

(11) सस्थाओं के सुरक्षित कोष और निक्षेप (डिपोजिट) आदि भी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में या राष्ट्रीय बचत प्रतिभूतियों जैसे— डाकघर, बचत बैंक खाता, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाणपत्र या सुरक्षा निक्षेप प्रमाणपत्र में भी विनियोजित किया जावेगा।

(111) अन्य समस्त आवश्यक एवं अनावश्यक अनुदान राशि जिसकी सीमा महीने की अवधि में आवश्यकता न हो, डाकघर बचत खाते में जमा कराई जावेगी।

टिप्पणी—सुरक्षित कोष को केवल ऊपर (11) में विहित तरीके से विनियोजित किया जावेगा, यदि सम्बंधित नियमों के अधीन ऐसे कोष का रखना अनुदान की पारता के लिये एक पूर्व शर्त हो।]

नियम 5 वार्षिक पुनरावत अनुदान का निर्धारण—(क) [ चालू वर्ष के अनुमानित व्यय व आधार पर वार्षिक आवतक अनुदान दिया जावेगा और वह अगले वर्ष में देय अनुदान से समायोजित किये जाने के अध्येक्षीन होगा।]

(ख) स्वीकार किया गया खच नियमों तथा ऐसे दूसरे अनुदेशों, जो इसके पश्चात शिक्षा निदेशक द्वारा समय समय पर निकाले गये हों, के अनुसार गिना जावेगा।

1 No F 1 (45) Edu/C/VI/67 dt 15-9-70 द्वारा सशोधित व दि 1-4-1970 से लागू। नीचे की टिप्पणी (1) विलोपित की गई जो इस प्रकार थी—

“टिप्पणी 1—जब कोई नया पाठ्यक्रम अथवा कक्षा प्रारम्भ की गई हो, अथवा एक नया प्रयोग या परियोजना हाथ में ली गई हो, अथवा सस्था को गम्भीर आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हो तो विशिष्ट परिस्थितियों में चालू साल के अनुमानित बजट के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है बशर्ते कि यदि अनुदान की समस्त राशि उसी साल में खच नहीं हुई तो बची हुई राशि सस्था के वापिस ले ली जायेगी अथवा आगामी वर्ष के अनुदान में से काट ली जायेगी।”

(c) Institutions shall be categorised under advise of the Grant in-aid Committee and shall receive Grant in aid as follows —

Category	A 80%	of the approved expenditure of the previous year plus likely annual increment of staff
	B 75%	
	C 60%	
	D 50%	

Spl Category—(institutions carrying on the work of education on experimental and pioneering lines in accordance with the criteria laid down by the Deptt of Education 90%

Note —The case for an increase in grant in aid can, as a rule be reviewed by the Grant in aid Committee ordinarily after 3 years on the basis of inspection reports and general improvements in other principles of categorisation

Grant in aid Committee will admit institutions to the special category after examination of their cases under criteria listed in Appendix X

(d) The total recurring grant in aid from Government of Rajasthan in any year shall not exceed the difference between the total approved expenditure taken into account and the income from the fees and other recurring sources during the same year including grants from other States and Central Government Sabhas, Societies and local Bodies

❖ For the purpose of this rule

(i) income from interest on reserve fund or rent of properties

(ii) fee income from fee charged at a rate higher than Government rates to the extent of the actual excess realised shall not be considered as income from other recurring sources

Note (2) —The income from fees and fines referred in sub rule (d) includes the following fees and shall be separately mentioned in the statement of audit prepared by the Chartered Accountant or other approved auditors —

(1) Tuition fees

(2) Tutorial fees

(ग) सहायता अनुदान समिति की सलाह के अनुसार, सस्यायें श्रृणियो मे विभक्त की जायेंगी तथा निम्न प्रकार से सहायता अनुदान प्राप्त करेंगी —

श्रेणी

क	80 प्रतिशत	गत वर्ष के माय खच का तथा
ख	75 "	कमचारी वग की वेतन वृद्धि का
ग	60	
घ	50 ,	

300  
विविध

विशिष्ट श्रेणी—शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित कसौटी के अनुसार प्रयोगात्मक शिक्षण कार्य को चलाये वाली सस्याएँ—90 प्रतिशत ।

टिप्पणी— सहायता अनुदान मे वृद्धि की स्थिति नियमानुसार सहायता अनुदान समिति द्वारा माघारणतया निरीक्षण प्रतिवेदन (Reports) तथा दूसरी श्रेणी के मिद्दानो मे सामाय उन्नति के आधार पर तीन साल पश्चात पुनर्वि लोकित की जा सकती है ।

सहायता अनुदान समिति, परिशिष्ट 10 मे सूचीबद्ध कसौटी मे सस्यायों की परिस्थितियों का निरीक्षण करने के पश्चात ही उनको विशिष्ट श्रेणी मे सम्मिलित करेगी ।

(घ) राजस्थान सरकार से किसी साल मे कुल भावतक अनुदान लेखा किमे हुए कुल स्वीकृत खच तथा उसी साल मे शुल्क तथा दूसरे भावतक साधनो से (जिसमें कि दूसरे राज्या तथा केन्द्रीय सरकार, समाम्री समितिया तथा स्थानीय सस्थाओ द्वारा प्राप्त अनुदान सम्मिलित है) हुई आय के अ तर से अधिक नहीं होगा ।

कृद्स नियम के प्रयोजन के लिए

- (1) सरक्षित कोष (Reserve Fund) अथवा सम्पत्ति के किराये से आय
- (ii) वास्तविक अधिक वसूली की परिधि तक सरकारी दर से ऊँची दर पर वसूल किये गये शुल्को से प्राप्त आय,

दूसर भावतक साधनो से हुई आय की तरह नहीं समझी जायगी ।

टिप्पणी 2—उपनियम (घ) से निर्दिष्ट शुल्क तथा ग्रथं दण्ड (Fines) से हुई आय मे निम्नलिखित शुल्क सम्मिलित है तथा चार्टर्ड अकाउटेन्ट अथवा दूसरे मायता प्राप्त लेखा परीक्षका द्वारा तैयार लेखा परीक्षा विवरण मे अलग से वर्णित होंगे —

- (1) शिक्षण शुल्क
- (2) थ्यूटोरियल शुल्क

कृद्स अध्याय (2) मे परिपत्र देखे

- (3) Admission and re admission fees
- (4) Transfer Certificate fees
- (5) Any other fees not covered by the above except
  - (a) subject fees for example Commerce fees, Science fees, Agriculture fees etc
  - (b) Games fees and fees charged for craft and other activities in Agriculture dairy, Home Science, etc referred in sub clause K M N Rule 6

### (6) Fines

With regard to other fees referred to in (a) and (b) above subject fees games and crafts shall be utilised for the specified purpose for which they are charged and in the event of their non utilisation in full or part, the amount is transferred to the Student Fund to be utilised in the next year. The Governing Body/Council or the Management shall in no case utilise any portion of the students fund for the purpose of running the institution or in payment of salaries of the staff, rent of the buildings etc

**Note (3) —**During each year every institution admitted to the grant in aid list shall provisionally be paid a monthly sum equal to  $1/12$ th or a quarterly sum equal to  $1/4$ th of the annual grant fixed for the previous year till the current year's grant is sanctioned subject to its final adjustment

The following will be the basis for the Categorisation of the institutions —

- (1) Quality of educational work judged on the results on an average of last 3 years of the public examinations of the Highest class in the institution
- (2) Correction work
- (3) Individual attention
- (4) Teaching efficiency
- (5) Discipline and tone of the institution (Rules of discipline Annexure II)
- (6) Extra curricular activities cultural life games, etc
- (7) Contribution to community life (special service in the area)
- (8) Classwise attendances throughout the year

- (3) प्रवेश तथा पुनः प्रवेश शुल्क
- (4) स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क
- (5) कोई दूसरा शुल्क जो उपरोक्त शुल्कों में न माना हो, सिवाय इनके कि—

- (क) विषय शुल्क, जैसे वाणिज्य शुल्क, विज्ञान शुल्क आदि
- (ख) मेल शुल्क तथा हस्तकला और कृषि दुग्ध शाला, ग्रह विज्ञान आदि दूसरे कार्यों के लिए शुल्क, जो कि नियम 8 के उपखण्ड (ट, ड एव ड) में निर्दिष्ट है।

### (6) अथ दण्ड

उपरोक्त (क) तथा (ख) में निर्दिष्ट दूसरे शुल्कों के सम्बन्ध में जैसे विषय शुल्क, मेल तथा हस्तकला शुल्क का उपयोग उल्लिखित उद्देश्य जिसके लिये वे लिये गये हैं में ही होगा और उनका पूरे अथवा किसी भाग के उपयोग न होने की दशा में, वह राशि प्रागामी वर्ष में उपयोग किया जान वाले छात्र कोष में स्थानांतरित कर दी जायेगी। व्यवस्थापिका सभा/समिति अथवा प्रबन्धिका किसी दशा में छात्र कोष का कोई भाग सस्था के चलाने में अथवा कमचारी को वेतन वितरण में अथवा भवन किराया आदि उद्देश्यों के लिये उपयोग नहीं करेगी।

3—सहायता अनुदान मूची में प्रविष्ट हर एक सस्था को हर साल गत वर्ष के निर्दिष्ट वार्षिक अनुदान 1/12 भाग के बराबर मासिक राशि के रूप में अथवा 1/4 भाग के बराबर, सिमाही राशि रूप में अस्थायी रूप से दिया जायगा, जब तक चालू साल का अनुदान, अन्तिम समायोजन (Adjustment) का ध्यान रखते हुए स्वीकृत न हो जाय।

सस्थाओं की श्रेणी विभक्ति का आधार निम्नलिखित होगा —

- (1) शिक्षण कार्य की श्रेणी का निम्न सस्था में सबसे ऊँची कक्षा के गत तीन वर्षों की सावजनिक परीक्षाओं के औसत परिणामों से किया जाये।
- (2) सशोधन कार्य (Correction Work)
- (3) वैयक्तिक ध्यान (Individual Attention)
- (4) शिक्षण दक्षता (Teaching efficiency)
- (5) सस्था का अनुशासन एवं प्रवृत्ति (अनुशासन के नियम, परिशिष्ट II)
- (6) अथ सहगामी प्रवृत्तियाँ (activities) यथा सांस्कृतिक जीवन, खेल इत्यादि।
- (7) सामुदायिक जीवन को योगदान (क्षेत्र में विशिष्ट सेवा)
- (8) सारे साल की कक्षावार उपस्थिति।

- (9) Facilities for games, sports, P T, and participation and achievement in tournaments
- (10) Provision for building and equipment
- (11) Absence of malpractices and irregularities
- (12) Absence of stagnation among students
- (13) Number of faculties and subjects provided

**Note**—The notice period pay recovered from the employees of the institution and the amount of the management share of the Provident Fund Scheme forfeited by the management during the year shall be shown as income in the audited statement and shall be created as income of the institution for the purpose of arriving at the figure of net approved expenditure

**Rule 6 Approved Expenditure**—Approved expenditure referred to in Rule 5 above shall relate to the following items only—

⊗ [Rule '6 (1)' All the items referred to in Rule 6 from (a) to (x) will form component A of the admissible items of expenditure]

(a) Actual salary and Provident Fund contribution not exceeding 6/1 4% in respect of teaching staff except the pre merger employees of the aided institutions of the former Jodhpur State and the C B Schools run by the Municipal Board in Bikaner, Ganganagar, Churu and Bundi District in whose case it shall not exceed 8/1 3 per cent

(b) Salaries and Provident fund contribution not exceeding 6/1 4% in respect of the Ministerial and Non ministerial staff, except the pre merger employees of the aided institutions of the former Jodhpur State and of the C B Schools run by the Municipal Board of Bikaner, Churu Ganganagar and Bundi District in whose case it shall not exceed 8/1 3 per cent

(c) Stationery and printing charges

(d) Postage stamps on official correspondence rent, charges on telephone for college and residential and partly residential High or Higher Secondary School only Aggregate limit will be laid down for postage

⊗ Added & amended vide No F 2 (194) Edu/cell/VI/66 dated 23-3-1968 Item (d) deleted and item (e) to (y) re numbered as (d) to (x)—Refer अध्याय (2)

(9) खेल कूद, पी टी तथा प्रतियोगिताओं में भाग लेने की सुविधायें तथा उपलब्धि ।

(10) भवन तथा सामान के लिए व्यवस्था ।

(11) दुराचरण एवं अनियमितता की अनुपस्थिति ।

(12) विद्यार्थियों में निष्प्रवाहित अनुपस्थिति ।

(13) व्यवस्थित विषय एवं विभागों की संख्या ।

टिप्पणी—संस्था के कमचारियों द्वारा प्राप्त किया गया सूचना अवधि वेतन और भविष्य निर्णय के अंश की प्रवचक द्वारा वष के मध्य में अधिग्रहित की गई है, को लेखा विवरण में भाग व्यक्त करना पड़ेगा और संस्था के वास्तविक स्वीकृत व्यय के अफडे के लिए भाग बताया जायेगी ।

नियम ॥ स्वीकृत खच —उपरोक्त नियम 5 में निर्दिष्ट स्वीकृत खच केवल निम्न लिखित से सम्बंधित होगा ।

॥ [नियम 6(1)—नियम 6 में (क) से (म) तक वर्णित समस्त आइटम ग्राह्य खच का भाग (क) होंगे ।]

(क) वास्तविक वेतन तथा भविष्य निर्णय अंशदान श्रेणीक कमचारियों का 6/1 4 प्रतिशत से अधिक, सिवाय पूर्ववर्ती जोधपुर राज्य के नागरिक सहायता प्राप्त संस्थाओं के कमचारियों, और C B शालाओं, जो बीकानेर, गगानगर, चूरू और बूंदी जिलों में म्यूनिसिपल बोर्डों द्वारा चलाई जाती है, के मामले में 2/1 3 प्रतिशत से अधिक न होगा ।

(ख) वास्तविक वेतन तथा भविष्य निर्णय अंशदान प्रशासी तथा अंशदासी कमचारियों का 6/1 4 प्रतिशत से अधिक, सिवाय पूर्ववर्ती जोधपुर राज्य में पूर्व नागरिक सहायता प्राप्त संस्थाओं के कमचारियों और C B शालाओं जा बीकानेर गगानगर, चूरू और बूंदी जिलों में म्यूनिसिपल बोर्डों द्वारा चलाई जाती है, के मामले में 8/1-3 प्रतिशत से अधिक न होगा ।

(ग) लेखन सामग्री तथा मुद्रण खर्च ।

(घ) कार्यालय सम्बन्धी पत्र व्यवहार के लिए डाक व्यय टिकट किराया, महाविद्यालय तथा निवासाथ तथा आंशिक निवासाथ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालाओं के लिए टेलीफोन के खर्च के लिए कुल सीमा निर्धारित की जायेगी । डाक व्यय के लिये कुल सीमा निर्धारित की जायेगी ।

॥ वि ॥ F2 (194) Edu/Cell/VI/66 दि 23-3-1968 द्वारा संशोधित-आइटम (घ) लोपित किया गया तथा (ड) से (म) को पुनः स्थापित किया गया ।



(e) Water and light charges

(f) Registration, audit fees and affiliation fees

(g) Recurring expenditure on equipment and apparatus

(h) Ordinary repairs to buildings (if these belong to the institution and furniture etc) Repairs may be calculated at 1% for pacca and 2% for Kachha buildings

(i) Building rent (if the building is rented) In all cases the department should be satisfied that the building is not owned by a society consisting of the same community or groups of persons running the institutions concerned. Rent will not be admissible if the building belongs to the same society or groups of persons (see not 5 and 6 below)

(j) Recurring (net) expenditure on Books, Library and Reading Rooms

(k) In the case of residential institutions or educational societies running more than one institution such expenses on management as are necessary or incidental to the establishment and maintenance of the institutions and the society

(l) Recurring net expenditure on games, physical education and other extra curricular activity e.g., camps, annual functions (including prizes) Dramatics, Educational Tours, Excursions, Social Services

(m) Recurring expenditure on craft including Agriculture, Dairy, Home Science after deducting the income accruing therefrom

(n) Expenditure on travelling of teachers in attending conferences and seminars conducted by the Government or Department connected with educational matters, Provided the same has not been paid by the authority calling the teachers or arranging the conferences or seminars, and on journeys

(o) Expenditure on advertisement for the posts of teachers and lecturers for Technical or Science subjects, Home Science, English, Psychology etc at the rate of not more than two advertisement in a year

(p) Petty expenditure according to the prescribed limits for brooms, dusters and earthen pots, rope for water, etc

(ड) जल एवं विद्युत खर्च ।

(च) पंजीयन (Registration) लेखा जोखा शुल्क एवं सलग्नता शुल्क ।

(छ) उपकरण तथा विज्ञान सम्बन्धी सामान के आवश्यक खर्च ।

(ज) भवन की साधारण मरम्मत (यदि सस्था तथा फर्नीचर आदि के सबंध में हो) मरम्मत पक्के भवनों के एक प्रतिशत तथा कच्चे भवनों के लिए 2 प्रतिशत के हिसाब से दी जा सकती है ।

(झ) भवन किराया (यदि भवन किराया का है)—सब अवस्थाओं में विभाग सन्तुष्ट होना चाहिए कि भवन, उसी समाज से वनी हुई समिति का अथवा सस्था को चलाने वाले व्यक्तियों के समूह का तो नहीं हैं । भवन का उसी समाज अथवा व्यक्तियों के समूह का होने की दशा में किराया स्वीकृत न होगा । (नीचे सूचना 5 व 6 देखिये ।)

(ञ) पुस्तकें पुस्तकालयों तथा अध्ययन कक्षों के लिये आवश्यक खर्च ।

(ट) निवासाथ सस्थाएं अथवा शिक्षण समितियाँ, जो कि एक से अधिक सस्था चला रही हैं, की दशा में प्रवर्धिका के ऐसे खर्च जो कि सस्था और समिति की स्थापना एवं बनाने में आवश्यक या आनुषंगिक (Incidental) हों ।

(ठ) खेल शारीरिक शिक्षा, तथा अन्य सह शैक्षणिक प्रवृत्तियों, जैसे शिविर वार्षिक महोत्सव (पारितोषिक आदि खर्च) नाटक, शिक्षण पर्यटन, भ्रमण सामाजिक सेवाएँ आदि, के लिए आवश्यक आधारण खर्च ।

(ड) कृषि दुग्धालय गृह विज्ञान आदि हस्तकलाओं के लिए उनसे अर्जित आय के काटने के पश्चात् आवश्यक खर्च ।

(ढ) शिक्षा सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में सरकार अथवा विभाग द्वारा संचालित सम्मेलन व सभाओं में उपस्थित होने के लिए अध्यापकों को यात्रा खर्च । बशर्ते कि ऐसा खर्च सम्मेलन बुलाने वाले अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया हो ।

(ण) मशीनरी अथवा विज्ञान विषयों गृह विज्ञान, अंग्रेजी शरीर शास्त्र आदि के लिए अध्यापक एवं व्याख्याताओं (Lecturers) के पदों के विज्ञापन के लिए खर्च जो कि वष में दो विज्ञापन से अधिक के लिए नहीं ।

(त) भाड़, इस्टर तथा पानी के लिये मिट्टी के घड़े तथा रस्ती आदि के लिए निर्धारित सीमा के अनुसार साधारण खर्च ।

- (q) Research bulletin for research institutions only
- (r) Book-binding (for public libraries only)
- (s) Training expenses for teachers (according to rules for Government employees)
- (t) Charges on account of taxes on school building to the extent of the amount if actually paid by the Manager
- (u) Travelling expenses of teachers accompanying school children on excursions, subject to the prior approval of the Director of Education
- (v) Expenditure incurred for obtaining rent verification certificates from P W D
- (w) A new institution coming into existence after the commencement of these rules shall not be eligible for grant in aid unless it has continued successfully, at least for one academic session from the date of recognition by the Department. In very special cases, however, this condition may be sanctioned against the approved budget of the First year. Such grants will not exceed half of the salaries of the teaching staff likely to be incurred during the year and will be payable in monthly or quarterly or half yearly instalments as may be required by the management.
- (x) **Expenditure on Hostels** — Approved expenditure for Hostels would relate to the following items —
  - (i) Salary or allowance of the Warden or Superintendent or the Matron
  - (ii) Ministerial and Class IV establishment considered necessary by the Department
  - (iii) Ordinary office contingencies
  - (iv) In the case of Societies running more than one boarding house, such expenses on management as are necessary for and incidental to the establishment and maintenance of the Society as provided under the rules above

**Note 1** — The expenditure on Central office mentioned in (1) shall be approved for grant only when the total approved expenditure of the Society exceeds Rs one lakh per year and at least 3 institutions are being run by the Society. By institutions are meant only those which are recognised as institutions for this purpose by the Department. Institution should not be of the

## अनुदान नियम

(ग) केवल अनुसंधान सस्थाओं के लिए अनुसंधान विवरणिका।

(द) पुस्तकों की जिल्दें (Book Binding) केवल सत्रसाधारण पुस्तकालयों के लिए।

(ध) अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए खर्च (सरकारी कमवारी के सेवा नियम के अनुसार)।

(न) शाला भवन में सीमित मात्रा तक करो का खर्च यदि वास्तव में व्यवस्थापक द्वारा चुकाया गया हो।

(प) शिक्षा निदेशक की पूरा अनुमति को ध्यान में रखते हुए, शाला के बच्चों के साथ यात्रा में जाने वाले अध्यापकों को यात्रा व्यय।

(फ) किराये के प्रमाण के लिए सावजनिक निर्माण विभाग (P W D) से प्रमाण पत्र प्राप्ति के लिए खर्च।

(ब) एक नई सस्था, जो कि इन नियमों के लागू होने के पश्चात् अस्तित्व में आ रही है, सहायता अनुदान पाने की अधिकारिणी तब तक नहीं होगी, जब तक विभागीय मायता की तारीख से एक शैक्षणिक सत्र तक सफलता पूर्वक चालू न रही हो तथापि अधिक विशिष्ट परिस्थिति में सरकार द्वारा इस शर्त को छोड़ना पड़ सकता है। ऐसी अवस्था में प्रथम वर्ष के स्वीकृत बजट के समान अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है। ऐसी अनुदान वर्ष भर के अंदर उठाये जाने वाले शिक्षक वर्ग के सम्पादित वेतन के आधे से अधिक नहीं बढ़ेंगे तथा प्रबन्धिका की इच्छानुसार मासिक, तिमाही तथा अर्द्ध वार्षिक किस्तों में चुकाया जायेगा।

(भ) छात्रावास पर खर्चें—छात्रावास के लिए स्वीकृत खर्चें निम्न विषय से सम्बंधित होंगे—

(1) प्रतिप लक (Warden) अथवा अधीक्षक (Superintendent) अथवा अधीक्षिका (Matron) का वेतन अथवा भत्ता।

(ii) विभाग द्वारा आवश्यक स्वीकृत किया हुआ प्रशासी एवं चतुर श्रेणी (Class IV) का स्थापन।

(iii) साधारण कार्यालय सम्भावयता खर्चें (Contingencies)।

(iv) सस्थाओं के एक से अधिक छात्रावास चलाने की अवस्था में, प्रबंध के ऐसे खर्च जो सस्था के स्थापन एवं साधारण के लिये आनुपमिक (Incidental) तथा आवश्यक हो जैसा उपर्युक्त नियमों में उपबंधित (Provided) है।

टिप्पणी। इस में वर्णित केन्द्रीय कार्यालय के खर्चें तब ही अनुदान के लिए स्वीकृत होंगे, जब कुल समिति स्वीकृत खर्चा एक लाख रु० सालाना से अधिक हो तथा समिति के द्वारा कम से कम तीन सस्थाएँ चलाई जा रही हों। सस्थाओं में अभिप्राय केवल वे जो विभाग द्वारा इसी उद्देश्य के लिए

nature of a Department or section or activity of the same institution

**Note 2** —Charges on account of contribution made by the institution to a pension fund or a gratuity scheme or an account of the pension or gratuity paid to former teachers are ordinarily not admitted for the purpose of grants-in aid unless the rules on the subject are approved by Government provided that in the case of staff obtained on lent services from any State Government or Government of India, pension and leave salary contribution shall be allowed as approved expenditure

**Note 3** —Charges on account of pension to widows of the deceased teachers are ordinarily not admissible for grant in aid unless the rules for grant of pension are duly approved by Government

**Note 4** —Expenditure on rent (to the extent assessed by the P W D for the particular period) is admissible to an institution only when the building has been actually taken on rent and rent-deed containing the terms and conditions of rent is executed and registered, No rent is admissible where a parent body has given a building to a trust for the charitable purpose of running an educational institution as a donation

No rent is admissible where grant in aid has already been given for repairs, additions and alterations of the building used for educational institutions run by a private body

In case institutions or society which is other than the parent body is entrusted with the running of a school and uses building which was got constructed by the parent body for the use of the school and then new managing body is required to execute a bond or agreement and get the same registered to the effect that rent for use of the building will have to be paid by the newly created management to the parent body for running a school, rent by the society will be admissible for grant in aid

**Note 5** —Save otherwise provided no expenditure on repairs of building for which rent is claimed is admissible for grant-in aid as such repairs are to be done by the landlord

**Note 6** —Legal expenses are not admissible for grant in aid as they are non recurring charges Exceptional cases should, however, be referred to the Director with pertinent details for orders, regarding the admissibility of the expenditure

सस्याए हो/सस्या विभाग अथवा शाखा अथवा उसी सस्या की गतिविधि की पकृति की हो, से है ।

टिप्पणी 2 निवृत्ति वेतन कोष अथवा निवृत्ति पारितोषिक योजना को सस्या द्वारा किये गये अशदान के कारण से व्यय अथवा पुराने अध्यापका को चुकाया हुआ निवृत्ति वेतन या निवृत्ति पारितोषिक के कारण साधारणतया तब तक सहायता अनुदान के उद्देश्य के लिए स्वीकृत नहीं किये जायेंगे, तब तक कि अधिनियम सरकार द्वारा मायता प्राप्त न हो, यज्ञते कि राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवाओं से प्राप्त किये गये कमचारियों के मामले में उनका निवृत्ति वेतन और अवकाश वेतन अशदान स्वीकृत व्यय में स्वीकृत किया जायेगा ।

टिप्पणी—3 मृत अध्यापकों की विधवा पत्नियों की निवृत्ति वेतन के कारण से व्यय साधारण तथा सहायक अनुदान के लिए तब तक ग्राह्य नहीं होगा जब तक निवृत्ति वेतन अनुदान के लिए नियम सरकार द्वारा स्वीकृत न हो ।

टिप्पणी - 4 सस्या को किराया खचा विशेष काल के लिये, सावजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर पर केवल तभी ग्राह्य होगा जब भवन वास्तव में किराये पर लिया गया हो तथा किराये नामे में किराये की अवधि तथा शर्तें लिखित एवं पजीकृत हो जहां उद्भव निकाय ने 'यास (Trust)' को भवन, शिक्षण सस्या की चलाने के धर्माय उद्देश्य के लिये दान में दिया हो किराया ग्राह्य न होगा ।

जहाँ गैर सरकारी सघ द्वारा चलाई गई शिक्षा सस्याओं के लिये दिये गये भवन की मरम्मत बढाव तथा परिवान के लिये पहले सहायता अनुदान दिया जा चुका हो कोई किराया ग्राह्य नहीं होगा ।

ऐसे मामलों में जहाँ कि शाला को चलाने का काय सस्याओं अथवा समिति जो उद्भव सस्या से अलग हो को सौपा गया हो तथा वे उसी भवन का उपयोग करते हो जिनको उद्भव सस्था ने शाला के लिये बनवाया था तथा तब नयी प्रब. समिति को एक बंध पत्र (Bond) अथवा सविदा (Agreement) लिखना आवश्यक है और इसी आशय से उसे पजीकृत करवाना है कि शाला को चलाने के लिए भवन के उपयोग का किराया नई सचित प्रबंधिका द्वारा उद्भव सस्था को चुकाना पड़ेगा, समिति के द्वारा सहायक अनुदान के लिये ग्राह्य होगा ।

टिप्पणी—5 भवन की मरम्मत का जो किराये पर हो, खचा सहायता अनुदान हेतु माय नहीं होगा क्योंकि ऐसी मरम्मत भवन स्वामी द्वारा की जानी चाहिये, जब तक इसके लिए विशेष प्रावधान न हो ।

टिप्पणी—6 'याय यय (Legal expenses) सहायता अनुदान के लिये ग्राह्य नहीं है, क्योंकि वे अनावतक (Non recurring) व्यय है, तो भी असाधारण परिस्थितियों में निदेशक की खर्च की ग्राह्यता के सम्बन्ध में आनाओं के लिये सगत विवरण अभिनिदिष्ट करना चाहिये ।

**Note 7 —Repayment of loans etc —**Repayment of loans or the amount transferred to the Revenue Fund is not an expenditure admissible for the purpose of grant in-aid

**Note 8 —Arrears of expenditure —**The expenditure which is incurred to meet the liabilities of any previous period but included in the expenditure of the year on which the grant is based is not admissible for the purpose of grant-in-aid

**Note 9 —**The authorised maximum limits of expenditure mentioned in Appendix VI

**Note 10 —**Any new or additional expenditure on any of the above items not provided in the approved budget will require previous sanction of the Department

**Rule 7 Non recurring Grants —**(a) Non-recurring grant shall not exceed 50% of the total approved and actual expenditure

(b) Non recurring grants may be given for construction repair and extension of building (including hostels), for purchase of furniture and equipment and for the purchase of library books

(c) Grant for the purchase or replacement of bus shall not exceed 25% of the controlled price of the bus Replacement will normally be allowed after an interval of at least 10 years such grants will ordinarily be considered only for Girls institutions and Montessory schools and preference will be given to institutions situated in cities or away from residential localities

**Note —**[In case of Girls institutions expenditure incurred for the construction of teachers residential quarters will be admissible for grant in aid),

(d) Grants in aid will be given on only those cases where the plan and estimates of expenditure have received the prior approval of competent authority as per schedule of powers in Appendix V (item 6)

(e) Plans and estimates up to Rs 25,000/- for the construction of building may be scrutinised and countersigned by the Inspector of Schools of the district concerned if the same are prepared by a qualified Engineer/Overseer

Plans and estimates above Rs 25,000/ must be prepared and verified by the P W D and be submitted to the Director of Education through proper channel

**टिप्पणी—7 ऋण वापसी —** ऋण वापसी अथवा राजस्व कोप की राशि का स्थानान्तरण, सहायता अनुदान के उद्देश्य से ग्राह्य खर्च नहीं है।

**टिप्पणी—8 खर्च का अवशिष्ट भाग —** ऐसा खर्चा जो किसी पहले के समय के देयघन की पूर्ति के लिए उठाया गया हो, परंतु जो उस वार्षिक खर्च में सम्मिलित हो, जिस पर अनुदान आधारित है, सहायता अनुदान के उद्देश्य के लिए ग्राह्य नहीं होगा।

**टिप्पणी—9 अधिकृत (Authorised) खर्च की अधिकतम सीमा** परिशिष्ट 6 में वर्णित है।

**टिप्पणी—10 उपरोक्त किसी भी विषयक्रम पर कोई नये अथवा अलग खर्च, जो कि स्वीकृत बजट में उपरिचित नहीं है के लिये विभाग की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।**

**नियम—7 अनावृत्तक (Non recurring) अनुदान —** (क) अनावृत्तक अनुदान, कुल स्वीकृत एवं वास्तविक खर्च के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(ख) अनावृत्तक अनुदान निर्माण, मरम्मत एवं भवन विस्तार (छानासय सहित) के लिए उपकरण (Furniture) एवं सामान की खरीद के लिए तथा पुस्तकालय की पुस्तकों की खरीद के लिए, दिये जा सकते हैं।

(ग) ऋण की खरीद अथवा प्रतिस्थापन के लिए अनुदान बस के नियमित मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ेगा। साधारणतया प्रतिस्थापन 10 साल के समय के पश्चात् स्वीकृत किया जायगा। साधारणतया ऐसे अनुदान केवल बालिका सस्थानों, मा-टैसरी शालाओं के लिए ही विचारित किये जायेंगे तथा शहरों में स्थित अथवा निवासस्थानों से दूर सस्थानों को ही प्राथमिकता दी जायगी।

**टिप्पणी—** बालिका सस्थानों के मामले में अभ्यापिकाओं के मामले में अभ्यापिकाओं के निवासस्थान के लिये गृह (Quarters) निर्माण के लिये उठाये गये खर्च सहायता अनुदान के लिए ग्राह्य होंगे।

(घ) सहायता अनुदान केवल उही विषयों में दिया जायेगा जहाँ खर्च की योजना एवं अनुमान (Estimate) योग्य प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर चुके हैं जसा परिशिष्ट 5 में उल्लेखित शक्तियाँ आइटम 6

(ङ) भवन निर्माण के लिये 25000 रुपये तक की योजनायें एवं अनुमान (Estimates) जिले से सम्बंधित विद्यालय निरीक्षक के द्वारा जांचे एवं प्रति हस्ताक्षरित (Countersigned) किये जा सकते हैं यदि (योजनायें एवं अनुमान) किसी योग्यताप्राप्त अभियंता (Engineer)/अधिदशक (Overseer) के द्वारा तयार की गई हो।

25000 रुपये से अधिक की योजनायें एवं अनुमान सावजनिक निर्माण विभाग द्वारा निमित्त एवं प्रमाणित होने चाहिये तथा उचित माग से शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत करने चाहिये।



(f) Grants in aid will be sanctioned and released to the institutions by the competent authority as per schedule of powers in Appendix V (item 8) Before the sanction of grant the competent authority shall be satisfied that —

- (i) Statement of expenditure audited by a Chartered Accountant has been received
- (ii) Certificate of P W D authorities for the value of construction has been received
- (iii) Certificate of the P W D authorities and Departmental authority that the expenditure is according to the approved plan or project
- (g) Normally grant in aid is to be released after the completion of the approved construction/project In special cases where interim instalments of grant are decided to be sanctioned, the competent authority shall be satisfied, that—
  - (i) Statement of expenditure audited by a Chartered Accountant has been received
  - (ii) Certificate of Dy Inspector or Inspector of Schools regarding work done and material used

The instalment sanctioned shall not exceed 50% of the approved and actual expenditure For final payment certificates as (f) above would be necessary

(h) In all cases before or at the time the money granted is paid over the grantee and the officer of the Government marking the grant shall sign a written agreement to the effect that the grant is made and accepted subject to the condition as to pre-emption and all other conditions contained in these rules the grantee undertaking to sell and registered under the Registration Act In case grant has been made by the Government for the erection purchase improvement or repair of a building that building shall not be transferred or used at any time for any other purpose except with the written permission of the Department Ordinarily, the Government shall have a prior lien on such a building for the recovery of the sum representing the grant in aid paid when the building is to be alienated or proposed to be used for purposes other than those for which its construction was undertaken The decision as to what the market value of such building be, shall rest with the Government The above condition shall be included invariably in the agreement referred to above

(च) सहायता अनुदान सुयोग्य अधिकारी द्वारा सत्या के लिए स्वीकृत एवं मुक्त किया (Released) जायेगा जैसा कि परिशिष्ट 5 (भद 8) में उल्लेखित, शक्तियाँ। अनुदान की स्वीकृति से पूर्व सक्षम अधिकारी सतुष्ट हो जायेगा कि —

(i) चार्टर्ड अकाउंटेंट (Chartered Accountant) के द्वारा लेखा परीक्षण किया हुआ व्यय विवरण पत्र प्राप्त कर लिया है।

(ii) निर्माण की लागत के लिए सावजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है।

(iii) सावजनिक निर्माण विभाग अधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों का प्रमाणपत्र कि व्यय स्वीकृत योजना अथवा परियोजना के अनुसार है।

(घ) साधारणतः सहायता-अनुदान स्वीकृत निर्माण परियोजना के पूरे होने पर ही छाड़ा जाता है। विशिष्ट अवस्थाओं में जहाँ कि अनुदान की मध्यवर्ती किश्तें स्वीकृति के लिए निश्चित की गई हैं, सक्षम अधिकारी सतुष्ट हो जायेगा, कि

(i) चार्टर्ड अकाउंटेंट (Chartered Accountant) के द्वारा लेखा परीक्षण किया हुआ व्यय विवरण पत्र प्राप्त कर लिया है।

(ii) निदेशक निरीक्षक अथवा विद्यालय निरीक्षक का काम एवं उपयोग में लाय गये सामान से सम्बंधित प्रमाण पत्र।

स्वीकृत किश्तें, स्वीकृत एवं वास्तविक व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक की नहीं होगी। अंतिम भुगतान के लिए, प्रमाण पत्र जैसा कि ऊपर (ब) में है, आवश्यक होगा।

(ज) सभी अवस्थाओं में स्वीकृत राशि के भुगतान के समय या इसके पूर्व अनुदान ग्राही (Grantee) एवं अनुदान कर्ता राज्याधिकारी इस अभिप्राय की एक लिखित सविदा हस्ताक्षरित करेंगे कि, अनुदान इस शर्त पर दिया जा रहा है व स्वीकार किया जा रहा है कि इन नियमों में बंणित समस्त शर्तें माय होगी। अनुदानग्राही (Grantee) इस के लिए आश्वासन देगा व पञ्जीकरण अधिनियम के अंतर्गत पञ्जीकृत करायगा। ऐसी अवस्था में जबकि, अनुदान राज्य सरकार द्वारा किसी भवन के निर्माण, खरीद, सुधार अथवा मरम्मत के लिये दिया गया हो, वह भवन न तो हस्तांतरित हो किया जावेगा तथा न ही विभाग की अनुमति के बिना किसी भी समय अन्य उद्देश्य के लिए काम में लाया जावेगा। साधारणतया ऐसे भवन पर दी गयी अनुदान राशि की वसूली हेतु राज्य सरकार का प्रथम ग्रहणाधिकार होगा जबकि या तो भवन को हस्तान्तरित किया जा रहा हो या उस किसी उद्देश्य के लिए काम में लेने का प्रस्ताव हो जा उस उद्देश्य से भिन्न हो कि जिसके लिए भवन का निर्माण किया गया था। ऐसे भवन का बाजार भाव निश्चित करने का अधिकार राज्य सरकार का होगा। उपरोक्त शर्तें ऊपर बंणित सविदा में अवश्य सम्मिलित की जायगी।

The form of the agreement by the management shall be as prescribed in Appendix VIII with such modifications as the Director of Education may agree to

(7) (i) In cases of well established institution under taking big construction projects Government, at its discretion may release initial instalments of the Grant in aid in advance of the expenditure

Rule 8 Working Days —If any institution has worked for less than 200 days during the twelve months ending on March 31, a proportional reduction may be made in the annual grant payable under the rules

Rule 9 Application for grant in aid —Application for grant in aid or special grant for any financial year must be made on the prescribed forms by the August of the year Such applications shall be accompanied by the following —

(1) A statement of accounts for the financial year ending 31st March of the preceding year duly audited by the Chartered Accountants

Note —Institutions with an annual expenditure of Rs 2,000/ (Rupees two thousand) per annum or below are exempted from getting their accounts audited by Chartered Accountants

(2) A declaration from the person authorised by the management of the institution for which the grant in aid is demanded that it has assets worth atleast three times of the amount of annual expenditure and that such assets (List to be annexed) are free of all encumbrances and do not include assets created or added out of the grant-in aid received and that the income of such assets supplemented by grant in aid will be adequate to enable the management to carry on the institution efficiently and to pay the salaries of the staff of the institution as are prescribed by the Government or other competent authority

Note —Provided that the condition shall be insisted upon during the first three years of an institution

Rule 10 Reduction withdrawal, withholding etc of the grant —The grant in aid shall be liable to be withhold reduced or withdrawn at the discretion of the sanctioning authority if in

प्रबंध कारिणी द्वारा किये जाने वाले सविदा का प्रारूप परिशिष्ट 8 क अनुसार, ऐसे सुधारों के साथ जो शिक्षा निदेशक द्वारा स्वीकृत कर लिये गये हों, होगा।

7 (1) बड़ी निर्माण परियोजनाओं के उपक्रम करने वाली मजबूत बुनियाद पर स्थापित संस्थाओं की व्यवस्था में सरकार, अपनी इच्छा से सहायता अनुदान की प्रथम वित्त व्यय के वेशगी में दे सकती है।

नियम 8 कार्य दिवस—यदि किसी संस्था ने 31 मार्च को समाप्त होने वाले 12 महिनो में 200 दिन से कम कार्य किया हो, तो नियमानुसार सालाना अनुदान के भुगतान में अनुपातिक कमी की जा सकती है।

नियम 9 सहायता अनुदान के लिए प्रायना पत्र—किसी भी वित्तीय वर्ष के सहायता अनुदान अथवा विशिष्ट अनुदान के लिए प्रायना पत्र हर साल के अगस्त माह में निर्दिष्ट प्रपत्रों (forms) में होना चाहिए। ऐसे प्रायना पत्र निम्नलिखित बातों सहित होगा—

(1) चार्टर्ड अकाउंटेंट (Chartered Accountant) से लेखा परीक्षण किया हुआ पिछले साल की 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष का लेखा विवरण।

टिप्पणी—संस्थाएं, जिनके वार्षिक खर्च 2000/- रुपये अथवा इससे कम प्रति वर्ष है, व चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने लेखा परीक्षण करवाने से मुक्त हैं।

(2) संस्था जिनके लिए अनुदान मांगा जा रहा है, की प्रबंधिका से अधिकृत व्यक्ति से एक घोषणा कि—वार्षिक व्यय की राशि से तिगुनी के करीब राशि इसकी परिसम्पत्त है तथा ऐसी परिसम्पत्त (सूची नम्बरी करनी चाहिए) सारे ऋणों से मुक्त है और प्राप्त किये हुए सहायता अनुदान से उत्पन्न बढी हुई परिसम्पत्त इसमें सम्मिलित नहीं है और न ही सहायता अनुदान से 'यूनता पूव' की हुई ऐसी परिसम्पत्त से प्राप्त संस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए, तथा संस्था कर्मचारी वग के वेतन की चुकोती करने के लिए जैसा सरकार अथवा सशम अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट है, प्रबंधिका को योग्य बनाने में पर्याप्त होगी।

टिप्पणी—वर्शों कि इस शत पर, संस्था के प्रथम तीन वर्षों में जोर नहीं जायेगा।

नियम 10 अनुदान में कमी, वापसी रोक्ना आदि—संस्था सहायता अनुदान स्वीकृति देने वाले अधिकारी की इच्छा से रोकें जाने, कमी वगैरे अथवा वापसी करने के लिए उत्तरदायी होगी यदि उसकी [स्वीकृति देने वाले अधिकारी] सम्मति में, संस्था इन नियमों में निर्दिष्ट किसी भी बात को संतुष्ट करने में असमर्थ हो गई

its opinion the institution has failed to satisfy any of the conditions enumerated in these rules but before any such action is taken under this rule, the management shall be informed and also be given an opportunity of showing cause against the charges levelled and action proposed to be taken against it

It will be open to the management to appeal to the Government against the order of the authority withholding, reducing or stopping the grants within two months from the date of the receipt of the said order

**Rule 11 Committee to scrutinise application**—All applications for (i) recurring grant to new institutions (ii) for increase in the percentage of recurring grants of the institutions already on aid list and (iii) nonrecurring grants will be considered and recommended to the sanctioning authority by a Committee consisting of the following members. The Committee will keep in view these rules, Government orders and circulars issued from time to time in this behalf and the provision in the budget—

- (1) Director of (P&S) Education Convenor
- (2) Director of Collegiate Education (When cases of colleges are considered)
- (3) Chairman, Board of Secondary Education
- (4) A representative of the Education Department
- (5) A representative of the Finance Department
- (6) Director of Sanskrit Education when cases of Sanskrit Educational institution are considered
- (7) Dy Director of Education of each range, when cases concerning his range are being considered
- (8) Three eminent non official educationists
- (9) Director Technical Education for proposals on technical education

The Director of Education shall intimate the amount that may be available for the above grants in the financial year to the above committee when meets to consider applications for grants-in aid

**Rule 12 Sanctioning authority**—(i) Recurring grants to new institution and all non-recurring grants above Rs 50,000/ (Estimate of expenditure) shall be sanctioned by the Government

(ii) The Director of Education shall have authority to approve expenditure and sanction—

है, लेकिन इस नियम के अंतर्गत कोई भी ऐसा कायवाही करने में पूरा प्रबंधन को सूचित किया जाएगा तथा लगाये गये अभियोगों के विरुद्ध कारण बताने के लिए तथा इसके विरुद्ध की जा जाने वाली कायवाही में बचाव प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया जायेगा। अनुदान को रोकने, कम करने अथवा वापसी के लिए अधिकारी के आदेश के विरुद्ध सरकार से अपील के लिए प्रबंधन को स्वतंत्रता होगी तथा यह अपील कथित आदेश की प्राप्ति की तारीख से 75 माह के अंदर होगी।

**नियम 11** प्रायना पत्र की जाचने के लिये सामान —

(1) नयी सस्थाओं के लिये आवतक (Recurring) अनुदान

(11) सहायक सूची में रही हुई सस्थाओं के आवतक अनुदान के प्रतिशत की वृद्धि तथा

(111) अनावतक अनुदानों के लिये सभी प्रायना पत्र निम्नलिखित सदस्यों से बनी हुई समिति द्वारा विचार किये जायेंगे तथा स्वीकृत करने वाले अधिकारी को सिफारिश किये जायेंगे। समिति को इन नियमों, सरकारी आदेशों तथा इसके लिये समय समय पर जारी किये परिपत्रों तथा बजट में व्यवस्था की ध्यान में रखना होगा —

(1) अपर निदेशक संयोजक।

(2) निदेशक, कालेज शिक्षा (जब कि महाविद्यालयों के मामले हों)।

(3) माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष।

(4) शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि।

(5) वित्त विभाग का प्रतिनिधि।

(6) मस्कृत शिक्षा निदेशक जब संस्कृत शिक्षण सस्थाओं के मामले पर विचार हों।

(7) हर क्षेत्र का उपशिक्षा निदेशक, जब उसके समाय स सम्बंधित मामलों पर विचार हों।

(8) तीन मुख्य असरकारी शिक्षा शास्त्री।

(9) शिल्प शिक्षण निदेशक, शिल्प शिक्षा के प्रस्तावों के लिये।

शिक्षा निदेशक उपरोक्त समिति को वित्तीय वर्ष में उपरोक्त अनुदानों के लिए ग्राह्य हो सकने वाली राशि की सूचना देगा, जब उपरोक्त समिति सहायता अनुदान के प्रायनापक्षों के विचाराय मिलती है।

**नियम 12** स्वीकृति प्राधिकारी —

(1) नई सस्थाओं को 5000 रुपये से ऊपर (व्यय की गणना) के आवतक अनुदान सरकार द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(11) शिक्षा निदेशक व्यय तथा स्वीकृति करने का अधिकारी होगा —

(a) Recurring grants to institutions already on the grants in aid list in accordance with these rules

(b) Non recurring grants up to Rs 50,000/ with the approval of Grant in aid Committee

(c) Non recurring grant up to Rs 25,000/- without the concurrence of the Grant in-aid Committee

**Rule 13 Alienation of the property**—An institution or a body which has received grant in aid under these rules shall not transfer any property to any persons, institutions or body without the concurrence of the Department/Government as the case may be, except the disposal of un serviceable articles

**Rule 14 Maintenance of registers etc**—All materials purchased from time to time out of the funds of an institution shall be entered in a stock register which shall be maintained by every institution on the grant in aid list. The Head of the Institution shall be responsible for the proper custody thereof. All the bills received for payments shall bear the following certificate —

"The quality of articles received is good, quantity correct and according to the specifications, rate is not more than those prevailing in the market and entered in stock register at page No "

**Rule 15 Purchase by tenders**—All purchases costing more than Rs 250/- shall be made after calling for tenders from the manufacturers, suppliers and contractors. As far as possible, lowest tenders shall be accepted unless for any special reasons to be recorded in writing the management decides otherwise

**Power of the Government to grant exemption from the provisions of these rules**—The Government may in special cases grant an institution exemption from one or more of the conditions contained in these rules

**Rule 16 Supersession**—The existing Rules for Grant in aid as contained in Chapter XVII of the Education Code of Rajasthan 1957 (as amended from time to time) are hereby superseded

## INDEX OF ENCLOSURES

Appendix I	Rule 3 Sub-Rule (v)— Constitution of Governing Body
" II	Discipline

(प्र) सहायता अनुदान सूची में स्थित संस्थाओं को अनावतक अनुदान इन नियमों के अनुसार होगा।

(ब) 50000 रुपये तक के अनावतक अनुदान, बिना सहायता अनुदान समिति की स्वीकृति से।

(स) 25000 रुपये तक के अनावतक अनुदान, बिना सहायता अनुदान समिति की सहमति के।

**नियम 13 सम्पत्ति का हस्तान्तरण** --संस्था प्र वा सभा जिसने इन नियमों के अनुसार सहायता अनुदान प्राप्त किया है किसी भी व्यक्ति, संस्था या समूह को बिना विभाग/सरकार की सहमति के सम्पत्ति वा स्थानांतरण अनुपयोग वस्तुओं के निपटारे के अतिरिक्त नहीं करेगी।

**नियम 14 रजिस्टर इत्यादि का परिक्षण** --समस्त वस्तुएं जो कि संस्था निधि से समय समय पर खरीद की जाती है, को सामग्री पत्रिका में प्रविष्ट किया जायेगा, जिनको प्रत्येक संस्था अनुदान सूची के अनुसार परिरक्षित करेगी। संस्था प्रधान इसकी ठीक सरक्षण के लिये उत्तरदायी होगा। तमाम प्रापका (Bills) पर जो एक छुकार के लिए प्राप्त किए गए हैं, निम्न प्रमाण पत्र होगा --

“प्राप्त की गई वस्तु के लक्षण अच्छे हैं, तादाद सही है और विशिष्ट गुणों के अनुसार है, दूर बाजार में प्रचलित दरो से अधिक नहीं है, तथा सामग्री पत्रिका के पृष्ठ संख्या में प्रविष्ट कर ली गई है।”

**नियम 15 निविदा (Tender) के द्वारा क्रय** --समस्त प्रकार का क्रय जो 250 रुपये के मूल्य में अधिक हो उत्पादक, वितरक और ठेकेदारों से निविदा प्राप्त कर खरीद किया जायेगा। जहां तक संभव हो सबसे निम्न निविदा को स्वीकार किया जायेगा, जब तक किसी विशेष कारण से प्रबंध कारिणी इसके अतिरिक्त तय न करे, जो अभिलिखित होना चाहिये।

इन नियमों के प्रावधानों में छूट देने का सरकार का अधिकार सरकार विशेष मामलों में संस्था को इन नियमों में उल्लिखित एक या अधिक परिस्थितियों में छूट स्वीकार कर सकती है।

**नियम 16 अतिक्रमण (Supercession)** --राजस्थान शिक्षा संहिता, 1957 के अध्याय (17) में उल्लिखित वर्तमान अनुदान नियमों (जैसा कि इसके द्वारा समय समय पर संशोधन किया गया है) का इसके द्वारा अधिक्रमण किया जाता है।

### सलग्नो (Enclosures) की सूची

परिशिष्ट 1 नियम संख्या 3 के उपनियम (5) --

प्रबंध कारिणी का गठन

” 2 अनुशासन



„ III	Rule 4 Sub-rule (a)—Governing Body and teacher
„ IV	Governing Body and Head of Institution
„ V	Rule 4 Sub rule (g) 11 Rule 7 Sub-rule (b)—Powers
„ VI	Rule 6 Notes 9—Maximum limit of expenditure
„ VII	Scale of class IV
„ VIII	Rule 7 Sub-rule (d)—deed

### APPENDIX I

#### Formation of Governing Bodies

(1) The Managing Committee or Governing Council shall consist of not more than fifteen members plus the Head or Heads of the institution or institutions run by the Society

(2) Not more than  $\frac{2}{3}$  of the management shall belong to any one community caste or sect

(3) Not less than  $\frac{1}{3}$  of the total membership should be from amongst donors or subscribers

(4) At least the member should be accepted from amongst the teaching staff of the institution or institutions run by the management

(5) The Education Department will nominate one member on the Managing Committee who will be a Senior Education Officer or eminent educationist

**Note**—Nominations will be made by the Director in the case of managing bodies or Societies running not more than three institutions or of at least High Schools standard whose expenditure does not exceed rupees 3 lakhs per annum, and the Government in consultation with the Director of Education in the case of managing bodies which run more than three institutions of at least High School standard or whose expenditure exceeds rupees three lakhs per annum

(6) At least one member shall be co opted from amongst the parents of the students of institution or institutions run by the management

- “ 3 नियम सख्या 4 का उपनियम (क)—  
प्रबंध कारिणी समिति तथा अध्यापक  
के बीच अनुबंध पत्र
- “ 4 प्रबंध कारिणी समिति तथा सस्था के  
प्रधान के बीच अनुबंध पत्र
- “ 5 नियम सख्या 4 के उपनियम (छ),  
नियमसख्या 11, का उपनियम (ख)—  
शक्तिया
- “ 6 नियम सख्या 6 की टिप्पणी सख्या 9—  
खर्च की अधिकतम सीमा
- “ 7 चतुर्थ श्रेणी की श्रुतिला
- “ 8 नियम सख्या 7 का उपनियम (घ)  
बंध पत्र (Deed)

## परिशिष्ट 9

### प्रबंध मण्डलों का निर्माण

(1) प्रबंध समिति या प्रबंध मण्डल में 15 सदस्य से अधिक नहीं होंगे ।  
इसके अतिरिक्त समाज द्वारा चलाई जाने वाली सस्था का प्रधान या सस्थाओं के  
प्रधान शामिल होंगे ।

(2) प्रबंध में किसी एक समुदाय, सम्प्रदाय या जाति का हिस्सा 213 से  
अधिक नहीं होना चाहिए ।

(4) कुल सदस्यों के 113 भाग से दान देने वाले या चंदा देने वाले कम  
नहीं होने चाहिये ।

(4) प्रबंधको द्वारा चलाई जाने वाली सस्था या सस्थाओं के अध्यापक वग  
म से कम से कम एक सदस्य स्वीकार किया जाना चाहिये ।

(5) शिक्षा विभाग प्रबंध समिति में एक सदस्य भेजेगा जो शिक्षा विभाग  
का उच्च अधिकारी या प्रमुख शिक्षाशास्त्री होगा ।

टिप्पणी —प्रबंध समिति या मण्डल जो तीन सस्था से अधिक न चलाती हो,  
या कम से कम हाईस्कूल स्तर पर चलाती हो, जिसका वार्षिक व्यय तीन लाख से  
अधिक न हो तो मनोनयन निदेशक द्वारा किया जायगा । प्रबंध मण्डल अगर तीन  
सस्था से अधिक चलाती हो जो कम से कम हाईस्कूल स्तर पर हो, जिसका खर्चा  
तीन लाख से अधिक हो तो इस स्थिति में शिक्षा निदेशक की सलाह से सरकार मनो  
नयन करेगी ।

(6) प्रबंधको द्वारा चलाई जाने वाली सस्था या सस्थाओं में विद्यार्थियों के  
सरक्षकों की ओर से कम से कम एक सदस्य सम्मिलित किया जावेगा ।

(7) At least one old student of the institution run by the management to be co opted by the other members of the Managing Committee or Governing Council under clauses 4, 6 and 7

**Note 1 —Doners —**Those who have donated at least Rs 250/- at a time or have been paying a subscription of at least Rs 3/ per month for at least one year shall be considered doners Institutions may fix higher minimum of donation or subscription according to their needs

**Note 2 —Doners and Founder members and Honorary members (if any) shall form an Electoral College for the election of the members (as may be fixed by them) to the Managing Committee or Governing Council under clause No 3**

**Note 3 —**While making nomination the department will see that the officer to be nominated is not inferior in status to the head of the institution concerned

## APPENDIX II

### Rules of Discipline in Educational Institutions

The managers of recognised Educational Institutions are required to enforce the following principles of discipline —

- (1) Strict regularity and implicit obedience must be exacted in class
- (2) Any reported or observed objectionable conduct out of institution should be punished
- (3) Parents must be given to understand that they can not dictate to managers but that the managers have a right to lay on what conditions they will admit or retain pupils in their institutions
- (4) *Politeness and courtesy of speech and conduct* should be inculcated as well as cleanliness of dress and person
- (5) No child suffering from a contagious or infectious disease shall be permitted to attend any recognised institutions
- (6) Persons at study who are over sixteen (16) are free to attend all public meetings Persons at study who are under that age may with the consent of their guardians be prevented by the Heads of their schools or colleges from attending any particular meeting

(7) उप बंध 4, 6, 7 के अंतर्गत प्रबंधकों द्वारा चलाई जाने वाली सस्था में से प्रबंध समिति या प्रबंध मण्डल के दूसरे सदस्यों द्वारा एक पुराना विद्यार्थी चुना जावेगा।

टिप्पणी — (1) दान देने वाले—वे जि होने कम से कम 250 रु० एक ही साल दिया हो, या 3 रु० प्रतिमास के हिसाब से कम से कम एक साल तक दिया हो, दान देने वाले कहे जायेंगे। सस्थायें अपनी आवश्यकानुसार दान या चंदे की अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकती हैं।

(2) दान देने वाले व निर्माण करने वाले एवं अवैतनिक सदस्य (अगर कोई हो) प्रबंध समिति या प्रबंध मण्डल उप बंध 3 के अनुसार सदस्यों का चुनाव करने के लिए (जो भी उनके द्वारा निर्धारित की जावे) एक चुनाव कालेज का ध्यान करेगी।

(3) नाम निवेशन करते समय विभाग यह देखेगा कि विभागीय अधिकारी जिसे प्रधान पद पर मनोनीत किया जावेगा, वह सस्था के प्रधान से निम्न श्रेणी का नहीं है।

## परिशिष्ट २

### शिक्षण सस्थाओं के अनुशासन के नियम

मायता प्राप्त शिक्षण सस्थाओं के प्रबंधकों को अनुशासन से सम्बंधित निम्न सिद्धान्तों का पालन करना चाहिये—

- (1) कक्षा में दंड नियमितता व आज्ञा पालन यथाय मे होना चाहिये।
- (2) सस्था के बाहर प्रतिकूल आचरण की सूचना पर दंड देना चाहिये।
- (3) सरक्षकों को यह समझा देना चाहिए कि वे प्रबंधकों को आज्ञा नहीं दे सकते, बल्कि प्रबंधकों की यह अधिकार है कि वे शिष्य को अपनी सस्था में भर्ती करें अथवा न करें।

(4) विनय, भाषण व व्यवहार में नम्रता तथा उसी प्रकार शक्ति धीरे कपड की सफाई होनी चाहिए।

(5) कोई भी मायता प्राप्त सस्था ऐसे छात्र को, जो कि मंत्रासक्त या दूध की बीमारी का रोगी हैं, उपस्थित होने की अनुमति नहीं देगी।

(6) पढते समय व्यक्ति जो 16 साल से ऊपर है, अपने मायता प्राप्त सस्थाओं में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र है। पढते समय 16 से कम उम्र के छात्रों को कालेज या स्कूल का प्रधान, सरक्षक को सहमति व निर्देश भी प्रदान करेंगे।

which the heads of the schools or colleges consider objectionable

- (7) Persons at study who are over eighteen (18) are free to become members of organisation other than those whose policy or programme involves the dissemination of ideas of violence or the use of violence
- (8) Persons at study may take part in the activities of all educational, social and religious associations
- (9) Such persons may not however become members of the executive or Managing Committee of any political or religious organisations likely to result in communal antagonism or take an active part in furthering their activities

### APPENDIX III

#### Form of Agreement

An agreement made this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ between (hereinafter called the teacher) of the one part and the Managing Committee of the \_\_\_\_\_ other part. The Committee hereby agrees to employ the teacher and the teacher hereby agrees to serve as \_\_\_\_\_ in the said school on the following terms —

(1) The teachers employment shall begin from the \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_. He shall be employed in the first instance for one year on probation and period of probation shall in no case exceed two years. If at the end of the period of two years, the teacher is not found competent or otherwise suitable his appointment shall be terminated

(2) If confirmed in his appointment at the end of his period of probation the teacher shall be employed on a monthly salary of Rs \_\_\_\_\_ in the grade \_\_\_\_\_

(3) The said monthly salary shall be paid regularly in the month following that for which it is due

(4) The duties of the teacher shall not be confined as to place to the school building nor as to time to the periods during which the school is open for the purpose of class tuition. The teacher shall perform all such duties connected with the work of the school as shall be required of him by the Headmaster and shall in carrying out those duties obey at all times and places

भाग लेने के लिये प्रतिबन्ध लगा सकता है अगर कालेज या स्कूल के प्रधान की इसमें भागीति हो।

(7) पढाई के समय 18 वर्ष से अधिक आयु होने पर किसी सगठन का सदस्य बनने की स्वतन्त्रता है, परन्तु जिनकी नीति या कार्यक्रम हिंसा के विचारों को फैलाना व उनमें सम्मिलित होना है अथवा जो हिंसा का प्रयोग में लेते हैं को छोड़कर।

(8) व्यक्ति पढते समय नमस्त शिक्षण सम्प्रदायी, सामाजिक व धार्मिक सभ्यता की गतिविधि में भाग ले सकता है।

(9) इस प्रकार के व्यक्ति किसी भी राजनैतिक व धार्मिक सगठनों की प्रबन्ध समिति के सदस्य नहीं बन सकते, जो सम्प्रदाय विरोधी हों, या उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिये सक्रिय भाग लेते हों।

## परिशिष्ट ३

### सविवा (इकरारनामा) का प्रपत्र

यह इकरारनामा दिन को (जो कि बाद में अध्यापक बहा जायगा) एक तरफ और दूसरी ओर प्रबन्ध समिति के बीच किया जाता है। समिति अध्यापक को सेवा में नियुक्त करने की सहमति देती है, और अध्यापक पद पर इन शर्तों के साथ मौजूद करने की सहमति देता है —

(1) अध्यापक का सेवाकाल दिनांक 19 से प्रारम्भ हो जायगा, वह प्रथम बार एक वर्ष तक परीवीक्षा पर नियुक्त किया जायगा, किसी भी स्थिति में परीवीक्षा का काल दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकेगा, दो वर्ष समाप्त होने के बाद अगर अध्यापक सुयोग्य या उपयुक्त नहीं पाया गया तो उसकी नियुक्ति समाप्त हो जावेगी।

(2) परीवीक्षा काल के समाप्त होने के बाद अगर अध्यापक को स्थायी किया जाता है, तो मासिक वेतन वेतन क्रम के अनुसार होगी।

(3) उपरोक्त मासिक वेतन जिस माह में देय हो उसी माह में नियमित रूप से दिया जायेगा।

(4) अध्यापक का कर्तव्य न तो स्कूल भवन के स्थान तक और न कक्षा को पढ़ाने के लिए स्कूल खुलता है उस समय तक ही सीमित है। अध्यापक का अपना कर्तव्य पालन के लिए समस्त समय उन कार्यों को करना पड़ेगा जिसकी प्रधानाध्यापक की आवश्यकता हो। अपने कर्तव्य पालन के लिए उसे प्रत्येक समय समस्त स्थानों

the direction of the head of the institution No work which is not connected with the school shall be required of him and the collection of subscriptions or donations for the School/College/Society funds shall not be considered as part of his duties But his voluntary engagement in such work is not prohibited

(5) Except during periods when the school is closed for not less than four consecutive days the teacher shall not leave the Station in which the school is situated without having first obtained the written permission of the Headmaster

(6) The teacher shall be allowed leave according to the leave rules of the Government of Rajasthan

(7) (i) Subject to the provision of sub-clause (iii) of this clause the Committee may at any time at a meeting regularly convened under its rule pass a resolution dismissing a teacher without notice for any one or more of the following offences —

(a) In subordination or disobedience of the orders of the Head of the institution or the management

(b) Deliberate neglect of duty

(c) Serious misconduct or the commission of an act which constitute a criminal offence

The teacher may at any time within 30 days after the passing of such a resolution apply to have the decision of the Committee reviewed by it at second meeting and the Committee shall on receipt of such an application be summoned to a second meeting within one month of the receipt of such an application At such second meeting the teacher may submit an additional statement of his case and shall if he so desires be allowed to appear before the Committee in person to state his case and to answer any question that may be put to him by any members present at the meeting If the teacher does not apply to have the resolution of the Committee reviewed or if the resolution is confirmed by the Committee at the second meeting no further notice of dismissal shall be given to the teacher but he shall be given a copy of the resolution by which he is dismissed together with written statement of the grounds of his dismissal He shall also be paid his salary up to and including the day on which he was suspended from duty but he may be required to refund or return any school money or any school property or the value thereof which he has misappropriated or wrongfully retained in his possession

पर, सपस्त आज्ञाओं को, जो सस्था के प्रधान द्वारा निर्दिष्ट की जाती हैं माननी होगी। जो काय स्कूल से सम्बन्धित न हो उसके द्वारा नहीं करवाया जायेगा। स्कूल/कालेज/सस्था के लिए दान व चंदा इकट्ठा करना उसके कर्तव्य का अंग नहीं है, परन्तु वे स्वेच्छा से इस प्रकार का काय करे तो रोक नहीं है।

(5) घण्टों के बीच की अवधि के अलावा जब स्कूल कम से कम क्रमागत चार दिनों के लिए बंद होता है तो अध्यापक, जब तक प्रधानाध्यापक से लिखित अनुमति प्राप्त न करले स्थान जहाँ स्कूल स्थित है नहीं छोड़ सकेगा।

(6) अध्यापक को राजस्थान सरकार के अवकाश नियमा के अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जायगा।

(7) (1) इस वाक्य के उपवाक्य (3) के अनुसार समिति बिना सूचना के किसी भी समय नियमित सभा में प्रस्ताव पास करके अध्यापक को निम्न में से एक या अधिक अपराध करने पर कायच्युत कर सकती है—

(1) सस्था के प्रधान या प्रबंधक की आज्ञा भंग करना या आज्ञाया की अवज्ञा करना

(2) जानबूझ कर काय की अवज्ञा

(3) गंभीर अवचार या ऐसा काय करना जो फौजदारी अपराध हो।

अध्यापक प्रस्ताव पास करने के 30 दिन के अंदर समिति के नियुक्त पर द्वितीय सभा में पुन विचार करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। समिति इस प्रार्थना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अंदर सभा बुलायेगी। दूसरी सभा में अध्यापक अपने मामले में सम्बन्धित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत कर सकता है। वह स्वयं उपस्थित होने की मांग करता है तो ऐसा हो सकता है व सभा में उपस्थित किसी भी सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे सकता है। यदि अध्यापक समिति को प्रस्ताव पर पुन विचार करने के लिए प्रार्थना पत्र नहीं देता है, और समिति दूसरी सभा में प्रस्ताव को स्थायी कर देती है तो अध्यापक को कायच्युत करने की दूसरी बार सूचना नहीं दी जावेगी परन्तु उसे प्रस्ताव की एक लिखित प्रति जिसमें कायच्युत करने के कारणों का विवरण हो भेजी जावेगी। उसे जब से कायच्युत किया या उन दिनों के साथ उसे उसका वेतन चुकाना होगा, परन्तु उसे स्कूल का रुपया या स्कूल सम्पत्ति धरवा उनकी कीमत जिसका उसने दुरुपयोग किया है या उसने गन्ती से अधिकार में रोक रखा है, उसका भुगतान करना होगा।



(ii) Instead of dismissing the teacher on any of the grounds aforesaid the Committee may pass a resolution inflicting a lesser punishment by reducing the pay of the teacher for a specified period or by stopping increments of his salary either permanently or temporarily and/or may deprive the teacher of his pay during the period of any of his suspension. The Teacher shall still be entitled to apply to have the resolution of the committee reviewed as provided in sub-clause (i). If the teacher so applies, the committee shall be at liberty to accept or reject his appeal at its second meeting or to pass a resolution dismissing the teacher instead of inflicting such minor punishment as aforesaid and in such case the resolution dismissing the teacher shall be final and no other notice of dismissal shall be necessary.

(iii) Before a meeting is held for the purpose of dismissing or otherwise punishing the teacher, the Committee or manager shall give to the teacher a statement in writing of the specific charge or charges against him with particulars of time and place and shall allow him at least ten days in to give a written reply thereto and pending the meeting of the committee considered the charge or charges as aforesaid, the committee or the manager may suspend the member from duty. The Teacher shall however, be allowed if he so desires to appear before the committee in person to state his case and answer any questions that may be put to him by any members present at the meeting.

Note—It will be incumbent upon the management to hold a meeting of the committee within a month from the time of receipt of a reply to the charge or charges framed against a teacher who is suspended and to pay to him subsistence allowance equal to  $\frac{1}{4}$  of his pay from the time of suspension till the case is finally decided. (Now it should be  $\frac{1}{2}$  of his pay)

(iv) If the teacher is exonerated of the charges brought against him, he shall be re-instated in his post and shall be paid his salary for the period during which he was suspended.

(8) While the teacher is on probation as provided in clause 1, the Committee may at any time terminate this agreement by giving the teacher one calendar month's notice in writing or upon paying to the teacher a sum equal to his salary for the month in addition to any pay which he has then earned. The teacher may similarly terminate this agreement by submitting one calendar month's notice in writing to the Committee through the

(11) उपरोक्त कारणों से अध्यापकों को कायच्युत करने के स्थान पर समिति प्रस्ताव पास करके अल्प दण्ड दे सकती है, जैसे निश्चित समय तक वेतन कम करके यथवा स्टाई व अस्वाई रूप से उसकी वेतन वृद्धि रोक करके, या निलम्बन के समय का वेतन न दे करके, अगर कोई हो साधारण दण्ड दे सकती है। उपवाक्य (1) के अंतर्गत अध्यापक समिति को पुन विचार के लिए प्रार्थना पत्र देता है, यह समिति को इच्छा पर निर्भर है कि उसकी अपनी स्वीकार करे अथवा नामज़ूर करे, या उपरोक्त लघु दण्ड के स्थान पर कायच्युत करने का प्रस्ताव पास करती है तो इस प्रकार के मामले में अध्यापक का कायच्युत करने का प्रस्ताव प्रतिम होगा और दुबारा सूचना की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

(11A) अध्यापक को दण्ड देने या कायच्युत करने के लिए सभा बुलाने से पहले समिति या प्रबंधक अध्यापक के विरुद्ध लगाये स्पष्ट दोष का या दोषों का समय और स्थान के साथ एक विवरण अध्यापक को देना होगा और कम से कम दस दिन का समय उसे लिखित उत्तर देने के लिए देना होगा। समिति की विचाराधीन सभा उपरोक्त दोष या दोषों पर विचार कर सकती है समिति या प्रबंधक सदस्य को निलम्बित कर सकता है। अगर अध्यापक की इच्छा अपने मामले का सम्झाने के लिए समिति के सामने स्वयं उपस्थित होने की है, तो ऐसा हो सकता है और सभा में उपस्थित किसी भी सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर दे सकता है।

नोट --प्रबंधक का यह कर्तव्य है कि अध्यापक के, जिसको निलम्बित किया गया है, दोषों का उत्तर पाने के एक मास के अंदर सभा बुलाये। जब तक उसे निलम्बित होने के समय से लेकर मामला तय नहीं हो जाय तब तक निर्वाह के लिए उसके वेतन का एक चौथाई भत्ता चुकाना होगा। (अब प्राये वेतन के बराबर निर्वाह भत्ता मिलता है)

(11) अगर अध्यापक अपने दोषों के विरुद्ध निर्दोष सिद्ध कर देता है, तो उसे अपने पद पर पूर्व अवस्था के अनुसार नियुक्त किया जायेगा और निलम्बन होने के समय का उसका वेतन चुकाया जायगा।

(8) वाक्य 1 के अनुसार जब अध्यापक परीक्षाकाल में हो तो प्रबंध समिति किसी भी समय इस इकरारनामे को एक माह का लिखित नोटिस देकर या पचिम माह का वेतन देकर हटा सकती है। अध्यापक भी एक माह का सत्या के

Head of the institution or on paying to the Committee a sum equal to his salary for one month

(9) If, within three months of the expiry of the period of probation no notice of termination of this agreement or of extension of the period of probation is received by the teacher he will be treated as confirmed in his appointment

(10) When the teacher has been confirmed, neither the teacher nor the committee subject to the provisions of clause 7, shall terminate this agreement except by giving to the other three calendar month's notice in writing or paying to the other a sum equivalent to thrice the monthly salary which the teacher is then earning

The committee shall not terminate the agreement in any case unless a resolution to this effect has been passed at a meeting of the Committee specially convened for the purpose and unless adequate reasons for such action are recorded in the resolution. Such reasons shall be (a) inefficiency (b) general retrenchment decided upon for reasons of financial stringency (c) abolition of a subject or (d) abolition of a section or class

(11) The teacher shall follow all rules in regard to public examinations and private tuitions etc in force in the institution

(12) If the teacher wishes to apply for any job elsewhere, the application shall be sent through the Head of Institution. The maximum number of places where one can apply shall not be more than two during an academic year

(13) If the teacher violates the provision of either clause 7 or clause 9 he will forfeit all pay then due to him and the committee may terminate his services or dismiss him as the case may be

(14) The committee will not except with the previous sanction (to be obtained in writing) of the Director of Education exercise its right under clause 8 between first day of January and 31st day of March of any year. But the three months notice required under clause 8 shall not include the vacation

(15) Similarly no teacher will terminate his services before the end of the session without the previous premission in writing from the Director of Education

(16) In case the Committee decides to impose any punishment under clause 7 of this agreement the decision of the

प्रधान के जरिये समिति को लिखित नोटिस देकर या समिति को एक माह का वेतन जमा करा कर इकरारनामा तोड़ सकता है।

परीवीक्षाकाल के समाप्त होने के तीन माह बाद इकरारनामा समाप्त करने की सूचना प्राप्त न हो, या परीवीक्षाकाल बढ़ाया जाने की सूचना अध्यापक को न मिले तो उसकी नियुक्ति स्थायी समझी जायेगी।

(10) जब अध्यापक को स्थायी कर दिया गया हो, तो वाक्य 7 के अनुसार न तो अध्यापक और न समिति ही इकरारनामे को तोड़ सकेगी। सिवाय या तो तीन माह की लिखित सूचना देकर या अध्यापक उस समय जो प्राप्त कर रहा है, उस दर पर तीन माह का वेतन एक दूसरे को जमा करा कर इकरारनामा तोड़ा जा सकेगा।

समिति किसी भी स्थिति से एककरारनामे को नहीं तोड़ सकेगी जब तक समिति की सभा भ इस प्रभाव के लिए प्रस्ताव पास न कर लिया हो, खासतौर से प्रस्ताव में उद्देश्य व प्रमुख कारण दिये जाने चाहिए। ये कारण —(1) अक्षमता, (2) आर्थिक कमी के कारण सामान्य छुटनी करना (3) विषय के समाप्त होने पर (4) कक्षा या वर्ग के समाप्त होने पर, होंगे।

(11) अध्यापक का परीक्षा व निजी ट्यूशन के लिए सस्था में लागू नियमों का पालन करना पड़ेगा।

(12) अगर अध्यापक की इच्छा किसी दूसरे स्थान पर कार्य के लिये प्रायना पत्र देने की है तो प्रायना पत्र सस्था के प्रधान द्वारा भेजा जायेगा। एक शैक्षणिक सत्र में वह अधिकतम दो स्थानों पर प्रायना पत्र दे सकेगा।

(13) अगर अध्यापक वाक्य 7 या 9 का उल्लंघन करता है तो उसका बकाया वेतन जब्त किया जावेगा और समिति उसकी सेवा से मुक्त कर सकती है या निकाल सकती है, जैसी भी स्थिति हो।

(14) शिक्षा निदेशक की पूर्व (लिखित) स्वीकृति के बिना समिति वाक्य 8 में दिये अधिकारों का प्रयोग एक जनवरी से 31 मार्च के बीच नहीं करेगी, परंतु तीन माह की सूचना में अध्यापकाल शामिल नहीं की जावेगी।

(15) इसी तरह किसी भी अध्यापक को शिक्षा निदेशक की पूर्व लिखित स्वीकृति बिना सत्र के अन्त से पहले सेवा मुक्त नहीं किया जा सकेगा।

(16) इस इकरारनामे के उप वाक्य (7) के अन्तर्गत समिति कोई दण्ड दना तय करती है तो समिति अपना निर्णय तत्काल प्रभावशील होगा, और अध्यापक

Committee shall become operative immediately and the teacher shall carry it out immediately. He will however, have the right to appeal to the Appeal Authority specified in Appendix III of the grant in aid Rules.

(17) In all cases of appeal the decision of the department or the Government shall be final and no suit shall lie in any Civil Court in respect of the matters decided by it. Further neither of the parties shall sue the other for the breach of this agreement nor refer it to arbitration without having first referred the question in dispute to the Director of Education and allowed him reasonable time not exceeding two months to settle the dispute.

**Note** — If the management fails to honour the judgement made by the Appellate Authority within three months of the date of award, the amount ordered for payment to the teacher shall be deducted from the grant in-aid bill of the institution and paid to the teacher concerned direct by the Director of Education under intimation to the management.

(18) If the teacher is not in the station at the time when any notice ought to be given to him in accordance with any of the provisions of the agreement such notice may be sent to him by registered post, to his address if known and a notice so posted whether even delivered or not shall have effect from the day when it would have reached him in the ordinary course of the post. If the teacher leave the station without leaving any address a resolution or decision of the Committee passed not less than fourteen days, after the date when notice would have been given to him if he had been in the station shall be effective whether the teacher gets notice of it or not.

In witness whereof the parties hereto have set their hands the day and year above written

Signed on behalf of the Committee \_\_\_\_\_  
under the authority of the Committee as passed on in the presence of —

Witness (1) \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

Witness (2) \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

तत्काल पालन करेगा। सहायक अनुदान नियम के परिशिष्ट 3 के अंतर्गत उस अपील प्राधिकारी कि पास अपील करने का अधिकार है।

(17) अपील के समस्त मुकद्दमों के लिए विभाग का या सरकार का नियुक्त प्रतिम होगा। नियुक्त किये मामलों के बारे में किसी भी दीवानी अदालत में मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकेगा। एकरारनामे को तोड़ने के लिए दूसरी पार्टी न तो मुकद्दमा ही चला सकती है और न पचाट को ही सौंप सकती है जब तक इस भगड के प्रश्न को शिक्षा निदेशक के पास न भेज दें। भगड को सुलझाने के लिए उचित समय देना चाहिये, परन्तु दो माह से अधिक नहीं।

**टिप्पणी —** अगर प्रबन्ध 3 माह तक अपील सुनने वाले अधिकारी का ध्यान पालन करने में असफल रहता है तो जो रकम अध्यापक का दी जाने वाली है, वह रकम शिक्षा निदेशक संस्था के सहायक अनुदान विस में से काट कर, प्रबन्ध को सूचना देकर, सम्बंधित अध्यापक को चुका देगा।

(18) एकरारनामे सम्बंधित दी जाने वाली सूचना के समय अगर अध्यापक स्टेशन पर नहीं है, तो इस प्रकार की सूचना उसको उसके पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजनी चाहिए, अगर जानते हो। सूचना जा भेजी जानी चाहिए भेजी जाय अथवा नहीं उसका असर उसी दिन से प्रारम्भ होगा जिस तरह साधारण डाक उसको प्राप्त होती। अगर अध्यापक बिना बता दिये स्टेशन छोड़ता है, उसे सूचना दिये जाने के 14 दिन के अंदर कोई प्रस्ताव या नियुक्त समिति पास करती है और वह स्टेशन पर मौजूद है, तो उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा, चाहे सूचना मिले अथवा न मिले।

उपरोक्त लिखित वष और दिन का पक्षी के साक्षी ने अपन हस्ताक्षर किये।

समिति की ओर से प्रस्ताव के प्राधिकार से अधिकारी  
न निम्न की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया —

साक्षी (1)

पता

साक्षी (2)

पता

Witness (1)-----

Address-----

Witness (2)-----

Address-----

## APPENDIX IV

Form of agreement to be executed by the Heads of  
recognised aided institutions

An agreement made this-----day of-----  
-----19-----between-----  
(hereinafter called the Headmaster) of the one part and the  
Managing Committee Proprietor of the -----school  
(hereinafter called the Manager of the other party The  
Manager hereby agrees to employ the Headmaster and the Head  
master hereby agrees to serve as Headmaster in the said school  
on the following terms—

(2) The Headmaster's employment shall begin from the  
-----day of-----19 He shall be employed  
in the first instance for twelve months on probation and during  
this period shall be paid monthly salary of Rs -----

(2) If confirmed in his appointment at the end of his  
period of probation the Headmaster shall be employed on a  
monthly of Rs -----with increment of-----

(3) The Manager shall pay the Headmaster the said mon-  
thly salary not later than the tenth day of the month following  
that for which the salary is earned, and the Headmaster shall, on  
receiving the salary sign the acquittance roll in token of such  
receipt

(4) The Headmaster shall perform all such duties as  
appertain to a Headmaster and shall be responsible to the Mana-  
ger of the said school for the due discharge of all such duties  
The Headmaster shall be solely responsible for the internal  
management and discipline of the said school, including such  
matters as the selection of text books, the arrangement of time  
tables, the allocation of duties to all members of the school  
staff the grant of casual leave to the staff in accordance with  
rules made by the Manager, the appointment, promotion, control  
and dismissal of the menial servants, the admission of free and  
half rate pupils within the number sanctioned by the Manager

साक्षी (1)

पता

साक्षी (2)

पता

## परिशिष्ट ४

मान्य एव अनुदान प्राप्त सस्याओं के प्रधानों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले  
एकरारनामों का ग्राह्य

यह एकरारनामा (जो कि  
बाद में प्रधानाध्यापक पुकारा जायगा) एक तरफ और दूसरी ओर प्रबन्ध समिति  
स्कूल के बीच यह तय किया जाता है। (जो कि बाद में प्रबन्धक  
बहा जायेगा) प्रबन्धक प्रधानाध्यापक को सेवा नियुक्त करने की स्वीकृति देता है और  
प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक के पद पर निम्न शर्तों के साथ सेवा करने की स्वीकृति  
देता है —

(1) प्रधानाध्यापक का सेवा काल (जो कि  
से प्रारम्भ हो जायगा। वह प्रथम बार 12 मास तक परीवीक्षा के तौर पर नियुक्त  
किया जायगा। इस काल में मासिक वेतन 19  
दिनांक 19

(2) परीवीक्षा काल के समाप्त होने पर अगर स्थायी हो जाता है तो उसका  
मासिक वेतन रु० ६ होगा।

(3) प्रबन्ध प्रधानाध्यापक को उसने द्वारा कमाया हुआ वेतन, उस माह के  
दस दिन के अन्दर भुगतान करे, और प्रधानाध्यापक रसीद के लिए हस्ताक्षर करे।

(4) प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक से सम्बन्धित समस्त कार्य करने  
चाहिए। इन समस्त वस्तुओं के लिए प्रधानाध्यापक प्रबन्धक के प्रति उत्तरदायी है,  
प्रधानाध्यापक या तद्विषय प्रबन्धक व अनुशासन के लिए पूर्णतया जिम्मेदार है जैसे  
अन्य पुस्तकों का चुनाव, समय सारिणी की व्यवस्था स्कूल अधिनारी वगैरे सदस्यों  
काय विवरण, प्रबन्धकों द्वारा बनाये गये अवकाश नियमों के अनुसार कमबारी



the control of the hostel through the Superintendent, the admission and promotion of pupils, the organisation of games and the administration of the games fund and other similar funds such as a reading room, or examination fund. In financial and other matters for which he is not solely responsible the Headmaster shall follow the direction of the Manager, all instructions by the Manager to the members of the staff shall be issued through the Headmaster.

The Headmaster shall have administrative control over the clerk and shall make recommendation to the Manager in regard to the number of free and half rate pupils to be admitted to the institutions. The Manager shall have the power to appoint, promote and dismiss the clerk, but the Headmaster shall have the power of controlling him.

(5) The Headmaster shall give his whole time to the services of the said school and shall not, take up any work unconnected with the said school without obtaining the previous sanction of the Manager, the Headmaster shall not leave the station in which the said school is situated during the holidays and the vacation without having first obtained the written permission of the Manager.

(6) The Headmaster shall conform to all the approved rules in force in the school inclusive of leave rules and shall obey all lawful orders and directions as he shall from time to time receive from the Manager.

(7) (a) The Manager may dismiss a Headmaster without notice for any one or more of the following offences —

(1) Insubordination

(2) Deliberate neglect of duty

(3) Serious misconduct or the commission of an act which constitute a criminal offence

After proper enquiry is made, a charge sheet is given and an opportunity to answer is given to the person concerned.

(b) Such termination will have to be supported by a resolution of the Committee specially convened for the purpose at least three fourth of the members are present by a two third majority of the members present and voting.

(c) The dismissal or removal of a teacher shall be subject to the approval of the Director. A teacher discharged with or

वग का ताकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना, सेवक की नियुक्ति, पदोन्नति, नियंत्रण व कायच्युत करना, प्रबंधकों की स्वीकृति के अनुसार भाषी शुल्क व शुल्क मुक्त छात्रों की भर्ती करना अधीक्षक द्वारा छात्रावास पर नियंत्रण, छात्रों की भर्ती व उनकी उन्नति खेल की व्यवस्था, खेल कोष और उसके समान भय कोषों जैसे वाचनालय या परीक्षा कोष पर अधिकार व भय मामलों में जिसमें प्रधानाध्यापक पूर्णतया जिम्मेदार नहीं है, उसे प्रबंधक के निर्देश मानने होंगे। प्रबंधक द्वारा दिए गये, स्टाफ के सदस्यों के लिए निर्देश प्रधानाध्यापक द्वारा दिए जावेंगे।

प्रधानाध्यापक का लिपिक पर नियंत्रित शासन होगा और प्रबंधकों को सलाह देगा कि कितने छात्र शुल्क मुक्त व कितने भाषी शुल्क के होंगे। प्रबंधक लिपिक को नियुक्त करने, पदोन्नत करने और उसको कायच्युत करने का अधिकार है, परंतु प्रधानाध्यापक को उस पर नियंत्रण रखने का अधिकार है।

(5) प्रधानाध्यापक को सब समय स्कूल की सेवा के लिए देना होगा। वह कोई भी ऐसा काम जो स्कूल से सम्बंधित नहीं है जब तक प्रबंधक से पूछ लिखित आज्ञा प्राप्त न करले, न करगा, प्रधानाध्यापक जहां स्कूल स्थित है, उस स्थान की इमारतों में या अवकाश में बिना प्रबंधक की आज्ञा के न छोड़ेगा।

(6) प्रधानाध्यापक को सत्या में लागू समस्त स्वीकृत नियमों व अवकाश नियमों का पालन करना होगा एवं उसे समस्त कानूनी आज्ञाओं व निर्देशों का, जो कि समय समय पर प्रबंधकों से प्राप्त होते हैं पालन करना होगा।

(7) (अ) प्रबंधक प्रधानाध्यापक को निम्न में से किसी एक या अधिक अपराध करने पर कायच्युत कर सकता है —

(1) आज्ञा भंग

(2) जान बूझ कर कर्तव्य की अवज्ञा

(3) गम्भीर दुराचार, या ऐसा काम जो कि फौजदारी अपराध हो।

उचित जांच करने के बाद एक दोपारोपण पत्र दिया जावेगा व सम्बंधित व्यक्ति को उत्तर देने की सुविधा दी जावेगी।

(ब) इस प्रकार की सेवा समाप्ति विशेष प्रस्ताव के द्वारा होगा जिसमें तान चौपाई सदस्य उपस्थित हो, व उपस्थित सदस्यों का दो तिहाई बहुमत प्राप्त हो।

(स) निदेशक की अनुमति से ही किसी अध्यापक को निलंबित जावेगा या कायच्युत किया जावेगा। अगर कोई अध्यापक बिना सूचना के या सूचना के

without notice may submit an appeal to the Director, provided that such an appeal is preferred within thirty days of the order of dismissal or removal

(8) While the Headmaster is on probation, as provided in clause 1, the manager may at any time terminate this agreement by giving the Headmaster two calendar month's notice in writing or upon paying to the Headmaster sum equal to two months salary in addition to any pay which may be due to him and the Headmaster may similarly terminate this agreement, by submitting two calendar month's notice in writing to the Manager or paying to the Manager a sum equal to his salary for two months

(9) If by end of his period of probation no notice of the termination of this agreement as provided for under clause 8 has been received or given by the Headmaster, he will ipso facto be confirmed in his appointment

(10) When the Headmaster has been confirmed, neither the Headmaster nor the Manager, subject to the provision of clause 7, shall terminate this agreement except by giving to the other three calendar month's notice in writing or by paying to the other a sum equivalent to three times the monthly salary which the Headmaster is then earning

(11) If the Headmaster at any time terminate this agreement otherwise than under the provisions of either clause 8 or clause 10 he will forfeit all pay then due to him and the Manager may dismiss him

(12) The parties to this agreement accept its conditions subject to such rules for the conduct of recognised schools as may be issued from time to time by the Education Department

In witness whereof the parties hereto have herein to set their hands the day and year first above written  
Signature

On behalf of the Managing Committee, under authority of resolution of the committee as passed on \_\_\_\_\_ in the presence of —

Witness (1)

Address

कायच्युत किया जाता है, वह कायच्युत या हटाए जाने की आज्ञा प्राप्त होने के तीस दिन के अंदर निदेशक के पास अपील कर सकता है।

(8) वाक्य 1 के अन्तर्गत जब प्रधानाध्यापक परीवीक्षा काल पर हो, तो प्रबंधक दो माह की लिखित सूचना देकर या दो माह का अग्रिम वेतन जो कि वह प्राप्त कर रहा था, देकर सेवा समाप्त कर सकता है। इसी तरह प्रधानाध्यापक प्रबंधक को दो माह की लिखित सूचना देकर या दो माह का वेतन जमा करवा कर इस इकरारनामे को तोड़ सकता है।

(9) परीवीक्षा काल समाप्त होने के बाद वाक्य 8 के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक न तो इकरारनामा समाप्ति की सूचना हो पाता है, और न देता ही है, तो उसकी नियुक्ति वास्तविक में स्वतः स्याई हो जायेगी।

(10) वाक्य 7 के अन्तर्गत, प्रधानाध्यापक के स्याई होने के बाद न तो प्रधानाध्यापक और न प्रबंधक ही तीन माह की लिखित सूचना दिये बिना या तीन माह का वेतन जमा करा करके बिना, जो कि प्रधानाध्यापक प्राप्त कर रहा है, इकरारनामे को नहीं तोड़ सकेंगे।

(11) अगर प्रधानाध्यापक वाक्य 8 या 10 के विरुद्ध किसी भी समय इकरारनामे का खण्डन करता है तो उसकी अकाया रकम जमन करली जावेगी और प्रबंधक उसको कायच्युत कर सकता है।

(12) इस इकरारनामे के पक्षों को शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर मायता प्राप्त स्कूलों के व्यवहार के नियमों के लिए लागू शर्तों को स्वीकार करना होगा।

उपरोक्त लिखित साल व दिन को दाना यमो ने साक्षी के सम्मुख लिखित हस्ताक्षर किये।

हस्ताक्षर

प्रबंध समिति की ओर से प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त प्राधिकार से

निम्न की उपस्थिति में प्रस्तावित किया —

साक्षी (1)

पता

Witness (2)

Address

Signed by the said Headmaster                      in the presence of

Witness (1)                      ..

Address

Witness (2)

Address

**Note 1** —In the case of an intermediate College, the word "School" where it occurs in the agreement should be altered to "College" and the word "Headmaster" to "Principal"

**Note 2** —In cases of girls schools, the word "Headmaster" where it occurs in the agreement should be altered to "Headmistress"

—————

साक्षी (2)

पता

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक

इनकी उपस्थिति में —

साक्षी (1)

पता

साक्षी (2)

पता

टिप्पणी — (1) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए जहाँ वही भी शब्द "स्कूल" आया है वहाँ "बालक" व "प्रधानाध्यापक" के स्थान पर भाषायें समझा जाय ।

(2) छात्रागो के संवध में जहाँ वही भी शब्द "प्रधानाध्यापक" आया है, वहाँ "प्रधानाध्यापिका" समझा जाय ।

-----

**APPENDIX V**  
**Schedule of power of Departmental Officers for aided institution**

S No	Name of expenditure	Govt	Director of Education	Dy Director of range	IOS	Remarks
1	2	4	4	5	6	7
1	Approval of appointment Full powers		D E (College) up to the Lecturers (285 25 510 EB 25-560 30 800)	Instructors in B S T C (170 10 310 12 1/2-335)	Up to Trg Inter (75-4 95 5 105 EB 5 130 FB 5-160)	
			2 D E (P&S) (i) Headmaster H S (285-20 385 25 510 540)	Trg Graduate or Graduate (115 5 155 10-16 EB 10 235 250)	L D C (90 4 102 EB 4-110 5 150)	

(ii) Headmaster  
H S S (270)

## परिशिष्ट १

भायता प्राप्त सम्पत्तों के विभागीय अधिकारियों के अधिकारों की अनुसूची

क्रम से	व्यय का नाम	सरकार	शिक्षा निदेशक	श्रेणी का उप शिक्षा निदेशक	विद्यालय निरीक्षक	विशेष अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	नियुक्ति के लिए	समस्त अधिकार	1 शिक्षा निदेशक प्राध्यापक तक (285-25- 519-दस्ता बरी 25 560 30 800	वेसिक एस टी सी में शिक्षक (170-10 310 1211-335)	प्रशिक्षित इन्टर तक (75-4 95-5 105 दस्ता बरी 5-160)	
2	अपर निदेशक (ग्रा व मा ) (1) प्रधानाध्यापक हाईस्कूल (285 20- 385 25 510 540)			प्रतिष्ठ स्नातक स्नातक (115 5 155 10 165-दस्ता बरी 10 235- 250)	कनिष्ठ लेखक (90 4-102 दस्ता बरी 4-110 5-150)	
	(11) प्रधानाध्यापक उच्चतर माध्य मिक शाला					



1	2	3	4	5	6	7

20 375-25-  
560 30 650)

(iii) Senior Teacher  
(225 10 275-  
EB 10 285 15  
435-25 485)

3 Director, Tech  
Education up to  
lecturers (360 25  
560 30 500 EB  
30 860 900)

4 Director, Sans  
Lrit Edu Lect  
in Sans Colleges  
Beyond this to  
the Govt  
Beyond this to  
Director  
Dy Director

2 Appeal by employees  
against the decision of  
the management

According to the  
powers noted in  
item No 1

मनुदान-निक  
मार्गिक  
Note — First  
appeal by the  
employees or

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

(270-20  
375-25-  
560-30-  
650)  
(ii) वरिष्ठ अध्यापक  
(225 10 275  
दस्तावरी 10  
285 15 435  
25 485)

3 निदेशक I प्राथमिक शिक्षा  
प्रधानाध्यापक तक (360  
25 460-30 500  
दस्तावरी 30 860 900)

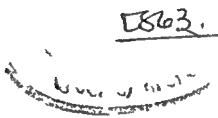
4 निदेशक संस्कृत शिक्षा इसके बाद निदेशक इसके बाद उप निदेशक

संस्कृत कालेज में  
प्राध्यापक तक इसके  
बाद मरजार  
मद न 1 में दी गई शक्ति  
के अनुसार

अध्यापकों के नियुक्ति  
के विच्छेद से सम्बन्धित  
कमचारी द्वारा

ऐसी सत्या के  
कमचारी द्वारा  
प्रथम मपील जो

4	DS Edu Lecturers in Sanskrit	Nil
1	Dr. K. S. Varma	1
2	Dr. K. S. Varma	2
3	Dr. K. S. Varma	3
4	Dr. K. S. Varma	4
5	Dr. K. S. Varma	5
6	Dr. K. S. Varma	6
7	Dr. K. S. Varma	7
8	Dr. K. S. Varma	8
9	Dr. K. S. Varma	9
10	Dr. K. S. Varma	10
11	Dr. K. S. Varma	11
12	Dr. K. S. Varma	12
13	Dr. K. S. Varma	13
14	Dr. K. S. Varma	14
15	Dr. K. S. Varma	15
16	Dr. K. S. Varma	16
17	Dr. K. S. Varma	17
18	Dr. K. S. Varma	18
19	Dr. K. S. Varma	19
20	Dr. K. S. Varma	20
21	Dr. K. S. Varma	21
22	Dr. K. S. Varma	22
23	Dr. K. S. Varma	23
24	Dr. K. S. Varma	24
25	Dr. K. S. Varma	25
26	Dr. K. S. Varma	26
27	Dr. K. S. Varma	27
28	Dr. K. S. Varma	28
29	Dr. K. S. Varma	29
30	Dr. K. S. Varma	30
31	Dr. K. S. Varma	31
32	Dr. K. S. Varma	32
33	Dr. K. S. Varma	33
34	Dr. K. S. Varma	34
35	Dr. K. S. Varma	35
36	Dr. K. S. Varma	36
37	Dr. K. S. Varma	37
38	Dr. K. S. Varma	38
39	Dr. K. S. Varma	39
40	Dr. K. S. Varma	40
41	Dr. K. S. Varma	41
42	Dr. K. S. Varma	42
43	Dr. K. S. Varma	43
44	Dr. K. S. Varma	44
45	Dr. K. S. Varma	45
46	Dr. K. S. Varma	46
47	Dr. K. S. Varma	47
48	Dr. K. S. Varma	48
49	Dr. K. S. Varma	49
50	Dr. K. S. Varma	50
51	Dr. K. S. Varma	51
52	Dr. K. S. Varma	52
53	Dr. K. S. Varma	53
54	Dr. K. S. Varma	54
55	Dr. K. S. Varma	55
56	Dr. K. S. Varma	56
57	Dr. K. S. Varma	57
58	Dr. K. S. Varma	58
59	Dr. K. S. Varma	59
60	Dr. K. S. Varma	60
61	Dr. K. S. Varma	61
62	Dr. K. S. Varma	62
63	Dr. K. S. Varma	63
64	Dr. K. S. Varma	64
65	Dr. K. S. Varma	65
66	Dr. K. S. Varma	66
67	Dr. K. S. Varma	67
68	Dr. K. S. Varma	68
69	Dr. K. S. Varma	69
70	Dr. K. S. Varma	70
71	Dr. K. S. Varma	71
72	Dr. K. S. Varma	72
73	Dr. K. S. Varma	73
74	Dr. K. S. Varma	74
75	Dr. K. S. Varma	75
76	Dr. K. S. Varma	76
77	Dr. K. S. Varma	77
78	Dr. K. S. Varma	78
79	Dr. K. S. Varma	79
80	Dr. K. S. Varma	80
81	Dr. K. S. Varma	81
82	Dr. K. S. Varma	82
83	Dr. K. S. Varma	83
84	Dr. K. S. Varma	84
85	Dr. K. S. Varma	85
86	Dr. K. S. Varma	86
87	Dr. K. S. Varma	87
88	Dr. K. S. Varma	88
89	Dr. K. S. Varma	89
90	Dr. K. S. Varma	90
91	Dr. K. S. Varma	91
92	Dr. K. S. Varma	92
93	Dr. K. S. Varma	93
94	Dr. K. S. Varma	94
95	Dr. K. S. Varma	95
96	Dr. K. S. Varma	96
97	Dr. K. S. Varma	97
98	Dr. K. S. Varma	98
99	Dr. K. S. Varma	99
100	Dr. K. S. Varma	100

1	2	3	4	5	6	7
3	नई पद स्थापन के सिये भनुमोदन	निदेशक की शक्ति के बाद के समस्त अधिकार	समस्त अधिकार इस तन्त्र - 1 शिक्षा निदेशक कालेज प्राध्यापक तक । 2 अपर निदेशक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, प्रधानाध्यापक/प्रधाना ध्यापिका/हाईस्कूल व उच्चतर माध्यमिक शाला तक ।	<div style="text-align: center;">  <p>1863.</p> </div>		
				3 निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, प्राध्यापक तन्त्र (360- 25-460-300-500 दसता बरी-30-860- 900)		कि इससे अधिक संस्थाएं चलाती हैं जिसका वार्षिक खर्च 1 लाख रु से अधिक हो निदेशक, शिक्षा विभाग के पास की जायेगी और दूसरी श्रेणील सर कार के पास होगी ।
				4 निदेशक संस्कृत शिक्षा प्राध्यापक संस्कृत कालेज		

1	2	3	4	5	6	7
84	Approval of raising of Full powers standard/sanction for opening of new subjects		Nil	Nil	Nil	Nil
5	Approval of opening of new section		Nil	Nil	Nil	Nil
6	Approval of non recurring expenses	Full powers with concurrence of G I Committee	Up to 50,000/ with concurrence of G I Committee	Upto middle acc- ording to approved pattern	Up to primary according to approved pattern	Nil
7	Approval of constitution Full powers (College)	Full powers above 50,000/	Full powers (School level)	Middle School	Primary School	
8	Sanction of non recurring grants (Within budget provision)	Full powers	Up to 25,000/	Nil	Nil	
9	Sanction of Grant in aid to new institutions with the concurrence of G I A	Full powers with the concurrence of G I A	Nil	Nil	Nil	

1	2	3	4	5	6	7
	4 स्तर ऊंचा उठाने के लिये अनुमोदन/ नये विषय सोलने की स्वीकृति]	समस्त अधिकार	X	X	X	
5	नया वग सोलने के लिए अनुमोदन	"	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	
6	अनावश्यक व्यय का अनुमोदन	सहायता अनुदान समिति की राय से 50,000 के ऊपर के समस्त अधिकार	सहायता अनुदान समिति की राय से 50,000 तक	अनुमोदित प्रणाली अ तयत माध्यमिक स्तर तक	अनुमोदित प्रणाली अ तयत माध्यमिक स्तर तक	
7	सविधान के लिए अनुमोदन	समस्त अधिकार (बालेज)	समस्त अधिकार (स्कूल स्तर)	माध्यमिक शाखा	प्रारम्भिक शाखा	
8	अनावश्यक अनुदान स्वीकृत बजट की अनुसार	समस्त अधिकार	25000 तक	X	X	
9	नई संस्थाओं को सहायता अनुदान की स्वीकृति	सहायता अनुदान समिति की राय से समस्त अधिकार	X	X	X	

छे न स एफ 29 (1) CAV/Edw/Gr V/72 दि 29-12-1973 द्वारा प्रतिस्थापित ।

1	2	3	4	5	6	7
10	Sanction of Grant in aid to institutions outside Rajasthan	Full powers with the concurrence of GIA	Nil	Nil	Nil	
11	Sanction of Grant in aid to institutions already in the grant in aid list within budget provision		Full powers	Nil	Nil	
12	Change in category of institution		Full powers with concurrence of GIA	Nil	Nil	
13	Approval of special increments Higher start & special level etc	Full powers	Full powers up to the powers of appointment	Nil	Nil	

1	2	3	4	5	6	7
10	राजस्थान से बाहर की सस्थाओं को सहायता अनुदान समस्त अधिकार	सहायता अनुदान समिति की राय से समस्त अधिकार	X	X	X	
11	सस्था को सहायता अनुदान की स्वीकृति, को पहले सही बजट से सहायता अनुदान प्राप्त कर रही है			+	+	
12	सस्था की श्रेणी का परिवर्तन				X	
13	उच्चतर व लाभ बढ़ोतरी का प्रमुख बढ़ोतरी के लिए अनुदान	समस्त अधिकारी		+	X	
			सहायता अनुदान समिति की राय से समस्त अधिकार	X		
			नियुक्ति के अधिकार तक समस्त अधिकार	X	X	





## परिशिष्ट ६

निजी सहायकों में सहायता अनुदान के लिये अनुमानित खर्च की अधिकतम सीमा का संबंधित भूभाग

क्रम	सहायक अनुदान में टेकनीकल स्नातकोत्तर	उपाधि महा प्रशिक्षण	उच्चतर	हाईस्कूल मिडिल प्राथमिक	माटेसरी						
सह	निर्दिष्ट सीरक इ-जीनियरिंग कॉलेज	उच्च विद्यालय 11 महा विद्यालय से 14 तक	माध्यमिक विद्यालय 9 से 12 तक	माध्यमिक या शाखा 6 से एस टी मी 12 तक	स्कूल प्राथमिक स्कूल मिडिल स्कूल 1 से 3 तक						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 धेतन --

(अ) सहायक वग राजस्थान धेतन क्रम या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित धेतन क्रम के अनुसार (जो अधिक हो) परन्तु कमबारी वग के बढ़ने पर या धेतनमान प्रथवा महगाई भत्ते के बढ़ने से होने वाले परिवर्तन से बढे हुए श्रद्धों के लिए विभाग से पहले स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिये ।

(ब) विभिन्न वर्गों

कमबारी वग

(स) वधुर्प श्रेणी

कमबारी वग

2 प्रोविडेंट फंड

6 1/2% से अधिक नहीं । जोधपुर राज्य में पहले और अनिवार्य शिक्षा स्कूल के पूर्व विलयी कमबारी के 8 1/2% तक । उपाधि महाविद्यालय और स्नातकोत्तर उच्च विद्यालय के राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 8% सरकार द्वारा स्वीकार की गई क्रम (Scale) से अधिक नहीं ।

3 महगाई भत्ता

4 धेतन सामग्री एम

मुद्रण

900 700 600 600 500 460 350 200 75 150



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 पानी और रोशनी												
खर्च			600	600	500	600	600	600	300	125	50	250
6 सामान पर भावतक			छे[रात्रि महाविद्यालयों के लिये 1000/- रु]									
खर्च			विश्वविद्यालय की शत के अनुसार बोड की शर्त के अनुसार और एस टी सी 150 50 250									
			स्कूल के लिए विवरण "द" में दी गई सीमा होगी।									
7 साधारण सरम्मत												
(1) भवन			यकै भवन के लिये लागत का 1% प्रतिवर्ष, और कच्चे भवन के लिए 2% प्रतिवर्ष 25000 तक और इसकी जाच निरीक्षक शिक्षा विभाग करेगा और पी० डब्लू० डी० द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।									
(2) फर्नीचर और												
उसका स्थानान्तरण			700	600	600	500	500	300	200	150	100	250
8 भवन किराया			वास्तविक बिना गया खर्च (मूल रसीदें प्रस्तुत की जावेंगी) या सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये निर्धारण प्रमाण-पत्र पर जो भी कम हो।									
9 पुस्तकालय की पुस्तकें												
व पाचनालय पर												
दिये जाने वाला			700	विश्वविद्यालय की शत		700	500	500	300	100	50	150
खर्च			के अनुसार									

छे स एफ 1 (26) Edu /Cell VI/68 दि 5-8-1969 द्वारा निविट।

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10 खेल शारीरिक शिक्षा व श्रम सांस्कृतिक कार्यों पर किए जाने वाले शुद्ध खर्च											
11	क्राफ्ट पर लेखी, डेरी पर किया जाने वाला शुद्ध खर्च	800	800	700	700	500	400	300	200	50	250
12	ग्रन्थालयों द्वारा सम्मेलन में भाग हेतु यात्रा व्यय	—	—	300	—	300	300	150	50	100	—
13 भर्त्ता सस्थाओं का प्रबंध करने वाले केन्द्रीय कार्यालय का खर्च—(1) विभाग द्वारा अनुमोदित 1 लाख का खर्च, और जो (2) दो लाख का खर्च या अधिक विभाग द्वारा, तीन भर्त्ता सस्थाओं रखती हो —											
[नियम 6 (ख) भी देखिये]											
(1) प्रबंध मंत्री × [150 350]											
(2) निम्न श्रेणी लिपिक 60 130											
(3) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक 25 40											
(4) कार्यालय का अनुसूचित व्यय 500											
(1) प्रबंध मंत्री × [225-525]											
(2) लेखापाल 150 300											
(3) उच्च श्रेणी लिपिक कम स्टेनो 80 200											
(4) दो निम्न श्रेणी लिपिक 60 130											

× वि स एक 20 (2) Edu / Gr V/73 वित्तक 14 10 75 द्वारा वेतनमान सशोधित ।



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	आम व्यय व	--	--	--	--	600	200	150	75	50	75
	अथ फुटकर खच	--	--	--	--	250	75	60	30	15	30

टिप्पणियाँ

- (1) पुस्तकालय की पुस्तकें और वाचनालय —अगर मिडिल स्कूल में छात्रों को सरया 300 से अधिक है, तो 150 रु और प्राथमिक शाला में छात्रों की सरया 200 से अधिक हो तो 75 रु स्वीकार किया जायगा।
- (2) पुस्तकालय के लिये।
- (3) मद न० 6 में सामान पर खच और मद न० 9 में पुस्तकालय की पुस्तकों पर खच, साधारण सीमा है, उपरोक्त अनुसार विषय के अनुसार किये जाने वाला खच परिशिष्ट (अ) में देखें।
- (4) मद (अ) और 3 मा यता प्राप्त सस्थाओं के विषय में—जब कि वह पहले मजमेर राज्य में 1 11 55 के बाद नियुक्त किया गया हो उस पर राजस्थान वेतन गृह खला लागू होगी।
- (5) सामान्य पुस्तकालय के लिए मद न० 9 में दिखाये गये विषय के अनुसार खच के लिए परिशिष्ट (अ) देखें।

छात्रावास

लडकी की सरया 25 होने पर और लडकियों की सरया 15 होने पर बक्षा भत्ता 30 रु० प्रति मास ११ हिसाब से दिया जा सकता है, और सरक्षक/अधीक्षक/भेटन का वेतन प्रतिमास 200 रु० से कम नहीं होना चाहिये।



**STATEMENT--B (ANNEXUR to APPENDIX VI)****Statement Showing Limits of Recurring Grants  
For S T C Schools Under Head Equipment  
And Apparatus**

1	History Maps & Charts	Rs	50 00
2	Geography	Rs	50 00
3	Commerce	Rs	100 00
4	Drawing & Painting	Rs	100 00
5	Music	Rs	100 00
6	Apparatus & Chemicals (Physics & Chemistry)	Rs	300 00
7	General Science	Rs	200 00
8	Domestic Science	Rs	200 00
9	Civics with Indian Admin	Rs	25 00
10	Biology	Rs	100 00
11	Agriculture	Rs	500 00

## सारणी-ब (परिशिष्ट ६ से संलग्न)

एस टी सी स्कूलों के लिए शीपिंग सामान तथा यंत्रों के अन्तर्गत

आवर्तक अनुदान की सीमा निर्धारण का विवरण पत्र

(1)	ऐतिहासिक मानचित्र और चाट स	—	50 00 रु०
(2)	भूगोल	—	50 00 रु०
(3)	वाणिज्य	—	100 00 रु०
(4)	चित्रकला	—	100 00 रु०
(5)	संगीत	—	100 00 रु०
(6)	यन्त्र और रसायन (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र)	—	300 00 रु०
(7)	सामान्य विज्ञान	—	200 00 रु०
(8)	गृह विज्ञान	—	200 00 रु०
(9)	भारतीय शासन तथा नागरिक शास्त्र	—	25 00 रु०
(10)	जीव विज्ञान	—	100 00 रु०
(11)	कृषि	—	500 00 रु०



संस्था से क्षतुय क्षेणी के विभिन्न कर्मचारियों की क्षेणी का विवरण

क्रम सं०	श्रीपक	टैक्नीकल इ अनियरिंग कालेज	स्नातकोत्तर उच्च विद्यालय	उपाधि महा विद्यालय	प्रशिक्षण महा विद्यालय	उच्च माध्यमिक विद्यालय	उच्च माध्यमिक शाळा	उच्च माध्यमिक एस टी सो	प्राथमिक शाळा	माटेसरो स्कूल	छात्रावास	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

क्षतुय क्षेणी कम चारी

चपरसी	4	4	4	4	3	3	3	---	---	2	जहाँ एक ही भवन
बोकीदार	1	1	1	1	1	1	1	1	---	1	मे दो गिफ्ट चलती
जलधारी	1	1	1	1	1	1	1	1	---	---	है बहा एक प्रतिरिक्त
प्रयोगशाळा सेवक											बोकीदार

(लेब बियरर) जहाँ पर प्रत्येक विषय के लिए प्रयोगशाळा काम मे लाई जाती है, वहाँ प्रत्येक वग विषय के लिए एक लेब बियरर

गसे यत्र के लिए मिस्त्री	---	1	1	1	1	1	1	---	---	---	हाईस्कूल और नीचे
हरिजन (भरी)	1	1	1	1	1	1	1	1	---	1	जहाँ विचारियों की
फर्राश	2	2	2	2	2	2	1	---	---	1	संख्या 500 से
नेम्स बाँय	1	1	1	1	1	1	1	---	---	---	अधिक हो बहा एक
बागवान	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	प्रतिरिक्त फर्राश रखा
खेतीहर कमचारी	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	जा सकता है।
पुस्तकालय परिचारक	1	---	---	---	1	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

**Class IV Servants**

Portentous course of the  
Higher Sec Schools Techni-  
cal

7 These depend upon  
the sub allotted to  
the institution

Agriculture

1

2

Fine Arts

2

Home Science

1

Commerce

1

Ministerial staff

1

Librarian

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

UDC

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

LDC,

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

NOTE —1,

1 part time

for all the students and enough facilities exist for the purpose provided the No of students is at least 300

2

Gardner —Allowed for High School and institutions of Higher Standard provided the institution maintain a suitable Garden and justified the work for the full time man

3

Lib Attendant —In all High Schools or above where there is a separate librarian and the issue of books justifies the necessity of a library attendant One extra hand for institution where open shelf system is in vogue be also given

4

Monfessory Schools —If there be middle section one add peon and one add waterman if the









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Class IV Servants													
Previous course of the Higher Sec Schools Technical													
Agriculture				1	2								
Fine Arts									2				
Home Science						1			1				
Commerce									1				
Ministerial staff													
Librarian				1	1	1	1	1	1	1			
UDC				2	2	2	1	1	1	1			
LDC,				2	2	2	2	2	2	2	1	1	part time
NOTE—1, Games Boys—In all the Secondary School and Inter Colleges where regular games are provided for all the students and enough facilities exist for the purpose provided the No of students is at least 300													
2	Gardner —Allowed for High School and institutions of Higher Standard provided the institution maintain a suitable Garden and justified the work for the full time man												
3	Lib Attendant —In all High Schools or above where there is a separate librarian and the issue of books justifies the necessity of a library attendant One extra hand for institution where open shelf system is in vogue be also given												
4	Montessori Schools —If there be middle section one add peon and one add waterman if the number exceeds 200												

7 These depend upon the sub allotted to the institution



## APPENDIX VIII

(To be stamped and registered on the amount of  
grant in aid)

## MORTGAGE DEED

This mortgage made the-----day of-----  
between the-----a Society registered under the  
Societies Registration Act/A Co registered under the Indian  
Companies Act, having its head office at----- (hereinafter  
called "the Mortgager" which expression shall include its liqui-  
daters, officials receivers and assignees) of the one part and the  
Governor of the State of Rajasthan (hereinafter called "the  
Government" of the other part )

Whereas the mortgager owns, runs and maintains an edu-  
cational institution know as-----at-----

And whereas the mortgager has applied to the Government  
for grant in aid amounting to Rs, -----for the purpose of  
-----and whereas, the Government is satisfied that  
according to the rules relating to such matters for the time being  
in force a grant in aid for the purpose for which the mortgager  
has so applied any property be given and Government has accor-  
dingly, on the recommendations of the Director of Education,  
sanctioned and paid grant of Rs -----to the  
mortgager

And whereas the property described in the schedule hereto  
annexed and more particularly delineated and marked on the plan  
hereto attached (hereinafter called "the said property") is owned  
by the Mortgager,

And whereas the mortgager has agreed to mortgage in the  
manner hereinafter appearing the said property/order to ensure  
that the grant in aid shall at no time be utilised otherwise than  
for the purpose for which it has been given —

## WITNESS

In consideration of payment by the Government to the  
mortgager of the sum of Rs -----as grant in aid (the  
receipt whereof the mortgager hereby admits) for the purpose of  
-----for the benefit of the aforesaid institution,  
mortgager does hereby declares to be free from any incum

trances, by way of simple mortgage to the intent that if at any time hereafter the amount of the grant-in-aid hereby given, or the assets created hereby used for any purpose other than for which it has been given or if the whole or any part of the said property is used for any purpose other than educational purpose or purpose legitimately connected with the maintenance of the aforesaid institution in accordance with the purpose for which the said institution was started, and every such case, there shall be recovered by the Government from the mortgager such sum, not less than the amount of grant thereby given, as shall, as the date when such sum becomes recoverable, be equal to such proportion of the value of the said property assessed in the manner hereinafter provided as the aforesaid amount of grant of Rs ————— bears to the value of the said property on the date of these present, and estimated at Rs ————— and in default of payment of such sum, the Government shall have the power without the intervention of any court to sell or concur with any person in selling the said property or any part thereof either together or in lots and either by public auction or private contract and subject to such conditions respecting title or evidence for title other matters on the Government may think fit with power to vary any contract for sale and to buy it at any occasion or to rescind any contract for sale and to resell without being liable to any loss occasioned thereby

Provided always that for the purposes of determining of the sum which may be recoverable by the Government by virtue of the security hereby created the value of the said property at the time when the Government seeks to enforce the security hereby created shall be assessed by the Government or by such person as may be appointed by the Government in this behalf and such assessment shall be binding on the mortgager

#### Schedule Above Referred to

Description of the said property —

North

South

East

West

In witness whereof the parties hereto have appended signature hereto in the manner and on the said indicated

	for the mortgager --
Signature	Signature
Date	Date
Designation	Authorised by article No of the articles of association by the resolution No date (seal in case the mortgager is a company)
Witness (1)	(1)
(2)	(2)

## APPENDIX IX

## Schedule of Fees

Rates of tuition fee to be charged in different kind of Institution in Rajasthan will follow Other fees will be charged as in Government Institutions

## APPENDIX X

The following recommendations of the sub-committee for suggesting criteria to categories educational institutions as special were approved after some modifications —

- 1 An institution will be considered as Special if it is carrying on some new educational experiments in teaching and maintained a record of the same
- 2 Registers improvement in methodology of teaching various subjects by experimenting on the devices, techniques and variation with child as a centre of education This should be reflected in the teachers diaries and student work and a written record of experimentation should be maintained by the Head of the institution from year to year with reasons for its success and failure This may not be insisted in case of colleges
- 3 Maintains cumulative comprehensive records of pupils work in all round education of the child during the period of the schooling
- 4 Relates education in the institution to community life and bears a hand in the community development

work in the areas A record of activities should be maintained.

- 5 Gives training in Crafts, producing saleable articles of proper finish and beauty and keeps accounts and necessary record
- 6 Has a co-ordinated programme of Home work with tutorial work in the institution
- 7 Has a proper scheme of regular curricular activities, follow up work
- 8 Has regular arrangement for physical education and medical inspection with its effective follow-up Records should be maintained
- 9 Has arrangements for mid day meal or tiffin
- 10 Has atleast 200 days of work with 5 hours of actual teaching including crafts, home science etc
- 11 Has a pupils' Government for training in democratic way of living

#### Finance

An Institution to be categorised as Special should have adequate teaching equipment, building, library, laboratory, work shop, playing field and other apparatus and appliances and has run efficiently for a period of 3 years This material should be necessary for the status and purpose of a particular institution

#### Administration

The Management provides security of tenure to teachers according to Education Code under an agreement with the teachers as approved by the Department

Minimum salaries are according to the Government scales at least 50% of the staff is trained in the institution as a whole

#### Teaching results in public examination

The institution shows above 75% results on 5 years average consisting of not less than 100 pupils in the public examination in High and Higher Secondary Schools separately as well as in internal examinations and 80% in Intermediate Examinations

Qualitatively the results should be satisfactory In Middle Schools the minimum percentage should be 80 on the enrolment of 75 pupils in Classes VI, VII and VIII

These institutions fulfilling the conditions mentioned above may be given grant in aid up to 90% of the net approved expenditure or 60% of the approved expenditure which is greater

### Special types of Institutions

The institutions doing original creative work in accepted by the grant in aid committee and the Department in the fields of -

- (a) Literature
- (b) Arts
- (c) Crafts
- (d) Cultural activities e g Music, Dance and Drama
- (e) Social Education
- (f) Women Education

may be considered special type of institutions on the recommendation of the department

Institutions engaged in pioneering literature work in regard to the production of original or research or approved literature for adult and children suiting the needs of age group may also be considered special types of institutions

Institutions imparting higher education in Humanities Science Commerce, Fine Arts and other technical courses may be given grant in aid from 80 to 90% of net approved expenditure and 60% of approved expenditure Institutions organising educational camps, tours may also be considered A sub-committee consisting of the following was appointed to apply the above recommendations various to the institutions and submit its report by 15th August, 1959 -

1 Shri K L Boardia, Director of Rural Institute, Udaipur

Convener

2 Shri J D Vaish, Dy Director of Education, Udaipur

Member

- |   |   |    |
|---|---|----|
| 3 | Miss Menon, Principal, Rajasthan<br>Mahila Vidyalaya, Udaipur | do |
| 4 | Shri P L Shrivastava, Principal, Training<br>College, Udaipur | do |
| 5 | Shri D P Joshi, Headmaster, Multi<br>purpose, H S S Chittor   | do |

An institution adjudged as Special for the purpose of grant in aid may be demoted from this category if the special features are not efficiently kept up or the institution shows signs of deterioration. The Inspector of Schools concerned will in that case, serve a caution to the institution and an officer of the rank not less than a Deputy Director of Education will inspect the institute on again after a period of 3 months but not later than 6 months and make final report on the working of the institution for the assessment of aid.



# अनुदान-नियम 1963 में महत्वपूर्ण संशोधन एवं आदेश

345  
विविध

[ 1 ]

## अधिसूचना

[क्रमांक एक 2(24) शि प्र 6/62 दिनांक 8 4 68]

राज्यपाल महोदय ने शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक 2 (24) शि प्र/6/62 दिनांक 19-1 63 द्वारा जारी किये गये अनुदान नियमों में निम्न लिखित संशोधन दिनांक 18-10 64 से करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है --

नियम 2 (b) के अंत में निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जावेँ--'निदेशक शिक्षा में अथवा निदेशक/संयुक्त निदेशक शामिल है'

उपरोक्त नियमों में जहाँ कहीं भी डाईरेक्टर ऑफ प्राईमरी एण्ड सैकण्डरी एज्युकेशन लिखा गया है, वहाँ उसके आगे अथवा निदेशक/प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा/संयुक्त निदेशक पढ़ा जावेँ।

[ 2 ]

### (A) Appendix VI—Item No 5

Under col 5 against "Water & Light charges" substitute  
Rs 1000/- instead of Rs 500

New entry inserted—

For night colleges Rs 1000/-

Amended vide No F 1 (126) Edu/cell VI/68 dated 26 10 68  
& was cancelled vide No F 1 (26) Edu/cell VI/68 dt  
4-8 69

vide No F 1 (26) Edu /cell VI /68 dt 5 8 1969

❖❖(B) After Rule 6 there shall be a Rule 6 (1)—

Rule 6 (1) All the items referred to in rule 6 from (a) to (x) will form component A of the admissible items of expenditure

Item 6 (d) be eliminated and items (e) to (y) in Rule 6 be numbered from (d) to (r) respectively

The expenditure incurred on D A will form component B The grant for D A should be computed on the basis of the D A rates prevailing in the year in which the grant is being released For example, if the total of admissible items forming component 'A' of particular institution on the basis of actuals of the previous year excluding dearness allowance is Rs 1 00 lakh then to this should be added the element of dearness allowance in component 'B' which will be the estimated dearness payable in the year in which grant is being released on the rates of dearness allowance prevailing in that year Supposing component of dearness allowance is Rs 20,000 at the rates prevailing in the year grant is being released, the total grant then shall be determined treating the total of admissible items of expenditure as Rs 1,20 lakhs This will take effect from 1st April 1967

❖❖(C) Rule 5 (d) Amendments

(1) The following may be added to rule 5 (d) after the words 'Local Bodies'

"as also the income from interest on reserve funds or rent of property"

(ii) Item (i) & (ii) appearing under rule 5 (d) may be substituted by following —

(1) the income which accrues occasionally in the form of donations etc

❖❖No F 2(194) Edu/Cell/VI/66 dated 23 3 1968

❖❖Vide No F 7 (10) (Gr V)/74 dated 19 7 1974 and operation of above amendment stayed till further orders vide No F 1 (6) Edu/C/6/70 dt 5 3 75

## कार्यालय आदेश

महालेखाकार राजस्थान, जयपुर के सुझावानुसार आवश्यक एवं अनुदान स्वीकृतियाँ जिस नाम से प्रसारित की जावे। अतः जो स्वीकृतियाँ समितियों के नाम से जारी की जाती रही है वे अब संस्था के नाम से की जावेगी।

[प्रभाव ईडीबी/एड/एफ/16007/69/72/73 दिनांक 5.1.72]

## [ 4 ]

विषय — सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लिपिकों के पदों का नियमों में प्रावधान।

प्रसंग — आरका पत्र क्रमांक ईडीबी/एड/एफ/16287/68-69/70-71।  
28-6-72।

महोदय

निदेशानुसार लेख है कि जिन 83 सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक कनिष्ठ लिपिक शिक्षा विभाग के अनुदान नियम लागू होने के पक्ष में चले आ रहे हैं एवं जिन पर शिक्षा विभाग अनुदान स्वीकार भी करता आ रहा है दिनांक 30 जून 1973 तक नियमित करने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति की जाती है इस अवधि के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में स्वीकृति नहीं जा सकेगा एवं अनुदान नियमानुसार ही दिया जावेगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जो कि उनके अन्तर्गत विभाग संख्या 37/वित्त/व्यय 1/73 द्वारा प्राप्त की गयी है जारी की जाती है।

[क्रमांक एफ 11 (22) शिक्षा 4/72 दिनांक 19 फरवरी 1973]

## [ 5 ]

## परिपत्र

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 11 (14) शिक्षा/प्र.प-2 73 दिनांक 1.12.73 के अनुसार राजकीय विद्यालयों में कार्य करने वाले पराजपत्रित मन्त्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को माह के द्वितीय शनिवार के अवकाश स्थान पर प्रत्येक माह में एक दिवस के क्षतिपूर्ति अवकाश का परिलाभ देय है अतः राज्य सरकार के इन आदेशों के अनुसार ही सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत मन्त्रालयिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी माह के द्वितीय शनिवार के

अवकाश के स्थान पर प्रत्येक माह में एक दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश का परित्याग देय होगा ।

[क्रमांक -शिविरा/अनु/ए/16011/75/76 दिनांक 26 7-76] ।

## [ 6 ]

विषय —अनुदान प्राप्त सस्थाओं के कमचारियों को सरेन्डर अवकाश का लाभ देने बाबत ।

उक्त विषय में राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय साधनों की कमी के कारण अनुदान प्राप्त सस्थाओं के कमचारियों को सरेन्डर अवकाश का लाभ देना सम्भव नहीं है ।

कृपया आपके अधीनस्थ समस्त अनुदान प्राप्त सस्थाओं को तदनुसार सूचित करें ।

[क्रमांक शिविरा/अनु/डी/17907/38/76 दिनांक 27-3 76]

## [ 7 ]

Sub —Transfer of Employees from one aided institution to another run by one parent body

Refer to your letter No Shivira/Anu/A/160 11/2/74 75 dated 29-4 74

The question has been examined by Government and it has been decided that if one parent body is running more than one institutions it may transfer employees from one institution to another subject to the following conditions —

- 1 The service conditions pay scale etc of the Persons transferred from one institution to other is the same
- 2 Both institutions where transfer is being made are aided upto the same percentage If it is not so transfer will be allowed subject to the condition that by doing so there is no increase in the actual grant in aid payable to the institutions

[No EDB/AID/160 11/74 Dated 16 8 74 ]

[No F 7 (33) Edu/Gr V/75 dated 25th Feb 1976]

Sub —Appointment of Sisters Staff for institutions management of the Director General of Diocesan Corporation Ajmer

In continuation of this Department letter of even dated 9 7 1975, addressed to the President, Society of M Sister of Ajmer and copy endorsed to you I am direct convey approval of the Government to grant the following ties to the Director General of Ajmer Diocesan Corpor Ajmer in respect of appointment of Sisters Staff of the national institutions in Rajasthan —

- 1 Such sister staff who may be working on an need not be sponsored by the Employment Excl and an exemption is granted to new recruits staff from among the sisters to be appointed institutions run by Ajmer Diocesan Corpor Ajmer provided they fulfil the minimum and qualifications prescribed for the posts
- 2 The appointment of duly qualified sisters staff by the Director General and the Governing B the Societies from the panel of Sisters, may be ted and confirmed by the Education Depa provided that they so appointed are duly select the selection committees of the institutions com as per Grant in aid rules, on which State Govern nominees should be represented
- 3 Permission may be also accorded for transfer of sisters staff from one mission institution to another within the State In such cases, the salary incumbent should be protected
- 4 Permission may also be accorded to accept on fer such sisters staff from the Mission Instit out side Rajasthan to this State and vice versa such cases also their salary will be protected

This issues with the concurrence of Labour and Employment Department I D No 580/STP/76 dated 12/25-2-76

[No EDB/AID/B/Pra/Ayojana/16809/54/72-73  
26-4-76]

[ 9 ]

I am directed to convey sanction of the Governor to the following —

(1) That the institutions imparting education to girls and whose total annual expenditure is Rs 75,000/ as against 1 lakh provided in the grant in aid rules be allowed recurring grant in aid on central office with effect from 1st, April 1966

(2) That recurring grant in aid on the salaries of political sufferers, who happen to work in the Aided Institutions as Secretary and in capacities other than teaching staff may be allowed till they are physically fit, that is no age limit be prescribed for these persons This will take effect from 1st April, 1966

This issues with the concurrence of the Finance Department No 6320 dated 11 12 1967

[No F 1 (144) Edu/Cell/VI/67 Dt 6th Feb 68]

[ 10 ]

It was decided in the Abu Conference held in June, 74 as follows —

- 1 Payment of Salary to the employee and Teachers working in Aided Institutions should be made by cheques
- 2 Before termination of services of employees of aided Institutions proper show cause notice should be given to them Due notice for termination of service should also be given to them

You may kindly issue necessary instructions to ensure that these decision are implemented with immediate effect

[No F 7 (224) Edu/Gr V/74, Dated 31 3 74]

[ 11 ]

आदेश

राज्य सरकार के यह ध्यान में लाया गया है कि अगर किसी संस्था को सब प्रथम अनुदान सूची पर लिया जाता है तो उस संस्था के कर्मचारियों का वेतन वेतन

श्रेष्ठता का 'न्यूनतम' व्यय राशि का ही मा'य व्यय माना जाता है। जब कि उस सस्था में वह कमचारी गत कुछ वर्षों से कायरत है और उसे उन वर्षों में देय सामयिक वेतन वृद्धियाँ आदि भी सस्था द्वारा स्वीकृत की जा चुकी होती है।

जैसे किसी सस्था को 1-7-76 से राज्य सरकार ने अनुदान सूची पर लि है और उस सस्था में कायरत कोई कमचारी पाँच साल से कायरत है और 17 को उसका वेतन 200 रु० है तो उसका वेतन वेतन श्रेष्ठता का 'न्यूनतम' रु० 161 मा'य व्यय मानकर उस पर देय प्रतिशत के अनुसार अनुदान दिया जाता है। प्रकार अनुदान देने की प्रक्रिया गलत है।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने निम्नलिखित किया है कि सब प्रथम अनुदान पर जो सस्थायें ली जाती हैं उनके कमचारियों का वेतन कमचारी की प्रथम नियति की 'न्यूनतम वेतन' मानकर उस पर देय सामयिक वेतन वृद्धियों का सम्मान करते हुए यदि सस्था वेतन का भुगतान करती है तो उसे मा'य व्यय मानकर अनुदान स्वीकृत किया जावे।

[अमाक एफ 24 (53) शिक्षा-5 76 दिनांक 2-7 76]

## [ 12 ]

विषय — अनुदान प्राप्त सस्थाओं में कायरत कमचारियों की संशोधित तबीयतान 1976 के नियम 12 के अन्तर्गत अग्रिम वेतन वृद्धि।

महोदय,

निदेशानुसार आपके पत्र स शिविरा/अनु/सी/16684/अप्रा/53/75 दिनांक 28 6-77 के प्रसंग में लिखा है कि एक ही सस्था में निरन्तर 10 वर्ष या 30 वर्ष की सेवा होने पर ही नियमानुसार वेतन वृद्धियाँ दी जा सका अन्यथा नहीं।

[अमाक प 24 (73) शिक्षा 6/77 दिनांक 24 अगस्त 1977]

[ 13 ]

राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग

# निजी शिक्षण सस्था मान्यता प्रार्थना पत्र

## 1 सस्था सम्बन्धी विवरण

नाम	प्रकार	स्तर	सस्था कब से चल रही है (तिथि)	सस्था के व्यवस्थापक का नाम पता प्रबन्धक समिति का विधान धोर यदि हो तो सदस्यों के नाम

## 2 सस्था द्वारा शिक्षा सम्बन्धी उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति से सम्बन्धी विवरण

व्यवस्थापक का वक्तव्य	निरीक्षक का अभिमत

## विवरण (अ) सस्था का विशेष उद्देश्य

व्यवस्थापक का वक्तव्य	निरीक्षक का अभिमत



## विवरण (आ)

सम्बन्धित स्थान पर सस्या की आवश्यकता एवं उपयोगिता और यदि सस्या नए सिरे से खोली जा रही है तो उसका वर्तमान सस्याभो पर सम्भावित प्रभाव।

व्यवस्थापक का वक्तव्य	निरीक्षक का अभिमत

(2) धनिदाय एवं ऐच्छिक विषय जिनके सम्बन्ध में मायता स्वीकृति प्राप्ति प्राप्त की जा रही है।

व्यवस्थापक का प्रस्ताव	निरीक्षक का अभिमत

## 3 कक्षानुसार छात्र सस्या

कक्षा (वर्ग सहित)	छात्र सस्या	भीतत उपस्थिति	व्यवस्थापक का वक्तव्य	निरीक्षक अभिमत

## 4 सस्या का भवन एवं छात्रावास-भवन विवरण

व्यवस्था का उल्लेख	निरीक्षक का अभिमत
1 कमरा की सस्या लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई	
2 पुस्तकालय एवं वाचनालय का कमरा।	
3 गोदाम।	
4 सम्मेलन गृह।	
5 छात्रावास के कमरों और विद्यार्थियों की सस्या।	
6 पेशाबघर।	
7	

सूचना- इस विवरण के साथ सस्था का उक्त विवरण प्रदशक मानचित्र सम्मिलित होना चाहिए--

**5 फर्नोवर एवं शिक्षा सम्बन्धी सामग्री, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएँ**

व्यवस्थापक का वक्तव्य	निरीक्षक का अभिमत

**6 छात्रों की शारीरिक व्यायाम डाक्टरी परीक्षा, स्वास्थ्य खलकव मनोरजन आदि**

व्यवस्थापक का विवरण	निरीक्षक का अभिमत

**7 अध्यापक सम्बन्धी विवरण**

क्रमांक	अध्यापकों के पूर नाम योग्यता सहित	पद	वेतन तथा ग्रेड	निरीक्षक का अभिमत

**8 यदि शुल्क लिया जाता हो तो मासिक या एक बार देय तथा असहाय छात्रों के शुल्क रहित प्रवेश सम्बन्धी विवरण**

व्यवस्थापक का उल्लेख				निरीक्षक का अभिमत
वक्षा	शिक्षण शुल्क	प्रवेश शुल्क	अन्य शुल्क	
अन्य विवरण				

## 9 सस्या की धारिक परिस्थिति

यदि शुल्क ली जाती हो तो उसकी मासिक धाय	सस्या कीप एवं धाय धाय	कुल मासिक धाय	कुल मासिक धाय	निरीक्षण का धाय
---	--------------------------	------------------	------------------	--------------------

## 10 धाय ज्ञातधाय विषयक प्रश्न

प्रश्न	व्यवस्थापक द्वारा उत्तर	निरीक्षण का धाय
1 क्या सस्या शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का अनुगमन करती है ?		
2 क्या सस्या में समस्त जाति तथा धर्मों वाले छात्रों को शुल्क सुविधा आदि के तथा किसी भी मतभेद के बिना प्रवेश खुला है ?		
3 सस्या के स्टाफ की योग्यता, वेतन श्रृंखला, उप वेतन, पूर्वोपायी कीप अवकाश नियम आदि शिक्षा विभाग की आवश्यकताओं एवं नियमों के अनुसार है ।		
4 शिक्षा विभाग द्वारा प्रमाणित अनुबंध पत्र (Agreement) के अनुसार सस्या के प्रत्येक अध्यापक की नियुक्ति की गई है ?		
5 क्या शैक्षणिक वातावरण में अव्यवस्था पैदा करने वाली किसी सांख्यिक वादविवाद एवं प्रवृत्ति में सस्या के अध्यापकादि भाग लेते हैं ?		
6 क्या धार्मिक एवं जाति विशेषीय शिक्षा में छात्रों को और अध्यापकों का सम्मिलित होना अनिवार्य है ?		

प्रार्थी व्यवस्थापक द्वारा प्रमाणिकरण एवं प्रतिष्ठा —

1 मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस प्राथना पत्र में अंकित विवरण सही है ।

2 मैंने मान्यता-प्रदान सम्बन्धी नियम ध्यानपूर्वक पढ़ लिए हैं।

3 मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि उक्त सस्था को मायता प्राप्त करदी जावगी ता मैं मायता प्रदान सम्बन्धी शर्तों से और तत्सम्बन्धित समस्त वतमान तथा समय से परिवर्तन एवं परिवर्द्धित नियमोपनियमो से भावद्ध रहूंगा और समय 2 पर प्रचलित विभाग के निर्देशो का अनुपालन करता रहूंगा।

तिथि

हस्ताक्षर

व्यवस्थापक

निरीक्षक का आवेदन --

(आवेदन करते समय निरीक्षक को नियमों का सदर्भ अङ्कित करना चाहिए और यह भी लिखना चाहिए कि उक्त सस्था को उसके अभिमतानुसार किस स्तर की एवं किन किन विषयों की मान्यता प्रदान करना किन किन शर्तों पर उचित है।)

तिथि

हस्ताक्षर

निरीक्षक का पद  
केन्द्र

[ 14 ]

राजस्थान शिक्षा विभाग

जिजो शिक्षण सस्था सहायतार्थ-अनुदान हेतु  
प्रार्थना-पत्र

प्रपक

प्रोमान शिक्षा निदेशक,  
राजस्थान, बीकानेर।

मायसर महोदय,

31 मार्च सन 196 का समाप्त होने वाले वर्ष के लिए (सस्था का नाम)

सस्था की सहायता स्वीकृति के सम्बन्ध में धराररर  
सूचना सेवा में प्रेषित करता हूँ।

राजस्थान शिक्षा संहिता का परिशिष्ट (14)

में प्रमाणित करता हूँ कि—

- 1 सलमन सूना प्रणतया साथ है ।
- 2 किसी उल्लेखनीय बात को जानबूझकर छिपाया नहीं गया है ।
- 3 यह सत्या मायता की आवश्यकताओं एवं सहायता के नियमों का पालन करती रही है और करती रहेगी ।
- 4 सत्या के वसुधायार एवं अध्यापकवार समय चक्र विभाग की प्रतिष्ठा प्राप्त अवलोकनाय साथ में सलमन है ।
- 5 मैं अनुमान करता हूँ कि ऊपर बण्ड में उल्लिखित नियमों में से किसी की अवलोकना हान की दशा में राजस्थान सरकार, सहायता बन्द कर सकती है ।

दिनांक

महदीय

हस्ताक्षर

पद

[सूचना—यह प्राधना पत्र शिक्षणसमस्याओं से सम्बन्धित निरीक्षक के पास जिस वष के लिए सहायता चाही गई है उस वष के पहले वाले अक्टूबर मास के अंत तक अवश्य पहुँच जाना चाहिए । परंतु सन् 196-6 की सहायता के लिए प्राधना पत्र शिक्षण समस्याओं से सम्बन्धित निरीक्षक के पास 31 जुलाई 196 तक अवश्य पहुँच जाने चाहिए ।]

### साधारण सूचना

सत्या का नाम	"
सत्या का स्तर	"
सत्या की स्थापना की तिथि	"
'मायता की तिथि	"
इसके वर्तमान स्तर की तिथि	"
सत्या की सहायता कब से मिल रही है	"
सत्या की गत वष कितनी सहायता मिली,	"
सत्या की कार्यकारिणी नियमानुसार सरकार में रजिस्टर्ड है अथवा नहीं ।	"
यदि हो तो रजिस्ट्रेशन नम्बर	"
सत्या का अन्य कोई विशेष वृत्तांत (यदि कोई हो तो)	"

### प्रबंध कारिणी समिति

क्रम सत्या	नाम सदस्य	निर्वाचा की तिथि
सूचना—प्रबंध कारिणी समिति के नये विधान तथा नियमों की प्रति साथ में सलमन हो ।		

लिपिक वर्ग

- 1
- 2
- 3
- 4

योग

लिपिक वर्ग पर मासिक व्यय

भरत वर्ग

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

योग—

भरत वर्ग पर मासिक व्यय

वृद्ध योग मासिक व्यय—

संस्था के गत 31 मार्च तक के वैतनिक कार्यकर्ताओं का विवरण

अध्यापक

क्रमांक	नाम अध्यापक	योग्यता व प्रवस्था	सेवा काल	पाठन कार्य का अनुभव	वेतन तथा प्रो. वेतन	प्रोविडेंट फण्ड	ग्रहणाई	भय पौर्द्ध	भत्ता	विशेष	वृत्तिल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

योग

अध्यापक वर्ग पर कुल मासिक व्यय

## कुल काय विवरण

गत सत्र की सम्प्रा एवं कक्षावार उपस्थिति का विवरण

कक्षा	काय दिवस	घोसत दैनिक छात्र संख्या	निधमी 31 मार्च को रजिस्ट्रार में प्रकृत छात्र सम्प्रा
-------	----------	-------------------------	---

नोट—दैनिक घोसत उपस्थिति के लिए सत्र के कुल काय दिवसों का कुल उपस्थिति की सम्प्रा में भाग देना चाहिए।

## गत तीन वर्षों के कक्षावार परीक्षाफल

गुप्त तानि दयानि कक्षा								
कक्षा	वर्ष 19		कक्षा	वर्ष 19		कक्षा	वर्ष 19	
छात्र संख्या	प्रविष्ट उत्तीर्ण	प्रतिशत परीक्षाफल	छात्रा संख्या	प्रविष्ट उत्तीर्ण	प्रतिशत परीक्षाफल	छात्र संख्या	प्रविष्ट उत्तीर्ण	प्रतिशत परीक्षाफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## आय धन्य का विवरण

आय

सम्प्रा का स्थाई कोष जो गत 31 मार्च को था इस स्थाई कोष का घन किस प्रकार लगा रखा है उसका संक्षिप्त विवरण

आय के मद	गत वर्ष की आय	चालू वर्ष की अनुमानित आय	आगामी वर्ष की अनुमानित आय
----------	---------------	--------------------------	---------------------------

- 1 पाठन शुल्क
- 2 दण्ड
- 3 प्रवेश शुल्क

# अनुदान नियम

अध्याय (2)/111

14	15	4 छात्र प्रत्यावर्तन शुल्क	योग
16	17	5 मासिक चयना भयवा स्याई चन्दा	
18	19	6 स्याई सस्यामो से प्राप्त धन	
20	21	7 सरकारी सहायता	
22	23	8 स्याई कोष के व्याज आदि से प्राप्त धन	
24	25	9 धन किसी प्रकार से प्राप्त धन	
26	27		
28	29		
30	31		
32	33		
34	35		
36	37		
38	39		
40	41		
42	43		
44	45		
46	47		
48	49		
50	51		
52	53		
54	55		
56	57		
58	59		
60	61		
62	63		
64	65		
66	67		
68	69		
70	71		
72	73		
74	75		
76	77		
78	79		
80	81		
82	83		
84	85		
86	87		
88	89		
90	91		
92	93		
94	95		
96	97		
98	99		
100	101		

प्रबंधक भयवा भन्नी के हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर

व्यय

भाय की मदें

गत वष की सही भाय  
 चालू वष की अनुमानित व्यय  
 भागामी व की अनुमानित भाय

- 1 अध्यापक वग का वेतन, प्रोविडेण्ड फण्ड के लिए देने योग्य धन
- 2 लिपिक वग का वेतन एवं प्रोविडेण्ड फण्ड के लिए देने योग्य धन
- 3 महगाई
- 4 स्टेशनरी व छपाई का व्यय
- 5 पानी तथा प्रकाश का व्यय
- 6 पाठन सामग्री को ठीक रखने के लिए व्यय
- 7 सस्या के भवन तथा फर्नीचर की माधारण मरम्मत का व्यय
- 8 मकान किराया, यदि सस्या किराये मकान में हो



- 9 पुस्तकालय, पुस्तकें तथा वाचनालय का मरम्मत व्यय
- 10 जो शिक्षणालय एक से अधिक सम्भा बला रहा है वहा पर उस सस्या का सचालन सम्बन्धी आवश्यकीय व्यय
- 11 अन्य व्यय

योग

बृहद योग

तिथि

हस्ताक्षर यन्त्री तथा प्रबन्धक

हस्ताक्षर प्रधानाचार्य

## राजस्थान सरकार

## शिक्षा विभाग

सस्या को सहायता देने के सम्बन्ध मे अधिकारी वग का अभिमत ।

- 1 सस्या को सहायता प्राप्ति के लिए उपयुक्तता  
(सहायता सम्बन्धी नियमो मे से चौथा नियम)
- 2 प्रबन्धक द्वारा प्राप्त हुई सूचना की सत्यता ।
- 3 अन्य कोई विशेष घृतात ।
- 4 अभिसया

अभिसयक के हस्ताक्षर तथा  
स० सहायता के लिए

सन् 196 तक के लिए

सदस्या का स्वीकृत किये गये  
स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी के  
हस्ताक्षर एवं पद

अध्याय-७

## फीस संबंधी आदेश/परिपत्र

[ 1 ]

[No F 2(41)Edu/C VI/66, Dated the 30 December, 1966]

Subject -Representation of aided institutions against Govt  
Order No 2(41) Edu/C-VI/66, dated 25-3 66

Ref -Your letter No EDB/Aid/A/11007/113/65, dated  
20th August, 66

Sir

I am directed to convey the sanction of the Governor to allow the aided Educational Institutions to spend on educational item of recurring and non recurring nature to be so recognised by the Director of Education upto the 50% of the income from fees charged by them over and above the rates prevalent in Government Institutions of similar category the remaining 50% being so only calculated for limiting grant in aid plus income up to 100% of the approved Expenditure

The expenditure so recognised as "Educational" will not automatically be treated as an approved expenditure in subsequent years

The above decision will take effect from the year, 1965 66

This issues with the concurrence of the Finance Department vide their ID No 6667, dated 24-12-1966

[ 2 ]

कार्यालय अपर निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर  
परिपत्र

अनुदान प्रायना पत्रों की इस कार्यालय द्वारा जांच से पता चलता है कि काफी अनुदान प्राप्त सस्याएँ पाठन तथा अन्य शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से कम वसूल करती हैं और वसूल की गई राशि का पूरा रूप से हिसाब में नहीं दर्शाती हैं। जो इस विषय पर अनुदान नियम 3 (12) एवं कार्यालय के भिन्न 2 परिपत्रों की भवहेतना है —

पत्राक इडोबी बीयूडी डी	15382	107 58	दिनांक 7 10 58)
पत्राक इडोबी बीयूडी डी	15382	110 58	दिनांक 10 10 58)
पत्राक इडोबी एमोए सी	14186	(4) 59	दिनांक 17 1 59)

2 अतः पुन स्पष्ट किया जाता है कि सभी प्रकार की शुल्क इम कार्यालय क पत्राक इडोबी एफ बी 2 14188 57 62 दिनांक 16 10 62 म दो गई दरो व बाद मे समय समय पर जारी किये गए शुद्ध पत्रो से कम वसूल न की जाय तथा वसूली का छात्रानुसार माग व वसूली रजिस्टर (Demand and Realisation Register) रखा जाय। यदि कोई सस्था इन भादशा में वर्णित फीम वा उसकी सीमा से अधिक बिना इस कार्यालय की स्वीकृति से वसूल करती है तो वह राशि राज्य सरकार के भादश क्रमांक एफ 2 (41) शिशा प्रकोष्ठ 66 दिनांक 25-3 1966 के अन्तर्गत धाय मानी जायेगी।

3 फीस सम्बन्धी अय स्पष्टीकरण इम प्रकार हैं —

- (क) क्या पाठशालामो के पाठन शुल्क को छोडकर अय फीसें बालकों के विद्यालयों क अनुसार वसूल होनी चाहिये।
- (ख) शिक्षक प्रशिक्षण महा विद्यालय, बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय तथा मा टेसरी स्कूलो क लिए भी शुल्का का निर्धारण हो चुका है। अत वे भी उन दरो के कम दरो पर शुल्क वसूल न करें।
- (ग) जिन सस्थाओ की अय सस्था के रूप म अनुदान प्राप्त होता है वे जिस स्तर के लिए छात्र तैयार करने हैं या अनुदान के लिए स्थापन व अय व्यय हेतु मांग पेश करते हैं ऐसे ही स्तर की सस्था के लिए निर्धारित दरो स कम दर पर फीस वसूल नहीं करें।
- (घ) जिन सस्थाओ का स्तर निर्धारित नहीं हुआ है या जिनके स्तर की सस्था के लिए राज्य सरकार ने फीस निर्धारित नहीं की है वे सस्थाएं फीस वसूली के अपन प्रस्ताव शीघ्र भेजकर निणय प्राप्त कर लें।
- (ङ) सत्र 64 65 मे वसूल की गई शुल्क की दरों मे इस कार्यालय की पूव स्वीकृति के बिना कमी नहीं हो सकेगी।
- (च) वसूल करने योग्य फीस यदि वसूल नहीं की जायेगी तो उहे प्रानु मानित धाय मानी जायेगी।

4 सस्थाएं चंद तथा दान से प्राप्न होने वाली राशि का भी हिसाब रतें दान दाता के नाम, मय वस्तिगत व पूरे पते के रमोद जारी करें और इसका नियमित हिमाव जाच के समय पेश करना होगा।

5 सस्था का वार्षिक हिसाब चाट्ट एकाउण्टेंट द्वारा जाच कराया जाकर रिपोट में धाय का विवरण अनुदान नियम 5 के नोट 2 में दर्शाई गई मदो के

अनुसार बताया जायेगा पैरा (ए) और (बी) यानी पाठन शुल्क, छात्र प्रव्यावतन शुल्क, प्रवेश व पुनः प्रवेश शुल्क तथा दण्ड को छाड़कर शेष सभी प्रकार की शुल्क का पिछले वर्ष का पोत वाकी भी दिखाया जाकर प्रमाण स्वरूप निम्न समापन नोट के रूप में दिया जाये —

“सरथा की आय का हिसाब मनुदान नियम 5 के नोट 2 के अंतर्गत ठीक है फीस। आय नियमानुसार पूरा वसूल हो चुकी है वर्ये छात्रों से निम्न मदों से वसूल करन गेय हैं। पाठन शुल्क के आकड़े निश्चित प्रतिशत पर पूरा शुल्क व अर्द्ध शुल्क माफी को ध्यान में रखते हुए दर्शाये गये हैं।”

इस पत्र की प्राप्ति रसीद भेजी जाये।

[प्रमाण इडीबी/एड/ए/16004/स्पेशन/65 दिनांक 31-5-1967 ई०]

[ 3 ]

### CIRCULAR

[No EDB/Bud/D/15383/107/58, dated 7th Oct, 1958]

Government aided Educational Institutions in Rajasthan should henceforth (from the session 1957-59) change all kinds of fees at the rates sanctioned by the Government for Government Educational Institutions in those Localities and for the periods prescribed by the Government

If this will not be adhered to the aided institutions will forfeit grant in aid upto the extent they deviate from this office

Director of Education

[ 4 ]

### CIRCULAR

[No EDB, Bud/D/15382/110/58, Dated 10th Oct, 1958]

In continuation of this office circular No EDB/D/15382/107/58, dated the 7th Oct, 58, it is further clarified that if any institution charges higher rates of prescribed fees, than sanctioned by the Government, one at present being charged, these should not be reduced without obtaining prior approval of this office

Director of Education  
Raj Bikaner

[ 6 ]

## CIRCULAR

No EDB/Aca/(C)/14186 (4) (59) Dated 17.1.59

In continuation of this Directorate circular No EDB/Bud/D/15382/107/58 dated 7th Oct, 1958 and No EDB/D/15382/110/58 dated 10th Oct, 1958, regarding fees in Aided and Recognised institutions, it is once again enjoined upon all the Dy Directors of Education, Inspector of Schools, Deputy Inspectors of Schools I/c District and the Assistant Director of Education (women), that every recognised and aided institutions should at least charge the minimum fees as per schedule of the Department from class IX and upwards and that no institution should be allowed to decrease the rates of fees they are charging now in any of the classes from I to XII without the prior permission of the Department.

It may be added that in Government institutions no tuition fees are charged in classes from I to VIII, but fees other than tuition fees are charged as per schedule in the Education Codes. It is enjoined upon all the aided institutions that they should not reduce fees below these rates from the students in their institutions and all the income derived as such should be properly accounted for in their accounts.

Sd/  
Director of Education

[ 6 ]

## Clarification

The Accountant General,  
Rajasthan JAPUR

Subject Grant in aid Rules 1963

Ref Your letter No CAD II GIA/7785 dated 5.1.72

Sir

I am directed to say that under Rule 5 (d) of Grant in aid Rules the words 'income from fees and other recurring sources during the same year' denote the actual income during the year.

This issued in consultation with the finance Department vide their I.D. No 577 dated 15/23.12.72.

[Education (Group-IV) Department, No 1 (6) Edu/c/6/Gr/IV/70, Dated the 24/3/72]

[ 7 ]

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

स्याई आदेश सख्या-12/72

अनुदान नियम 1963 की धारा 5 (डी), धारा 5 के नोट 2 (5) के अन्तर्गत जो शिक्षण सभ्यायें शिक्षण तथा अन्य शुल्क छात्र छात्रागो से वसूल करती हैं, उन्हें यह शुल्क राशि धारा 5 नोट 2(5) के अनुसार अनुदान प्रायना पत्र (भावतक) अन्तर्गत, आय मद में प्रदर्शित करने का प्रावधान है। अनुदान नियम-1963 के रीगिस्टर्ड 111 में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य सभी शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही छात्र छात्रागो से वसूल करने का प्रावधान है। अनुदान नियम 1963 की धारा 3(12) में छात्र छात्रागो से शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम दर वसूल नहीं करने का एवं बिना विभाग के पूव अनुमति प्राप्त अन्य किसी प्रकार की शुल्क न वसूल करने का प्रावधान है।

महालेखाकार राजस्थान, जयपुर तथा विभागीय आडिट पार्टी ने अनुदान प्राप्त शिक्षण सस्थागो के अकेक्षण जाच प्रतिवेदन में यह आक्षेप प्रस्तुत किया है कि अतिपय शिक्षण सस्थायें सरकारी दर से कम और अनेकानेक सरकारी दर से अधिक दर पर शिक्षण व अन्य शुल्क वसूल करती हैं तथा शिक्षण तथा अन्य शुल्क हेतु विभागीय स्याई आदेश 2/68 एवं उपरोक्त अनुदान नियमों के प्रावधान की पूरण अनुपालना नहीं की जा रही है। शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य शुल्क को सरकारी दर से अधिक दर पर बिना विभागीय पूर्वानुमति के छात्र छात्रागो से वसूल किया जाना अनियमित है और इस शुल्क द्वारा प्राप्त धन राशि का अनुदान प्रायना पत्र (भावतक) में आय मद में प्रदर्शित न करना विभाग को गलत सूचना माना जा सकता है एवं विभाग के नोटिस में ऐसे मामले लाये जाने पर इस प्रकार वसूल की गई राशि को अनुदान हेतु स्वीकृत व्यय मानकर अधिव भुगतान की गई राशि को वसूल की जा सकती है।

इस आदेश द्वारा समस्त अनुदान प्राप्त शिक्षण सस्थागो को आदेश दिया जाता है कि अनुदान नियम 1963 के शुल्क सम्बन्धी प्रावधानों एवं इस सम्बन्ध में प्रसारित विभागीय आदेशों की पूरण अनुपालना की जावे। इन प्रावधानों व आदेशों का उल्लंघन या अवहेलना करने पर ऐसी शिक्षण सस्थागो के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने अथवा अनुदान बन्द करने को विभाग बाध्य होगा। जो सस्थायें सरकारी दर से अधिक दर पर शिक्षण व अन्य शुल्क विगत वर्षों में बिना विभागीय अनुमति व स्वीकृति प्राप्त किये छात्र छात्रागो से वसूल करती रही हैं, वह अब अनुमति या स्वीकृति प्राप्त करें।

प्रायः यह भी देखा गया है कि अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाएँ छात्र छात्रों से सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य प्रकार के शुल्क भी वसूल कर रही हैं। सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क की बिना सरकार की स्वीकृति के वसूली अनियमितता है और इस प्रकार की प्रवृत्ति अविलम्ब समाप्त किया जावे।

विभाग के सम्मुख यह समस्या भी आई गई है कि कुछ संस्थाएँ बस सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर से ही वसूल नहीं करती बरन जो छात्र छात्रों वस का उपयोग नहीं करती है उनसे भी पिवनिव या सिनेमाशो देख जाने की सुविधा हेतु मासिक बस फीस वसूल की जाती रही है यहां तक का प्रोप प्रवकाश प्रवधि को भी बस फीस ली जाती रही है। बस की सुविधा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थाओं को आदेश दिया जाता है कि वे बस फीस नियमानुसार सरकारी दर से ही छात्र छात्रों से वसूल करें, ड्राईवर का वतन बस में टेनेन्स खर्चा, डिप्रीसियेशन राशि के व्यय से अधिक राशि को संस्था की आय में म प्रवि किया जावे जिससे कि अनुदान स्वीकृत करते समय इस राशि का नियमानुसार अनुदान हेतु समायोजित किया जा सके।

प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी इसकी जाँच अनुदान प्रायना पत्र (माइतक) जाँच करते समय अवश्य कर दें एवं ऐसे मामले आवश्यक कायवाही हेतु अनुदान प्रायना पत्र के साथ अपनी टिप्पणों सहित प्रस्तुत करें।

[क्रमांक ई डी बी/एड/ए/16011/85/72 दिनांक 11-12-72]

[ ८ ]

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीरानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के परिपत्र संख्या ईडोबी/एड/बी/15382/107/58 दिनांक 7-10-58, ईडोबी/एड/बी/17382/110/58 दिनांक 10-10-58 तथा ईडोबी/एके/सी/14186/(4)/59 दिनांक 17-1-59 के द्वारा समस्त अनुदान प्राप्त संस्थाओं के प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारियों को निर्देश प्रसारित किए गये थे कि अनुदान प्राप्त संस्थाओं में पाठन तथा अन्य शुल्क राजकीय शालाओं के लिए निर्धारित दरों पर ही छात्रों से वसूल किया जावे।

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कुछ अनुदान प्राप्त संस्थाएँ निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूल करती हैं जो नियमानुसार नहीं है।

प्रत्येक समस्त प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारियों (अनुदान प्राप्त सस्थाओं के) को पुनर्निर्देश दिया जाता है कि वे यह देखें कि अनुदान प्राप्त सस्थाओं में प्रत्येक प्रकार के शुल्क इस कार्यालय के पत्रांक ईडीवी/एड/वी-2/57/62 दिनांक 6-10-62 व इस सम्बन्ध में बाद में समय समय पर प्रसारित आदेशों। शुद्धिपत्रों। दी गई दरों से अधिक शुल्क वसूल न करें, यदि कोई सस्था उक्त दरों से अधिक शुल्क वसूल करती है तो ऐसे वसूल किया गया शुल्क सस्था की आय मानकर सस्था में तदनुसार अनुदान दिया जावेगा। इसी प्रकार वसूल करने योग्य शुल्क यदि सस्था द्वारा वसूल नहीं किया जाता है। तो वह भी सस्था की अनुमानित आय माना जावेगा और तदनुसार ही सस्था को अनुदान स्वीकृति होगा। प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारियों का यह दायित्व है कि यह देखें कि निर्देशों का पालन सही ढंग से हो रहा है। उक्त निर्देशों से सस्थाओं को भी अवगत करा दिया जावे।

[क्रमांक-शिविरा/अनु/डी/16022/125/दि 3-9-75]

## [ ९ ]

कार्यालय निर्देशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीनानेर।

### परिपत्र

इस विभाग के समस्त सरयक आदेश दिनांक 3-9-75 के द्वारा निर्देश दिये जा चुके हैं कि यदि कोई सस्था इस विभाग द्वारा समय समय पर प्रसारित किये गये आदेशों में दी गई दरों से अधिक दरों पर पाठन तथा अन्य शुल्क वसूल करती है तो ऐसे वसूल किया गया शुल्क सस्था की आय माना जावेगा तथा तदनुसार अनुदान दिया जावेगा। उक्त आदेश में ध्यायित्व से शोधन करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई सस्था इस विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई दरों से अधिक दरों पर पाठन तथा अन्य शुल्क वसूल करती है तो इस प्रकार से प्राप्त होने वाली राशि में सिर्फ निर्धारित दर के हिसाब से बनने वाली राशि को ही सस्था की आय माना जावेगा अर्थात् निर्धारित दर से बनने वाली राशि से अधिक प्राप्त हुई राशि को सस्था की आय में शामिल नहीं किया जावेगा।

पूव प्रसारित आदेश दिनांक 3-9-75 के अनुसार यदि कोई सस्था निर्धारित दर से कम दर पर शुल्क वसूल करती है तो अनुदान हेतु निर्धारित दर के हिसाब से बनने वाली शुल्क की राशि को ही सस्था की आय माना जावेगा चाहे सस्था ने उक्त उक्त राशि शुल्क के रूप में वसूल न की हो।

[क्रमांक-शिविरा/अनु/डी/16022/125/71-72, दि 16/21-11-75]





भारत सरकार से पुरस्कृत—  
 अनुशासन सम्बन्धी जाच के लिये—  
 सर्वश्रेष्ठ कानूनी पुस्तक  
**अनुशासनिक कार्यवाही**

लेखक • दत्त

प्राधक्यन न्याय मूर्ति श्री कानसिंह

1979 संस्करण ]

[ मूल

आपके विद्यालय के लिये

- ☐ पुस्तकालय के लिये पुस्तकें
- ☐ शिक्षण सामग्री
- ☐ कानूनी व नियमों की पुस्तकों के लिये

सम्पर्क कीजिये—

फोन नं०



श. द. हीरा बिल्डिंग (सहमी पेट्रोल पम्प के पास)

एम० आई० रोड जयपुर-302001

संगीत विषय पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित द्वितीय वेतन श्रृंखला के समतुल्य माना गया है।" इसी प्रनुच्छेद के अन्त में निम्नांकित पंक्तियाँ जोड़ी जाय —

"भविष्य में जो व्यक्ति मेट्रीकुलेट है तथा उन्नोक्त सस्थाओं में किसी सस्था का संगीत प्रमाण पत्र भी रखता है तो उसे भी प्रशिक्षित द्वितीय वेतन श्रृंखला दी जावगी।

प्रनुच्छेद 3 का शीपक निम्न प्रकार पढ़ा जाय—

"निम्नांकित सस्थाओं से जो व्यक्ति संगीत का प्रमाण पत्र रखते हैं उनको संगीत विषय पढ़ाने के लिये वरिष्ठ अध्यापक के समतुल्य माना गया है।"

इसी प्रनुच्छेद के उप प्रनुच्छेद 7 को रद्द किया गया है। किंतु प्रनुच्छेद के अन्त में निम्नांकित पंक्तियाँ जोड़ी जाकर पढ़ा जायें —

राज्य सरकार की विभागीय परीक्षाओं को निम्नानुसार मान्यता दी गई है।

संगीत भूषण — तृतीय वेतन श्रृंखला के लिये प्रशिक्षित बी एस टी सी समकक्ष अगर व्यक्ति हाई स्कूल पास हो।

संगीत प्रमाकर — द्वितीय वेतन श्रृंखला के लिये प्रशिक्षित स्नातक स्तर के समकक्ष अगर व्यक्ति हाई स्कूल पास हो।

संगीत निपुणः—वरिष्ठ अध्यापक के पद के लिये योग्य अगर व्यक्ति हाई स्कूल पास है।

[क्रमांक शिबिरा/प्रनु/एफ/16059/15/74, दिनांक 14-2-74]

[ 7 ]

आदेश

[क्रमांक - 9 (63) साप्र/3/71, दिनांक 30-3-74]

प्रारम्भिक बाल्यावस्था प्रशिक्षण (Early Child Education Diploma) विद्यामदन गोविन्दराम सेक्सरिया टीचर्स कालेज, उदयपुर द्वारा संचालित प्रशिक्षण को राज्य सरकार ने अपने पत्र सं एफ 9 (63) सा/प्रा/3/71 दिनांक 22 जुलाई, 1971 के प्रनुसार शिक्षा विभाग द्वारा संचालित बुनियादी प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्रदान की थी। बुनियादी प्रशिक्षण (बी एस टी सी) दो वर्ष बीम हो जाने में राज्य सरकार ने प्रारम्भिक बाल्यावस्था प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों के लिए यह नियम लिया जाता है -

1. इस सस्था द्वारा सत्र 1970-71 से सत्र 1972-73 तक प्रगत डिप्लोमा का इस सत्र पर मान्यता प्रदान की जाती है कि इन डिप्लोमा प्राप्त पंक्तियों की शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एक वर्षीय पत्राचार पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा और ऐसा करने पर ही उनकी तृतीय श्रेणी प्रशिक्षित

अध्यापक का वेतनमान दिया जाना सम्भव होगा। जिन डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा नवत पत्राचार पाठ्यक्रम उत्तीर्ण नहीं किया जाता है उन्हें केवल अप्रतिष्ठित तृतीय श्रेणी अध्यापक वेतनमान दिया जावेगा। प्रारम्भिक वात्स्यायन्या प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों, जो कि विशेष तौर पर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिये प्रशिक्षित होते हैं, के लिये शिक्षा विभाग द्वारा विशेष पत्राचार पाठ्यक्रम निर्धारित किया जावेगा। जिससे वे प्राथमिक कक्षाओं को भी पढ़ा सकें।

[क्रमक -शिविरा/अनु/ए/एफ/16059/35/74, दिनांक 28-5-74]

### [ 8 ]

**विषय** — हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की विभिन्न व्यायाम परीक्षाओं को मायता प्रदान करने हेतु।

[क्रमक -9 (10) सा प्र/ख/72 दिनांक 20 अप्रैल, 1974]

राज्य सरकार द्वारा श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की निम्नांकित विभिन्न व्यायाम परीक्षाओं का उनके सामने अंकित स्तर तक मायता प्रदान करने का नियुक्त लिया है —

मायता प्रदान दिये जाने वाले  
प्रमाण पत्र/उपाधि का नाम

समकक्ष उपाधि प्रमाण पत्र का नाम

- |   |   |
|---|---|
| 1 शारीरिक शिक्षा सर्टिफिकेट कोस         | 1 राजस्थान सरकार के राजकीय कालेज आफ फिजिकल एज्युकेशन जोधपुर, के सर्टिफिकेट कोस के समकक्ष तृतीय वेतन श्रृंखला में नियुक्ति हेतु।   |
| 2 शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा कोस (अमरावती) | 2 राजस्थान सरकार के राजकीय कालेज आफ फिजिकल एज्युकेशन, जोधपुर के डिप्लोमा कोस के समकक्ष द्वितीय वेतन श्रृंखला में नियुक्ति हेतु।   |
| 3 (1) व्यायाम प्रवेश                    | 3 सन् 1970 तक नियुक्त व्यायाम अध्यापकों की नियुक्ति को नियमन करने हेतु राजस्थान कालेज आफ फिजिकल एज्युकेशन, जोधपुर के सर्टिफिकेट के समकक्ष निम्नलिखित शर्तों के अनुसार — |

(क) व्यायाम प्रवेश, व्यायाम एंड एव व्यायाम विहारद में II कोई एक योग्यता प्राप्त हो और हाई स्कूल उत्तीर्ण नहीं हो तो अप्रतिष्ठित मैट्रिक श्रृंखला में नियुक्ति नियमन करने हेतु।

(व) व्यायाम प्रवेश व्यायाम पटु एवं व्यायाम विचारद म स कोई एक योग्यता प्राप्त हो और मैट्रिक/हार्ड स्कूल उत्तीर्ण हो तो प्रशिक्षित मैट्रिक -टृग्गना ॥ नियुक्ति नियमन करने हेतु ।

(ग) व्यायाम विचारद सहित किसी विधिवत् विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि प्राप्त हो तो प्रशिक्षित स्नातक केनन श्रु खला मे नियुक्ति नियमन करने हतु ।

[क्रमांक -शिविरा/प्रनु/एफ/16059/56/परिपत्र/74/57, दिनांक 19-7-74]

### [ 9 ]

विषय -बोर्ड द्वारा संचालित प्रशिक्षण एवं उपाध्याय सम्बन्धित परीक्षाओं का मायता ।

[क्रमांक एफ 9 (8) सा प्र/11/72 दिनांक 11 जनवरी, 1975]

राज्य सरकार ने हम विभाग के मम सन्ध्या आदेश दिनांक 2 सितम्बर 1974 में संशोधन करके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित निम्न शिक्षा परीक्षाओं को उनके नाम के आगे उल्लेखित परीक्षाओं के समक्ष राजकीय सहायता में नियुक्ति हेतु मायता प्रदान करने का निणय लिया है -

नाम परीक्षा	समकक्ष परीक्षा
1 प्रवेशिका परीक्षा (अंग्रेजी सहित)	संक्रण्डरी स्कूल परीक्षा
2 उपाध्याय (प्रथम खण्ड) परीक्षा अथवा उपाध्याय परीक्षा एवं वर्षीय (अंग्रेजी सहित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर)	हायर मैकेण्डरी परीक्षा
3 उपाध्याय (सम्पूर्ण खण्ड) परीक्षा उपाध्याय द्वितीय वर्षीय परीक्षा (अंग्रेजी सहित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर)	इंटरमीडिएट परीक्षा

### [ 10 ]

#### आदेश

[प 0 (75) सा प्र/ख/71 शिक्षा 5, दिनांक 12 मार्च 1975]

राजस्थान राज्य सरकार ने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित निम्न परीक्षाओं को उनके समक्ष अंकित परीक्षाओं के समकक्ष मायता प्रदान किये जाने का निणय लिया है --

## नाम संस्कृत परीक्षा

## समकक्षता

शास्त्री राजस्थान विश्व विद्यालय की शास्त्री परीक्षा के सम  
मध्यमा परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उपाध्याय परीक्षा/हा  
संस्कृत परीक्षा के समकक्ष ।

## [ 11 ]

## आदेश

[ प 9 (76) सा प्र/ख/71/शिक्षा 5, दिनांक 15/18 मार्च, 75 ]

इस विभाग के आदेश सम संस्कृत दिनांक 12 3 75 के क्रम में राज्  
राज्य सरकार राष्ट्रीय मस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित शिक्षा शास्त्री परीक्षा  
वी एड परीक्षा के समकक्ष केवल संस्कृत विषय में मायता प्रदान करती है ।

## [ 12 ]

## आज्ञा

[ आदेश संख्या प 9 (66) सा/प्र/3/69, जयपुर दिनांक 17 सित  
1973 ]

राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश को प्रशिक्षण प  
एल टी इलाहाबाद को राजस्थान विश्व विद्यालय द्वारा संचालित वी एड के सम  
नियुक्ति-तु मायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ।

## [ 13 ]

विषय — प्राचीन कला केन्द्र, चण्डीगढ़ को संगीत ध्यवा वाद्य में भाष्कर  
तथा संगीत ध्यवा वाद्य में विशारद परीक्षा को मायता प्रदान  
करने के संस्वध में ।

[ एक 9 (13) साप्र/11/72, दिनांक 29 मई, 1975 ]

राज्य सरकार के प्राचीन कला केन्द्र चण्डीगढ़ को संगीत नृत्य विशारद  
(Bachelor of Music) तथा संगीत नृत्य भाष्कर (Master of Music) परीक्षाओं  
को मायता प्राप्त विद्यालयों में संगीत अध्यापक हेतु निम्नानुसार मायता प्रदान करने  
का निर्णय लिया है —

1. मैट्रिक द्वितीय थ्रेणी उत्तीर्ण ध्यवा समकक्ष  
परीक्षा एवं प्राचीन कला केन्द्र चण्डीगढ़ की  
गायन ध्यवा वाद्य में विशारद परीक्षा  
द्वितीय थ्रेणी में ।

सहायक अध्यापक संगीत  
(कक्षा 9 व 10) के अध्या  
पन हेतु)



[ ३ ]

## घोषणा पत्र

क्रमिक  
श्रेणियों

दिनांक

- (1) अपर निदेशक,  
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर ।
- (2) उप निदेशक (महिला ग्रंथवा पुरुष),  
शिक्षा विभाग,
- (3) प्रतिहस्ताक्षरकर्ता,  
विषय — वचन बद्धता (Under Taking)

मैं

आत्मज

वर्तमान निवासी

(नाम सत्या)

का वधानिक मंत्री/व्यवस्थापक/ सभापति के माते  
(जैसा कि व्यवस्थापन समिति के प्रस्ताव स  
द्वारा अधिभूत किया गया), राजस्थान सरकार, के शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत  
राशि प्राप्त करने तथा उससे संबंध सत्या के लेखा जोखा को व्यवस्थित ढंग से  
रखने का संपूर्ण उत्तरदायित्व सेन की लिखित वचन बद्धता देता हूँ तथा मेरे इस  
पद पर कार्यकाल के दौरान यदि कोई ग्रंथ हानि, गबन, दुरुपयोग व अनियमितता  
प्रकट हुई, उसके लिये उपरोक्त सत्या के पदेन अधिकारी के रूप में, जिम्मेदार हूँगा,  
तथा राजस्थान सरकार, अपर निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा व प्रति  
हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी द्वारा समय समय पर प्रसारित नियमों व आदेशों का यथावत  
अनुपालन करने को बाध्य हूँगा ।

हस्ताक्षर,

पद का नाम

दिनांक

सत्या का नाम

[ 4 ]

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

संस्थाई आदेश संख्या 6/62/7/72

राजस्थान सरकार से अनुदान प्राप्त कतिपय संस्थाओं की व्यवस्थापक।  
प्रबंधकारिणी समिति का गठन अनुदान नियम 1963 के परिशिष्ट एक के अनुसार  
विधिवत नहीं होने की सूचना प्राप्त हुई है। ऐसी संस्थाओं में प्रबंधकारिणी समिति  
के विवाद के कारण संस्था संचालन मुभारू रूप से नहीं होने की स्थिति उत्पन्न

होती है। इन कठिनाईयाँ एवं समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए समस्त अनुदान प्राप्त सस्थाओं को आदेश दिया जाता है कि वे नवम्बर 1972 तक विधिवत अनुदान नियम 1963 के परिशिष्ट एब में दिये गये निर्देशनों का पूरा पालन करते हुए सस्था प्रबंधकारिणी समिति का गठन करले तथा प्रबंधकारिणी के विधिवत गठन होने का सत्यापन पंजीयक सस्थायें, राजस्थान, जयपुर द्वारा करवाकर इसकी एक सत्यापित प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्रेषित की जावे। सस्थायें जिनमें प्रबंधकारिणी नियमानुसार गठित हो, इसके सदस्यों की सूची अनुदान विपत्र पर प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का प्रेषित की जावे यदि किसी सस्था ने इस आदेश की अनुपालना में विधिलता की तो उसके विपत्र पर दिसम्बर, 1972 से प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी हस्ताक्षर नहीं करें और ऐसी दशा में अनुदान राशि प्राप्त न होने पर सस्था में उत्पन्न समस्त समस्याओं का दायित्व सस्था अधिकारियों का होगा। अनुदान नियम 1963 के अनुसार गठित समिति का कार्यकाल यदि तीन वर्ष से अधिक हो गया है तो पुनर्निर्वाचन किये जावे।

प्रबंधकारिणी समिति का गठन नियमानुसार हो, इस हेतु प्रत्येक सस्था को आदेश दिया जाता है कि निम्नलिखित अभिलेख रखा जावे तथा प्रतिवर्ष निरीक्षण अधिकारी द्वारा इसकी जांच की जावे —

- (क) आज़म सदस्यों की नामावली।
- (ख) मानद (Honorary) सदस्यों की नामावली। तथा
- (ग) दानगता (Donors) सदस्यों की नामावली।

प्रबंधकारिणी। व्यवस्थापक समिति चुनाव हेतु निम्न प्रणाली का अनुसरण किया जावे।

- (1) एक चुनाव अधिकारी मनोनीत किया जावे।
- (2) चुनाव तिथि के कम से कम एक माह पूर्व चुनाव अधिकारी समस्त चयन मण्डल के सदस्यों को चुनाव हेतु आवश्यक सूचना प्रसारित करेंगे।
- (3) चुनाव सम्बन्धी सूचना प्रसारित की जावे। इसमें चुनाव तिथि, चुनाव स्थल समय का उल्लेख किया जावे।
- (4) चुनाव सम्बन्धित समस्त विवरण चुनाव अधिकारी रखेंगे।
- (5) चुनाव विवरण में प्रस्तावित सदस्यों की एवं चयनित सदस्यों की नामावली तथा उसके द्वारा प्राप्त मत सत्यापन का उल्लेख किया जावे।
- (6) चुनाव शुद्ध मत प्रणाली द्वारा ही सम्पन्न हो। शुद्ध मत प्रणाली के सम्बन्ध के कार्य प्रणाली का चुनाव अधिकारी स्वयं निर्धारण करें।
- (7) चयनित सदस्य चुनाव के एक माह भीतर सहचरण (Co Opted) सदस्यों का चुनाव कर लिया जावे।



(8) चुनाव के तुरंत बाद विभागीय प्रतिनिधि की सदस्यता नियोजन हेतु उचित कार्यवाही की जावे।

(9) प्रबंधकारिणी समिति के गठन हो जान पर व्यवस्थापक सचिव, समापति, कोषाध्यक्ष आदि पदों का चुनाव चयनित एवं मनोनीत सदस्य करेंगे। प्रनिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वह अपने अधीनस्थ समस्त सत्या प्रबंधकारिणी। व्यवस्थापक समिति की सूचना निम्न प्रपत्र में रखें एवं इसकी एक प्रति प्रत्येक वष माह जावरी में निदेशक प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित करें।

[क्रमांक ई डी बी/एड/ए/16007/66/72 73, दिनांक 15 जून, 72]

प्रपत्र

प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय की मुहर  
प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी का पूरा नाम

सत्या का नाम	प्रबंधकारिणी की वार्षिक सदस्यता की मर्यादा	विभागीय नियोजित अधिकारी का नाम
सम्मानने की तिथि	---	---
1	2	3
	4	5

[ 5 ]

कार्यालय निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर  
परिपत्र

विभागीय अधिकारियों द्वारा समय समय पर अनुदान प्राप्त शिक्षण सत्याओं संबंधी अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में इनके द्वारा विभागीय नियमों की अनुपालना न किये जाने की घटना विभाग के सम्मुख लायी जाती रही है यह देखा गया है कि अनुदान प्राप्त सत्याओं की तेरी प्रबंधकारिणी समिति जो दो या दो से अधिक शिक्षण सत्याओं का संचालन करती है और इनमें से सभी या कुछ शिक्षण सत्याओं अनुदान प्राप्त है, एक सत्या हेतु निर्धारित एवं स्वीकृत स्टाफ का रवाना पर दूसरी सत्या में बिना विभागीय अनुमति प्राप्त क्रिय करती रहती है। किसी सत्या का निरीक्षण करते समय यह सूचित किया जाता है कि समुक्त बमबारी का नाम इस सत्या की उत्पत्ति पत्रिका में है परन्तु यह दूसरी सत्या की प्रबंधकारिणी द्वारा गवांतिन दूसरी सत्या में बांध कर रहा है सत्या प्रबंधकारिणी द्वारा इन प्रकार की जाने वाली कार्यवाही अनियमित कार्यवाही है। जिस सत्या विरोध हेतु विभाग द्वारा जो पद स्वीकृत किये गये हैं, उन्हें उसी सत्या विरोध में बांधे करना अनिवार्य

है। यदि वह किसी दूसरी सस्था में प्रतिनियुक्त किया हो तो विभाग को इसकी सूचना प्राप्त होते ही ऐसे स्वीकृत पद को कम कर दिया जावेगा एवं इस पद के वेतन पर अनुदान प्रस्वीकृत कर दिया जावेगा। यह भी देखा गया है कि कुछ अनुदान प्राप्त शिक्षण सस्थाओं में छात्र/छात्रा सस्था में कमी हो जाने के कारण स्टाफ में कमी कर दी गई है परंतु इसकी सूचना विभाग को नहीं दी जाती रही है। ऐसी शिक्षण सस्थाओं की प्रबंधकारिणी, समिति का दायित्व है कि वह ऐसे मामलों की रणनीति विभाग को प्रेषित करें। जो सस्थायें इस नियम का पालन नहीं करती, विभाग के सामने ऐसी अनियमितता को लाये जाने पर, सस्था को दिया जाने वाला अनुदान प्रतिशत में कमी या अनुदान बन्द किया जा सकता है।

कुछ अनुदान प्राप्त सस्थायें प्राइमरी स्तर मिडिल स्तर और माध्यमिक स्तर पर अनुदान सूची में ली गई है परंतु इनके द्वारा क्रमशः मिडिल, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाओं भी चालू की गई है। जिस स्तर हेतु अनुदान नहीं दिया जा रहा है।

उस स्तर हेतु भवन से अध्यापक, लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति कर भवन भवन में ये कक्षाओं संचालित करना आवश्यक है। अनुदान प्राप्त स्तर के अध्यापकों, लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये अलग उपस्थिति पंजिका एवं वेतन भुगतान रजिस्टर, आय व्यय रचना तथा जिस स्तर पर अनुदान प्राप्त हो रहा है उसके लिए अलग खिचरण रचना आवश्यक है। जो सस्थायें भविष्य में इस अनुसार कार्य करती नहीं पायीं जावेगी उन्हें सब तक अनुदान राशि देय नहीं होगी जब तक वह इस निर्देशन का का पूरा पालन न करे। अनुदान प्राप्ति पत्र में अनुदान प्राप्त पत्र में अनुदान प्राप्त स्तर के कर्मचारियों की नामावली एवं उस स्तर की कर्मचारियों की नामावली जिस पर अनुदान नहीं दिया जा रहा है अलग भवन प्रस्तुत करना आवश्यक है। अध्यापक की नियुक्ति पत्र में भी ऐसी सस्थाओं को यह प्रकट करना आवश्यक होगा कि अध्यापक की नियुक्ति किस स्तर हेतु की जा रही है। यह भी देखा गया है कि प्राइमरी स्तर हेतु जिस भवन का किराया पर भुगतान दिया जा रहा है जिस भवन में मिडिल स्तर, जिसको मिडिल स्तर पर भवन किराया पर अनुदान दिया जा रहा है उसी भवन में माध्यमिक स्तर आदि की कक्षाओं संचालित की जा रही है। जसा कि इस निर्देशालय के स्पाई आदेश 11/72 दिनांक 1-9-72 में आदेश दिया गया गया है ऐसा करना नियमानुसार नहीं है अतः अनुदान प्राप्त स्तर पर भवन किराये की गणना करते समय अनुदान प्राप्त स्तर से उच्च स्तर हेतु प्रत्येक विषय आधारित का पृथक से भूल्याकन कर भवन किराये के एक-एक से भी अधिक राशि कम करना आवश्यक है। इस सूचना के अभाव में ऐसी सस्थाओं के भवन किराये पर भुगतान देय नहीं है।

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर  
परिपत्र

विषय —सहायता प्राप्त सस्थाओं के एक दूसरी व्यवस्थापन समिति के  
अधीन हस्तांतरण ।

ऐसे अनेक मामले विभाग के सामने आये जिनमें एक सहायता प्राप्त सस्था या तो इनकी रजिस्टर्ड सहायता प्राप्त सस्था के नियंत्रण में आने अथवा दोनों ही एक दूसरे को नियंत्रण में लेने या देने सबको कायवाही अपने ही स्तर पर कर लेते हैं तथा उसके प्रस्ताव बाद में भेजते हैं । यह अनुदान नियम 13 के अंतर्गत सबको अनुचित है । नियमानुसार ऐसी कायवाही को बंध नहीं माना जा सकता ।

अतः सभी सहायता प्राप्त सस्थाओं को आदेश दिये जाते हैं कि जब भी किसी सस्था का हस्तांतरण या विलीनीकरण किया जावे उसके लिये विधिवत अनुमति विभाग से पूर्व में प्राप्त की जावे तथा रजिस्ट्रार समितियाँ की सूचना भेजी जावे सबधित प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारियों से भी निवेदन है कि वे ऐसे प्रस्तावों अपनी विशिष्ट टिप्पणी दिया करें । भविष्य में बिना पूर्वानुमति प्राप्त मामलों विचार करना समझ नहीं होगा ।

[क्रमांक ईडीबी/एड/ए/16011/77/72, दिनांक 25-11-72]

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर  
संशोधन स्टाई आदेश 7/72

इस कार्यालय के पूर्व पृष्ठांकन सस्था ईडीबी/एड/ए/16007/66/72 73 दिनांक 15-6-72 की मूल भावना यह थी कि सहायता प्राप्त सस्थाओं अपने व्यवस्थापन समिति का गठन अनुदान नियम परिशिष्ट एक के अनुसार करेंगे । अब यह संशोधित किया जाता है कि एक से अधिक सस्थाओं का संचालन करने वाली रजिस्टर्ड सस्था (ट्रस्ट) को उससे अधीन चल रही अनुदान प्राप्त सस्था के लिये भ्रमण से प्रबंधकारिणी समिति के गठन अनुदान नियम 1963 के परिशिष्ट एक के अनुरूप किया जावे परंतु ऐसी समिति के सदस्यों की सूची को रजिस्ट्रार सस्थाओं द्वारा रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता नहीं है ।

[सत्या —ईडीबी/एड/ए/16011/108/72, दिनांक 3-2-73]

[ ८ ]

Sub -Transfer of employees from one aided institution to another run by one parent body

[No F 29(29)Edu/Gr v/73 dated 15 May, 1974]

Refer to your letter No Shivira/Anv/A/16011/2/74 75 dated 29-4-74

The question has been examined by Government and it has been decided that if one parent body is running more than one institutions it may transfer employees from one institution to another subject to the following conditions -

- (1) The service conditions, pay scale etc of the persons transferred from one institution to other is the same
- (2) Both institutions where transfer is being made are aided upto the same percentage If it is not so transfer will be allowed subject to the condition that by doing so there is no increase in the actual grant-in aid payable to the institution

[No EDB/Aid/A/16011/74, Dated 16-8-64]

[ ९ ]

Subject -Revision of Pay Scales of organising Secretaries in the aided institutions

[No F 29(2)Edu/Gr V/73 dated 14 Oct , 1974]

I am directed to convey sanction of the Governor to the revision of the pay scales of the posts of organising Secretaries in the various aided Educational institutions as under with effect from 1-10-1974 -

Existing pay scales	Revised pay scales	Remarks
1	2	3
150-300	150 8 190 10 210 15 350	For Institutions with approved expenditure upto Rs 100 lakh
200-300	225 15 345 20 525	For institutions with approved

1	2	3
		expenditure upto Rs 2 00 lakhs & above

This issued with the concurrence of Finance Deptt  
(Exp I) vide their ID No 3602 dated 25 9 74

## अध्याय-६

### भवन किराये के सबध मे आदेश

[ 1 ]

कार्यालय, निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजहरान, सीकरी  
स्थाई आदेश संख्या 11/72

[कमांक — ईडीसी/एड/ए/16011/72/16 दिनांक 1-9-72]

इस कार्यालय के ध्यान में समय समय पर अनुदान प्राप्त निम्नल सत्याधों के भवन किराया सबधी अनेक समस्याएँ आई गई उदाहरणतः किराया में वृद्धि, सस्था भवन परीक्षोक्षा या भवन में अतिरिक्त आवास व्यवस्था हेतु नया निर्माण बाय । अनुदान नियम 1963, 6 (बि) नोट 4 के अनुसार निम्न शर्तों की पूर्ति होने पर ही भवन किराये पर अनुदान देय है, —

(1) सस्था भवन किराया नामा शत एवं दशांशों सहित मकान मालिक तथा सस्था अधिकारी द्वारा नियमानुसार हस्ताक्षरित होना आवश्यक है ।

(2) किरायानामा पञ्जीयक विभाग द्वारा पञ्जीकृत किया जाना आवश्यक है । नोटेरी (Notary) द्वारा पञ्जीकृत किरायानामा अनुदान हेतु माय नहीं समझा जावेगा ।

(3) भवन का मूल्यांकन सावजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाकर उसी के अनुसार उचित किराया प्रमाण पत्र (एक भार सो) प्रस्तुत किया जावे । इस प्रमाण पत्र में भवन कि आवास सबधी सूचना, कमरों को सख्या प्रत्येक कमरे की सम्बाई चौड़ाई एवं ऊँचाई का विवरण भी अंकित किया जावे ।

(4) किराया चुकारा रसीद की सत्यापित प्रतिलिपि अनुदान प्रापता पत्र के साथ मलग की जावे ।

इसके प्रतिरिक्त शिक्षण सस्थाओं को निम्न निर्देश दिये जाते हैं —

(1) भवन परिवर्तन को पूर्वअनुमति सस्था के विपत्र प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी से प्राप्त की जावे । अनुमति प्रदान आदेश जारी की गई तिथि से पहले का भवन किराया अनुदान हतु अमान्य समझा जावेगा ।

(2) भवन में प्रतिरिक्त नये कमरे बनाने की सूचना विभाग को सस्था द्वारा हस्तान्तरित किये जाने के तुरन्त बाद प्रेषित की जानी चाहिए ।

(3) सस्था के भवन का कोई भाग सस्था के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका व्यवस्थापक सत्री आदि किसी सस्था अधिकारी के आवास हेतु काम में लाया जाता है तो इसका पूर्ण विवरण एवं मासिक किराया का गणना पत्र भी अनुदान प्रापता पत्र में साथ प्रस्तुत किया जावे तथा सस्था भवन के जो भाग किराये पर दिय गये हों उसका पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जावे ।

(4) ऐसी सस्थाओं को जो किसी स्तर पर अनुदान हेतु मा य है, परन्तु सस्था में उच्च स्तर की कक्षाएँ भी चालू करने की विभाग से अनुमति प्राप्त हो और दोनों स्तरों की कक्षाएँ एक ही भवन में लगाई जाती है और समस्त भवन किराया अनुदान प्राप्त स्तर हेतु चार्ज किया जाता हो तो ऐसी सस्थाओं को उच्च स्तर की कक्षा हेतु प्रयुक्त कमरों का पूर्ण विवरण एवं एतद्वय अनुमानित किराये का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा अपेक्षित सूचना के अभाव में ऐसी सस्था का भवन किराया अनुदान हतु स्वीकृत व्यय नहीं माना जावेगा ।

(5) कुछ सस्थाएँ सस्था भवन को स्कूल समय के पहले या बाद में प्राय प्रवृत्तियों हेतु प्रयुक्त करते पाये गये हैं । ऐसी अवस्था में सस्था भवन को मा य प्रवृत्तियों हेतु प्रयुक्त करने को अनुमति विपत्र प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक है । पूर्ण अनुमति के अभाव में सस्था के विरुद्ध अनुशासनारमक कार्यवाही की जा सकती है । जिसमें भवन किराये पर अनुदान स्वीकृत न किया जाना भी सम्मिलित है ।

(6) भवन किराये में वृद्धि अनुदान हेतु तभी मा य होगी जबकि तत्प्रा प्रतिरिक्त आवास की आवश्यकता का प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी से प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करे एवं प्रतिरिक्त आवास की व्यवस्था का पूर्ण विवरण एवं मूल्यांकन पी० डब्लू० डी० से करवाकर उसका भी प्रमाण प्रस्तुत करे ।

(7) शिक्षा सस्था को जो विभाग से भवन किराये पर अनुदान प्राप्त करती है, सन 1972-73 से प्रतिवर्ष निम्न प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही मा य किया जावेगा । अधिकारी भवन किराया स्वीकृति हेतु अनुश्रुत पा करेंगे ।

मैं व्यवस्थापक/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका का भवन, जिस प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि सस्था हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है, पूणत अनुदान हेतु स्वीकृत स्तर की रक्षाओं हेतु ही काम में लाया जा रहा है। भवन का कोई भाग सस्था अधिकारी के धावास हेतु या किराये हेतु काम में नहीं लाया जा रहा है। सस्था भवन अन्य प्रवृत्तियों हेतु भी प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है। अथवा सस्था भवन का मासिक किराया भवन के अन्य प्रवृत्तियों हेतु काम में लाने के कारण जिसके प्रमाण सलग्न है केवल रूपमा मात्र मासिक भवन किराया अनुदान हेतु स्वीकृत व्यय माना जावे।

## [ 2 ]

## Clarifications (1)

The provisions of grant in aid Rules are very clear and rent is admissible from the actual date the building is taken on rent and not from the date of registration of rent deed. The actual occupation on rent is to be confirmed either on the basis of the P W D Certificate or an stipulation in the deed itself

[No F 1(3)Edu/C-6/71, Dated the 23 Jan , 1971 ]

## Clarifications (2)

The rent is admissible from the actual date the buidng is taken on rent and not from the date of registration of rent deed

[No F 1(101)Edu/6/70, Dated the 5 June, 1974 ]

# रेलवे-शालाओं के संबंध में अनुदान-नियम

[ 1 ]

Sub — Grant in aid to Railway Schools situated in Rajasthan

In continuation of this Department letter of even No. 1000 dated the 4th April 1958 on the above subject, I am directed to say that the State Government propose to give grant in-aid to the various Railway Schools situated in this state from next year according to the grant in aid rules at the following rates:—

- |                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Primary Schools                   | 50% of approved expenditure |
| 2 Middle Schools                    | 33% of approved expenditure |
| 3 High Schools & Higher Sec Schools | 25% of approved expenditure |

The State Government have also considered the case of the Anglo Indian Schools but they do not propose to give any grant in aid to such schools

[No F 18 (4)/56 dated 17 Oct, 1958]

[ 2 ]

विषय — अनुदान प्राप्त संस्थाओं में नियुक्ति हेतु निर्धारित व्यय समिति में विभागीय प्रतिनिधि नियोजित करने के क्रम में ।

विभाग के सम्मुख यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय रेलवे द्वारा संचालित समस्त शिक्षण संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति केन्द्रीय सरकार के रेल मन्त्रालय द्वारा निर्मित सेवा नियमा के अनुसार की जाती है । प्रत्येक रेलवे के मुख्य कार्यालय पर स्थित रेल सेवा आयोग इन कर्मचारियों को चयन करने के लिये व्यक्तियों की सूची प्रत्येक मंडल कार्यालय अधिकारी को भेज देता है । कार्यालय अधिकारी द्वारा चयन करने वाले स्थित रेलवे स्कूलों के अध्यक्ष के सूची में स क्रमवार नियुक्ति की जाती है । विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त कर्मचारियों की तब नियुक्ति हेतु गठित व्यय समिति में विभागीय चयन करने का मुख्य उद्देश्य उपरोक्त प्रणाली में से सुयोग्य व्यक्ति का



की जा रही अनियमितता को रोकना है। रेलवे बोर्ड द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के कमचारियों का भ्रजन रेल सेवा आयोग द्वारा विधिवत किया जाता है। प्रत मस्याओं की नव नियुक्ति हेतु निर्मित भ्रजन समिति में विभागीय प्रतिनिधि का समा योजित करना आवश्यक नहीं समझा जावे। रेलवे आयोग द्वारा नियुक्त व्यक्ति को नियुक्ति की शक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता पूरा होने पर अनुमोदन किया जावे जिससे इन पदों पर अनुदान स्वीकृत किया जा सके।

[क्रमांक — ई डी बी/एड/ए/16011/86/72, दिनांक 11-12-72]

[ ३ ]

Sub —Depositing the P F amount in the Post-Offices by the Institutions Governed by the Central Government

Ref —Your letter No EDB/AID/G/17104/77 dated 9 11 72

Sir,

I am directed to convey sanction of the Governor to relax the rule 4 (k) of the Grant in aid Rules, 1963 for depositing the Provident Fund amount in the Post Office Saving Bonds in respect of Institutions the employees of which are governed by the Central Government service Rules

This issues with the concurrence of Finance Department vide their U O No 4656/GD/(Exp-I)/73 dated 27th/30 Decemb r, 1973

[No F 2 (24) Edu-G-VI/62, the 31st January, 1973]

[ 4 ]

परिपत्र

अनुदान नियम 1963 की धारा 4 (बी) के अंतर्गत राजस्थान सरकार से अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कमचारियों को राजस्थान वेतन श्रृंखला के समकक्ष वेतनमान में भुगतान की गई राशि पर ही अनुदान स्वीकृत करने का प्रावधान है। रेलवे स्कूल के कमचारियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित वेतन मान में ही वेतन भुगतान की व्यवस्था है तथा इन संस्थाओं द्वारा अनुदान प्राप्ति पत्र (भावतक) में अपेक्षित सूचना इन कमचारियों को वास्तव में भुगतान की गई

राशि पर आधारित रहती है। परंतु अनुदान वेतन केवल राजस्थान वेतनमान में देय राशि पर ही दिया जाता है। निदेशालय स्तर पर राजस्थान वेतनमान में समस्त कमचारियों का वेतन गणित कर अनुदान स्वीकृत करने में अनावश्यक श्रम करना पड़ता है। अब यह नियम लिया गया है कि वह अपने प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान हेतु स्वीकृत पदा पर देय वेतन राशि का स्टेटमेंट ही अपने अनुदान प्राथना पत्र के साथ सलग्न कर प्रस्तुत करें। यदि वह चाहे तो समस्त केन्द्रीय वेतन श्रृंखला में भुगतान की गई राशि का भी विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं।

कमचारियों का नाम नियुक्ति तिथि, ज मतिथि आदि सूचना भी निम्न प्रपत्र में अनुदान प्राथना पत्र के साथ सलग्न किया जावे —

प्रपत्र

नाम कमचारी	पद	वेतनमान	वेतनमान	योग्यता	ज मतिथि
		केन्द्रीय	राजस्थान	शैक्षणिक   प्रशासनिक	
1	2	3	4	5	6
7					
नियुक्ति तिथि	वेतन वृद्धि तिथि	राजस्थान वेतनमान में 1 4-72 से 3 1 3 73 तक देय वेतन			
8	9	10			

प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह रेलवे स्कूल के अनुदान प्राथना पत्र की जांच करते समय सत्या के अनुदान हेतु स्वीकृत समस्त पदों की प्राथिक धप की देय राशि का विवरण पत्र तैयार कर ही स्वीकृत राशि की गणना करे तथा अनिवार्य रूप से रेलवे स्कूल के अनुदान प्राथना पत्र (आवतक) की जांच कर दिनांक 31 10 73 तक निदेशालय को प्रेषित करे ताकि इसकी जांच समुचित रूप से की जा सके।

इन प्रादेशों की अनुपालना न किये जाने पर संबंधित रेलवे स्कूल को अनुदान स्वीकृत नहीं किया जावेगा। अपेक्षित सूचना के समुचित रूप से प्राप्त होने पर ही निदेशालय द्वारा अनुदान स्वीकृत करने की कामवाही की जावेगी। अतः रेलवे स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं प्रतिहस्ताक्षर-कर्ता अधिकारियों का यह दायित्व है कि वह उक्त अपेक्षित सूचना सहित अनुदान प्राथना पत्र (आवतक) को प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक इस कार्यालय को प्रेषित करने की व्यवस्था करें।

[क्रमिक-शिविरा/अनु/ए/16011/74/73, दिनांक 5 9 73]

[ 5 ]

## Sub —Grant in aid to Railway Schools

Sir,

I am directed to refer to your letter No 149 dated 24 5 73 on the subject cited above and to convey sanction of the Governor to exempt the Railway Schools run by the Railway Board in Rajasthan from operation of the following provisions of the Rules for payment of Grant in aid to non Govt Educational, Cultural and Physical Educational Institutions in Rajasthan, 1963, for the purpose of regulating payment of Grant in aid to these schools —

(1) Note (2) below Rule 1

(2) Condition no 5 below Rule 3

(3) Rule 9 (2)

This issues with the concurrence of the Finance Department vide their I D No 4289/PA/FC/73 dated 4 9 73

[No F 1 (33) Edu-V/70, Dated the 5-12 73 ]

[No Shivira/Anu/H/17404/Vol/65, Dated 29 12 73 ]

अध्याय-४

## परीक्षाओं की मान्यता संबंधी आदेश/परिपत्र

[ 1 ]

[क्रमांक डीईओ/14/यू/ए/बी/72 जयपुर दिनांक 31-3 72]

विषय --सहायता प्राप्त मोटेसरी स्कूलों में बाल सेविका प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की नियुक्ति।

सम्भ --भाषका पत्र सहायक शासन सचिव शिक्षा (प्र 6) के नाम क्रमांक डीईओ/गड/ए/16353/11531/69 दिनांक 23 12-71।

महोदय,

निर्देशानुसार लेख है कि मामले पर पुनर्विचार किया गया। बाल सेविका प्रशिक्षण को राज्य सरकार द्वारा अव्याई रूप से तीन साल के लिए मान्यता प्रदान की गई थी, जो अवधि दिनांक 11 अगस्त 1967 को समाप्त हो गई। मत इस

विभाग के पत्र सख्या एक 9 (11) सा प्र/ख/64 दिनांक 6 मई, 1970 को मशौचित करते हुए स्पष्टीकरण दिया जाता है कि जिन व्यक्तियों ने मायता अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है उन्हें नियुक्ति के योग्य समझा जावेगा।

[क्रमांक इंडोबी/एड/ए/16353/157/69 दिनांक 28-4 72]

## [ 2 ]

विषय — विभिन्न परीक्षाओं को मायता।

क्रमांक एक-9 (10) सा/प्र/ख/67 दिनांक जयपुर 17-7-72।

सामान्य प्रशासन (ग्रुप) विभाग के आदेश समसूचक दिनांक 3 अप्रैल 1972 के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि विधानानुसार गठित विश्व विद्यालयों को समस्त परीक्षाएं राज्य सरकार के आदेश सख्या एक 5 (85) सा/प्र/क/52 पाठ 2 दिनांक 25 11 52 व 28-2-58 के अनुसार स्वतः ही मायता रखती है, किंतु विभिन्न सेवाओं के लिए इनकी मायताएं सेवा नियमों में दी गई शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर निर्भर करती है।

इस प्रकार कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्व विद्यालय की "शिक्षा शास्त्री" परीक्षा विश्व विद्यालय की परीक्षा होने के नाते मायता है। राज्य सरकार द्वारा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की शिक्षा शास्त्री परीक्षा का राजस्थान की 'बी एड' के समकक्ष की गई मायता समाप्त की गई है।

[क्रमांक शिविरा/रिकाड/5911/2/32/15 दिनांक 30-8 72]

## [ 3 ]

विषय — केस्मिक मोटेसरी प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर एवं जोधपुर व उदयपुर विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित मोटेसरी डिप्लोमा को बी एस टी सी प्रशिक्षण के समकक्ष मानने के विषय में।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक स एक 10 (95) शिक्षा/ग्रुप 4/72/ दिनांक 29 8 72 में यह निर्णय लिया गया है कि मोटेसरी प्रशिक्षण को बी एस टी सी प्रशिक्षण के समकक्ष मानने का प्रश्न विचाराधीन है। जब तक यह प्रश्न विचाराधीन रहता है सरकार न आदेश दिये है कि केस्मिक मोटेसरी प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर विश्व विद्यालयों द्वारा आयोजित मोटेसरी प्रशिक्षण डिप्लोमा प्राप्त कर्मचारियों को यथावत काम करने दिया जावे।

[क्रमांक - ईडीबी/एड/ए/16012/34/72 दिनांक 7-10 72]

[ 4 ]

## भाज्ञा

[क्रमांक एफ 9 (63) सा/प्र/3/72 दिनांक जुलाई, 12, 1973]

केस्मिक मोटेसरी प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर द्वारा संचालित मोटेसरी पाठ्यक्रम एवं जोधपुर विश्व विद्यालय जोधपुर द्वारा संचालित पूर्व प्राथमिक शिक्षा (5 प्राईमरी एज्युकेशन) डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण हेतु कुछ विद्यार्थियों ने इच्छा ज्ञाति में प्रवेश ले लिया था कि इन पाठ्यक्रमों को राज्य सरकार यथा समय मायता प्रदान कर देगी। ऐसे व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखते हुये निम्न नियम निम्न गया है —

- (1) उक्त सस्थाओं द्वारा सत्र 1968-69 तक प्रदत्त डिप्लोमा को राज्य सरकार के अधीनस्थ सेवाओं के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (बी एम टी सी) के समकक्ष मायता प्रदान की जाती है।
- (2) इा सस्थाओं द्वारा सत्र 1969-70 से सत्र 1972-73 तक प्रदत्त डिप्लोमा को भी उक्त प्रयोजनाय मायता इम शत पर प्रदान की जानी है कि इ डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों की शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एक वर्षीय पत्राचार पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा और ऐसा करने पर ही उनका तृतीय श्रेणी प्रशिक्षित अध्यापक वेतनमान दिया जाना सम्भव होगा। जि डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा उक्त पत्राचार पाठ्यक्रम उत्तीर्ण नहीं रिय जाता है उहे केवल अप्रशिक्षित तृतीय श्रेणी अध्यापक का वेतनमान दिया जावेगा।
- (3) मोटेसरी/पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों जो कि विशेष तौर पर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिये प्रशिक्षित होते हैं के लिये शिक्षा विभाग द्वारा विशेष पत्राचार पाठ्यक्रम निर्धारित किया जावेगा जिस के प्राथमिक कक्षाओं को भी पढा सकें।
- (4) सत्र 1972-73 के पश्चात् उक्त सस्थाओं द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा को बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (बी एस टी सी) के समकक्ष मायता नहीं दी जावेगी।

[प्रतीक शिबिरा/प्रनु/ए/16011/स्वे/72-73 दिनांक 26-7-73]

[ 5 ]

प्रतीक --प ३ (67) सा/प्र/3/71, दिनांक 27-8-73

विषय --समीत परीक्षाओं का मायता।

राजस्थान सरकार द्वारा निम्न लिखित मस्थाओं की समीत परीक्षाओं को

संगीत विषय अध्यापन के लिए नियुक्ति हेतु मापता प्रदान करने को नियम लिया गया है ---

संगीत (कठ अथवा वाद्य)

- 1 हिंदुस्तानी संगीत में विश्व विद्यालय की उपाधि ।
  - 2 माधव संगीत महा विद्यालय की अथवा इंदोर के गवर्नमेन्ट म्यूजिकल कालेज की सर्वोच्च परीक्षा ।
  - 3 बड़ोदा स्टेट स्कूल आफ म्यूजिकल की सर्वोच्च परीक्षा,
  - 4 माधव महाविद्यालय की अन्तर्कार परीक्षा,
  - 5 इलाहाबाद विश्व विद्यालय द्वारा संचालित वोकल तथा इस्ट्रुमेण्टल म्यूजिकल की डिप्लोमा परीक्षा,
  - 6 माधव महा विद्यालय बोर्ड की सन् 1939 से पूर्व संगीत की विस्तारद परीक्षा,
  - 7 भातखण्डे कालेज आफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की इन्टर मिडियेट परीक्षा का प्रमाण पत्र
  - 8 हाई स्कूल परीक्षा सहित इलाहाबाद की प्रयाग संगीत समिति संगीत में मीनियर डिप्लोमा ।
  - 9 जयपुर के राजस्थान कला नृत्यन अथवा जयपुर के राजस्थान का संगीत संस्थान का त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम ।
  - 1 किसी माधव विश्व विद्यालय का संगीत लेकर स्नातक,
  - 2 ग्वातियर के माधव म्यूजिक कालेज का संगीत में इन्टर मीजियट (ये परीक्षाएं बाद में शिला विभाग मध्य भारत और इसके बाद मध्य प्रदेश द्वारा संचालित हुईं)
  - 3 सतलुज के भातखण्डे संगीत विद्यापीठ की मध्यमा ।
  - 4 सरदार ग्वातियर के शहर माधव महाविद्यालय की संगीत विस्तारद,
  - 5 खेरगढ़ के इन्द्रा कला संगीत विश्व विद्यालय की मध्यमा,
  - 6 बम्बई के माधव महा विद्यालय बोर्ड का संगीत विस्तारद,
  - 7 राजस्थान सरकार की विभागीय परीक्षाओं का संगीत भूपर
  - 8 मद्रास में हाई स्कूल अथवा समकक्ष योग्यता के साथ निम्नलिखित योग्यताओं में से कोई ---
- (क) हिंदुस्तानी संगीत में विश्व विद्यालय की उपाधि
  - (ग) ग्वातियर के मध्य संगीत महा विद्यालय की अथवा इंदोर के गवर्नमेन्ट म्यूजिक कालेज की सर्वोच्च परीक्षा
  - (न) बड़ोदा स्टेट स्कूल आफ म्यूजिक की सर्वोच्च परीक्षा
  - (प) माधव महाविद्यालय मद्रास की अन्तर्कार परीक्षा

- (ड) कठ तथा बाघ्य संगीत में डिप्लोमा परीक्षा (दोनों इलाहाबाद विश्व विद्यालय द्वारा संचालित)
- (घ) महाविद्यालय मण्डल की 1939 की परीक्षा से पूर्व की संगीत विहार परीक्षा,
- (छ) भात खण्डे बालेज आफ हि दुस्तानी म्यूजिक का इटर मिडियट परीक्षा प्रमाण पत्र,
- (ज) इलाहाबाद की प्रयाग संगीत समिति का संगीत में सीनियर डिप्लोमा
- (झ) जयपुर के राजस्थान कला संस्थान का त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम

संगीत का चरिष्ठ अध्यापक :—

- 3 1 माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर का संगीत रत्न (ये परीक्षा बाद में मध्य भारत के द्वारा उसके बाद मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हुई)
- 2 ग्वालियर राज्य के माधव संगीत विद्यालय की उच्चतम परीक्षा,
- 3 भातखण्डे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विहार
- 4 इन्द्रा कला संगीत विश्व विद्यालय खेरामठ की 'कीविद'
- 5 लक्ष्मी ग्वालियर के लक्ष्मी गायन महाविद्यालय का 'संगीत प्रवीण'
- 6 गायन महाविद्यालय मन्डल बम्बई का 'संगीत प्रकाश'
- 7 राजस्थान सरकार की विभागीय परीक्षा का संगीत प्रमाण

4 विभागीय परीक्षार्थ, शिक्षा विभाग, बीकानेर —

- 1 संगीत भूषण
- 2 संगीत निपुण

[क्रमांक - शिविरा/अनु/एक सरकूलर फाईल/16039/73 दिनांक 23-11-73]

[ 6 ]

शुद्धि पत्र

[क्रमांक एफ/9/(67) प्रा/स 71, दिनांक 11 जनवरी 74]

इस विभाग द्वारा प्रसारित आदेश सम मस्यूर दिनांक 27-8-73 के अनुच्छेद 1 का शीपब निम्न प्रकार पढ़ा जावे —

निम्नांकित संस्थाओं से जो व्यक्ति संगीत का प्रमाण पत्र रखते हैं उनकी संगीत विषय बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित तृतीय वेतन श्रृंखला में समतुल्य माना गया है।" अनुच्छेद 2 का शीपब निम्न प्रकार पढ़ा जावे —

निम्नांकित संस्थाओं का जो व्यक्ति संगीत प्रमाण पत्र रखते हैं उनकी

## अध्याय--8

प्राप्त एवं सेवा निवृत्ति संबंधी आदेश/परिपत्र

[1]

Government of Rajasthan, Education (Cell VI) Department  
ORDER

No F 6 (d) (34) Edu/Cell/VII/67 Dated 4th August, 1967

Governor is hereby pleased to order that the displaced teachers from Pakistan employed as teachers in Government schools in Rajasthan may be allowed to continue in Government service upto 60 years, provided they joined service before 1952

Governor is further pleased to order that the sons and daughters of displaced teachers should, however, treated on par with other teachers appointed in Government service

[2]

No F 1(114) Edu/Cell/VI/67 dated the 6th Feb , 1968  
Sir,

I am directed to convey sanction of the Governor to the following —

(1) That the institutions imparting education to girls and whose total annual expenditure is 1 s , 75000/-as against 1 lakh provided in the grant in aid Rules be allowed recurring grant in aid on central office with effect from 1st April, 1966

(2) That recurring grant in aid on the salaries of political sufferers, who happen to work in the Aided Institutions as Secretary and in capacities other than teaching staff may be allowed if they are physically fit, that is no age limit be prescribed for these persons This will take effect from 1st April, 1966

शिक्षा का उद्देश्य है विद्यार्थी को मनुष्य बनाना ।



This issues with the concurrence of the Finance Department  
No 6320 dated 11 12 1967

[3]

स्पष्टीकरण

उपरोक्त विषय से मुझे यह लिखने का निर्देश है कि स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र डी एम एण्ड एच ओ, पी एम एच ओ अथवा प्रिंसिपल मेडीकल कालेज द्वारा प्रदत्त प्रस्तुत किया जावे ।

राजनैतिक पीडित का प्रमाण पत्र जिलाधीश द्वारा प्रदत्त माना जावे ।

[स एफ 1 (114) सि प्र 6/67]

दिनांक 22 मार्च 1968

[4]

## NOTIFICATION

No F 1 (164) Edu/Cell/VI/68 Dated the 21st March, 1968

The Governor has been pleased to order that the following new para may be added to Rule 3 (16) of the Rules for payment of Grant in Aid to Non Government Education, Cultural and Physical Education Institution in Rajasthan 1963, published in Rajasthan Gazette vide No F 2 (24) Edu/Cell/VI/62 Dated 19 1 1963

"The age of superannuation of employees holding post equal to Class III and Class VI employee of Government shall not exceed 58 and 60 years respectively "

This order shall be applicable from 1st July, 1969

This issues with the concurrence of Finance Department (Exp 1) vide their I D No 1046 dated 20 3-1969

[ 4-क ]

परिपत्र

इस कार्यालय के पूर्व परिपत्र 9 स ईडीवी/एड/ए/16007/स्वेणल/67 दिनांक 28-6-1967 के अनुक्रम से सूचित किया जाता है कि अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी जो राज्य सेवा के तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के पदों

दिलवाटी विनम्रता यव की चरम सीमा है । —गिम्बन

समकाल पदा पर सेवा रत हैं, के लिए सेवा निवृत्ति की आयु क्रमशः 58 तथा 60 वर्ष होगी।

अतः यह विरोध रूप से सस्याभा के ध्यान में लाया जाता है कि दिनांक 30-6-69 के बाद ऐसे पदा पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आयु पहुँचते ही सेवा निवृत्त कर दिया जावे क्योंकि ऐसी मसलों में सेवाकाल में वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं होने से उन पर विचार करना सम्भव नहीं होगा तथा फलस्वरूप होने वाले व्यय भार पर कोई अनुदान देय नहीं होगा।

कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति रसीद भेजे।

( क्रमांक इ डी बी/एड/ए/16007/237/67 दिनांक 11-6-1969 ई )

[ 5 ]

### NOTIFICATION

No F 1 (164) Edu/Cell/VI/68 Dated the 13th March, 1970

The Governor has been pleased to order that the following new para may be added to Rule 3 (15) of the Rules for payment of Grant in Aid to Non Government Educational, Cultural and Physical Education Institutions in Rajasthan 1963, Published in Rajasthan Gazette vide No F 2 (24) Edu/Cell/VI/62 dated 19-1-1963

"No Government Servent retired on Superannuation will be re employed by any Institution receiving grant under these Rules"

This order shall be applicable from 1st July, 1970

This issues with the concurrence of Finance Department

(Exp (1) vide their I D No 712 dated 5-3-70

[No F 1 (164) Edu/Cell/VI-63 Dated the 13th March, 1970]

[6]

### CLARIFICATION

Some Institutions have sought clarification regarding applicability of this Department Notification of even number

आलस्य और अज्ञान मनुष्य के बड़ शत्रु हैं।

dated 13-3-70 as to whether those retired Government Servants already employed by aided Institutions will continue in service upto the age of 58 years or not

I am, therefore, directed to state that the provision of existing Rules will apply to the employees, who have been re-employed by aided Institutions after retirement

[ No EDB/AID/A/16007/48/70 Bikaner, Dated 21-8-70 ]

[ 7 ]

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर  
स्थायी आदेश 14/1972

समय समय पर विभाग के सम्मुख जो समस्याएँ प्रस्तुत की जाती रही हैं उन पर विचार कर निम्न निर्णय लिये जाते हैं तथा समस्त शिक्षण संस्थाओं को आदेश दिया जाता है कि संबंधित समस्या पर इन निर्णयों के अनुकूल ही कार्यवाही को जावे अथवा इस आदेश की अनुपालना के अभाव में आगामी कार्यवाही सम्भव नहीं होगी।

(1) अनुदान नियम 1963 को धारा 3 (13) के अनुसार नये बग प्रारम्भ करने की पूर्वानुमति विभागीय सक्षम अधिकारी से प्राप्त करली जावे।

(2) किसी कक्षा में नवीन बग प्रारम्भ तब तक नहीं किया जावे जब तक छात्र-छात्राओं की 'यूनतम' संख्या कम से कम 20 तक न हो जावे, किसी भी नवीन वर्ग में इस निर्धारित 'यूनतम' छात्र संख्या से कम छात्र छात्राओं के होने की स्थिति में ऐसे बग प्रारम्भ नहीं किये जा सकते हैं। उदाहरणतः किसी कक्षा के प्रथम बग में 40 दूसरे में 40 छात्र छात्रा होने पर ही तीसरा बग प्रारम्भ किया जा सकता है। जबकि तीसरे बग हेतु भी कम से कम 20 छात्र छात्रा उपलब्ध हों।

(3) (अ) अतिरिक्त अध्यापक पद स्वीकृति हेतु प्रायः पत्र प्रस्तुत करते समय विगत तीन वर्षों के छात्र छात्रा संख्या विवरण प्रस्तुत किया जावे, इस विवरण में प्रत्येक सत्र हेतु चार कालम बनाये जावे, जिनमें —

(1) निचली कक्षा से प्रमोटेड

(2) इस कक्षा में फल

(3) नये प्रवेश प्राप्त एवं

(4) कक्षा छोड़कर अन्यत्र चले गये छात्र संख्या कक्षा वार व बगवार में कितनी गई है।

समय ही जीवन का सर्वांगीण भूत है।

(व) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर हेतु उस नगर में शिक्षण सुविधा प्राप्त है या नहीं इसका भी उल्लेख किया जावे एवं उन सस्थाओं के नाम अंकित किये जावे जिनमें यह सुविधा प्राप्त है।

(4) बड़े नगरों में जहां माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षणार्थी अप्र विद्यालय उपलब्ध हो बिसी वर्ग हेतु, (विज्ञान, कला, वाणिज्य) 20 से कम छात्र उपलब्ध होने पर यदि इस विषय के अध्यापक की सुविधा अप्र विद्यालय में उपलब्ध हो तो ऐसे वर्ग को समाप्त कर दिया जावे। एक ही वर्ग में 40 छात्रों के प्रवेश प्राप्त करने एवं दूसरा संवत्स प्रारम्भ करने हेतु न्यूनतम संख्या 20 होने पर ही प्रतिरिक्त संवत्स को अनुदान हेतु स्वीकृत माना जा सकता है। यह प्रतिबंध उन माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु लागू नहीं होगा जहां दूसरे विद्यालय में उस वर्ग के छात्र छात्राओं के प्रवेश की सुविधायें उपलब्ध नहीं है।

(5) मिडिल स्तर तक सामान्यतः कोई विशिष्ट योग्यता के अप्रारक जैसे आपट, सिलाई, ड्राईंग आदि स्वीकृत नहीं किया जाता है क्योंकि इस स्तर तक तृतीय वर्ग में खुला अध्यापकों को ही नियोजित किया जाता है और ऐसे अध्यापक इस स्तर हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ाये जाने वाले विभिन्न विषयों के अध्यापन हेतु सक्षम माने गये हैं। मिडिल स्तर तक के शिक्षण सस्थाओं में छात्र संख्या की कमी आदि कारणों से यदि अध्यापक पद में कमी करनी हो तो सबसे कमिष्ठ अध्यापक को ही सेवा मुक्त किया जाना आवश्यक है।

(2) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किसी विषय के समाप्त किये जाने की स्थिति में उस विषय विशेष के सबसे कमिष्ठ अध्यापक की ही सेवा मुक्ति का प्रावधान नियमांतर्गत माना जावे।

शिक्षण सस्थाओं के अध्यापकों के पद हेतु प्रकाशित किये गये विनापन में शैक्षणिक व प्रशिक्षणिक योग्यता के प्रतिरिक्त अप्र कोई प्रतिबंध लगाना अनुचित समझा जावे। अध्यापक पद हेतु योग्यता अनुभव आदि की वही शर्त लागू होगी जो अप्र ई एम एस 1971 नियमांतर्गत राज्य सेवा हेतु निर्धारित है। प्रधानाध्यापक पद हेतु भी वही योग्यताएं व अनुभव जो कि राजकीय सेवा हेतु अप्र ई एम 1970 में निर्धारित की गई है आवश्यक समझी जावे। इन योग्यताधारित प्रत्याशी प्राप्त न होने पर निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, की पूर्व अनुमति प्राप्त करने पर ही नियम में शिथिलन सम्भव होगा।

समस्त प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारियों को निर्देश दिये जाने हैं कि व इन नियमों के अनुसार ही कार्यवाही करे और अपने स्तर पर ही इन नियमों के अनुपालन न किये जाने की अवस्था में सस्था को अनुपालना हेतु आदेश प्रदान करे।

स्था में प्राप्त इन समस्याओं को सीधे निदेशालय स्तर पर ही निणय लिये जाने हेतु प्रपित न किये जागे । क्योंकि इनके कारण शिक्षण सस्थाओं की समस्याओं पर निणय लेने एव उनका निपटारा करन हेतु निदेशालय द्वारा अनानश्यक पत्र व्यवहार करना पडता है और निणय लेने में अनावश्यक विलम्ब हो जाता है ।

(अमाक — ईटीवी/एड/ए/16011/89/72

दिनांक 29 12 72)

( 8 )

स्याई आदेश 14/1972 में सशोधन

इस कार्यालय के स्याई आदेश स 14/72 दिनांक 29-12-72 में निम्न लिखित सशोधन किया जाता है -

“शिक्षण सस्थाओं में नियुक्त अध्यापकों की आयु के विषय में राजस्थान शिक्षा नियमों में निर्धारित आयु सीमा में शिथिलन दिया जाना है तथा प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक होने पर उस विमी भी आयु में नियुक्त किया जा सकता है ।”  
( क्रमांक-शिविरा/अनु/ए/16001/41/73-74 दिनांक 26-5-73)

( 9 )

स्याई आदेश 14/72 में सशोधन

इस कार्यालय के स्याई आदेश 14/72 दिनांक 29-12-72 में निम्न लिखित सशोधन किया जाता है -

प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी की दृष्टि में रखते हुए अनुदान प्राप्त शिक्षण सस्थाओं में नव नियुक्त प्रशिक्षित अध्यापकों पर राजस्थान आर ई एस एस नियम 1571 में आयु सम्बन्धी प्रतिबन्ध में शिथिलन किया जाता है । प्रशिक्षित अध्यापकों के नियुक्ति अनुदान नियम 1963 के तहत निर्धारित अधिकतम आयु तक की जा सकती है परन्तु राजकीय सेवा से मुक्त प्रशिक्षित अध्यापकों हेतु राज्यादेश क्रमांक एफ 1(164) /शिक्षा/सी 6-68 दिनांक 19-5-70 लागू समझा जावे ।

इस कार्यालय द्वारा प्रसारित आदेश क्रमांक शिविरा/अनु/ए/16001 41-73-74 दिनांक 26-5-73 को निरस्त समझा जावे ।

( अमाक — शिविरा/अनु/ए/16001/60 73- 74

दिनांक 2 8 73 )

पापीम नही, पाप में घण्टा करो—गांधी

(10)

## कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर परिपत्र

अनुदान नियम 3 (16) के अनुसार सहायता प्राप्त सस्थाओं के कमचारियों को 58 वर्ष की आयु प्राप्त पर सेवा निवृत्त आयु (Superannuation) मानने का प्रावधान है। केवल विशेष मामलों में 60 वर्ष की आयु या उससे अधिक 5 वर्ष के सेवाकाल वृद्धि की राज्य सरकार की अनुमति पर माय करन का नियम में आगे चलेख है। साथ ही इसी नियम में राज्यादेश संख्या एक (164) शिभा/सल 6/68 दिनांक 21-3-69 के द्वारा यह वाक्य और जोड़ा गया है "सहायता प्राप्त सस्थाओं के अधिकारियों जिनके पद तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के बराबर है, की सेवा निवृत्त आयु (Superannuation age) क्रमशः 58 और साठ स आगे नहीं बढ़ाई जावेगी।"

नियमों के उक्त दोनों प्रकार के प्रावधान समाविष्ट होने के उपरांत भी सस्थाओं से कमचारियों को सेवा निवृत्ति की आयु सम्बन्धी प्रकरण यदाकदा प्राप्त होने रहते हैं एवं नियमों की भावना अब भी स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है। अतः समस्त शिकायतों के समाधान एवं इस हेतु सस्थाओं व अधिकारियों के मागदर्शन हेतु निम्न बिबुधों के द्वारा इस नियम के आशयों को स्पष्ट किया जाता है —

1. सहायता प्राप्त सस्थाओं में मायगत सभी श्रेणियों के कमचारियों (केवल चतुर्थ श्रेणी कमचारी के अलावा) के लिये नियमानुसार सेवा निवृत्ति का आयु 58 वर्ष हो रहा है। चतुर्थ श्रेणी कमचारी को इस हेतु 60 वर्ष का आयु पर सेवा निवृत्ति माना जावे।

2. इन दोनों प्रकार के श्रेणियों के कमचारियों का आयु की सीमा में ऊपर माग सेवा में रहने का कोई प्रावधान नहीं है। यहां तक कि अध्यापन कमचारी का भी सत्र के समय में 58 वर्ष की आयु प्राप्त करन पर सेवा निवृत्त किया जावे। सत्रांत तक सेवा में रहने पर विभाग द्वारा ऐसे अध्यापकों के वतन पर कोई अनुदान नहीं होगा।

3. सेवा निवृत्ति की उपरोक्त आयु में पूर्व यदि किसी सस्था अपने म को हटाती है या सेवा निवृत्त करती है, तो ऐसी सेवा मुक्ति की कृपा का ही नियम के प्रावधान के अनुसार ही की जावे।

[क्रमांक-शिविरा/अनु/ए/16001/33/73 दिनांक

अज्ञान जैसा शत्रु दूसरा नहीं-चाणक्य

# NOTIFICATION

No F ((10) Edu//Gr V/74

Dated the 19 July, 1974

Governor is pleased to make the following amendments in the Rajasthan Grant-in aid to Educational Cultural Institutions, Rules, 1963 :—

(a) The following may be added after sub rule (16) of rule 3—

"Teachers who have received National and State Awards may be re employed by the aided institutions till such teachers complete 58 years Such aided institution would receive the usual grant in aid on expenditure incurred on Such teachers also "

(b) The following may be added to rule 5 (d) after the words "Local Bodies" ~

"As also the income from interest on reserve funds or rent of property "

Item (i) & (ii) appearing under rule 5 (d) may be substituted by the following —

(i) the income which accrues occasionally in the form of donations etc

[No F 7 (10) Edu/Gr, V/74 Dated the 19 July, 1974 ]

(12)

(No F (31) Edu C-6 168 Dated the 6 Sept, 1975)

I am directed to convey sanction of the Governor to the following amendments being made in this department letter No F 1 (114) Edu/Cell vi/67 dated 6-2-68 —

For para (2) of the above letter, the following may be Substituted —

"That recurring grant in aid on salaries of political sufferers who happen to work in the aided institution as Secretary and

in capacities other than teaching staff may be allowed upto age of 65 years provided they are physically fit "

This issues with the concurrence of F D (Exp I) vide their I, D No, 3801 dated 3-9-74

(13)

### कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर कार्यालय आदेश

इस विभाग के सामने इस प्रकार के कई मामले ध्यान में लाये गये हैं कि प्रदान प्राप्त सत्यायें अपने कर्मचारियों को सेवा निवृत्त आयु प्राप्त करने से पूर्व ही सेवा मुक्त कर देती हैं तथा कर्मचारी पुन सेवा में आने के लिये भी विभाग को बार-बार प्रतिबन्धन देते रहते हैं ।

अनुदान नियम 3 (16) व राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-1 (164) शिक्षा सेल-6/68 दिनांक 21-2-69 के प्रावधानानुसार अनुदान प्राप्त शालाग्रा के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु साधारणतया क्रमशः 58 व 60 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

कुछ सत्याग्रही ने यह तर्क दिया है कि नियमों में सेवा निवृत्ति की अधिकतम आयु 58 वर्ष तृतीय श्रेणी तथा 60 वर्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये निर्धारित की है अतः सत्याग्रा चाहे तो पहले भी सेवा निवृत्त कर सकती है ।

इस सम्बन्ध में राज्यादेश तथा इस विभाग के आदेश क्रमांक शिविरा/अनु/ए/160.1/33/73 दिनांक 29.1.74 स्पष्ट है फिर भी पुन स्पष्ट किया जाता है कि उक्त नियम का आशय यह कदापि नहीं है कि सत्यायें अपने कर्मचारियों को निर्धारित सेवा निवृत्ति आयु प्राप्त करने से पहले ही सेवा निवृत्त करदे, निर्धारित सेवा निवृत्त आयु के पूर्व निवृत्ति के आदेश कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप ही की जा सकती है अतः नहीं । मर्यादा ही अधिक स्पष्टि खराब होने अथवा किसी पद के समाप्त किये जाने के फलस्वरूप यदि सत्या किसी कर्मचारी को सेवा मुक्त करना चाहें तो उसके सामने राजस्थान सेवा नियम 215 के अन्तर्गत निम्न लिखित विकल्प है

1—कर्मचारी को अपने पद के अलावा निम्न श्रेणी के पद (Lower Post) पर रखने के लिए निर्देशित किया जाय ।

2—यदि कर्मचारी निम्न पद पर कार्य करने के लिये राजी भी हो तो उसे निम्न व पद श्रेणी पर नियुक्ति दी जाय तथा उस श्रेणी व कनिष्ठतम कर्मचारी की सेवायें समाप्त की जाए ?

अनुशासन ही प्रगति की सीढ़ी है ।



3—यदि किसी संस्था में एक ही प्रकार के पद स्वीकृत हैं तो उस श्रेणी में कनिष्ठतम कर्मचारी की सेवायें समाप्त की जाय न कि वरिष्ठ कर्मचारी की।

यदि अकारण बिना नियमों का अनुसरण किये कोई संस्था किसी कर्मचारी को सेवा निवृत्त आयु प्राप्त करने से पूर्व सेवा निवृत्त करती है तो वह नियम विरुद्ध माना जायगा तथा विभाग को संस्था के विरुद्ध उचित कार्रवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

[2]

(दिनांक 26-8-75)

It has been observed that some of the 'Grant in Aid' Institutions have been retiring their employees keeping in view the provisions of Rule 244 (2) of the Rajasthan Service Rules. It is pointed out that neither Rule 4 (c) nor the approved bond of Agreement as per appendix III & IV of the Grant in Aid Rules, 1963 provide for compulsory retirement of the employees of the Grant in aid Institutions. Keeping in view the said provisions, the compulsory retirement of such employees, may create complications for the institutions as well as for this Department.

It is, therefore, enjoined upon all the Grant in aid Institutions that whenever there are any serious allegations against the employees of their institutions, they should take action against them as per provisions of Rule 4 (c) and

A copy of this order may be sent to the Grant in Aid Institution under jurisdiction and they may be asked to comply with the provisions contained therein.

[15]

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर  
परिपत्र

इस कार्यालय के स्टाई आदेश संख्या 13/66 प्रमाणिक शिविरा/अनु/स/16007 विशेष/65 दिनांक 8-6-66 के अंतर्गत सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत अध्यापकों को 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त दी जाने वाली सेवा वृद्धि के बारे में विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे। तदुपरांत राजस्थान सेवा नियम 56 के नोट 1 में संशोधन हो जाने के कारण उक्त आदेश को वापिस लेते हुए अनुदान

प्राप्त सस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों की सेवा वृद्धि के लिये भविष्य में निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है।

1-31 दिसम्बर के बाद सेवा निवृत्त होने वाले जिन अध्यापकों की छानों के हित को ध्यान में रखते हुए सेवा में रखने के लिए प्रबंध समिति ने निष्पत्ति ले लिया है तथा जिनकी सेवाएं सस्था में उत्तम रही हैं उनकी सेवा वृद्धि 30 जून तक की जा सकती है।

2-ऐसे अध्यापकों के प्रस्ताव प्रति हस्ताक्षर कर्ता अधिकारी इस निदेशालय को अपनी टिप्पणी सहित भिजवायेंगे जिन पर विचारोपरांत स्वीकृति जारी तक की जायेगी।

3-अप्रशिक्षित एवं साधारण अध्यापकों के प्रस्ताव नहीं भिजवाये जावें।

4-सेवा वृद्धि के प्रस्ताव सेवा निवृत्ति के कम से कम 6-6 माह पूर्व इस निदेशालय को भिजवा दिये जावे अन्यथा समय पर स्वीकृति जारी नहीं होने के लिये निदेशालय जिम्मेदार नहीं होगा। प्रत्येक प्रस्ताव के साथ प्रार्थी का प्राथना पत्र प्रबंध समिति का प्रस्ताव व कमचारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।

अनुदान नियम 3 (16) के अन्तर्गत 58 वर्ष की आयुपरांत 60 वर्ष की आयु तक अधिवृद्धि के लिए अगर सस्था आवश्यक मानती है तो ऐसे मामले भी उचित माध्यम से उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार ही इस कार्यालय को प्रस्तुत किये जान पर ही कोई कार्यवाही की जा सकेगी। बशत कि ऐसी अभिवृद्धि के लिए कारण सतोषजनक पाये जावें।

यह आदेश निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर की पूर्वानुमति से प्रसारित किये जाते हैं।

[क्रमांक-शिविरा/अनु/७/17907/104/78/79 दिनांक 18-3-1979]

## अध्याय--9

संस्थाओं के लिए पदों के निर्धारण के संबंध में आदेश। परिपत्र

[1]

कार्यालय, अपर निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर  
परिपत्र

विषय -- अनुदान प्राप्त प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ कर्मचारियों के पद।

अनुदान नियम 1963 के परिशिष्ट 7 के अनुसार प्राथमिक शालाग्रो के लिए एक भी चतुर्थ श्रेणी कमचारी का पद नियत नहीं है तथा माध्यमिक विद्यालय में तीन से अधिक पद माय नहीं हैं लेकिन कुछ शालाएँ ऐसी हैं जो कि 1 4 63 से पहले भी अनुदान सूची पर थी और उनमें पहले से ही उपरोक्त सीमा से अधिक चतुर्थ श्रेणी कमचारी नियुक्त हैं तथा उन पर अनुदान भी स्वीकार किया जाता रहा है।

इस सम्बन्ध में महालेखाकार, रात्रस्थान, जयपुर द्वारा आडिट मापेप होने के फलस्वरूप निम्न निष्पत्ति लिया गया है जिसे लागू करने के लिए तत्काल कार्यवाही शुरू कर दी जावे —

(1) जिन माध्यमिक शालाग्रो में 1-4 63 से पहले से तीन से अधिक चतुर्थ श्रेणी कमचारी नियुक्त हैं तथा जिनके बारे में विभाग की विशिष्ट स्वीकृति (Specific Sanction) 1 4 63 के बाद नहीं ली गई है उन पर दिनांक 1 4 63 से अनुदान स्वीकार नहीं किया जायगा।

(2) जिन प्राथमिक शालाग्रो में 1-4 63 से पूर्व एक से अधिक चतुर्थ श्रेणी कमचारी नियुक्त थे उन पर भी दिनांक 1 4 68 से अनुदान नहीं दिया जायगा।

(3) जो प्राथमिक शालाएँ 1-4 63 से या उसके बाद में अनुदान सूची पर आई हैं उनमें चतुर्थ श्रेणी कमचारी का एक भी पद दिनांक 1 4 68 से अनुदान हेतु माय नहीं किया जायगा।

अतः सम्बन्धित प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारी अपने अधीनस्थ माध्यमिक व प्राथमिक शालाग्रो के चतुर्थ श्रेणी कमचारियों के पदों की जाच करके दिनांक 1 4 68 से संस्थानुसार अधिक (Surplus) होने वाले पदों का व्योरा दिनांक 29 2-1968 तक इस कार्यालय को पेश करने की व्यवस्था करें। कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति रसीद भेजें।

(क्रमांक —ईडीबी/एड/ए/16007/50/67

दिनांक 5 2 1968)

[2]

परिपत्र

अनुदान नियम 1963 के परिशिष्ट 7 के अनुसार प्राथमिक शालाग्रो के लिये एक भी पद चतुर्थ श्रेणी कमचारी का पद निर्धारित नहीं होने के कारण विभाग द्वारा विगत वर्षों में जो प्राथमिक शालाग्रो के लिये चतुर्थ श्रेणी कमचारियों के पदों पर अनुदान दिया गया था उस पर लेखा आक्षेप बन कर जनलेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ और उस प्रसंग में राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार विभाग को ऐसे भुगतान की वसूली करना संभव नहीं होगा।

माता पिता की सेवा पुत्र का प्रथम कर्त्तव्य है

अतः इस कार्यालय के परिपत्र संख्या ईडीबी/एडा/ए।16007/50/67 दिनांक 7/68 के अधिलेखन में सूचित किया जाता है कि आवश्यक अनुदान 69-70 में किना भी प्राथमिक शाला में अनुयथेष्टी कर्मचारी का कोई पद स्वीकार नहीं किया जा सकेगा अतः इन बिन्दु पर विभाग में अनावश्यक पत्राचार नहीं किया जावे।  
(क्रमांक ईडीबी/एडा/ए।16007/बी-2/69-70 दिनांक 10 2 70)

[3]

[No F 5 (d) (24) Edu Cell VI 67 Dated 4th June, 1970]  
Sub Grant in aid on the posts of Class IV Servants in  
aided Primary Schools

Sir,

In supersession of this Department letter of even number dated 14th July, 1969 I am directed to convey sanction of the Governor to treat the posts of Class IV Servants sanctioned before the Revised Grant in Aid Rules came into force, in aided primary Schools as an approved item of expenditure subject to condition that as and when such class IV employee retires, resigns or is removed, dismissed, the post shall not be filled and grant reduced.

This issues with the concurrence of the Finance Department vide their I D No 1050 dated 22 5 70

(No F 5 (d) (24) Edu Cell VI 67 Dated 4th June, 1970)

[4]

(क्रमांक एक 11(22) जिला 4/72 दिनांक 19 फरवरी 1973)

विषय — सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिपिकों के पदों का अनुदान नियमों में प्रारक्षण।

महोदय,

निर्देशानुसार लेख है कि जिन 83 सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक में एक कनिष्ठ लिपिक शिक्षा विभाग के अनुदान नियम लागू होने के पश्चात् भी चले आ रहे हैं एवं जिन पर शिक्षा विभाग अनुदान रु 1 करत प्रेषा है वो दिनांक 30 जून 1973 तक नियमित करने की र स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस अवधि के पश्चात् किमो भी र्फ नहीं दी जा सकेगा एवं अनुदान नियमानुसार हो दिया जायगा।

विपत्ति अनुप्य की कसौटी है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जो कि उनके अतिरिक्त सहायक सचिव 371 /वित्त/अध्य/1/73 द्वारा प्राप्त की गयी है, जारी की जाती है।

(अर्थात् शिविरा अनु/ए/16011/72

दिनांक 14 3 73)

[5]

(अर्थात् प स 5 (डी) (24) जिगा/6/67

दिनांक 29 जून 1973)

विषय — प्राथमिक शालाया में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वतन पर अनुदान इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 6 70 के क्रम में निदेशानुसार लेख है कि राज्यपाल महोदय ने ऐम कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में 1 4 63 के बाद परन्तु राज्यपाल 4 6 70 के जारी होने से पूर्व की गई थी के वतन को अनुदान हेतु माय समझने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इस स्वीकृति हेतु वित्त विभाग ने अपनी सहमति उनके पृष्ठान्न स 29925 दिनांक 23 6 73 द्वारा प्रदान कर दी है।

[6]

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

अर्थात् शिविरा/अनु/डी/17906/76 77

दिनांक 3 5 76

विषय — अतिरिक्त पद हेतु।

अनुदान प्राप्त सस्यामों द्वारा समय समय पर अतिरिक्त कर्मचारियों हेतु माग की जाती है। भविष्य में अतिरिक्त स्टाफ की माग माह अप्रैल में निम्नांकित परिपत्र में भरकर भेजी जाये ताकि विभागीय वार्षिक बजट में उचित प्रावधान की माग वित्त विभाग को प्रस्तुत की जा सके। जो सस्या 40 मई तक यह माग प्रस्तुत नहीं करगी उस की माग पर वष के मध्य में विचार नहीं किया जायगा। वष 77-78 की माग हेतु प्राथमिक पत्र दिनांक 30 5 76 तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए एवं भविष्य में ऐसी माग प्रतिवर्ष अप्रैल के अंत तक प्राप्त हो जानी चाहिए। माग पत्र प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत होना आवश्यक है।

परिपत्र

- 1 सस्या का नाम
- 2 सस्या स्तर जिसके लिए अनुदान मिल रहा है
- 3 प्रतिशत जिस पर सस्या को अनुदान मिल रहा है
- 4 बजट शीपक जिसके अंतर्गत प्रावधान करना है

.. ..

आलस्य भी एक प्रकार की हिंसा है।

- 5 वतमान कुल पद कैंडर वाईज (जिम पर अनुदान मिल रहा है)
- 6 अतिरिक्त पद जो चाहिये कैंडर वाईज
- 7 किम आधार पर माग की जा रही है
- 8 छात्रों की सरया गत वर्ष एव चालू वर्ष में एव कला वग के अनुसार
- 9 अतिरिक्त पदों का वर्ष भर का व्यय तथा अनुदान राशि

(1) वेतन

(2) महगाई भत्ता आदि

(3) कुल व्यय

(4) अनुदान राशि

- 10 प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारों की अभिशपा —

प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारी,

संस्था व्यवस्थापक

[7]

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर  
परिपत्र

इस कार्यालय के पूर्व परिपत्र संस्था शिविरा/अनु/डी/17006/76-77 दिनांक 3 5 76 में अनुदान प्राप्त संस्थाओं के लिये अतिरिक्त पदों के प्रापना पत्र प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्रक्रियाओं के निर्देश दिये गये थे। इन निर्देशों के साथ निर्धारित प्रापना पत्रों को क्रम सं 8 व अन्तर्गत छात्रों की सरया गतवर्ष एवं चालू वर्ष की संस्थाओं से मांगी जाती रही है। अनेक संस्थायें इस प्रकोष्ठ में जुलाई की छात्र संख्या बताते हैं जो अनुदान नियमानुसार सही नहीं है। अतः अब यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी संस्थाओं को अतिरिक्त पदों की मांग के साथ सलग्न प्रापना पत्र में छात्रों की सरया गत तीन वर्षों के माच की बतानी चाहिए। इसके अलावा अगस्त माह की छात्र संख्या की पदों का आधार नहीं माना जावेगा।

(अनाक शिविरा/अनु/ए/17907/78 79/103 दिनांक 15 मार्च 1979)

## अध्याय-10

सविष्य निधि । पी डी प्रकाश

[1]

Office of the Director of Primary & Secondary Education,

No EB/Bud/C-1/16518/18/62-63 Dated 31st October, 1962

### CIRCULAR

It has come to the notice of the Department that the aided institutions where provident fund scheme is prevalent are not following the correct Procedure of accounting for the amount of Provident contribution received from the staff as well as contribution from the Management. In some cases it has also been observed that individual accounts of the member of staff have not been opened in Banks or Post offices to deposit their Provident Fund amount in their accounts. In some cases the amount of Provident Fund is being utilised for the purposes other than those for which the fund has been started, such as utilisation of the amount of Provident Fund for the normal expenditure of the day to day activities of the institutions. It is highly objectionable and is against the Rules.

Therefore in order to regularise it, it is hereby notified for all concerned that the amount of provident fund contribution from the staff as well as from the management should be deposited in the Post Office/State Banks or any other standard Bank in the Saving Bank Account of the individual concerned. This procedure should be followed immediately if not already in vogue and the

amount so far standing at the credit of each individual should also be deposited immediately failing which the aid on the amount of Provident Fund contribution from the management will not be paid by the Department

A certificate to the effect that the individual Accounts of Provident Fund in Post Office/Banks have been opened and the amounts standing at the credit of each individual have been deposited should be sent to this office with a copy to the Inspector of Schools concerned within a month failing which finalisation of the aid for the year 1962-1963 will not be done

(NO EDB/BUD/C-1/16518/18/62-63 dated 31-10-1962)

[2]

विषय — सहायता प्राप्त सस्याओं को प्रोविडेंट फंड तथा अनुदान नियमों के अनुसार सुविधायें देना ।

ऐसी सूचनायें यदा कदा प्राप्त होती रहती हैं कि सहायता प्राप्त सस्यायें अनुदान नियम 1963 के अनुसार अपने कमचारियों को वेतन, भत्ते प्रोविडेंट फंड की सुविधायें नहीं देती । वेतन तथा भत्ते के विषय में इस कार्यालय के क्रमांक ईडीबी ए/ए/16005/16/65 दिनांक 22-8-65 के द्वारा उचित आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं ।

प्रोविडेंट फंड के सम्बन्ध में यह आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक सहायता प्राप्त सस्या के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने प्रत्येक कमचारी के नाम से भ्रमण भण्ड पोस्ट ऑफिस या बैंक में खाता खोले । केवल प्रोविडेंट फंड को धनराशि न देना पोस्ट ऑफिस में जमा करवा देना पर्याप्त नहीं है । ऐसा न करने से किसी भी स्थिति में प्रोविडेंट फंड के लिये अनुदान प्राप्त नहीं हो सकेगा ।

विभाग के सम्बन्धित अधिकारी इसका ध्यान रखें कि सहायता प्राप्त सस्याओं के कमचारियों के लिये भ्रमण भण्ड खाता खोला जाता है तथा ऐसा न करने पर प्रोविडेंट फंड के लिये किसी प्रकार का अनुदान न दिया जाय ।  
(क्रमांक-ईडीबी/ए/ए 16007 65 56 दिनांक 16-4-66)

\* आवश्यकता दुबल को भी साहसी बना देती है । टेलर



[3]

## NOTIFICATION

(No F2 (24) EduCell VI 62 Dated Jaipur, the 18th July 1967)

The Governor has been pleased to order that the following may be added as sub clause (K) to Rule 4 of the Rules for payment of Grant in aid to Non Govt Educational, cultural and physical Institutions in Rajasthan, 1963, Published in Rajasthan Gazette vide No F 2 (24) EduCell VI 62 dated 19 1 63 -

"4 (k) All aided Institutions which receive Grant in aid under these Rules shall invest (i) all moneys belonging to the Employees Provident Funds and deposits etc, including past accumulations, in State Government Securities or National saving securities viz Post Office Savings Bank Account, National Defence Certificates, or National Defence Deposit Certificates only

(ii) All the other recurring and non recurring Grants which are not needed within a period of three months, in Post office Savings Bank Account

[4]

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के स्याई आदेश स 20 (ईडीबी/एडाए/16007/27/65/67 दिनांक 31-7-1967 ई.) के विरुद्ध कुछ संस्थानों द्वारा प्रस्तुत समस्त अभिवेदनों पर विचार के पश्चात् आदेश दिया जाता है कि जिन संस्थानों ने 'छात्र कोष' का तथा कमचारियों की भविष्य निधि के पृथक् पथक् खाते खोलकर चालू वर्ष की राशि डाकखाने में जमा करवा दी है, उनके अनुदान बिलों का यथावत चुकारा जारी किया जा सकता है।

अप्य बिदुओं पर अलग से आदेश प्रसारित किये जावेंगे।

(अमाक ईडीबी/एडाए/16007/47/65/166 दिनांक 23 दिसम्बर 1967 ई०)

[5]

कार्यालय अपर निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर

स्याई आदेश स 20

राज्य सरकार की विज्ञप्ति स एफ-2 (24) शिक्षा/प्रकोष्ठ 6/62 दिनांक 18 7 67 (प्रतिलिपि सलग्न है) के अनुपालनाय निम्न विभागीय आदेश प्रसारित किये जाते हैं —

\*ईमानदारी सवधेष्ट नोति है।

1—प्रत्येक अनुदान प्राप्त सस्था के व्यवस्थापक निकटतम डाकघाने में निम्न प्रकार बचत खाते खोलेंगे —

(प्र) सस्था का 'रिजर्व फण्ड'—जो शिक्षा विभाग के प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्रकारी और सस्था के व्यवस्थापक का सम्मिलित खाता (जोइंट एकाउंट) —

इस खाते में सस्था का रिजर्व फण्ड जो नियमानुसार निर्धारित राशि से कम हो जमा कराया जायगा परन्तु (with drawal) बिना अपर निदेशक की स्वीकृति हो सकेंगे ।

(भा) सस्था का 'छात्र कोष'—व्यवस्थापक के द्वारा संचालित खाता

इस खाते में सस्था द्वारा छात्रों से प्राप्त होने वाली व सभी राशि जमा की जावे जो अनुदान हेतु भाग्य की परिभाषा में नहीं आती है और जिनका उल्लेख अनुदान प्रायना पत्र भाग-1 खण्ड-4 के कालम 20 में किया जाता है ।

भाग्य व्यय का सविस्तार हिसाब 'छात्र कोष' की रोकड वही cash book) रहेगा । 'वार्षिक भाग्य' सस्था द्वारा बनाये 'वार्षिक बजट-अनुसार खर्च की जायगा जिस मद की भाग्य हो उसी मद में व्यय की जाय । प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को बिलार पीते बाकी की सूचना आगामी वर्ष के अनुदान प्रायना पत्र के साथ निर्धारित तालिका में सलग्न की जायेगी । एक माह की आवश्यकता से अधिक राशि भाग्य मन्त्रालय कोष में न रखी जाकर इस खाते में जमा रहेगी ।

(इ) 'सस्था कोष'—व्यवस्थापक द्वारा संचालित खाता—

सस्था के नाम में सभी श्रोतों जैसे दान, धन, राजकीय आवतक व नवतक अनुदान (नियम 4 (के) (ii) से प्राप्त होने वाली राशि इन खातों में जमा होगी जिसमें प्रायना पत्र भाग 1 खण्ड 4 अ के कालम 8 व 14 में दिखाई राशि भी सम्मिलित होगी ।

(ई) सस्था के कमचारियों की भविष्य निधि (प्रोविडेंट फण्ड) के व्यक्तिगत खाते—(सस्था व कमचारियों के नाम पर सम्मिलित खाता) ।

1463 या इससे पूर्व सस्था द्वारा प्रोविडेंट फण्ड नियमानुसार लागू करने विधिस 31767 तक कमचारियों के वेतन से काटी गई या बचने योग्य राशि व सभी के समतुल्य सस्था का हिस्सा तथा ब्याज इन खातों में जमा कराया जाय । इसके बाद माहवारी किश्त हर महीने डाकघर में जमा होती रहे ।

इस आदेश की अवहेलना करने वाली सस्थाओं के अनुदान हेतु भाग्य व्यय 1967-68 से वेतन पर भाग्य राशि का 10 प्रतिशत आदेश पालन करने तक लागू रहेगा ।

\*स्वर उनकी सहायता करता है जो स्वयं अपना सहायक है ।

2 - डाकघरों में खोले गये उपरोक्त बचत खातों में से खातेदार (कर्मचारी) किसी भी समय अपनी सुविधानुसार अपनी विनियोजित (भविष्य निधि की) राशि से घन निकाल कर राष्ट्रीय बचत प्रतिभूतियों जैसे राष्ट्रीय रक्षा पत्र, राष्ट्रीय रक्षा जमा पत्र एवं अन्य राजकीय प्रतिभूतियों में इस अनुबन्ध के साथ राशि विनियोजित कर सकेंगे कि इन प्रतिभूतियों के परिपक्व होने पर जो राशि प्राप्त होगी, वापस डाकघर बचत खाते में जमा करानी होगी।

3—चू कि राज्य भाजानुसार सलग्न आदेश अनुपालन करने पर ही प्रब घोर कोई अनुदान राशि स्वीकार की जा सकेगा। अतः निम्न प्रमाण पत्र\* भवने प्रति हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के माध्यम से दिनांक 31 10 67 तक प्रेषित कर दें अथवा अनुदान प्राप्त न होने को जिम्मेदारी सस्या की ही होगी।

### प्रमाण पत्र

( अनुदान नियम 4 (के) 1963)

मैं (नाम व पता)

व्यवस्थापक (सस्या का नाम व पता)

प्रमाणित करता हूँ कि सस्या के सभी निक्षेप (Deposits) का निवेश (Investment) राज्य सरकार की विज्ञप्ति सस्या एक 22 ( 4 ) शिक्षा/प्रकोष्ठ 6/62 दिनांक 18 7 67 के अनुसार दिनांक को निम्न प्रकार से किया जा चुका है।

		दिनांक	निवेश का विवरण (रकम)		
		31 जुलाई			
क्र	स निवेश का भद	67 को	डाकखाने का	राज्य सरकार	राष्ट्रीय बचत
	(Investment)	पोते	नाम भय	की	प्रतिभूतियां
		बाकी	हिसाब	प्रतिभूतिया	
1	2	3	4	5	6

1 सस्या का 'रीजर्व फंड'

2 सस्या 'छात्र कोष'

3 सस्या का कोष

4 सस्या के कर्मचारियों की भविष्य निधि के व्यक्तिगत खातों की कुल सस्या।

\*मालस्थ दरिद्रता का दूसरा नाम है।

संस्था के प्रत्येक कमचारी के व्यक्तिगत खाने के सम्बन्ध में अलग से निम्न प्रारूप में सूचना सलग्न की जाय —

क्र.सं.	नाम कमचारी मय पिता का नाम	उत्तराधिकारी का नाम	प्रथम कटौती की तिथि
1	2	3	4
31-7-67 को खाते का पोते बाकी कमचारी का अनुदान	संस्था का अनुदान	डॉक्यूमेंट का नाम मय वसंत खाता संस्था	
5	6	7	8

(प्रमाण ईडीबी/एड/ए/16007/27/65-66 दिनांक 31-7-67 ई.)

[6]

# NOTIFICATION

NO F 2 (24) /Edu/C-11-VI/62 Dated the 4th Sept 1968

The Governor has been pleased to order that following may be added as a Note Below Rule 4 (ii) of this Deptt Notification No F 2 (24) Edu/Cell-VI/62 dated the 18th July 1967 —

Note—"Reserve Funds will be invested in the manner prescribed under 4 (k) above only if under the relevant rules the maintenance of such funds is a condition precedent for entitlement to grant in aid"

[7]

कार्यालय अवर निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राज्य की अनेक अनुदान प्राप्त संस्थाओं के पास रिजर्व फंड न होने के कारण इस कार्यालय के आदेश सं ईडीबी/एड/ए/16007/104/67 दिनांक

\*जो व्यक्ति सार्वजनिक से मुक्त है—सदैव स्वतंत्र है।

31 8 67 को अक्षरशः अनुपालना में अनुदान का चुकारा रोक दिया गया है जिससे इन सस्थाओं के अध्यापकों का वेतन देना व्यवस्थापकों के लिए कठिन हो गया है। राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति सं. एफ 2 (24) शिक्षा प्रकोष्ठ 6162 दिनांक 4 9 68 को प्रसारित की गई जिस का मूल उद्देश्य अनुदान चुकारा सम्बन्धी कठिनाईयां को दूर करना था। राज्य सरकार से इस मामले में गंभीर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि तमाम दिक्कतें दूर हो सकें।

इस सस्थाओं को व इनके अतहत काम कर रहे अध्यापकों को गंभीर अधिक कठिनाई न हो इस हेतु निम्न आदेश प्रसारित किये जाते हैं, जिनकी तुरन्त पालना की जाय -

(1) चूंकि अनुदान के नियमों में प्राथमिक एवं माध्यमिक सस्थाओं के लिए रिजर्व फंड (Reserve Fund) रखना जरूरी नहीं है, इस प्रकार की समस्त अनुदान प्राप्त सस्थाओं को अनुदान का चुकारा तुरन्त कर दिया जाय।

(2) उच्च माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शालाओं को जो कि राज्य से अनुदान प्राप्त करते हैं उनके लिए रिजर्व फंड की राशि 15000 रु व 25,000 रु क्रमशः बोर्ड के नियमानुसार रखना जरूरी है जब तक यह शत पूरी न हो जाय तब तक अनुदान का चुकारा नहीं किया जा सकता किंतु रिजर्व फंड का एकदम जमा कराना भी सस्थाओं के लिए व्यवहारिक दृष्टि से समभव नहीं है। लेकिन इस की शुरुआत की जानी नितांत आवश्यक है। इन सस्थाओं को अनुदान का चुकारा कई महीनों से नहीं हो रहा है। हर एक सस्था के अनुदान की राशि में से दो महीने का अनुदान ये सस्थाएं रिजर्व फंड में रखने को तैयार हो जाय तो इनको बाकी राशि का चुकारा कर दिया जाय व भविष्य में अनुदान का चुकारा निरन्तर किया जाता रहे। इन सस्थाओं के व्यवस्थापकों को यह भी निर्देश दे दें कि धीरे धीरे रिजर्व फंड में राशि जमा करते रहे ताकि वह कालांतर में पूरे रूप से स्थापित हो जाय।

(3) प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए भी रिजर्व फंड बनाना आवश्यक है इसलिए इनको भी जो अनुदान दिया जाना है इसमें दो महीने का अनुदान रिजर्व फंड में रखवा लिया जाय व बाकी राशि का चुकारा तुरन्त कर दिया जाय। इन विद्यालयों के व्यवस्थापकों को कहा जाय कि वे रिजर्व फंड को पूरा कायम करने के लिए धीरे धीरे राशि जमा करने रहे।

{ क्रमांक — शिविरा अनु. ए. 16007/183167168 दिनांक 27-9-68 }

[8]

कार्यालय आदेश

विभाग के बारम्बार यह ध्यान में लाया जाता है कि अनुदान प्राप्त सथायें अपने कमचारियों को यथा समय एवं पूरा भुगतान नहीं करती है तथा उनके भविष्य

\*जिना शारीरिक उन्नति के आध्यात्मिक उन्नति असम्भव है।

निधि की राशि भी समय पर टाकपर में जमा नहीं कराई जाती है जिससे उन्हें न्याय की हानि हानी है। इनके प्रतिरिक्त प्रशासनिक दृष्टिकोण से दृष्टिगत मासिक भुगतान भी कई समस्याओं द्वारा भेजे हो गये हैं। समय पर नहीं भेजे जाते हैं जिससे आवश्यकता पड़ने पर विभाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुनः प्रयास करने पड़े हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए आदेश दिये जाते हैं कि प्रत्येक विभाग सस्था को अपने अनुदान के मासिक बिलों के साथ विगत माह में सम्बन्धित त्रिमासिक सूचनाएँ सतत करना आवश्यक होगा अथवा सूचना के महत्व के अनुसार प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी उन पर अपने प्रतिहस्ताक्षर करने से मना कर सकेंगे।

परिशिष्ट 'क' सस्था के कर्मचारियों की योग्यता व भुगतान का विवरण

क्र.सं.	नाम सस्था	नाम कर्मचारी मध्य नियुक्ति तिथि योग्यता	वेतन श्रेणी	माह में चुकाए गए वेतन का विवरण		
				वेतन	डी.ए.	कुल
1	2	3	4	5	6	7
पी.एफ. की राशि टाकपर में जमा कराने का विवरण जो चुकाई गई - स्वल्प हस्ताक्षर				कर्मचारी का सस्था का जमा कराने का शब्दान, अशब्दान की तिथि		
8	9	10	11	12	13	
विशेष विवरण						
14						

प्रमाण पत्र - म (बिल पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारी व पद) प्रमाणित करता है कि उपरोक्त सूचना सस्था के हिसाब के आधारित है तथा मैंने इनका सत्यापन करने के बाद सही पाया है।  
 दिनांक \_\_\_\_\_ (हस्ताक्षर मोहर)

\*भाग खोज निकाली अथवा अपना भाग स्वयं बचाली

नोट इन आदेशों व अन्तर्गत प्राप्त नहीं होने वाले प्रथम [विल या अधिव्य में -

(1) प्रत्येक साल के माच व बिन के साथ माप्यता व निपुवन तिथि का पूरा विवरण देना आवश्यक होगा अथवा नया नाम दज होन पर केवन उमकी ही एसी सूचना देनी आवश्यक होगी ।

(2) अगर किसी कर्मचारी का भुगतान नहीं हुआ हो तो उसके भागे सक्षिप्त विवरण लिखा जाय ।

### परिमिष्ट 'स' धान विवरण माह

सत्या का नाम

क स बदा कुल धानों परिगणित पिछड़ी जाति परिगणित जन स्थलाकार अथ धानों की सरया जाति के के धाना की जाति के धाना धाना की स धानों की सत्या की सत्या की सत्या की सत्या सत्या

1	2	3	4	5	6	7	8
माह म भर्ती किये गए धानो की सत्या	माह में शाला छोड कर जाने वाले धानो की सत्या	माह की नई भर्ती के मामल में अगर नियमानुसार विभागीय अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक ही तो वह उपतन्त्र की या नहीं अगर हा तो पत्रा	बिरोप विवरण				
टी सी एपेडेविट के आधार पर							
9	10	11	12	13			

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सही है ।

प्रतिहस्ताक्षर कर्ता

(सत्या के विल पर

प्रतिहस्ताक्षर करने वाला)

पदाधिकारी

(हस्ताक्षर सत्या प्रणाल्यावर)

अवितन्त्रित वतन सत्या अधिव्य निधि की राशि के बारे में सत्या का प्रतिकूल व्यवहार प्रकट होने पर भी प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी मामले में अपनी पूर्ण रिपाट अविलम्ब इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे ।

ये आदेश तुरन्त प्रभावशील होगे ।

(अमांक ईडीबी/एडाए/16007/29/69

दिनांक 30-5-70)

\*समय पर काम करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है । पञ्चतन्त्र

[9]  
कार्यालय

(अभिव्यक्ति स्याई आदेश 20।67 में)

संस्थाओं के हिसाब की जांच के दौरान पाया गया है कि उनके विभिन्न खातों तथा रिजर्व फंड छात्रकोष। संस्था कोष, भविष्य निधि की विगत वर्षों की लेख बारी ( ) को अभी तक प्राईवेट पार्टियों से हटाकर राजाणा स एफ2 (24) गिदा प्रबोष्ट 6।62 दिनांक 18-7 67 के अनुरूप निवेश नहीं किया गया है।

बू कि राजाणा को प्रसारित हुए काफी समय गुजर चुका है तथा उसे दुबारा इस कार्यालय स्याई आदेश 20।67 के रूप में भी प्रसारित किया जा चुका था। अब एक बार पुन ध्यान में लाया जाता है कि संस्थाएं अपने विभिन्न खातों की जांच पाते बाकी का भी तुरन्त प्राईवेट पार्टिज से हटाकर उसका नियमानुसार निवेश करें अन्यथा इसे नियमों की अवहेलना की सजा देकर भावी कार्रवाही की जावेगी।

(शमाक -ईडीबी।एडा।ए।16007।स्पे 170

दिनांक 1-8-70)

[10]  
कार्यालय आदेश

विषय - अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के भविष्य निधि के मामले हेतु।

प्रायः यह ध्यान में लाया गया है कि राज्य की अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के भविष्य निधि की रकम जो डाकघर में जमा होती है उसमें से कर्ज लेने एवं खात को बंद करने हेतु इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति लेनी पड़ती है जिसमें काफी समय व्यतीत हो जाता है तथा सम्बन्धित व्यक्ति को समय पर राशि का भुगतान नहीं हो पाता है।

अतः उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में समस्त प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारियों को भविष्य में भविष्यनिधि के खाते से कर्ज दिलाने हेतु स्वीकृति एवं उसे बंद कर देने हेतु शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

(शमाक -ईडीबी।एडा।ए।160।16007।

दिनांक 12-11-71)

[11]  
(No F 2 (24)/Eud-C VI/62 dated the 31s Jan 1973 )  
Sub Depositing the P F amount in the Post Offices  
by the Institutions Governed by the Central Govt

\*उपदेश देना सरल है तदनुसार काम करना काठिन-पचतंत्र



I am directed to convey sanction of the Governor to relax the rule 4 (k) of the grant in aid Rules, 1963 for depositing the Provident Fund amount in the Post Office Saving Banks in respect of institutions the employees of which are governed by the Central Government Service Rules

This issues with the concurrence of Finance Department vide their U O No 4656/FD (Exp 1)/73 dated 27th/30th December, 1973

(No EDB/AID/G/17104/67

Dated 16-5-73)

[12]

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर  
परिपत्र

समस्त प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि महालेखा कार के जाच दल द्वारा अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कमचारियों के भविष्य निधि से सम्बंध मामलों पर यह आलेख प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी द्वारा संस्था कमचारियों की भविष्य निधि से संस्था अनुदान के डाकखाने में सम्बंधित कमचारी के खाते में जमा होने की जाच किये बिना यह राशि अनुदान हेतु स्वीकृत व्यय में सम्मिलित की जाती रही है जिसके फलस्वरूप अनेक संस्थाओं की भविष्य निधि राशि पर गलत रूप से अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है। अनुदान प्राप्ति पत्र (आवतक) के साथ माय व्यय 2000/- रु से अधिक होने पर चाटड एकाउण्टेंट प्रतिवेदन के साथ स्थिति विवरण (Balance sheet) का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक शर्त मानी गई है परंतु अधिकांश मामलों में यह पाया गया है कि बलेस शीट संस्थायें चाटड एकाउण्टेंट प्रतिवेदन के साथ सलग्न नहीं करती रही है जिससे इस कार्यालय में बलेस शीट की लेनदारी देनदारी मद में अंकित राशि के आधार पर प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी द्वारा अनियमित भविष्य निधि के माय व्यय की सायकता की जाच करना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः इस कार्यालय में आदेश क्रक ईडा बी/ए ड/ए/16003/68-69 दिनांक 26-7-68 क्रमांक डीडी/एड/ए/16001/27/65-66 दिनांक 31-7-67 स्थाई आदेश 20 की ओर ध्यान आकषित करते हुए पुनः समस्त प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारियों को आदेशा दिया जाता है कि —

\*महान् उद्देश्य वाले व्ययित को भाग्य नहीं रोक सकता।

1 उनके द्वारा प्रत्येक सप्ताह से गत पाँच वर्षों का भविष्य निधि का ब्यवहार विवरण सलग प्रपत्र में प्राप्त कर उसकी जाँच सप्ताह के रिकार्ड के आधार पर की जावे एवं इस विषय को दिनांक 31-10-73 तक इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। प्रत्येक वित्तीय वर्ष सप्ताह की भविष्य निधि राशि पर स्वीकृत अनुदान राशि का उल्लेख भी किया जावे।

2 भविष्य में बेलेस शीट चाट्टर एकाउण्टेंट प्रतिवेदन के साथ सलग होने पर ही अनुदान प्रार्थना पत्र (भावतः) को इस कार्यालय को अग्रेषित किया जावे।

3 यदि कोई मन्त्रालय अपने स्थाई कर्मचारियों के भविष्य निधि जमा नहीं करती हो तो उसका अनुदान प्रार्थना पत्र प्रत्येक स्थाई कर्मचारी के भविष्य निधि के बिल डाकघर में खोलने एवं दिनांक 1-4-73 से डाकघर में कर्मचारी व मन्त्रालय के प्रमाणित जमा किये जाने की स्थिति में ही इस कार्यालय को अग्रेषित किया जावे।

4 सप्ताह के आगामी अनुदान प्रपत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करने से पूर्व सभी प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारियों को आवश्यक होना होगा कि सप्ताह के कर्मचारियों का एक की राशि विगत माह की डाकघर में जमा करानी है और डाकघर द्वारा कर्मचारियों के स्टेटमेंट पर मोहर लगा दी है। यदि कोई सप्ताह डाकघर से प्राप्त विवरण प्रस्तुत नहीं करती है तो अनुदान बिल रोक जावे।

5 भविष्य में सभी प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारियों को यह देखना है कि अनुदान नियम 1963 के परिशिष्ट 4 (के) (ii) के अनुसार सप्ताह की सभी निधियाँ यदि दो तीन महीने से अधिक सप्ताह के पास पड़ी हुई है डाकघर में जमा होनी चाहिए अन्यथा सप्ताह की जिम्मेदारी होगी।

6 भविष्य निधि की राशि से कर्मचारी को कज दत्त समय ध्यान रखा जावे कि यह कज कर्मचारी के 3 माह के भेदन से ज्यादा नहीं हो तथा पूर्ण वकाया कज की कोई राशि शेष न हो।

अनुदान प्राप्त सप्ताहों के भविष्य निधि (पी एफ) के मामले में यदि भविष्य निधि जारी जाने पर इसका पूरा दायित्व प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का माना जावेगा क्योंकि सप्ताह के लेखा की फिनीकल चैकिंग का पूरा दायित्व प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का है। निदेशानुसार द्वारा केवल प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुतित अर्थ व्यय पर ही अनुदान स्वीकृत पत्र जारी किया जाता है।

(क्रमांक -शिविरा/अनु/ए/16011/58/73 74 दिनांक 2-6-73)

\*टीटना यह है मुख्य बात तो समय पर निकलना है।

अनुदान नियम भाग 2

( 28 )

हाकखाने का  
नाम व  
यास वुक  
का नम्बर  
6

1	कमचारी का नाम मय शैक्षणिक सभा प्रशिक्षणिक योग्यता	2	प्रप्रैष माह का वेतन ( वे + डीपी )	3	मविष्य निधि सबचो प्रपत्र मविष्य निधि की मासिक दर	4	वत्तमान वित्तीय वर्ष तक जमा राशि व्याज योग करण
5	गत मास खाते का पोते बाकी सत्या का प्रशदान	6	कमचारी का प्रशदान	7	कमचारी का प्रशदान	8	कमचारी का प्रशदान
9	कमचारी का प्रशदान	10	कमचारी का प्रशदान	11	कमचारी का प्रशदान	12	कमचारी का प्रशदान
13	कमचारी का प्रशदान	14	कमचारी का प्रशदान	15	कमचारी का प्रशदान	16	कमचारी का प्रशदान
17	कमचारी का प्रशदान	18	कमचारी का प्रशदान	19	कमचारी का प्रशदान	20	कमचारी का प्रशदान

हस्ताक्षर  
सह्याध्यवस्थापक  
(मय मुहर)

प्रतिदूताधार कर्त्ता भणिकारी  
हस्ताक्षर (मय मुहर व तिथि)  
एकाग्रता से हो विजय प्राप्त होती है ।

[13]

भविष्य निधि के नियम (अनुदान प्राप्त सस्थाओं हेतु)

[ राज्य सरकार के पत्रांक एफ 7 (13) शिष्टाग्रुप 74 दिनांक 12-11-74 के अन्तर्गत अनुमादित ]

- (1) अनुदान प्राप्त सस्थाओं में कार्य करने वाले कमचारियों के लिए यह भविष्य निधि रूप से आवश्यक है कि एक वर्ष की सेवा उपरान्त भविष्य निधि राशि की कटौती 6% बचत की दर से की जावे।
- (2) सस्था प्रबंधकारिणी समिति प्रत्येक मास कमचारी के अनुदान के बराबर अनुदान कमचारी की भविष्य निधि के खाते में जमा करेगी।
- (3) सस्था के कमचारियों की भविष्य निधि का खाता डाकखाने में कमचारी के व्यक्तिगत नाम से खोला जावे एवं प्रत्येक मास बचत भुगतान तिथि के अधिक से अधिक तीन दिन भीतर कमचारी व सस्था का अनुदान डाकखाने में भविष्य निधि रूप से जमा किया जावे।
- (4) कमचारी के भविष्य निधि अनुदान की गणना करते समय 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावे और 50 पैसे से अधिक राशि का एक रुपया मान लिया जावे भविष्य निधि राशि केवल पूरे रूपों में ही जमा की जावेगी।
- (5) भविष्य निधि के डाकखाने की पास बुक सस्था के सरक्षक में रखी जावे एवं विभागीय स्तर के समय प्रत्येक कमचारी की पास बुक को प्रस्तुत करने का दायित्व सस्था प्रबन्धनाध्यापक का होगा।
- (6) प्रत्येक अधिक वर्ष के डाकखाने में जमा भविष्य निधि का विवरण अनुदान प्रार्थना पत्र (आवेदन) के साथ निर्धारित प्रपत्र में सलग्न किया जावे (प्रपत्र 'ग')।
- (7) प्रत्येक मास सस्था को अपने विपत्र के साथ गत मास में डाकखाने में सस्था कमचारियों के भविष्य निधि में जमा राशि का डाकखाने से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस निर्धारित प्रपत्र सलग्न किया जाता है। (प्रपत्र 'ख')।
- (8) प्रत्येक कमचारी की उसकी व्यक्तिगत पास बुक प्रत्येक वर्ष मास में दिखाई जावे एवं इस हेतु कमचारी के हस्ताक्षर प्राप्त करे। यह कार्यवाही सस्था द्वारा रखे गये व्यक्तिगत भविष्य निधि का विवरण पत्रिका में की जावे।

\*स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है।

- (9) भविष्य निधि राशि के लेखा विवरण में ऋण आदि भुगतान की कायदाही सस्था सचिव, व्यवस्थापक एवं संबंधित कमचारी दोनों के हस्ताक्षर से किया जायेगा ।
- (10) भविष्य निधि के सम्बन्ध में कमचारी के अधिकार —
- (क) कमचारी द्वारा अपने भविष्य निधि के कानून अधिकारी की घोषणा सलग्न (विभाग द्वारा आयोजित प्रपत्र घ में की जायेगी ताकि कमचारी की मृत्यु या पागल होने की दशा में भुगतान सही व्यक्ति को किया जा सके ।
  - (ख) कमचारी से की जाने वाली किसी भी प्रकार की वसूली भविष्य निधि से नहीं की जायेगी ।
  - (ग) यदि कोई कमचारी भविष्य निधि जमा करने की तिथि से दो साल या इससे कम अवधि में सस्था की सेवा स्वेच्छा से छोड़ दे तो ऐसे कमचारी को प्रबंधकारिणी समिति के अश्वदान व उस पर प्राप्त ब्याज दोनों भुगतान नहीं किया जायेगा परन्तु सस्था द्वारा सेवा से हटाये जाने पर सम्पूर्ण भविष्य निधि राशि का भुगतान कमचारियों को किया जायेगा ।
- (11) (क) ऋण निम्न लिखित कि ही एक कारण पर कमचारी को तीन माह का घेतन या 50 प्रतिशत भविष्य निधि राशि (इनमें से जो भी कम हो) ऋण दिया जा सकता है —
- (1) कमचारी के आश्रित का विवाह ।
  - (2) कमचारी या उस पर आश्रित व्यक्ति के अस्त्वस्य होने पर
  - (3) कमचारी के बच्चों की शिक्षा हेतु ।
  - (4) भवन निर्माण या भवन हेतु भूमि क्रय करने हेतु ।
  - (5) कमचारी के आगे अध्ययन करने हेतु ।
  - (6) कमचारी अपने हेतु सार्दकिल आदि वाहन क्रय करने हेतु ।
- (ख) उपरोक्त किसी भी प्रकार के ऋण हेतु कमचारी विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रब व कारिणी समिति को प्राथना पत्र प्रस्तुत करेगा ।
- (ग) ऋण हेतु प्राथना पत्र प्राप्त होने पर सस्था सचिव/व्यवस्थापक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा ।
- (घ) कमचारी के घेतन के 1/8 भाग के बराबर किश्तों में ऋण का वसूली की जाये ।

\*पटना सब जानते हैं, पर क्या पटना चाहिए कोई नहीं जानता ।

- (इ) एक या दो ऋण किसी कमचारी को स्वीकृत कर भुगतान किये जाने पर ऋण राशि की वसूली प्रत्येक ऋण के  $1/24$  वें भाग प्रति माह की दर से की जावेगी।
- (च) यदि कमचारी बिना वेतन भवकाश या अर्द्ध वेतन भवकाश पर हो ता उससे ऋण की वसूली नहीं की जावेगी।
- (ख) ऋण दिये गये राशि पर 6 प्रतिशत व्याज कमचारी से वसूल कर भविष्य निधि खाते में जमा की जावें
- (ज) एक ऋण का चुकारा किये बिना सस्था दूसरा ऋण भविष्य निधि खाते से कर्मचारी को प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता की पूर्वअनुमति प्राप्त कर लिये जाने पर ही दिया जाने।
- (12) कर्मचारी के सेवा मुक्त (Retired) होने निलम्बित (Dismissal) होने पर ही भविष्य निधि का अन्तिम चुकारा किया जा सकता है।
- (13) कर्मचारी के सेवा मुक्त होने पर भविष्य निधि राशि का पूर्ण भुगतान किये जाने पर प्राप्त कर्त्ता के हस्ताक्षर (Revenue stamp) पर लिखे जाने आवश्यक हैं।
- (14) प्राप्त कर्त्ता कमचारी के भविष्य निधि का कोई claimant न होने पर निदेशक के निर्देशानुसार इस राशि का उपयोग सस्था द्वारा किया जा सकता है।
- (15) प्रतिवर्ष माह अप्रैल में सस्था को समस्त कमचारियों की भविष्य निधि का गत वर्ष का लेखा विवरण निर्धारित प्रपत्र में डाकबाने से माह अप्रैल में जारी किये गये प्राप्ति पत्र (Acknowledgement) के साथ निदेशक कार्यालय को प्रेषित करना आवश्यक होगी (प्रपत्र ग)
- (15) किसी कमचारी के एक अनुदान प्राप्त सस्था में स्थानान्तरित होने पर सम्बन्धित कमचारी की भविष्य निधि राशि को भी दूसरी सस्था के प्रबंधकारी सम्बन्धित को स्थानान्तरित किया जावेगा, स्थानान्तरण दोनों सम्बन्धित सस्थाओं की सहमति से होने पर ही ऐसा किया जा सकता है।
- (17) किसी कमचारी को प्रबंधकारिणी समिति द्वारा नियमानुसार नोटिस देकर नोटिस अवधि के वेतन भुगतान की स्थिति में नोटिस अवधि के वेतन पर भी (कमचारी व सस्था दोनों का अनुदान) भविष्य निधि राशि की कटौती की जाकर कमचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जावेगी।
- (18) 6½% से अधिक दर पर भविष्य निधि राशि की कटौती नहीं की जा सकती है और इससे अधिक कटौती को गई राशि को भविष्य निधि खाते में जमा नहीं किया जावेगा।

\*पुराना कोट पहनी और नई किताब खरीदा।

- (19) भविष्य निधि की कटौती विधिवत जारी न करने की स्थिति में सस्था का अनुदान बन्द किया जावेगा तथा सस्था की मायता को भी निरस्त किया जा सकता है ।
- (20) राज्य सरकार द्वारा भविष्य निधि पर अनुदान सम्प्राप्ति की बात-एकाउण्टेण्ट के प्रतिवेदन के साथ सलग्न की । एस मे Assets व Liabilities दोनों और भविष्य निधि का उल्लेख होने एवं अनुदान प्राप्ति पत्र (भावतक) के साथ की । एस सलग्न किये जाने पर ही स्वीकृति किया जावेगा ।
- (21) भविष्य निधि के लिये निम्नांकित रिकार्ड रखे जावे —
- (1) प्रत्येक कर्मचारी के भविष्य निधि के खाते की डाकखाने का पास बुक ।
  - (2) प्रत्येक कर्मचारी के भविष्य निधि का लेखा विवरण ।
  - (3) प्रत्येक मास डाकखाने मे जमा की गई भविष्य निधि राशि का डाकखाने से प्राप्त प्रमाण पत्र ।
  - (4) प्रतिवर्ष माह अप्रैल मे निदेशालय को प्रेषित किये गये भविष्य निधि सम्बन्धि स्टेटमेण्ट की प्रतिलिपि पत्रिका ।
- (22) भविष्य निधि राशि का भुगतान कर्मचारी को किये जाने के बाद पास बुक सस्था रखेगी ।

(क्रमांक—शिविरा।अनु।ए।16011।73

दिनांक 29-11-73)

\*प्रकार की नयी धिकारें प्रख्या, हो एक दीप जलाएँ ।

काम — (क)  
सस्था के कमचारियों की भविष्य निधि का लेखा विवरण

सस्था का नाम  
पद  
कमचारी का नाम  
वेतन श्रृंखला

माह महिने में प्राप्त वेतन पास बुक जमा की गई राशि

वेतन राशि भुगतान निधि का न

कमचारी सस्था जमा करने

द्वारा द्वारा की तिथि

7

1 2

3

4

5

प्रारम्भिक ऋण वसूली व्याज योग ऋणलेने ऋणलेने ऋणलेने अतिम प्रधाना विवरण

दिए की राशि

की तिथि

गई

का कारण

क्षेप

अध्यक्ष के

हस्ताक्षर

8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

काम — (ख)

प्रत्येक डाक खाने में जमा की गई भविष्य निधि राशि का विवरण पत्र

भविष्य निधि लेखा

वर्मांक पास बुक क्रमांक

वर्मांक का नाम

मासिक वेतन राशि

कमचारी का भुगतान

सस्था का अदान

योग

रिमाक्स

1 2

3

4

5

6

7

8

9

\*गभी घोषणियां भ रासोत्तम के, विधायक और निम्न ।



फॉर्म--(ग)  
मविष्य निधि का वार्षिक लेखा विवरण

से सम्बन्धित ।

सन् 197

स सस्था नाम	स सस्था का नाम	स सस्था का नाम	स सस्था का नाम	स सस्था का नाम	स सस्था का नाम	स सस्था का नाम	स सस्था का नाम	स सस्था का नाम	स सस्था का नाम
स सस्था का नाम	स सस्था का नाम	स सस्था का नाम	स सस्था का नाम	स सस्था का नाम	स सस्था का नाम	स सस्था का नाम	स सस्था का नाम	स सस्था का नाम	स सस्था का नाम
स सस्था का नाम	स सस्था का नाम	स सस्था का नाम	स सस्था का नाम	स सस्था का नाम	स सस्था का नाम	स सस्था का नाम	स सस्था का नाम	स सस्था का नाम	स सस्था का नाम

फॉर्म--(घ)

एतद द्वारा यह घोषित करता हूँ कि मेरे मविष्य निधि मे जमा समस्त धन राशि मेरी मृत्यु के बाद निम्नांकित मे जमा समानुसार नीचे अंकित है । भुगतान की जावे

उत्तराधिकारी की मृत्यु होने की दशा मे भुगतान

क्रमक उत्तराधिकारी का नाम व पता	कर्मचारी से सम्बन्ध	आयु	उन व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है ।	दिनांक	जमा कर्ता का नाम व पता पद
1	2	3	4	5	हस्ताक्षर

जमा कर्ता का नाम व पता पद

(1) हस्ताक्षर व पद

(2) हस्ताक्षर व पद

[14]

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर  
परिपत्र

राज्य सरकार के निगयानुसार सहायता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान नियम 4 (के) के अनुसार सुरक्षित निधि रखना जरूरी है, इस बारे में इस कार्यालय द्वारा पूर्वादेश संशिरा अनु।ए।16007/183167 68 दिनांक 27 9 68 के अनुसार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु रिजर्व फण्ड की राशि क्रमशः 15000/- एवं 25000/- रखने के पूर्व आदेश दिये जा चुके हैं। अब प्राथमिक विद्यालयों उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा माटेसरी विद्यालयों के लिए भी निम्न प्रकार से रिजर्व फण्ड की राशि सृजित करना जरूरी है।

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) प्राथमिक विद्यालय      | 2000 रु - |
| 2) उच्च प्राथमिक विद्यालय | 5000 रु - |
| 3) माटेसरी विद्यालय       | 5000 रु - |

अतः उपरोक्त स्तर वाली समस्त संस्थाओं को आदेश दिये जाते हैं कि अनुदान नियम 4 (क) तथा इस कार्यालय के परिपत्र दिनांक शिविरा/अनु।ए। 16007/123167 68 दिनांक 27 9 68 के अनुसार सुरक्षित निधि सृजित करने की कार्यवाही पूर्ण करें एवं अनुपालना इस कार्यालय को भेजें।

(नमांक-शिविरा/अनु।ए।17903/18176

दिनांक 17/6/1971

[15]

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

(नमांक — शिविरा/अनु।ए।17906/सशो/384/79—80 दिनांक 21 7 79)

विषय—अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कमचारियों के भविष्य निधि राशि को पी डी खाते में जमा करने हेतु।

विशेष शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर की विज्ञप्ति सं एफ 10/1201/शिक्षा/11/78 दिनांक 28 5 79 के अंतर्गत अनुदान नियम 1963 में निम्न प्रकार से संशोधन किये गये हैं। ये संशोधन 1 4 79 से प्रभावी होंगे —

- (1) नियम 1 का (ii) परिभाषा में उपर्याप्त (जी) नया प्रावधान जोड़ा गया है।
- (2) नियम 4 (जे) के अगले नया प्रावधान जोड़ा गया है।
- (3) नियम 4 (के) में नये भाग (i) (ii) (iii) जोड़े गये हैं।

उक्त आदेश के साथ साथ वित्त विभाग की एक आज्ञा सं. एफ 3/44/एफ 5/प्रार.ए.ए.5/आई दिनांक 16 5 79 एवं दिनांक 10 5 79 में सभी अनुदान

\*प्रत्येक कार्य किसी कारण का परिणाम है-अनु।

प्राप्त सस्थाओं के कायरत कमचारियों के भविष्य निधि खाता को पी डी खाते में जमा कराने के आदेश भी जारी किये हैं जिसके अनुसार अब दिनांक 1 9 79 से समस्त खाते राजकीय प्रतिभूति में परिवर्तित हो जाते ह । विस्तृत निर्देश इन आदेशों के साथ में सलग्न हैं

उक्त सभी आदेशों की प्रतिया आपको भेज कर लेख है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त सहायता/अनुदान प्राप्त सस्थाओं को इन आदेशों की प्रतिया उपलब्ध करावें और राज्यादेश अनुसार तुरत कायवाही के निदेश दें । यदि इस विषय में आपको कोई शका हो तो उसे मय पूरे विवरण के निम्न हस्ताक्षरकर्ता को भिजवावें, ताकि स्पष्टीकरण भेजा जा सके ।

[ 16 ]

Government of Rajasthan, Education (Cell VI) Department  
NOTIFICATION

No F 10(102) Edu/Vl/78

Dated 28 May, 1979

The Governor has been pleased to make the following amendments in the Rules for payments of Grant in aid to Non Government Educational, Cultural Physical Education Institutions in Rajasthan, 1963 —

- (1) The following may be added after sub rule (ii) (f) of Rule 1  
(g) 'Examiner' means the Examiner Local Fund Audit Department, Rajasthan, Jaipur
- (2) The following may be added as proviso to existing Rule 4 (j) ,

Provided that the institutions shall follow the directions issued by the Government of Rajasthan with regard to investment of past accumulations as well as current and future accretions to the G P F account and ancillary matters from time to time

Note —The Department/Board of Secondary Education/University /Universities to be established shall make necessary amendments in the respective rules framed by them

परिवर्तन में विश्वास करो परम्परा में नहीं

(3) The existing rule 4 (k) shall be substituted by the following —

(i) All accumulated, current and future accretions to the P F amount of the employees and contribution of the institution shall be deposited in the interest bearing personnel deposit account by the institutions in Government Treasury in the manner and as per directions laid down by the State Govt from time to time

(ii) The reserve funds and deposits etc of the institutions shall also be invested in the State Govt securities or National Savings Securities viz post office Savings Bank Account, National Defence Certificates only

(iii) All the other recurring and non recurring grants which are not needed within a period of three months shall be deposited in the post office Savings Account

Note — Reserve Funds will be invested in the manner prescribed under (ii) above only if under the relevant rules the maintenance of such funds is a condition precedent for entitlement to grant in aid

This shall come into force with effect from 1 4-1979

[ 17 ]

क्रमांक एफ 3 (44) एफ डी/आर/एण्ड आइ/79

दिनांक 16-5-79

आज्ञा

इस समय नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर विकास याता याचक मरकरी स्कूलों तथा कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में नियुक्त व्यक्तियों के भविष्य निधि खातों की धनराशि के विनियोग में एकरूपता नहीं है। फलस्वरूप अलग अलग संस्थाओं को इस राशि के विनियोजन पर अलग अलग व्याज की दरें प्राप्त होती हैं। इस उदाहरण भी सामने आये हैं जिनमें कमचारियों से प्राप्त राशि का समयावधि में जमा नहीं कराया गया है अथवा नियाजको न अपना हिस्सा निधि में जमा नहीं कराया है। कुछ दृष्टांत ऐसे भी हैं जहां स्थानीय निकाया अथवा संस्थाओं ने इस राशि से अपनी अन्य आवश्यकताएँ पूरी करली हैं। कमचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उक्त समस्त निकायों तथा

कायर तभी धनकी देता है जब सुरक्षित नहीं है।

सस्याओं के कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि को तुरन्त प्रभाव में परिग्रहित की जावे।

अतः विभिन्न स्थानीय निकाया, नगर विकास न्यासो, अराजकीय अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों आदि द्वारा इस निधि में उपलब्ध एवं भविष्य में जमा होने वाली राशि से राज्य कोष में तुरन्त जमा कराना होगा। राज्य सरकार इस राशि पर, राज्य कर्मचारियों की भविष्य निधि पर दायरे में व्याज देगी। इसके साथ इन कर्मचारियों को राज्य सरकार के प्रचलित नियमों एवं उप नियमों के समान निर्धारित उद्देश्यों के लिए ऋण अथवा प्रतिभुगतान की सहायता भी प्रदान कर दी जावेगी, परन्तु इस आहरण की स्वीकृति देने के लिए सक्षम अधिकारी पूर्ववत् अपनी अधिकारों का प्रयोग करते रहेंगे।

इस विषयक बाय प्रणाली व लेखा सम्बन्धी विस्तृत निर्देश पृथक् से जारी किये जा रहे हैं।

[18]

## GOVERNMENT OF RAJASTHAN

No F 3 (44) F D/R&AI/79 Jaipur, dated 17, May, 1979

Sub — Investment of contributory Provident Fund Monies of the municipalities, U I T Universities and Aided Educational Institutions in Interest bearing Personal Deposit Accounts with Government Treasury Instructions regarding

The Finance Department vide its order No F 3 (44) FD/R&AO/79 dated 16-5-79 has directed that the Contributory Provident Fund monies of the Municipal Councils Municipal Boards and Urban Improvement Trusts, Universities and aided Educational Institutions shall be deposited in the interest bearing F D Accounts with Government Treasuries with immediate effect. In this connection the following instructions regarding the procedure to be followed are laid down for guidance of all concerned —

### Opening of Interest Bearing Personal Deposit Account

(1) A separate Interest Bearing F D Account under Head "S Deposits and Advances (4) Deposits bearing interest 238-

क्रांतिया उत्पन्न नहीं की जाती, वे स्वयं होती हैं।

Deposits of Local Funds personal Deposit accounts for C P F of Local Bodies shall be opened by the Treasury officer on the written request of each of the Municipalities/Urban Improvement Trusts/Universities/Aided Educational Institutions under the four new heads viz

- 1 Deposit account for C P F Municipalities
- 2 Deposit Account for C P F of Urban Improvement Trusts
- 3 Deposit account for C P F of Universities
- 4 Deposit account for C P F of Aided Educational Institutions

With the District or Sub-Treasury concerned in the name of the Institution which will be termed as interest bearing C P F Personal Deposit Account of the institution concerned. An intimation of the Account opened by the Treasury Officer shall be given to the Examiner, Local Fund Audit Department. Pass book shall be supplied to each Account Holder by the Treasury Officer.

(2) The entire balance of the C P F account of the employees of the Institution comprising of their upto date subscription, institution's contribution and the interest accrued thereon after proper verification by the Head of the Institution shall be transferred to this Personal Deposit Account with immediate effect. As regards existing investment of the provident fund in Government or Government Guaranteed Securities, Fixed Deposits and/or Time Deposits in Banks and Post Offices etc. Now available with the Institutions the same shall be endorsed in favour of the District Sub-Treasury by the respective holders for credit to the P D account concerned of the Institution on maturity. Cash Balance and the amount available under the Post Office savings Bank Account or in other Bank Account

भीख मागना देश के लिए अभिशाप है—माधो ।

shall also be deposited in the District/Sub-Treasury for credit in the respective P D account. The Head of the institution concerned shall take necessary action to verify the corrections of the balances and ensure that these are credited in the respective P D Accounts.

#### Procedure for regular deposits and withdrawals

(3) The following procedure shall be followed in respect of Provident Fund subscriptions to be realised from the employees and its deposit along with the contribution by the Institutions and withdrawals —

(a) while drawing the pay bill of the staff by cash institution, the provident Fund subscription shall be shown separately in the pay-bills. The amount representing the P F subscription shall be deposited and the prescribed contribution by the Institution as per rules in force shall be deposited in the respective P D Account in the District/Sub-Treasury by means of triplicate challans not later than 2 days in any case on which the cheques representing the salary of the employees are encashed or the payment of salary is effected in cash.

(b) The respective institutions shall maintain individual P F ledger account in respect of individual employees in which the monthly subscription to P F and the contribution paid by the institution shall be credited promptly. For withdrawals from this account a separate cheque book shall be issued by the Treasury Officer to the Officer operating the P D Account.

(c) In respect of the withdrawals from the P D Account employees will be allowed to avail of the facility of the temporary and final withdrawal from the Provident Fund for the prescribed objective according to the rules and regulations of the Government respective institutions. Separate cheque in respect of such withdrawal shall be issued by the competent authority of the institution operating the account. A copy of the sanction for temporary or final withdrawal, as the case may be, shall invariably be forwarded to the Examiner Local Fund Audit Department for scrutiny at the

\*नियमों का विधान मनुष्य के लिये है। मनुष्य का निर्माण नियमों के लिये नहीं।

end of, the month the competent authority of institution sanctioning such withdrawals shall forward to the Examiner, Local Fund Audit department for scrutiny. At the end of the month the competent authority of the institution sanctioning such withdrawals shall forward a certificate to Examiner, Local Fund Audit Deptt. that all the monies withdrawn are in accordance with the sanctions issued during the month and have been disbursed to the respective beneficiary employees. The Treasury officer will ensure that the withdrawals are supported by sanctions issued by the competent authority.

#### Rate of Interest etc -

(4) At the end of each financial year, interest will be allowed on the minimum balance in the P D Account between 6th to end of individual months by the Treasury Officer at the rates to be prescribed at par with the rate allowed on G P F of Government Servants. A separate intimation for credit of interest at the end of Financial year shall be sent by the District Treasury Officer to each of the Institution. The expenditure on account of interest will be debitable to the minor head concerned below the major head 249-Interest payment-F Interest on other obligations -

1-Interest on P D Account for C P F of Municipalities

2-Interest on P D Account for C P F of U I T

3-Interest on P D Account for C P F of Universities

4-Interest on P D Account for C P F of Aided

Educational Institutions

5-The head of the Institution shall arrange to credit the interest in the respective P F Ledger account of the Individual employees on pre rate basis as per balance appearing in such individual's provident fund account.

\*चरित्रवान बनो, जयत तुम पर स्वयं भुग्ध हो जावेगा।



(6) Audit of P F Accounts maintained by Institutions and deposits & withdrawals from the P D Accounts of individual institutions with the Distt Treasuries —

(7) The examiner, Local Fund Audit Department shall arrange for the detailed audit of the C P F Accounts maintained by the Institutions concerned and examine the position of reconciliation, deposits and withdrawals from the P D Account. He will submit Budget Estimates of Receipt, withdrawals and interest payment on these accounts to the Government in Finance Deptt (Budget) on the basis of estimates obtained from the Treasury Officer.

#### Periodical returns to be furnished by Head of the Institution

(8) The Head of the Institution will furnish an initial return showing the position to the Examiner, Local Fund Audit Department within the month of the issuance of this order. This return will include information of the following points —

(1) Total number of Employees in the Institution as on the date of issue of this order

(2) Number of employees, entitled and subscribing to the Contributory Provident Fund on the above date

(3) Total accumulated amount of Contributory Provident Fund including employees subscription, employer's contribution, and interest as on above date

(4) Balance of unrecovered/outstanding temporary advances granted out of C P F beneficiary employees, as on above date

(5) Total amount transferred in the personal Deposit Account in the Treasury alongwith Challan number and date

(6) Details of term/fixed deposits, National Savings certificates and other securities endorsed in favour of the Treasury Officer concerned, showing amount, rate of interest, date of

\*यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो तो प्नेा सीया ।

maturity of each investment and periodicity of payment of interest on such securities

(B) The Head of the Institution shall furnish a monthly return by 10th of the next month to the Examiner, Local Fund Audit Department in the enclosed proforma

This issued with the concurrence of Finance Department W M ) and Finance Department (Budget)

PROFORMA OF MONTHLY RETURN TO BE SENT BY  
HEAD OF THE INSTITUTION TO THE EXAMINER,  
LOCAL FUND AUDIT DEPARTMENT, RAJASTHAN,  
JAIPUR

1 SUBSCRIBERS —

- (1) Number of subscribers on the last day of the previous month
- (ii) Number of subscribers enrolled during the month
- (iii) Number of subscribers who have ceased to pay contributions during the month on account of cessation of employment
- v) Number of subscribers on the last day of the month
- ) Total number of employees in the establishment on the last day of month
- ) Reasons for difference in the number given in (iv) and (v) above, to be appended

2 ACCUMULATIONS —

- (1) Total net accumulations as per last return
- (ii) Accumulations during the month
  - (a) Employee's subscriptions
  - (b) Employer's contribution
  - (c) Total
  - (d) Amount transferred to Personal Deposit Account

★ यमिमान नरक का मूल है—महाभारत ।

### 3 WAGES & CURRENT CONTRIBUTION —

- (i) Total amount of gross wages liable to Provident Fund contributions (Basic/Salary wage, Dearness Allowance & other allowance to be mentioned separately)
- (ii) Current contributions during the month
  - (a) Employer's Share
  - (b) Employee's share,
  - (c) Total

### 4 OTHER INCOME —

- (i) Amount received in repayment of temporary advances
- (ii) Interest recovered on temporary advances
- (iii) Amount transferred to Personal Deposit Account against (i) and (ii) above

### 5 PAYMENT —

- (i) Temporary advances
- (ii) Final claims of withdrawal
- (iii) Total

### 6 NET ACCUMULATION IN THE C P F PERSONAL DEPOSIT ACCOUNT

(This should tally with the total of the amount indicated in sub paras 2 (1), +2(ii), +4(i), +4(ii) Minus 5(iii) above)

[19]

राजस्थान सरकार शिक्षा (प्रकोष्ठ-6) विभाग

प 10 (102) शिक्षा 16178

दिनांक 20 7 79

विषय—अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि को पी डी खातों में जमा करने हेतु।

महोदय,

निदेशानुसार इस विभागीय समस्यक आदेश दिनांक 28 5 79 के क्रम में लेख है कि अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि को राज्य कोष में पी डी खातों के रूप में जमा करने की अवधि 1 9 1979 तक बढ़ाने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

★ परहित सरिस घम नहीं आई— तुलसी ।

यह स्वीकृति वित्त (ग्रार एण्ड ए आई) विभाग की सहमति आई डी सरया 423 एफाडी।ग्रार ए।79 दिनांक 18 7 79 द्वारा प्राप्त कर प्रचलित की गयी है ।

## अध्याय--11

**अनुदान प्राप्त संस्थाओं में कमचारियों की नियुक्ति करने की  
चयन प्रक्रिया संबंधी आदेश परिपत्र**

Government of Rajasthan-Department of Education

No EDB।A।d।A।16007 68।65-66

dated 26 11 65

Sub —Appointment of Trained & Qualified Staff in Aided  
Institution<sup>c</sup>

Where as an adequate number of Qualified and trained teachers is now available in all, except Science Subjects, it is hereby ordered with immediate effect that all aided institutions should appoint only qualified and trained teachers in future. This will however not apply to science teachers Appointment of under qualified and/or untrained teachers if subjects other than science will be considered for Grant in aid only if a non availability certificate to this effect is obtained from the Employment Exchange

[2]

**कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर  
परिपत्र**

अनुदान प्राप्त संस्थाओं में नियोजन हेतु प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धि की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए इस विषय में पूर्व प्रसारित पत्रांक इडी बी/

★ जीमा और जीने दा ।

अध्याय (9)

एड/ए/16007/68/65-66 दिनांक 26-11-65 में निम्न सीमा तक शिथिलन प्रदान की जाती है।

(क) अप्रशिक्षित अध्यापक जो दिनांक 1-1-69 तक नियोजित किये जा चुके हैं उनके तथा सस्था के सस्थापकों से इस आशय का घोषणा पत्र कि अध्यापक आगामी तीन वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा, उन पर हुए व्यय को अनुदान हेतु माय किया जाता रहेगा।

(ख) छोट बस्वों में प्रशिक्षित अध्यापिकायें सुलभ नहीं है अत अप्रशिक्षित अध्यापि कामों की नियुक्ति की जा सकती है लेकिन एक लात्व व उससे अधिक सस्था वाले नगरों में अध्यापिकाओं के लिए भी नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित होना आवश्यक होगा।

प्रत्येक सस्था के व्यवस्थापक अनुच्छेद (क) के अनुपालन में उचित प्रायना पत्र भिजवावें, ताकि उन्हें ध्यान में रखते हुए उनके अनुदान में से की गई अप्रशिक्षित अध्यापकों के वेतन से सम्बन्धित कटौतियों को निस्तारित किया जा सके।

[क्रमांक — ईडीबी/एड/ए/16007/238/67 दिनांक 11 6 68]

[3]

परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र सं ईडी बी/एड/ए/16007/238/67 दिनांक 11-6-1968 के अतगत अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं के नियोजन से सम्बन्धित विभागीय नीति स्पष्ट करत हुए कहा गया था कि 1-1-69 तक नियोजित अप्रशिक्षित अध्यापकों के मामलों में इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर कि वे आगामी तीन वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे, विभाग उनका वेतन से सम्बन्धित अनुदान में से की गई कटौतियों को निरस्त करके अनुदान स्वीकार कर लेगा। पर तु ऐसे घोषणा पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

अत एक बार पुन' सभी सस्थाओं के ध्यान में लाया जाता है कि वे कृपया समुचित घोषणा पत्र तथा अपने अभिवेदन इस परिपत्र की प्राप्ति के 15 दिन की अवधि में भिजवाने की व्यवस्था करे अन्यथा उसके बाद अप्रशिक्षित अध्यापकों के वेतन से सम्बन्धित अभिवेदना पर कोई विचार नहीं किया जायगा।

[क्रमांक — ईडीबी/एड/ए/16007/स्पेशल/67 दिनांक 30-8-69]

[4]

परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र सं ईडी बी/एड/ए/16007/238/67 दिनांक 11-6-1969 के सद्वर्ग में प्रशिक्षण के मामलों को लेकर कुछ सस्थाओं ने कठिना

\*अनुप्य की दुशहानी उसकी सचचरित्रता का फल है।

इसकी धारा ध्यान आकर्षित किया है जो कि व्यावहारिक होने के कारण पूरा ।  
म निम्न सशोधन किया जाता है —

1 जो अध्यापक/अध्यापिकाएँ सब धित प्रशिक्षण के लिए निर्धारित अविकलम  
आयु सीमा पार कर चुके हैं तथा 1-12-65 से पूर्व सवारत है उह ट्रेनिंग के  
शर्तों से मुक्त किया जाता है लेकिन सम्बन्धित वेतनमान में जो ट्रेनिंग की ई वी  
होगी वह उस सम्बन्ध में बनाय गये नियमों की पूर्ति पर ही पार का जा सकेगी ।

2 दिनांक 1-12-65 से पूर्व नियुक्त जो अध्यापक/अध्यापिका प्रशिक्षण में  
प्रवेश की आयु पार नहीं कर चुके हैं अगर यूनतम शैक्षिक योग्यता कारण नहीं कि  
हुए हो तो उन्हें पहले यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के लिए उचित समय  
दिया जाकर फिर प्रशिक्षण के लिए बल दिया जाय ।

3 1-12-65 से 31-12-68 तक नियोजित सभी अध्यापक/अध्यापिकाओं  
के लिए 30-6-72 तक प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा । अतः जो शैक्षिक  
योग्यताओं की कमी के कारण ऐसा करने में असमर्थ है उह सम्बन्धित शैक्षिक  
योग्यता व प्रशिक्षण दोनों निश्चित अवधि में प्राप्त करने का नोटिस दिया जाय ।

( क्रमांक — ईबीडी/एडाएफ।16007।स्पे।67

दिनांक 17.1.1970 )

[5]

परिपत्र

( क्रमांक — ईबीडी/एडाएफ।16007।71

दिनांक 7.9.74)

विषय — अनुदान प्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों की नियुक्तियाँ अनुमोदन

ऐसा करने को आया है कि अनुदान प्राप्त संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति

के अनेक मामले बहुधा अपूर्ण प्राप्त होते हैं । अधीनस्थ अधिकारी या तो संस्थाओं  
के मूल पत्र सलग्न कर देते हैं या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्तिक कार्यालय आदेश को  
प्रति सलग्न कर इस कार्यालय का अनुमति देने हेतु भेज देते हैं । इस तरह से प्राप्त  
हुए पत्रों में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं । फलस्वरूप सूचना के अभाव में  
पुनः इन कार्यालय से या तो पूछा जाता है या मामला लौटाया जाता है । इसमें  
अनावश्यक पत्र व्यवहार में समय नष्ट होता है । अतः भविष्य में इन मामलों में  
शीघ्रता जाने हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं जिनके आधार पर मामले  
इन कार्यालय में प्रस्तुत किये जाएँ ।

1 नियुक्ति नियोजन कार्यालय द्वारा भेजे गये प्रार्यियों में संकीर्ण है या  
विनापन द्वारा की गई है ।

2 नियुक्ति के लिए कितने प्रार्थी साक्षात्कार के लिए आये उनकी पूरी सूची  
में पूर्ण योग्यता, कार्य अनुभव एवं अन्य विवरण । साक्षात्कार के समय बनाय गए  
मूल्यांकन शीट की प्रतिलिपि साथ में भेजी जाय ।

\*श्रेष्ठ जीवन ही सबसे बड़ा धर्म है ।

4 सस्था की व्यवस्थापन समिति द्वारा नियुक्ति का प्रस्ताव एवं चयन समिति के सदस्यों का नाम भी लिखा जावे। यह देखा जावे कि चयन समिति में विभागीय प्रतिनिधि की हस्तियत से कोई अधिकारी उपस्थित रहा अथवा नहीं। विभागीय अधिकारी की अनुपस्थिति में चयन किये गये कर्मचारी के मामले को ग्रहण न किये जावे।

5 प्रत्येक नियुक्ति पर, सस्था से निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्राप्त की जावे जिसमें, कर्मचारी का नाम, जन्म तिथि, योग्यता, पूर्ण अनुभव, नियुक्ति का पद, वेतन मय वेतन श्रृंखला नियुक्ति तिथि रिक्त स्थान की उपलब्धि। निर्धारित प्रपत्र का नमूना संलग्न है।

6 अध्यापक की ज्यादातर नियुक्तियां जुलाई और अगस्त के बीच में होती हैं, अतः सभी सस्थानों से प्राप्त मामले एक स्टेटमेंट में दर्ज करके उक्त पूर्ण विवरण सहित एक साथ इस कार्यालय में 31 अगस्त के बाद में भेजे जावें। विशेष मामले पहले भेजे जा सकते हैं।

7 कर्मचारी के त्याग पत्र के कारण हुए रिक्त स्थान पर नियुक्ति का विनियम स ध्यान में रखते हुए यह प्रमाणित किया जावे कि त्याग पत्र देने वाला व्यक्ति बिना किसी दबाव या पूव में लिख गये त्याग पत्र के कारण छोड़कर नहीं गया है। त्याग पत्र देने की तिथि और उसके नियमानुसार नोटिस समय का वेतन देने की भी विशेषतया निर्धारित प्रपत्र के अन्त में टिप्पणी होना जरूरी है।

8 जिस विषय के अध्यापक पद का रिक्त स्थान हुआ है, उसी विषय के दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति का मामला विचारार्थ भेजा जाय।

#### प्रपत्र

संस्कृत का नाम	चयन समिति के सदस्यों का नाम	रिक्त पद मय वेतन श्रृंखला	सामाजिक में चयन किये गये व्यक्ति का नाम	
			व्यक्तियों के क्रमानुसार नाम	
1	2	3	4	5
जन्म तिथि	योग्यतापूर्ण अनुभव	नियुक्ति तिथि	वेतन मय श्रृंखला	रिक्त स्थान का उपलब्धि के कारण सेवानिवृत्त/सेवा समाप्ति। त्याग पत्र
6	7	8	9	10

त्याग पत्र पर हुए रिक्त स्थान  
में पूर्व नियोजित कमचारी का नाम

क्या वह सस्था से  
त्याग पत्र देकर  
गया है ।

टिप्पणी

11

12

13

[6]

### स्थायी आदेश सा 3

विषय — अनुदान प्राप्त सस्थाओं में अध्यापक एवं अन्य अतिरिक्त पद स्वीकृत करने के सम्बन्ध में—

समस्त अनुदान प्राप्त शिक्षण सस्थाओं तथा प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारियों का ध्यान इन कार्यालय के परिपत्र क्रमांक इडीवी/एड ए/16007/111174 दिनांक 4-9-71 की धारा आकषिप्त किया जाता है कि जिसमें मे निदेशन दिए गए थे कि अध्यापक एवं अन्य अतिरिक्त पद स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रकरण एक निर्धारित समय में भेजे लेकिन इस धारा कोई ध्यान न देकर ऐसे प्रकरण वप के अत तक भेजे गये । जिन पर कार्यवाही करना न तो उचित था और न ही समयाभाव और अन्य कारण वश इन पर विचार किया जा सका । अब इस सत्र अर्थात् 72-73 एवं भविष्य के लिए यह आदेश दिये जाते हैं कि समस्त सस्थाएं अपने विद्यालय में छात्र सरपा के वृद्धोत्तरी के फलस्वरूप तथा अतिरिक्त वग (section) खालने की विभागीय अनुमति प्राप्त करने पर स्टाफ के अतिरिक्त पदों की माग के प्रस्ताव प्रत्येक सत्र के माह अगस्त के अत तक प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे वयाकि शिक्षा सत्र एक जुलाई से शुरू होगा और इसी माह के अत तक छात्रों का पूर्ण रूप से प्रवेश का कार्य समाप्त हो जाता है । अत अतिरिक्त पदों की माग के लिए उनकी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी ।

अतिरिक्त वग खोलने की अनुमति देने के लिए सम्म अधिकारी अनुदान नियम 1963 के परिशिष्ट 4 के क्रम सं 4 के अनुसार हाने । प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी अपने जिले के ऐसे माते प्रकरणों की जाच कर अपनी उचित तथा विस्तृत अभिशपा इस कार्यालय को दा माह अर्थात् अक्टूबर तक अनश्य प्रस्तुत करेंगे ताकि एम प्रकरण एक बार में ही तय किया जा सन । प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी प्रकरणों में अलग अलग तथा टुकड़ा (piece meal) में भेजेगे लेकिन अक्टूबर के अत तक भेज जा सकेगे । ताकि ऐसे प्रकरणों पर समय पर उचित कार्यवाही की जा सके प्राय अंतिम रूप से इस विषय के प्रकरण नवम्बर तक निरटाय जा नके । उक्त निधि के वान किमी भी सस्था के एस प्रकरणों पर विचार नहीं किया जायगा ।

(क्रमांक — इडीवी/एड/ए/16007/23172 73

दिनांक 9 > 72)

★ विनय पानता प्रदान करती है ।



[7]

स्थाई आदेश सं 4/22

ममस्त अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का भ्रष्टा इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक एबीडी/एड/एफ/16007/16 दिनांक 7-9-71 की ओर आर्क्षित किया जाता है जिसमें अन्तर्गत यह निबंदन दिया गया था कि अध्यापक तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति का विभागीय अनुमान केन आवश्यक है जो केवल प्रशामनिक विदु से ही आवश्यक नहीं है अतः अनुदान नियम 1963 के परिशिष्ट-5 (पॉर) की पालना के लए भी आवश्यक है। लेकिन 70-71 के अनुदान प्राप्ता पत्र के अतिमीकरण की जाच करते समय यह पाया गया है कि अनेक संस्थाओं द्वारा अध्यापक तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति की विभागीय अनुमान प्राप्त नहीं किया है जो अव्याख्यनीय है। अतः यह पुनः आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त परिपत्र में दिये गये निद शना की अनुपालना किया जाय। इस आदेश की अवतना करनी वाली संस्थाओं को सत्र 72-73 तथा अविष्ट म ऐसी नियुक्तियों पर राजकीय अनुदान स्वीकृत नहीं किया जावेगा। नियुक्ति के अनुमान हतु सक्षम अधिकारी अनुदान नियम 1963 के परिशिष्ट पाच के अनुसार होंगे। जो निम्न प्रकार से है —

निदेशक — 1 वरिष्ठ अध्यापक एवं उससे उच्च पद पर नियुक्त अध्यापकों की नियुक्ति।

2 शोध अधिकारी, सहायक अन्य विशेष श्रेणी की नियुक्ति।

संयुक्त निदेशक (महिला) / द्वितीय ग्रेड अध्यापक तथा वरिष्ठ लिपिक

उपनिदेशक।

विद्यालय निरीक्षक/का तृतीय श्रेणी अध्यापक, वरिष्ठ लिपिक तथा विद्यालय निरीक्षिका चतुर्थ श्रेणी कमचारी

नियुक्त संस्थानों सूचना संस्था द्वारा निम्नलिखित प्रपत्र में प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के कार्यालय में नियुक्ति के 15 दिन के भीतर भीतर प्रस्तुत करेंगे और प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी प्रकरण की जाच कर म तस अधिकारी के कार्यालय में एक पक्ष के भीतर भीतर प्रस्तुत करेंगे।

( ज्ञान ईडीबी/एड/एफ/16007/128/72-73 दिनांक 12-5-72

[8]

स्थाई आदेश सं 5172

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि प्रायः अनुदान प्राप्त संस्थाओं के व्यवस्थापक अपने कमचारियों को एक वर्ष की नियुक्ति देते हैं तथा मंत्र की समझौता

प्रपत्र पृष्ठ 48 पर देखिये।

★ प्रसन्नता ही स्वास्थ्य है और मलीनता ही राग।

के दिन बिना कारण बताये सेवा मुक्त कर देते हैं या एक माह का नोटिस देकर पद से हटा देते हैं। ऐसा वे सम्भवतया शोष्मावकाश का वेतन बचाने हेतु करते हैं। कुछ सस्थायों अग्रेज सत्र में भी पुनः उन्हें सेवा में रख लेती हैं। अकारण सेवामुक्त होने से अध्यापका में असन्तोष होना स्वाभाविक है क्योंकि वे शोष्मावकाश के वेतन से वंचित रहते हैं तथा उन्हें पिछले वर्ष की सेवा का लाभ आगे के वर्ष में नहीं मिलता।

सम्बन्धित व्यवस्थापका को आदेश दिया जाता है कि रिक्त पदों पर नियुक्ति का एक वर्ष का परिविक्षाकाल पर ही एवं वर्ष उपरान्त नियुक्ति स्थाईकरण का आदेश प्रसारित कर इस विभाग के सूचित किया जाये। परिविक्षाकाल की माप्ति पर केवल वे ही व्यक्ति सेवा मुक्त किये जा सकते हैं जो या तो स्थानापन्न रिक्त पद पर नियुक्त किये गये हों अथवा जिनका कार्य एवं व्यवहार में तोषजनक न रहा हो जिन व्यक्तियों का कार्य एवं व्यवहार सतोषजनक न हो। उन्हें नियमानुसार कारण बताकर नोटिस दिया जाना चाहिए तथा व्यवस्थापक समिती को जिस बैठक में सम्बन्धित सेवा मुक्त करने का निर्णय लिया जावे उसमें विभागीय प्रतिनिधि को बुलाना आवश्यक है। नियुक्ति के समय नियुक्ति सम्बन्धी इस कार्यालय परिपत्र ईडी बी।एडाएफ।16007/76 दिनांक 7-9-71 का पूर्णतः पालन करना आवश्यक है। इस आदेश की अवहेलना करने पर नियुक्तियाँ अनियमित समझी जावेंगी एवं उनके वेतन की राशि पर अनुदान नहीं दिया जायेगा।

विद्यालय निरीक्षक कृपया देखेंगे कि इन आदेशों का पालन उचित प्रकार से हो रहा है तथा अध्यापका को अनावश्यक रूप में सत्राभुक्त नहीं किया गया है और यदि सम्बन्धित नियमों का समुचित पालन नहीं करती तो उसकी मायता समाप्त की जा सकती है तथा अनुदान कम या बढ़ किया जा सकता है।

[शमाक-शिविरा ईबीडी/एड/एफ।16007/15/72/73 दिनांक 17-5-1972]

[9]

स्थायी आदेश 6172

विषय — अनुदान प्राप्त सस्थाओं में अध्यापका की नियुक्ति के सम्बन्ध में

अनुदान प्राप्त पत्रों की जांच करते समय प्रायः यह देखा गया है कि अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अप्रशिक्षित अध्यापका की नियुक्तियाँ की जाती हैं और विभाग द्वारा समय समय पर प्रमाणित आदेशों की अवहेलना की जाती है। सम्बन्धित अनुदान प्राप्त सस्थाओं का नव नियुक्ति के हेतु विभागीय आदेश दिनांक 9-7-69 का पूर्णतः पालन करना एवं नियुक्ति का अनुमोदन सक्षम विभागीय अधिकारी द्वारा

★ हम कोई धोखा नहीं देते, हम स्वयं अपने आपको धोखा देते हैं।

प्राप्त करना आवश्यक है। जिसे अनुमान प्राप्त नियुक्ति या अनियमित समझी जायेगी एवं इस प्रकार नियुक्त अधिकारियों के वेतन व्यय पर अनुदान नहीं दिया जायेगा। प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति रीति पर। हनु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये जाये साथ इस हेतु पूर्व विवरण विज्ञान बायानय को दार उतरना माने जाये प्राप्त प्राप्ति पत्र का विवरण मन्त्र प्रत्यक्ष तयार किया जाये। चयन समिति का गठन किया जाना जिसमें एक विभागीय अधिकारी अध्यक्ष सम्मिलित हो किंग हनु आदेश क्रमांक इडीडी/एड/एफ/16007/123171 72 दि 12-5-72 द्वारा सूचित किया जा चुका है। चयन विवरण पत्र अनुमान मन्त्र अधिकारी का पत्र पर सम्भालने की तिथि के दा माह भीतर प्रस्तुत किया जाये। अगर दो माह की अवधि में चयन विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो ऐम पदा पर अनुमान देन में कटिनाई होगी। प्रशिक्षित अध्यापक प्राप्त न हान पर रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अप्रशिक्षित अध्यापकों को अस्थाई नियुक्ति नियोजन बायानय द्वारा अनुमान प्रमाण पत्र प्राप्त हान पर ही की जाये। इस सम्बन्ध में निम्न रिवाज रचना आवश्यक होगी।

(क) नियोजन अधिकारी को भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि।

(ख) नियोजन अधिकारी से प्राप्त उत्तर की प्रति।

(ग) साप्ताहिक हनु भेजे गये निम्न पत्र की प्रति।

(घ) प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र।

(ङ) चयन समिति के सदस्यों की नामावली।

(च) चयन समिति की बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारी का नाम एवं पद।

(छ) चयन एवं अनुमान विवरण पत्र।

नियुक्ति हेतु व्यक्तियों का चयन विवरण पत्र

प्रार्थी का नाम	पद जिसके हेतु	योग्यता	अनुभव	चयन समिति
(इसमें समस्त साक्षात्कार के	साक्षात्कार के			द्वारा दिये गये
आ 100 वर्तमानों	लिए बुलाया	शक्षणिक प्रशिक्षण		अ क
व नाम अ कित	गया	(इसमें प्रशिक्षण व		
किये जायेंगे)		प्रशिक्षण अ क		
		लिये जाये)		
1	2	3	4	5

नोट — चयन समिति द्वारा अ क दिये जाने का मापदण्ड संक्षेप में लिखा जाय।

[क्रमांक—इडीडी/एड/एफ/16007/136/12-73 दिनांक 16/11-5-73]

★ पाप पाप का मूल है—तुलसा।

[10]

स्थायी आदेश 61/72 में संशोधन

सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति सम्बन्धी विस्तृत निर्देशन जो इस कार्यालय के स्थायी आदेश स 6-72 क्रमांक ईबीडी/एड/एफ। 60071/36/72-73 दिनांक 17.5.72 के अन्तर्गत प्रसारित किये गये हैं, व निर्देशन अध्यापकों के साथ साथ सहायता प्राप्त संस्थाओं में अथवा सभी पदों की नियुक्तियों के लिए लागू होगा।

[क्रमांक — ईबी डी/एफ/एड। 60071/2172 73/49 दिनांक 25.5.72]

[11] परिपत्र

अनुदान प्राप्त संस्थाओं को आदेश दिया जाता है कि किसी भी वार्षिक या साप्ताहिक समाचार पत्र में अध्यापकों तथा माध्यमिक स्तर के पदों हेतु विज्ञापन प्रकाशित करते समय निम्न सूचनाएँ अवश्य दी जाए —

(क) पद का नाम

(ख) पद हेतु अपेक्षित योग्यताएँ शैक्षणिक एवं प्रशासनिक

(ग) पद की भेदन शृंगार

(घ) पद हेतु अपेक्षित अनुभव या अथवा योग्यता सम्बन्धी आवश्यकताएँ।

(ङ) द्वितीय भेदन शृंगार के स्नातक परीक्षा के विषय सम्बन्धी सूचना यदि आवश्यक है।

विज्ञापन व्यय पर अनुदान स्वीकृति हेतु निम्न प्रमाण प्रस्तुत किये जायें —

(अ) विज्ञापन की कतरन जिसमें समाचार पत्र का नाम एवं प्रकाशन तिथि के प्रमाण हो।

(ब) प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत विपत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि।

(स) प्रकाशक द्वारा भुगतान के पश्चात् प्रदत्त रसीद की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि।

यह भी आवश्यक है कि विज्ञापन दो ऐसे समाचार पत्रों में दिए जाएं जो परिचालन के आधार पर राज्य स्तरीय रूप में जाएं।

उपरोक्त निर्देशन की अवहेलना या अनुपालना में अभाव में विज्ञापन में व्यय की गई राशि पर अनुदान स्वीकृत करना सम्भव नहीं होगा।

(क्रमांक ईबीडी/एड/एफ। 6007 71-22 दिनांक 31.7.72)

[21]

स्थायी आदेश 40/72

अनुदान नियम 1963 धारा 3 (14) के अन्तर्गत वार्षिक प्रशिक्षित अध्यापकों को अनुदान प्राप्त संस्थाओं में स्थायी रूप में नियुक्ति करने का प्रावधान है। इस

★ सच्चा मिन वह है जो कि समय पर काम आये।

कार्यालय के परिपत्र ईडीबी/एड/ए160071238167 दिनांक 11.7.69 द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापक जो दिनांक 1-1-69 तक नियोजित किए जा चुके थे उन्हें आगामी तीन वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर देने पर ही उनके उत्तम ध्येय पर अनुदान देय था तथा इस कार्यालय के समसूचक परिपत्र दिनांक 17.1.70 द्वारा अनुदान प्राप्त सस्थाओं में नियोजन हेतु प्रशिक्षित अध्यापकों की उपनविक्र के कठिनाईयाँ का ध्यान में रखते हुए एक लाख से कम आवासी वाले कस्बों की शिक्षा सस्थाओं में अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति का प्रावधान है। यह प्रावधान 30.6.72 तक ही प्रभावी समझा जाये।

अब विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अनुदान प्राप्त शिक्षण सस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति विभागीय स्टाई आदेश 6172 दिनांक 17.5.72 की अपालना करत हुए की जावे। नये शैक्षणिक मंत्र में समाचार पत्रों में अध्यापक पत्रों हेतु विशासन प्रकाशित करने तथा नियोजन कार्यालय से भी प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध न होने की स्थिति में चयन समिति द्वारा चयनित प्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति केवल एक शैक्षणिक सत्र के लिये ही की जाय तथा यदि नियुक्ति 31 दिसम्बर के पूर्व तिथि की हो तो सस्था द्वारा ऐसे अध्यापकों की ग्रीष्मावकाश का बेलन भुगतान करना आवश्यक है परन्तु अध्यापक का सेवाकाल 30 जून को स्वतः समाप्त माना जाये। नियुक्ति करने वाले अधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र में हो इस बात का समावेश कर दिया जावे।

विभाग द्वारा प्रसारित अध्यापकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी पूर्व आदेश में कोई शिथिलता देना सम्भव नहीं है।

समाक — ईडीबी/एड/ए1601117273

दिनांक 10.8.72

[12]

परिपत्र

विभागीय स्टाई आदेश सं 6172 दिनांक 17-5-72 के अनुसार अनुदान प्राप्त सस्थाओं के स्वीकृत पदों पर नव नियुक्ति हेतु सस्था द्वारा चयन समिति गठित करना आवश्यक है। समिति में एक विभागीय प्रतिनिधि भी सम्मिलित किया जावेगा विभिन्न स्तर की सस्थाओं द्वारा निमित्त चयन समिति द्वारा विभिन्न श्रेणी की नियुक्ति हेतु निम्न विभागीय अधिकारियों का विभागीय प्रतिनिधि नियोजित किया जाता है—

नियुक्ति पद का नाम	सस्था का नाम	नियोजित विभागीय अधिकारी
1-प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक शिक्षक प्रशिक्षण महा तथा अन्य पद	विद्यालय	संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (पुरुषोत्तमगढ़ी)

\*जननी और जन्मभूमि स्मरण से भी बढ़कर है।

- उच्च माध्यमिक विद्यालय सशुक्त निदेशक।उप निदेशक  
2 प्रधानाचार्य।प्रधानाध्यापक (पुरुष।महिला) तथा विद्यालय  
उच्च माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक कया विद्यालय  
निरीक्षिका
- 3-प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय निरीक्षक/क या विद्या  
प्रोन्नताइ जिग मेकेटरी (1) मा यमिक निरीक्षिका तथा प्रधानाचार्य  
विशिष्ट सस्थाप्रा के अ य पद विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय  
(2) विशिष्ट सस्थाएँ  
(3) केन्द्रीय कार्यालय
- (4) वरिष्ठ अध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य तथा प्रधानाध्यापक  
उच्च माध्यमिक विद्यालय
- 5-द्वितीय वतन श्रु खला (1) माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक  
अध्यापक तथा प्रयाग (2) उच्च प्राथमिक विद्यालय विद्यालय तथा विद्यालय  
शाला सहायक (3) मोटेनरी उप निरीक्षक  
(4) अय विशिष्ट सस्थाएँ
- 6-तृतीय वतन श्रु खला सम्बन्धित सन्ध्यायें विद्यालय अवर उप निरीक्षक  
अः ३३ (एस0 डी0 आई)
- 7-लिपिक बग सम्बन्धित सन्ध्यायें विद्यालय उप निरीक्षक

विभागीय अधिकारियों को इस योजना की समुचित ढंग से कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में निम्न निर्देशन दिये जाते हैं ।

1—उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य।प्रधानाध्यापक की नव नियुक्ति हेतु प्रत्येक र न के संयुक्त निष्पन्न उप निदेशक (महिला।पुरुष) द्वारा अपने श्रव के अनुदान प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालय की सूची बनाली जावे तथात्मन स सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक विद्यालय निरीक्षिका स विचार विमर्श कर इन शिक्षण सन्ध्याया को उपरोक्त काय हेतु आस मे बाट लिया जाव और सम्बन्धित सन्ध्याया का इसकी सूचना प्रेषित करणी जाव । इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित कर दी जाव ।

2—केन्द्रीय कार्यालय के ओगनाइजिंग मेकेटरी की नव नियुक्ति हेतु विद्यालय निरीक्षक तथा कया विद्यालय निरीक्षिका द्वारा अपने अधीनस्थ निरीक्षणा लय का समस्त अनुदान प्राप्त सन्ध्याया की सूची बनाली जाव, तथा प्रत्येक सन्ध्या

\*प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का विधाता है ।

के लिए इस कार्य हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को नियोजित कर लिया जावे। निरीक्षणालय के समीपस्थ विद्यालय हेतु स्वयं ही विद्यार्थी निरीक्षक यह कार्य करेंगे। नियोजित अधिकारी एवं सस्या को यह सूचना प्रेषित करदी जावे।

3—चरिष्ट अध्यापक की नव नियुक्ति हेतु विद्यालय निरीक्षणालय विद्यालय निरीक्षक द्वारा निरीक्षणालय के समस्त अनुदान प्राप्त सस्याओं की सूची बनानी जावे। निरीक्षणालय निरीक्षक द्वारा चयन समीपस्थ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्यको को इस कार्य हेतु नियोजित किया जाय। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक तथा सस्या की तत्सम्बन्धी सूचना प्रेषित करनी जावे।

4—द्वितीय चेतन शृंगला अध्यापक तथा प्रयोगशाला सहायक की नव नियुक्ति हेतु विद्यालय निरीक्षणालय विद्यालय निरीक्षणालय द्वारा निरीक्षणालय के समस्त अनुदान प्राप्त शिक्षण सस्याओं की जिनमें द्वितीय चेतन शृंगला एवं प्रयोगशाला सहायक पद स्वीकृत हो सूची बनानी जावे। उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय उप निरीक्षणालय के विद्यालय निरीक्षक का इस कार्य हेतु नियोजित किया जावे। सम्बन्धित सस्या तथा अधिकारी की तत्सम्बन्धी सूचना प्रेषित की जावे।

5—तृतीय चेतन शृंगला अध्यापक की नव नियुक्ति हेतु निरीक्षणालय का समस्त अनुदान प्राप्त सस्याओं की सूची बनानी जावे तथा विद्यालय अथवा उप निरीक्षक को इस कार्य हेतु नियोजित किया जावे और तत्सम्बन्धी सूचना शिक्षण सस्याओं का प्रेषित करदी जावे।

6—यदि किसी शिक्षण सस्या की नव नियुक्ति चयन समिति विभिन्न पदों हेतु सप्ताहवार एक ही दिन कर तो इस हेतु उच्च पद हेतु नियोजित अधिकारी का ही कार्य पदा के चयन हेतु भी विभागीय प्रतिनिधि माना जावेगा। प्रत्येक पद हेतु नियोजित अधिकारी से इस चयन समिति की बैठक में सम्मिलित हान हेतु पत्र व्यवहार न किया जावे।

7—अनुदान प्राप्त सस्याओं के विभिन्न प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारी के कार्यालय में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र की अनुदान प्राप्त सस्या के अध्यापक या शिक्षक तथा अन्य कर्मचारियों के चयन हेतु सस्या के समीपस्थ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को विभागीय प्रतिनिधि नियोजित किया जावे।

8—अनुदान विषय पर प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारी अपने क्षेत्र का समस्त शिक्षण एवं अन्य सस्याओं हेतु नियोजित अधिकारियों की सूची इस कार्यालय को सितम्बर 30, 1972 तक प्रेषित करें। यह सूचना निम्न प्रपत्र में भर कर प्रेषित की जावे -

\*नियम अनुच्छेद का सबसे बड़ा उपकार करता है।

## प्रपत्र

नियोजित अधिकारी का पद एवं पता	शिक्षण संस्था का नाम	नियुक्ति स्तर
-------------------------------	----------------------	---------------

अनुदान प्राप्त संस्थाओं को आदेश दिया जाता है कि संस्था द्वारा नव नियुक्ति सम्बंधित पत्र व्यवहार सीधे सम्बंधित विभाग द्वारा नियोजित अधिकारी से ही किया जाय। नव नियुक्ति का विभागीय अनुमोदन सामान्यतया तभी किया जावेगा जबकि चयन समिति की बैठक में विभागीय प्रतिनिधि भी उपस्थित रहा हो, अतः चयन समिति की बैठक की तिथि सम्बंधी सूचना विभागीय अधिकारी को कम से कम 15 दिन पहिले दी जाये तथा आवश्यक हो तो विभागीय प्रतिनिधि की सुविधानुसार चयन समिति की बैठक की तिथि निश्चित की जावे। चयनित कर्मचारी की नियुक्ति अनुमोदन पत्र के साथ साथ उपरोक्त आदेशानुसार निर्धारित मूल्यांकन प्रपत्र पर चयन समिति के समस्त उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इस निर्देशन की अवहेलना करने पर ऐसी चयनित नव नियुक्ति का अनुमोदन सम्भव नहीं होगा। इस हेतु समस्त अनुमोदन वर्त्ता अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि नियुक्ति अनुमोदन के समय मूल्यांकन प्रपत्र पर विभागीय नियोजित अधिकारी के हस्ताक्षर होने की स्थिति में ही नव नियुक्ति का अनुमोदन किया जाव।

(क्रमांक ईडीबी/एड/ए/16011/12/72/73

दिनांक 16 अगस्त 1972)

[14]

स्थायी आदेश सं 5172 में मशौघन

इस कार्यालय के स्थायी आदेश सं 5172 तम सं ईडीबी/एड/ए/16007 135172-73 दिनांक 17-5-72 में सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में एक वर्ष के परीक्षाकाल में नियुक्त अस्थाई कर्मचारियों का सेवा समाप्ति के नियम में जो निर्देशन पूर्व में दिये गये हैं उनके लिये निम्न संशोधन किया जाता है —

सभी स्थायी कर्मचारियों की सेवाये हेतु उनके परीक्षाकाल की समाप्ति पर संस्था प्रबंध कारिगार समिति द्वारा अनुदान नियम 1963 के परिशिष्ट-3 धारा (1) व (8) अनुसार ही कार्यवाही की जाव। अनुदान नियम 1963 के परिशिष्ट 3 के अनुसार परीक्षाकाल एक वर्ष से कम तथा दो वर्ष से अधिक नहीं माना जा सकता है। यदि नियुक्ति पत्र श्रवण शतनामा में उक्त नियम के विपरीत, प्रावधान है तो ऐसा प्रावधान नियमों के विरुद्ध माना जाएगा एवं इसका अन्वयक के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

(क्रमांक — ईडीबी/एड/ए/16012/143/72

दिनांक 3-11-72)

\*जिनमें समय नष्ट किया उसको समय नष्ट कर दगा।



## [15] परिपत्र

1 अनुदान नियम 1963 परिशिष्ट 3 की धारा (8) व (10) में अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के क्रमशः परिवीक्षण काल में तथा स्थाई नियुक्ति पर सेवा मुक्त होने पर संस्था तथा अध्यापक द्वारा की जाने वाली कायवाही का प्रावधान है। परिवीक्षण काल में नोटिस अवधि हेतु एक माह तथा स्थाई कमचारी का नोटिस अवधि का तीन माह तक की वेतन राशि संस्था को भुगतान करने का प्रावधान है। नोटिस अवधि के लिए अध्यापक से वसूल की गई राशि को संस्था की आय मानने का प्रावधान भी अनुदान नियमों में है। इस प्रावधान के अंतर्गत समस्त अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं का आश्रय दिया जाता है कि वह अध्यापक से वसूल की गई नोटिस अवधि के वेतन राशि का उल्लेख अनुदान प्राथना पत्र एवं चाटर्ड एकाउंटेंट रिपोर्ट दोनों में करें। अनुदान हेतु इस राशि का वह प्रतिशत जो संस्था के अनुदान हेतु निर्धारित है संस्था की स्वीकृत अनुदान राशि से कम कर दी जावेगी जिससे कि अध्यापक से नियमांतगत वसूल की गई राशि संस्था की आय का स्रोत बन सके। इन नियमों के विरुद्ध सेवा मुक्त किये गये कमचारी के नोटिस अवधि के वेतन को इसी नियम के अंतर्गत संस्था की आय मानी जावेगी और इसकी अनुपालना में समुचित ढंग से न किये जान का ग्राह्यत्व संबंधित संस्था का होगा।

2 अनेक भविष्य निधि मामले विभाग के सम्मुख प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें संस्था की मंदा छोड़ने पर अध्यापक को उसकी भविष्य निधि राशि का भुगतान नहीं किया जाता रहा है। संस्था इस प्रकार प्राप्त राशि को अनुदान हेतु अपनी आय लेखा विवरण में प्रदर्शित करती रही हैं। अनुदान प्राप्त संस्थाओं के भविष्य निधि संबंधी नियमों का राज्य सरकार में स्वीकृत होकर प्रकाशित होने तक समस्त अनुदान प्राप्त संस्थाओं को आदेश दिया जाता है कि वे इस प्रकार प्राप्त राशि का उल्लेख अपने अनुदान प्राथना पत्र में अवश्य करें। अध्यापक एवं संस्था के अंशदान पर दी गई अनुदान राशि को संस्था की आय मानी जावेगी तथा इस राशि की स्वीकृत अनुदान राशि से कम कर दिया जा सकता है जिससे इस प्रकार प्राप्त धन राशि संस्था की आय में होकर सरकार की आय होगी जिससे कि ऐसा मामला में कमी हो सके जिससे कारण अनुदान प्राप्त संस्था का छोड़ने से अनावश्यक रूप से अध्यापक या अथवा कमचारी का आर्थिक कष्ट एवं संस्था व अध्यापक के बीच विवाद उत्पन्न हो जाते हैं।

3 प्रायः यह देखा गया है कि कुछ अनुदान प्राप्त संस्थाएँ निर्धारित प्रपत्र में रसीद प्राप्त न कर लेटर पेड के माध्यम पर रसीद प्राप्त करती हैं। अनुदान हेतु इस प्रकार की वित्तीय रसीद की राशि को माय धन्य स्वीकृत न किया जावे। निर्धारित

रसीद जिसमें नम्बर भी नियमानुसार अंकित हो की ही अनुदान हेतु स्वीकृत व्यय माना जाये।

4 अनुदान प्राप्त सस्थाभा में काय करन वाले उन कमचारियों का जिह नियमानुसार आय कर आयकर विभाग में जमा कराना आवश्यक है आदेश दिया जाता है कि वह अपने आय कर रिटनस का भरे जिसमें वाद में आयकर में उपलब्ध रिक्वाड के आधार पर किसी द्वारा आयकर जमा न करने की स्थिति न पाये तो सब घित कमचारी को दण्ड का भागी न होना पड। प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त अनुदान प्राप्त सस्थाभा में कायरत आयकर देने वाले कमचारियों की नामावली की सूची वषवार एक रजिस्टर में रखने जिससे कि आवश्यकता पडने पर यह रिक्वाड सरलता से उपलब्ध किया जा सकें।

5 नोटिस अवधि की अध्यापक/कमचारी से वसूल की गई धन राशि भविष्य निधि के मामले जिसमें अध्यापक/कमचारी को भविष्य निधि का भुगतान न किया गया है, के संबंध में प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी अपने कार्यालय में रिक्वाड रखेंगे।

[16]

[अमाक--ईडीबी/ए/ए/16011/66/72 दिनांक 22-11-72]

स्थाई आदेश 1 (1973),

अनुदान प्राप्त सस्थाओं के कमचारियों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित नियमों की अनुपालना की जावे —

(1) चयन समिति का गठन —

शिक्षण सस्थाओं के चयन समिति में विभागीय प्रतिनिधि एवं शिक्षण सस्था के प्रधानाध्यापक सहित पांच सदस्य रखने का प्रावधान किया जावे।

(2) प्रथम चयन समिति का गठन प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा इस आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर किया जावे एवं इस समिति के सदस्यों की नामावली दो माह के भीतर प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को प्रेषित की जावे।

(3) चयन समिति का गठन करते समय प्रबन्धकारिणी के सदस्यों को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा 10 दिन का नोटिस दिया जावे ताकि सभी सदस्य समिति की बैठक में भाग लेकर चयन समिति के सदस्यों के नियोजन या चुनाव में सम्मिलित हो सकें।

4 चयन समिति का कार्यकाल सस्था प्रबन्धकारिणी समिति के कार्यकाल के साथ ही समाप्त समझा जावे। चयन समिति के रिक्त पद पर नियुक्ति रिक्त पद होने के तीन माह भीतर अवश्य की जावे।

5 चयन समिति का कोई सदस्य विभागीय प्रतिनिधि के अतिरिक्त, यदि

\*अध्ययन हमें आनन्द प्रदान करता है।

चयन समिति में लगातार दो बैठक में सम्मिलित न हो सके तो उसका चयन समिति में अलग कर उसने स्थान पर तब सदस्य को नियुक्ति करने की कार्यवाही की जावे।

6 चयन समिति का बोरम 3 सदस्यो तक का होगा इससे कम सदस्यों की उपस्थिति में किया गया चयन अनियमित माना जायगा।

7 किसी पत्रकारी के नियुक्ति के संबंध में अप्रति 4 आवश्यक कार्यवाही मर्यादा व्यवस्थापक/मन्त्री करेंगे एव चयन तिथि से चयन समिति को अवगत कराना भी उसी का दायित्व होगा।

8 सीधी नव नियुक्ति के संबंध में निम्न विधि एवं शर्तों की अनुपालना आवश्यक है —

1 विभागीय स्टाई आदेश 6/72 दिनांक 17 5 72 एवं दिनांक 10 8 72 के अनुसार रिक्त पदा हेतु विनापन प्रकाशित करना जिला नियोजन कार्यालय से प्रत्याशी सूची प्राप्त करना आवश्यक है।

2 किसी अनुदान प्राप्त संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारी का आवेदन पत्र अनुदान नियम 1963 के परिशिष्ट 3 (14) के अनुसार प्राप्त किया जावे ऐसे मामलों में संस्था व्यवस्थापक आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र प्राप्ति से एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित अधिकारी को अवगत करें।

3 प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर प्राप्ति सत्यापन कर एक पत्रिका में दर्ज कर लिया जावे। प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता मध्य श्रेणी एवं अनुभव भी प्रत्याशी के नाम के मम्मू दज किये जाये। यह पत्रिका का स्टाई रिकार्ड माना जाये। चयन हेतु कम से कम तीन गुने प्रत्याशी बुलाये जाने चाहिए। चयन समिति के बैठक के कम से कम 10 दिन पूर्व संस्था व्यवस्थापक चयन समिति के सदस्यों एवं प्रत्याशियों को रजिस्टर्ड पास्ट द्वारा साप्ताहिक हेतु निर्धारित स्थान तिथि एवं समय से अवगत करेंगे।

4 साक्षात्कार हेतु बुलाये गये प्रत्येक प्रत्याशी के सम्बन्ध में संक्षिप्त रूप से शैक्षणिक व प्रशासनिक योग्यता अनुभव आदि विवरण चयन के समय प्रत्येक चयन समिति के सदस्यों को उपलब्ध किया जावे, चयन प्रत्याशी की शैक्षणिक व प्रशासनिक योग्यता अनुभव की जांच करने के पश्चात् मूल्यांकन चाट बनाकर किया जाये। चयन समिति तीन व्यक्तियों के नाम मूल्यांकन चाट के आधार पर अनुशंसित करे। चयन के मूल्यांकन चाट पर चयन समिति के उपस्थित सभी सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

5 चयन समिति के सदस्यों के सम्बन्धी प्रत्याशी होने की स्थिति में ऐसे सदस्य को चयन समिति की ऐसी बैठक में न लिया जावे। सदस्य के सम्बन्ध में

★ इसकी कल्पना भी मत करो कि अवसर तुम्हारे द्वार पर दुबारा आवेगा।

निम्न व्यक्ति शामिल है। पिता, माता, श्वशुर, मामा, तथा पुत्र, चाचा पोता, जामाता, भाई, पुत्री पोता, पोती, पत्नी दादी, भतीजा चाचा जात भाई (पैत्रिक व मात्रिक) साले, साला, बहनोई, जेठ, ननद, पति, पुत्रवधू बहिन, सास, चाची आदि।

4 (ब) चयन समिति द्वारा दिय गए अ को का आधार मूल्यांकन चाट, के नीचे नोट के रूप में अंकित किया जाय।

9 विभागीय अनुमोदनाथ सूचना प्रेषित करते समय निम्न सूचना प्रेषित करना आवश्यक है -

1 नाम

2 जन्म तिथि

3 पता

4 शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यता परीक्षा का नाम परीक्षा प्राप्त करने का वर्ष, परीक्षा लेने वाली संस्था का नाम श्रेणी, परीक्षा के विषय (एवं विशेषयोग्यता)।

5 मह शैक्षणिक प्रवृत्ति।

6 अध्यापक अनुभव पद जिस पर कार्य किया गया वेतन, सेवा प्रवेश व मुक्ति तिथि।

10 किसी पद हेतु प्रत्येक या समस्त प्रत्यागी विवरण जिनके नाम पर साक्षात्कार हेतु विचार किया गया हो। विभाग द्वारा मागे जान पर, प्रस्तुत किये जाने का पूर्ण दायित्व संस्था का होगा।

1 नियुक्ति पत्र संस्था व्यवस्थापक, मंत्री के हस्ताक्षर द्वारा चयनित व्यक्ति को रजिस्टर्ड पान्ट द्वारा प्रेषित किया जावे। नियुक्ति पत्र में वेतन, वेतन शृंखला परिधीमाकाल और नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद 15 दिन की अवधि तक संस्था में अपना कार्य भाग न सभालने की स्थिति में दूसरा स्थान प्राप्त व्यक्ति की नियुक्ति किया जावे।

12 (अ) परीक्षार्थी कर्मचारी से अनुदान नियम 1963 में परिशिष्ट 2 (1) के अनुसार सभालन के दो माह तक एग्जीमेट भर लिया जाने का पूर्ण दायित्व संस्था व्यवस्थापक/मंत्री का होगा।

(ब) संस्था द्वारा प्रत्येक कर्मचारी से सलग्न प्रपत्र अपेक्षित सूचना प्रार्थी के ईष्ट राइटिंग में प्राप्त कर ली जा। एवं नव नियुक्त कर्मचारियों के इस रिकार्ड की एक प्रतिका बनाली जावे। विभागीय अधिकारी के संस्था निरीक्षण के समय इस फाईल को प्रस्तुत करने का पूर्ण दायित्व संस्था प्रधान या शिक्षण संस्था प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापिका का होगा। इस रिकार्ड के अभाव में संस्था के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। संस्था के पुराने कर्मचारियों का यह रिकार्ड 30.4.73 तक पूरा कर लिया जाय। प्रपत्र का प्रारूप सलग्न है कृपया अनुमोदन करने का कष्ट करें।

\*असफलता निराशा का सूत्र नहीं अपितु नई प्रेरणा का स्रोत है।

13 विभागीय आदेश दिनांक 7 9 72, स्थाई आदेश 6/72 दिनांक 11 5-72 एवं परिपत्र दिनांक 16 8 72 के अनुसार सक्षम विभागीय अधिकारी द्वारा नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। नियुक्ति अनुमोदन सम्बन्धी कायवाही माह्र मकदूर तक पूरी करली जावे। अनुमोदनाथ चयन समिति के मूल्यांकन खाते को प्रस्तुत करना एवं अनुमानाथ प्रस्तुत किये जान वाले प्रपत्र में अध्यापक द्वारा परीक्षाओं में प्राप्त श्रेणी (डिवीजन) एवं इस प्रमाण की सत्यापन प्रतिलिपि सलग करना आवश्यक है।

14 यदि सक्षम अधिकारी किसी नियुक्ति का अनुमोदन नियुक्ति सम्बन्धित कार्य प्रणाली में कभी रहने के कारण नहीं करे तो वह अनुमोदन न करने के कारण से सत्याध्यक्ष/अधीक्षक को अवगत करेगा। द्वितीय व तृतीय चयन श्रेणी अध्यापकों का अनुमोदन उच्च अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है।

15 किसी पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता वाले प्रत्याशी प्राप्त न होने पर विभागीय आदेश दिनांक 10 8 72 के अनुसार कायवाही की जावे।  
(क्रमांक — शिविरा/अनुए/16011:102/72 दिनांक 6 10 73)

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

कार्यालय अवर निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

प्रार्थी का पासपोर्ट साईज  
फोटो जिसको प्रतिहस्ताक्षर  
कर्ता अधिकारी अपनी मुहर  
सहित एटेस्ट करेगा

(1)

(अ) पद का नाम जिस पर नियुक्ति हुए है।

(ब) सत्याध्यापक का नाम व पता

..

(स) चयन श्रेणी

(2) प्रार्थी का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

★ बुरी आदत से हमारी सुदृढ़ता प्रकट होती है।

(3) डाक का पूरा पता

(4) जिले का नाम जिसके आप स्थायी निवासी है

(5) जन्म की सही तिथि तथा मृत्यु प्रमाण

(6) स्थायी पता (ग्राम, नगर डाकखाना जिला, राज्य का उल्लेख करें)

(7) नीचे उन स्कूल और कालेजों के नाम अंकित करें जिनमें आपने शिक्षा पाई है —

विद्यालय व महाविद्यालय	विश्वविद्यालय	वर्ष जिसमें	
		प्रवेश किया	त्याग किया

(8) नीचे हाई स्कूल या उसके समान परीक्षा से लेकर सम्पूर्ण विश्वविद्यालय सम्बन्धी परीक्षाओं जिसमें सफल हुए हो या प्रशिक्षण जो प्राप्त किया हो —

परीक्षा या डिग्री	श्रेणी	विषय	परीक्षा में उत्तीर्ण होने का वर्ष	दिया हुआ प्रमाण
-------------------	--------	------	-----------------------------------	-----------------

(9) यदि आप पहिले से ही काम में लगे हो तो उसका विवरण नीचे दें —

पद का नाम	नियोजक नाम	पद सम्भालने की तिथि	पद छोड़ने की तिथि	दिया हुआ प्रमाण
-----------	------------	---------------------	-------------------	-----------------

(10) प्रार्थी की हस्ताक्षर युक्त घोषणा—

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस प्रार्थना पत्र की ममस्त प्रतिया मेरी पूरी जानकारी तथा विश्वास से सत्य है तथा मेरा निवास स्थान राज्य में है।

दिनांक                      संस्था व्यवस्थापक                      कर्मचारी के हस्ताक्षर (महामोहर)                      हस्ताक्षर

★ अशुद्धि से पूर्व सदैव ही अक्षर होता है।

(11) सस्था द्वारा यह प्रायना पत्र प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी की प्रस्तुत किया जाये। वह निम्न सत्यापन अंकित करें —

(1) प्रार्थी के फोटो पर हस्ताक्षर कर अपने पद की मुहर अंकित करें।

(2) प्रमाणित करें कि निम्न हस्ताक्षर प्रार्थी द्वारा उसके सम्मुख किये गये।  
प्रार्थी के हस्ताक्षर

(1)

दिनांक

(2)

(3)

प्रमाणित किया जाता है कि यह हस्ताक्षर मेरे सामने किये गये।

दिनांक

प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी  
के हस्ताक्षर  
(मय मुहर)

[17]

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर  
परिपत्र

अनुदान समिति द्वारा गठित निरीक्षक दल द्वारा जयपुर की अनेक शिक्षण सस्थाओं के निरीक्षण प्रतिवेदन में अनेक सुझाव विभाग को प्रस्तुत किये गये हैं। इस वर अनुदान प्रायना पत्र (भावतक) की इस कार्यालय में जाँच करते समय यह देखा गया कि निरीक्षण दल द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार अय स्थानों पर भी कार्यवाही करना आवश्यक है। अतः समस्त प्रतिहस्ताक्षरकृत अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि यह अपने अधीनस्थ समस्त शिक्षण सस्थाओं की नव नियुक्ति हेतु सस्था चयन समिति की बैठक में अवश्य उपस्थित हों। यदि निर्धारित तिथि को-कारणवश उपस्थित होना सम्भव न हो तो इसकी सूचना सस्था और विभाग दोनों को दी जावे तथा सस्था को अपनी सुविधानुसार दूसरी तिथि निर्धारित करने हेतु लिखा जाव। सस्था को बिना सूचित किये या बिना कारण चयन समिति की बैठक में अनुपस्थित रहने की स्थिति में विभागाध्यक्ष प्रतिनिधि के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए विभाग का बाध्य होना पड़ेगा। विभागीय प्रतिनिधि का दायित्व है कि वह योग्य प्रत्याशी के चयन में सस्था का मांग दर्शन करे। चयन समिति की बैठक में विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थिति को केवल औपचारिक कार्यवाही न माना जावे।

★ मस्तिष्क के लिए अध्ययन की उतनी ही आवश्यकता है जितनी शरीर को व्यायाम की।

समस्त अनुदान प्राप्त सस्थाओं को आदेश दिया जाता है कि ये नव नियुक्ति हेतु विभागीय आदेशों का पूरा अनुपालन कर तथा विभागीय प्रतिनिधि को विधिवत चयन समिति की बैठक की तिथि की सूचना यथा समय प्रेषित करे तथा चयन समिति में विभागीय प्रतिनिधि के अनुपस्थिति रहने पर इसकी सूचना प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी एवं निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्रेषित की जावे। विभागीय प्रतिनिधि के बिना कारण ही चयन समिति की बैठक में अनुपस्थित रहने की दशा में प्रत्याशियों को नियुक्ति की अनुमोदन करना सम्भव नहीं होगा तथा नियुक्ति अनुमोदन व अभ्यास में एस नियुक्त कमचारी के वेतन ध्यय पर अनुदान अस्वीकृत किया जायेगा। पूर्व प्रसारित आदेशों के स दम में सस्थाओं को पुन सूचित किया जाता है कि वह चयनित व्यक्ति की नियुक्ति अनुमोदनार्थ मामला सक्षम अधिकारी को चयन के दो माह के भीतर प्रस्तुत करने की व्यवस्था करे। चयन के दो माह पश्चात अनुमोदनार्थ प्रस्तुत मामला पर भविष्य में कायवाही करना सम्भव नहीं होगा। अनुमोदनार्थ मामला प्रस्तुत किय जाने पर दो माह तक सक्षम अधिकारी द्वारा कोई कायवाही न किय जाने की स्थिति में रजिस्टर्ड पत्र द्वारा निदेशालय को वस्तु स्थिति स अवगत किया जावे, ताकि निदेशालय द्वारा ऐसे मामलों पर आवश्यक कायवाही की जा सके।

प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारियों को किदेश दिये जाते हैं कि वह सस्था द्वारा नव नियुक्ति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत मामला को प्राथमिकता देकर अनुमोदन जारी करने की व्यवस्था करे। इस प्रकार जारी किये गये नियुक्ति अनुमोदन आदेश की एक प्रति अनुमोदित नियुक्ति से सम्बंधित शक्षणिक एवं प्रशक्षणिक योग्यता प्रभाग की सत्यापित प्रतिलिपि सलग्न कर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा निदेशालय को सूचनाय एवं आवश्यक कायवाही हेतु प्रेषित किये जाये। शक्षणिक सन 1971-72 एवं 1972-73 के चयनित कमचारियों की चयन समिति की बैठक में विभागीय प्रतिनिधि के आमंत्रित किये जाने का प्रमाण सस्था द्वारा प्रस्तुत किय जान एवं विभागीय प्रतिनिधि के सूचना प्राप्त होने पर भी चयन समिति की बैठक में अनुपस्थित रहने की दशा में ऐसे चयनित कमचारियों की नियुक्ति का अनुमोदन जारी करने का आदेश नियमों में शिथिलन करते हुए दिया जाता है परंतु एम मामले जुलाई 1973 तक निपटा लिये जाये और इसकी सूचना निदेशालय को प्रेषित की जावे।

(क्रमांक — शिविरा.अनु.ए।16911/19/73 74

दिनांक 1-5-73)

[18] स्थाई आदेश स 4/1973

इस कार्यालय के स्थाई आदेश स 10/72 क्रमांक ए/16011/1/72 दिनांक 10-8-72 के क्रम में सहायता प्राप्त सस्थाओं में निवाजित प्रशिक्षित

★स्वाध्याय स सस्ता कार्ड मतारजन नही।



अध्यापकों के सम्बन्ध में जो आदेश दिए गए थे, संस्थाओं की कठिनाइयों की एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को ध्यान में रखते हुए पूर्व आदेश में शिथिलता किया जाता है । निम्नलिखित निदेश दिए जाते हैं —

1. सहायता प्राप्त संस्थाओं के प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारियों द्वारा सम प्रशिक्षित व्यक्तियों की एक सूची (मेरिट लिस्ट) प्रतिवर्ष बनाई जाती है। भविष्य में अब इन विद्यालयों में रिक्त स्थानों की पूर्ति इसी सूची में से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा की जायेगी। जब भी संस्था की अध्यापक की आवश्यकता होगी तो सीधे जिला अधिकारी का अपनी मांग (Requisition) पत्र करेंगे तथा जिला अधिकारी अपने द्वारा बनाई गई सूची में से मेरिट के आधार पर संस्था के पद के लिए व्यक्ति का नाम की निश्चित करेंगे। इन्हीं में से अध्यापक को नियुक्त करना संस्था के लिए आवश्यक है तथा उनकी नियुक्ति हेतु चयन समिति के अनुमोदन की भी आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को विभागीय अनुमोदन ही समझा जाये।

2. विज्ञान विषय के अध्यापकों की कमी को देखते हुए अब यह निर्देश दिया जाता है कि उनकी नियुक्ति अप्रशिक्षित होने पर बड़ी प्रक्रिया होगी जो पूर्व में निश्चित की जा चुकी है। अतः किन्हीं दो गमाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन तथा चयन समिति द्वारा उसका चयन व विभाग द्वारा अनुमोदन आवश्यक है।

3. कला व वाणिज्य विषय के पदों के लिए जिन्हा अधिकारी से अनुपलब्धि प्रमाण पत्र ( एन ए सी ) प्राप्त कर नियुक्ति की जा सकती है। प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी ऐसे अभ्यासियों के उपलब्ध नहीं होने पर ही नियुक्ति की स्वीकृति हेतु अभिशपित किया करेंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया वही होगी जो विभाग द्वारा पूर्व में निश्चित की गई है। अर्थात् पद को विकसित करने प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी से अनुपलब्धि प्रमाण पत्र ( एन ए सी ) प्राप्त करेंगे तथा चयन समिति से चयन करा कर विभाग से अनुमोदित करावेंगे।

4. वे पुराने अप्रशिक्षित अध्यापक जो दिनांक 1-9-61 के बाद व 1 12 65 से पूर्ण नियुक्त थे तथा अब भी सेवाशक्त हैं, यदि उनकी आयु 30-6-73 को 40 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन्हें नियम नुसार प्रशिक्षण से मुक्त किया जाता है। किंतु एम कर्मचारियों के वेतन का राजकीय विद्यालयों के लिए लागू नियमों के समानांतर ही वेतन का स्थिरीकरण किया जायेगा। इस अवधि में नियुक्त अप्रशिक्षित अध्यापक जिनकी आयु दिनांक 30-6-73 को 40 वर्ष से कम है, का आगामी तीन मास के भीतर अर्थात् 30 6 76 तक प्रशिक्षण प्राप्त करना परमावश्यक होगा। इस अवधि तक इन्हें अनुदान हेतु वेतन माया किया जायेगा। दिनांक 30 6 74 के बाद जो अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेंगे उनके वेतन को इस

★ आपत्तियां सबसे बड़ा शिक्षक है—पंचतंत्र।

तिथि के बाद किसी भी स्थिति में अनुदान हेतु माय नहीं किया जाएगा तथा सस्था द्वारा इनकी सेवा समाप्ति के फलस्वरूप विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

5 ऐसे प्रशिक्षित अध्यापक जो दिनांक 1-12-65 के बाद व दिनांक 1-1-69 से पूर्ण नियोजित है, को आगामी तीन उप अर्थात् 30-6-76 तक हर हालत में प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। अथवा इनका वेतन किसी भी स्थिति में अनुदान हेतु माय नहीं होगा। सस्था द्वारा इनकी सेवा समाप्ति के फलस्वरूप विभाग पर कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

6 ऐसे प्रशिक्षित अध्यापक जो दिनांक 1-1-69 के बाद नियोजित होंगे, उनके अनुदान पर वे ही निदेशन लागू होंगे जो पूर्ण में प्रसारित किये जा चुके हैं, अथवा इस आदेश में सन्निहित है।

(क्रमांक — शिविरा/अनु/ए/16011/40/73-74 दिनांक 28-5-73)

### [19]

स्थाई आदेश 4/73 के क्रम में

स्थाई आदेश 4/73 में सहायता प्राप्त शिक्षण सस्थाओं में नव नियुक्तियों की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसके पूर्व नव नियुक्ति हेतु जो आदेश समय समय पर प्रसारित किये जाते रहे हैं, वे यथावत रहेंगे अर्थात् पद विज्ञापित करना, जिला नियोजन कार्यालय के माध्यम से आशार्थी बुलाना चयन समिति के द्वारा चयन किया जाना, चयनित व्यक्ति का विभागीय अनुमोदन प्राप्त करना इत्यादि प्रक्रियाएँ पूर्ण करनी हैं। परंतु जो सस्था इस प्रक्रियाओं को अपनाने में कठिनाई अनुभव करती हो, तो उनके लिए दूसरा विकल्प स्थाई आदेश 4/73 दिनांक 26-4-73 में निर्देशानुसार कायवाही कर माना जा सकता है।

[क्रमांक—शिविरा/अनु/ए/16011/57/73-74 दिनांक 17-6-73]

### [20]

परिपत्र

स्थाई आदेश सं 1/73 दिनांक 10-1-73 के क्रम में शिथिलन देते हुए यह आदेश दिया जाता है कि केवल अशकालीन अध्यापकों एवं अशकालीन कमचारियों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित करना एवं नियोजन कार्यालय से प्रत्याशी नामावली प्राप्त करना आवश्यक नहीं है परंतु ऐसी नव नियुक्ति का अनुमोदन विभागीय सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक है।

क्रमांक—शिविरा/अनु/ए/16011/150/73 दिनांक 16-2-74

★ ईमानदार व्यक्ति ईश्वर की सेवा तम कृति है।

[21]

An extract from the Rajasthan Grant in aid to Educational and Cultural Institutions Rules, 1963 is reproduced below --

"The Notice period pay recovered from the employees of the institution and the amount of the management share of the Provident Fund Scheme forfeited by the management during the year shall be shown as income in the audited Statement and shall be credit as income of the institution for the purpose of arriving at the net approved expenditure "

It has been observed that this Rule is not being followed by the officers of Education Department. The rule clearly says that notice period pay recovered from the employees by the institution shall be counted as income for purposes of grant in aid. There have been cases where an employee has left the institution without giving notice and in such case it has not been possible for the management of that institution to recover the notice period pay from him. In that case also notice period pay not actually recovered is being counted as income of the institution. It is hereby clarified that this amount will be treated as income for calculation of grant in aid only if the same is recovered by the institution from the employees concerned.

(No F 2 (21)) Edu /Gr V/74/Dated the 23 August, 1974)

[22]

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग (ग्रुप 5)

स 7 (6) शिक्षाग्रुप 5/75

दिनांक 22 अगस्त 75

महोदय,

सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं (संगम) के दिनांक 4 जनवरी, 75 से 6 जनवरी 75 को हुये अधिवेशन में पारित प्रस्ताव संख्या 2, 6, 14, 21 (प्रतिसलण) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का मुझे निदेश हुआ है। इस सम्बन्ध में सरकार

\*क्रोध पर नियंत्रण रखने वाला ही स्वयं का सच्चा अधिकारी है।

ने यह निणय लिया है कि कमचारियों के चयन और पदोन्नति के लिए एक छोटी समिति का गठन सस्था की प्रबंधक समिति द्वारा किया जाय। इस समिति में शिक्षा विभाग का भी एक प्रतिनिधि होगा। इस चयन और पदोन्नति समिति की बैठक में अगर शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि समय पर सूचना मिलने के बाद भी उपस्थित नहीं होते हैं तो भी इस समिति का निणय आखरी होगा और दूसरी कोई मीटिंग की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार यह भी निणय लिया गया है कि जिन सस्थाओं में पूर्व में कमचारियों की सस्था कम कर दी गई यद्यपि न तो विद्याधिया का स में कमी हुई थी और न कोई सक्शन में कोई भी कमी हुई थी तो ऐसी सूरत में जो अनुदान में कटौती की गई थी उसको निरस्त कर दिया जाय। (The cut made in Grant-in-aid may be restored) भविष्यमें किसीभी सस्था के कमचारियोंमें अनुदान के लिए कोई कटौती नहीं की जायेगी जब तक सस्था को अपने मामले प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जाता है।

#### प्रस्ताव स 2

मायता प्राप्त एवं अनुदान प्राप्त सामाजिक शिक्षण सस्थाओं के आत रिक् मामलों में शिक्षा विभाग का वर्तमान हस्तक्षेप समाप्त किया जाय।

#### प्रस्ताव स 6

अनुदान प्राप्त शिक्षण सस्थाओं में अध्यापक एवं अन्य कार्यक्ताओं की नियुक्ति के लिए विभागीय अनुमोदन लेने सम्बन्धी प्रतिबंध को हटाया जाय। चयन समिति की बैठक में विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थिति को ही विभागीय अनुमोदन माना जाय। निर्धारित अवधि में पूर्व सूचना द देने पर भी चयन समिति की जिस बैठक में विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित न हो उनमें शेष सदस्या द्वारा चयनित व्यक्ति का विधिवत चयनित व्यक्ति स्वीकार किया जाय।

#### प्रस्ताव स 42

अनुदान प्राप्त सामाजिक शिक्षण सस्थाओं में कार्यरत कार्यक्ताओं की पदोन्नति के लिए विभागीय स्वीकृति आवश्यक समझी जाय।

#### प्रस्ताव स 21

निदेशालय द्वारा कइ बार पूर्ण नोटिस के भी स्वीकृत पदा में कटौती कर दी जाती है जिससे सस्थाओं के सामने बड़ी कठिनाइया उपस्थित हो जाती है। अत यह अधिवेशन माग करता है कि स्वीकृत पदा में कटौती से पूर्व सस्था को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का पूर्ण अवसर दे तथा कटौती से पूर्व समुचित समय पहिले सूचना दी जाय।

★ कुछ अवस्था में किसी का उत्तर न दो।

[23]

### आदेश

**विषय — अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कमचारियों की नियुक्ति के संबंध में ।**

1 विभाग के ध्यान में लाया गया है कि अनुदान प्राप्त संस्थाओं में जो नियुक्तियाँ की जाती हैं उनके अनुमादन संबंधी कार्यवाही संबंधित मध्यम अधिकारियों द्वारा समय पर नहीं की जाती है, जिससे उन शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण कार्य में रूकावट उत्पन्न होती है। अतः इस कार्यालय के स्टार्ड आदेश 4172 (क्रमांक शिविरा।अनु।एफ।16007129172-73 दिनांक 12.5.72) के क्रम में पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि अनुदान प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों पर मध्यम अधिकारियों द्वारा 15 दिन के भीतर भीतर अनुमोदन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करदी जानी चाहिये।

2 अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नव नियुक्ति हेतु चयन समिति में विभागीय प्रतिनिधि मनोनीत करने व उयवे चयन समिति में भाग लेने के संबंध में आवश्यक निर्देश इस कार्यालय के परिपत्र संख्या शिविरा।अनु।ए।16011112172-73 दिनांक 16-8-72 व शिविरा।अनु।ए।160111173-74 दिनांक 1-5-73 द्वारा पूर्व में प्रसारित किये जा चुके हैं।

अनुदान प्राप्त संस्थाओं को सूचित कर दिया जावेगा कि वे चयन समिति की बैठक की तिथि की सूचना मनोनीत विभागीय प्रतिनिधि को बैठक 11 वम से वम दो सप्ताह पहले दें।

विभागीय प्रतिनिधि सूचना मिलने के उपरान्त भी किसी कारणवश यदि चयन समिति की बैठक में उपस्थित हानही सके तो बैठक की कार्यवाही नियमित मानी जाएगी। नियुक्ति का विभागीय अनुमोदन 15 दिन के भीतर लेना आवश्यक होगा।

3 यदि किसी अनुदान प्राप्त संस्था में कोई रिक्त पद हो तो संस्था उस पद का एक माह के लिए अस्थाई तौर पर भर सकती है लेकिन उस पद की स्थाई रूप से भरने के लिए चयन समिति की बैठक माह के भीतर बुलवा कर स्थाई रूप में रिक्त पद को भरने की कार्यवाही सम्पन्न करनी होगी।

4 अनुदान प्राप्त संस्थाओं में जो अध्यापिका प्रसूति अवकाश पर जाती है उससे हुए रिक्त पद की संस्थाओं द्वारा अस्थाई नियुक्ति से भर जा सकता है। ऐसी नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक बुलाने व विभागीय प्रतिनिधि के शामिल

\*जब आवे स-तोष घन, सब घन धूरि समान ।

होने की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन उक्त कारण से हुए रिक्त पद को अस्थाई रूप से भरने के लिये नियोजन कार्यालय से आशाचिया की सूची प्राप्त कर उसमें से प्रशिक्षित व्यक्ति की नियुक्ति करना आवश्यक होगी।

5 अनुदान प्राप्त संस्थाओं में किसी अध्यापक/अध्यापिका के बी एड प्रशिक्षण में जान के पत्र-व्यवहार हुए रिक्त पद को भी अस्थाई रूप से भरा जा सकता है लेकिन ऐसी नियुक्ति के लिए संस्था का वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो नव नियुक्ति के लिए निर्धारित है।

6 अनुदान प्राप्त संस्थाओं में लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कमचारी के पद को भरने के लिए वही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जो एक अध्यापक/अध्यापिका के पद को भरने के लिए अपनानी पड़ती है। जैसा कि इस कार्यालय के पत्र संख्या शिविरा/अनु।गफ।16007/72-73/49 दिनांक 25.5.72 में इसका उल्लेख है। इस संबंध में उक्त पत्र दिनांक 25.5.72 में आशिक सशोधन करते हुए आदेश दिये जाते हैं कि अनुदान प्राप्त संस्थानों में चतुर्थ श्रेणी कमचारी के पद को भरने के लिये चयन समिति की बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसी नियुक्ति संस्थाओं द्वारा नियोजन कार्यालय से प्राप्त आशाचिया की सूची में से की जा सकती है।

7 यदि किसी अनुदान प्राप्त संस्था में किसी एक वर्ष में छात्रों की संख्या में कमी होती है तो ऐसी संस्थाओं में स्वीकृत अध्यापक पद उसी वर्ष में कम न किये जायें लेकिन यदि छात्र संख्या दूसरे वर्ष भी कमी जारी रहती है तो संस्था को आवश्यक नोटिस देकर उस संस्था में अध्यापक पद छात्र संख्या के अनुपात में कम किये जा सकते हैं।

[क्रमांक शिविरा/अनु/डी/16022/75-76 दि 22.6.76]

[24]

Sub -- Appointment of Sisters Staff for institutions under the management of the Director General of Ajmer Diocesan Corporation Ajmer

[No F 7 (33) Edu/Gr, V/75 Dated the 25 Feb, 1976]

- 1 Such Sister Staff of may be working on any post need not be sponsored by the Employment Exchanges and an exemption is granted to new recruits for the staff from among the sisters to be appointed in the institutions run by Ajmer Diocesan Corporation Ajmer provided they fulfil the minimum academic qualifications prescribed for the posts

\*कोच एक क्षणिक पाणलपन है—होरेस

- 2 The appointment of duly qualified sisters staff made by the Director General and the Governing Body of the Societies from the panel of Sisters, may be accepted and confirmed by the Education Department provided that they so appointed are duly selected by the Selection committees of the institutions concerned as per Grant-in aid rules, on which State Government nominee should be represented
- 3 Permission may be also accorded for transfer of such sisters staff from one mission institution to another within the State In such cases, the salary of the incumbent should be protected
- 4 Permission may also be accorded to accept on transfer such sisters staff from the Mission Institutions outside Rajasthan to this State and vice versa In such cases also their salary will be protected

This issues with the concurrence of Labour and Employment Department I B No 580/STP/76 dated 12/25 2 76

[25]

विषय — अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कमचारियों को सरेडर अवकाश का लाभ देने बाबत ।

उक्त विषय में राज्य सरकार द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय साधनों की कमी के कारण अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कमचारियों का सरेडर अवकाश का लाभ लेना संभव नहीं है ।

कृपया आपके अधीनस्थ समस्त अनुदान प्राप्त संस्थाओं को तदनुसार सूचित कर दें ।

क्रमांक शिविरा/अनु।डी।17907/38।76

दिनांक 27 3 76

[26]

आदेश

इस कार्यालय द्वारा पूर्व प्रसारित स्टाई आदेश संख्या 4।73 क्रमांक शिविरा/अनु।ए।16011।40।73-74 दिनांक 28-5 73 में आशिक संशोधन करत हुय आदेश दिये जाते हे कि अनुदान प्राप्त संस्थाओं में जिन अध्यापकों का 30 6 76

\*धर्म की महत्ता सर्वोपरि है ।

तक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य था, एवं जो अभी तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सके हैं उनके लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि एक वर्ष अर्थात् 30.6.77 तक बढ़ाई जाती है।

(क्रमांक शिविराग्रनु।ए।17906।14।76-77

दिनांक 14.5.76)

[27]

### — परिपत्र —

इस कार्यालय के पूर्व स्थाई आदेश संख्या 4।72 क्रमांक शिविराग्रनु।ए।16007।28।72-73 दिनांक 12.6.72। एवं स्थाई आदेश संख्या 6।72 क्रमांक शिविराग्रनु।ए।16007।36।72-73 दिनांक 17.5.72 में चतुर्थ श्रेणी कमचारियों के लिए नियुक्ति पर विभागीय अनुमोदन की आवश्यकता की शर्त लगाई गई थी। बाद में इस कार्यालय के परिपत्र संख्या शिविराग्रनु।डी।16002।75.76।54 दिनांक 22.5.76 में यह शिथिलन दिया गया था कि चतुर्थ श्रेणी कमचारी की नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक बुलाने की आवश्यकता अब नहीं होगी और केवल नियोजन कार्यालय से प्राप्त आशाधियों की सूची में से ही व्यक्ति नियुक्त किया जा सकेगा।

उपरोक्त स्थाई आदेश एवं परिपत्रों के उपरांत संस्थाग्रा नेष श्रे क की नियुक्ति का अनुमोदन विभाग से करवाने के मागों में अनुदान नियमों में प्रावधान नहीं होने की बिना पर शिथिलन चाहा है। इस बिंदु पर विचार करने के बाद भी चतुर्थ श्रेणी कमचारियों के लिए योग्यता का कोई विचारण नहीं है और विभागीय अनुमोदन केवल औपचारिकता है। अतः उक्त अनावश्यक पत्राचार का रोकने हेतु स्थाई आदेश 4।72 एवं 6।72 में चतुर्थ श्रेणी कमचारियों की नियुक्ति के विभागीय अनुमोदन की शर्त को अब हटाया जाता है एवं यह स्पष्ट आदेश दिए जाते हैं कि भविष्य में ऐसी नियुक्तियों का विभागीय अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा किंतु चयनित आशाधियों का नियोजन कार्यालय से निदिष्ट होना जरूरी होगा और नियुक्ति आदेश की प्रति निदेशालय तथा प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का डाक प्रमाण पत्र के अंतर्गत तत्काल भेजनी अनिवार्य होगी।

[क्रमांक-शिविराग्रनु।ए।17906।परि।76-77

दिनांक 12.10.76]

[28]

### कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या शिविराग्रनु।डी।16022।75.76।54 दिनांक 22.3.67 के बिंदु संख्या 3 में सहायता प्राप्त संस्थाग्रा में एक माह के लिए हुए

★अति परिचय से अवज्ञा होती है।



रिक्त स्थान को भरा हेतु चयन प्रक्रिया अगनाने में छूट दी गई थी। अनुर सस्याग्र ने इस प्रकरण में पुनः स्पष्टीकरण चाहा है कि ऐसी नियुक्तियों का विभागाय अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है या नहीं ?

इस बिन्दु पर अब आदेश दिय जाते हैं कि छात्रों के अध्ययन का शिष्टांत रचित हुए किसी पद का अस्थायी तौर से एक माह की अवधि तक के लिए भरा हो तो चयन प्रक्रिया अगनान के साथ साथ विभागीय अनुमोदन प्राप्त करना भी आवश्यक नहीं है लेकिन सस्या ने लिए यह आवश्यक होगा कि यह ऐसे कर्मचारी के नियुक्ति आदेश तथा माग्यता प्रमाण पत्र की प्रतिया तत्काल प्रतिहस्ताक्षरकता अधिकारी का भेजे।

[क्रमांक-शिविराअनु।ए।17906।26।76 77

दिनांक 22.11.76]

[29]

### परिपत्र

अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु बनाई गई चयन समिति में विभागीय प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए इस कार्यालय द्वारा पूर्व प्रसारित परिपत्र में उल्लेख किया गया है। ऐसा देखने में आया है कि कई विभागीय चयन समिति की बैठक में ही उपस्थित होते हैं किन्तु चयन समिति की कार्यवाही का वह दिनांक अपने पास ही रखा लेते हैं तथा चयन बाट पर हस्ताक्षर करने में विलम्ब करते हैं। उनकी इस कार्यवाही से अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः सभी प्रति हस्ताक्षरकता अधिकारियों को यह आदेश दिए जाते हैं कि वे अपने अधीन संस्थाओं में नियुक्त विभागीय प्रतिनिधियों का निर्देश दे कि चयन समिति का बैठक का कार्य बानी पर वे उही दिन हस्ताक्षर करें जिस दिन संस्था में चयन समिति की बैठक होती है।

[क्रमांक-शिविराअनु।ए।17906।77-78

दिनांक-1.8.77]

[30]

### — परिपत्र —

संसाधन के आधार पर आदेश संख्या 10।72 में यह नियम प्रसारित किया गया था कि नियोजन कार्यालय में प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध न होने की स्थिति में चयन समिति द्वारा चयनित अप्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति केवल एक गैरस्थायी मन के लिए ही की जाय तथा यदि 31 दिसम्बर से पूर्व नियुक्ति हुई हो तो संस्था में 3 मास का प्रोबेशन कायम रहेगी। अब राजस्थान सेवा नियम के नियम 97 के तहत दिए गए नियम में राजाजा संख्या 6 एफ।(22) एफडा (मू-2) 75

★ धन का महत्ता सर्वोपरि है।

दिनांक 9-6-75 द्वारा मशोधन हो जाने के फलस्वरूप उक्त स्थाई आदेश सख्या 10172 में निम्न संशोधन किये जाते हैं —

1- आदेश के अनुच्छेद 2 की लाइन 5 में शब्द 'नियुक्ति केवल एवं ही शैक्षणिक सत्र के लिए ही की जावे' के बाद विराम (।) का चिह्न लगाया जावे।

2 अनुच्छेद 2 में लाइन 5 में शब्द "तथा यदि नियुक्ति 31 दिसम्बर व उसके आगे की सभी तीन लाइनों विलोपित करत हुए उनके स्थान पर निम्न नई प्रविष्टियाँ की जावे, —

"वे अध्यापक जिनकी नियुक्ति किन्तु पद पर सक्षम अधिकारी द्वारा माय है एवं जिन्हें 31 दिसम्बर को या उससे पूर्व नियुक्त किया गया है श्रीधमावकाश का वेतन माय होगा यद्यपि कि उस पर अथ किसी कमचारी द्वारा श्रीधमावकाश वेतन नहीं उठाया गया हो और ऐसे कमचारी ने उस पद पर आगामी सत्र में शान्ता छुलने के एक माह के भीतर भीतर काय ग्रहण कर लिया हो तथा यह आगामी सत्र में माह दिसम्बर तक काय रत रहें।"

[अमाक-शिविरा(अनुए)17907175177-78

दिनांक 29-10-77]

## अध्याय-12

अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कमचारियों द्वारा व्यवस्था समिति के  
निर्णय के विरुद्ध अपील के क्रम में

Subject Procedure for dealing with appeals

[No EDB/AID/ /16007/sp1/5

Dated 27-12-65)

The Grant in aid Rules published in Rajasthan Rajpatra, January 24 1963, rule 4(e), provide that a member of the staff of an institution who has been dismissed or removed or reduced in rank can appeal to the Education Department according to Appendix-5, Item No 2 page 854 According to this, Officers

\*परिचय से दूर भागने वाला भी घोर है।—गांधीजी

of the Education Department who have powers for approval of appointments according to item 7(1) have also the power to hear the first appeal This implies —

1 That the Inspectors of Schools will hear the appeals of all the employees working in III grade, L D C grade or any lower grade

2 That the Dy Director of Education of the range concerned can hear appeals of teacher working in II grade and S T C Instructors

3 That the Addl Director of P&S Education can hear appeals of Headmasters, Senior teachers and other employees above the grade of Instructors of S T C Schools and of all employees of Institutions which are running three or more institution and whose total approved expenditure exceeds Rs one lakh

The aforesaid Rules also provide that the second appeal will lie with the immediate superior officer of the officer of the first appeal No further appeal is provided in the rules

#### Procedure for appeals

A teacher aggrieved against an order the Management may appeal to the authority as mentioned above within one month of the order represented against He shall State clearly the reasons for his appeal He must note that appeal against dismissal, removal and reduction in rank alone can be entertained by the Department Appeal against an order awarding any other punishment may not be entertained by the Department

The teacher appealing against the order of the Management shall furnish two copies of appeal and is advised to send it by Registered A D post to the appellate Authority He should clearly mention the ground of appeal and should enclose copies of all relevant documents

On receipt of an appeal the appellate authority will send by registered A D post one copy of the appeal to the Manage-

\*व्यक्त व्यक्ति के पास अथवा प्रवाह का समय नहीं होता ।

ment and invite their comments within a period of 15 days of the receipt of the copy. If the Management fails to send its comments, the appellate authority may decide the appeal exparte.

Where the management sends its comment and contradicts the contentions of the appellant teacher, the appellate authority shall examine the merits of the case. If, on the basis of the documents available to it, it is able to make up its mind in regard to the appeal, it shall do so under intimation to both the parties.

Where the appellate authority considers it necessary to conduct an enquiry in regard to a particular point in dispute it may do so either itself or may entrust it to a particular officer not below the rank of Deputy Inspector of Schools. The officer asked to conduct an enquiry should be asked to do so in respect of specific points and should be given a specific time within which to complete it. The Enquiry Officer shall generally make the enquiry in the presence of both the parties but may, in special cases, do so confidentially. A copy of the appellate authority directing an Officer to enquire into some specific points shall be sent to the Management and the appellant teacher, both of whom shall co-operate with the Enquiry Officer in the conducting of the enquiry.

On receipt of the report of the Enquiry Officer the appellate authority shall decide the merits of the appeal and shall appraise both parties of the decision immediately after it is arrived at.

As mentioned above, the second appeal may be filed by the aggrieved party within the period of one month of the receipt of the copy of the order of the authority of the first appeal. The second appeal shall be decided by the authority concerned by following the same procedure as for the first appeal.

Sufficient number of copies has been enclosed to be sent to the aided institutions who will please bring this to the notice of all the teachers by pasting it on the Notice Board.

**\*अपना काम ईमानदारी से करो ।**

**विवरण—अपीलों के सम्बन्ध में कार्य प्रणाली (हिन्दी अनुवाद—अप्राधिकृत)**

राजस्थान राज पत्र दिनांक 24 जनवरी 1963 में प्रकाशित सहायताय अनुदान नियमावली के नियम 4 (ड) में प्रावधान है कि किसी मम्बा के स्टाफ का कोई सदस्य जिसे बलास्त कर दिया गया है, या सजा स हटा दिया गया है प्रथम पदावनत कर दिया गया है, शिक्षा महिता व परिशिष्ट 5 की मद में 2 के अनुसरण में अपील कर सकता है। इसका अनुसार शिक्षा विभाग के अधिकारी जिन्हें मद 7 (1) के अनुसरण में नियुक्तियाँ की स्वीकृति देने की शक्ति है, प्रथम अपील को सुनवाई करने की शक्ति रखते हैं। इससे उपस्थित है कि—

(1) निरीक्षक स्कूल उन समस्त कमचारियाँ अपीलों की सुनवाई करेंगे जो कि श्रेणी 3 अध्यापक या निम्न लिखित वर्ग की वतन श्रृंखला में प्रथम किसी अन्य निम्नतर वेतन श्रृंखला में काम कर रहे हैं।

(2) उपनिदेशक शिक्षा विभाग, सम्बन्धित क्षेत्र, श्रेणी 2 में काम करने वाले अध्यापकों की तथा एस टी सी इमर्जेंट्स की अपीलों की सुनवाई कर सकते हैं।

(3) अतिरिक्त निदेशक प्राइमरी एवं सक्ण्टरी शिक्षा प्रधान अध्यापक, सीनियर अध्यापक और एस टी सी स्कूलों के इंसपेक्टरों के ग्रेड स ऊँचे ग्रेड में काम करने वाले कमचारियों के तथा ऐसी मम्बाओं के समस्त कमचारियों की जा कि तीन प्रथम बार सस्याए चला रही हैं एवं जिसका समय स्वीकृत अवधि एक लाख रुपये से अधिक है अपीलों की सुनवाई कर सकते हैं।

उपरोक्त नियमों में यह प्रावधान भी है कि द्वितीय अपील उन अधिकारियों की होगी जो कि प्रथम अपील के अधिकारियों में ठीक उच्चतर (सुरिगियर) अधिकारी हों। नियमों में और किसी अपील का प्रावधान नहीं है।

### अपीलों के लिए प्रणाली

कोई अध्यापक जो प्रथम समिति के आदेश से परिवेदित हो, ऊपर वर्णित प्राधिकारियों का उस आदेश की तारीख से एक महीने के अंदर जिसके विरुद्ध अपील करना (Representation) करना है अपील पेश कर सकता है। यह अपील के कारण स्पष्टतया व्यक्त करेगा। उस यह भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए कि केवल बलास्तगी हटायी जाने तथा पदावनति के ही विरुद्ध शिक्षा विभाग द्वारा अपील ग्रहण की जा सकती है। ऐसे आदेश के विरुद्ध जिसमें कोई अन्य दण्ड दिया गया हो कोई अपील विभाग द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती।

प्रथम समिति के आदेश के विरुद्ध अपील करने वाला अध्यापक अपील की दो प्रतियाँ पेश करेगा और उसे अपील अधिकारियों की रजिस्टर्ड एन्टी पोस्ट से लेने

उ.अपने प्रति किए गए उपकार को सदा याद रखे।

ज्ञान की सलाह दी जाती है। इस इच्छा के आधार पर आचार्य का स्पष्टतया उल्लेख करना चाहिए। तब समस्त सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियां शामिल करनी चाहिए। अधीन अधिकारी अधीन प्राप्त होने पर अधीन की एक प्रति रजिस्टर्ड एडोप्टेड प्रबंध समिति या जहां और उससे अधीन की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के अंदर ही (Comments) शामिल करेगा। यदि प्रबंध समिति टिप्पणी करने में असफल रहे, तो अधीन अधिकारी अधीन का एकतरफा निर्णय करेगा।

जहां प्रबंध समिति अपना टिप्पणी भेज तथा अधीनकर्ता अध्यापक के विवाद स्पष्ट करने (Clarify) के विरोध करे जो, अधीन प्राधिकारी मामले की जांच गुणवत्ता (Merit) के आधार पर करके अधीन के विषय में अपना निश्चित विचार बना सके ता वह दोनों पर ही सूचना देकर ऐसा करेगा।

जहां अधीन प्राधिकारी किसी विवादामय बात विशेष के बारे में जांच करना आवश्यक समझता है या तो स्वयं कर सकेगा अथवा उस किसी ऐसे अधिकारी विषय को साथ लेकेगा जो कि उस निरीक्षक स्कूल से नीचे पद का न हो। जिस अधिकारी का जांच काय सापा जाय उस उही निदिष्ट बातों के विषय में जांच करने का कहा जाना चाहिए और एक निदिष्ट अवधि दी जानी चाहिए जिसके अंदर उस काय का पूरा किया जाय। जांच अधिकारी साधारणतया जांच दोनों पक्षों की मौजूदगी में करेगा परंतु विशिष्ट मामलों में गौपनीय तरीके से भी कर सकेगा। जिस पक्ष के जरिए अपना अधिकारी किसी अधिकारी को कि ही निदिष्ट बातों की जांच करने का निर्देश दे उसकी एक प्रति प्रबंध समिति तथा अधीनकर्ता अध्यापक को भेजी जायगी व दोनों जांच अधिकारी के साथ जांच काय में सहयोग करेंगे।

अधीन अधिकारी जांच अधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अधीन को गुण दोष (Merit) पर निश्चित करेगा और दोनों पक्षों पर निर्णय की सूचना सुरक्षित दगा। जहां वर्णित है परिचालित गति द्वारा द्वितीय अधीन, प्रथम अधीन प्राधिकारी के आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक महीने के अंदर प्रस्तुत की जा सरेगी। द्वितीय अधीन का निर्णय सम्बंधित प्राधिकारों द्वारा उसी प्रणाली का अनुसरण करत हुए किया जायेगा जो कि प्रथम अधीन के लिए है।

इसकी प्रतियां पर्याप्त संख्या में सलग हैं जिन्हें सहायता प्राप्त संस्थाओं को भेजना है और व इस सूचना पट्ट पर चिपकाकर समस्त अध्यापकों का ध्यान रहे और आकर्षित करेंगी।\*

[स ई टी बी/एड/16007/स्पेशल/65 दिनांक 27-12-1965]

\* सुप्रसिद्ध पुस्तक 'अनुशासनिक कार्यवाही' (लेखक-रत्न) पृ. 44

## अध्याय-१३

अथ/विविध विषयो पर राज्य सरकार/विभाग द्वारा

प्रसारित आदेश,परिपत्र

राजस्थान सरकार

[शिक्षा (ग्रुप) विभाग]

क्रमांक-एफ 24 (53) शिक्षा/ग्रुप-5/76 जयपुर दिनांक 26 मई, 1976

— आदेश —

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि अगर किसी भी सस्था को क्रमोन्नत किया जाता है तो कुल अनुदान सस्था को पहले की अपेक्षा कम मिलने लगता है जो कि नीचे दिए हुए उदाहरण से स्पष्ट होता है—

जैसे किसी माध्यमिक स्कूल को 80% अनुदान मिल रहा था उसको उच्च माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत किया गया और जो कक्षाएँ खोली गई और उस पर जो अतिरिक्त खर्च हुआ है उस पर साधारणतया पहले साल 50% अनुदान दिया जाता है। क्रमोन्नत होने के फलस्वरूप कोई सेकेण्ड ग्रेड अध्यापक जमे उदाहरण के लिए पहले कुल वेतन 5000 रुपये वार्षिक था उसको वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नत किया गया जिसका वेतन बढ़कर 6000 रुपये वार्षिक हुआ और यह उच्च माध्यमिक कक्षाएँ भी लेने लगा। साधारणतया यह देखा गया है कि जो अनुदान दिया जाता है वह कुल वेतन का 50% हा दिया जाता है इसका मतलब यह हुआ कि पहले इस सस्था को उस शिक्षक के वेतन पर अनुदान 80% के हिसाब से 4000 रुपये मिल रहा था लेकिन अब बड़े हुए वेतन पर 50% को दर से उसको 3000 रुपये ही मिले। यह चीज मिलकुल गलत है और ऐसा लगता है कि हमारा अनुदान नियमों को या तो ठीक से समझा नहीं जा रहा है या जानबूझकर इनकी अवहेलना की जा रही है। लकिन जो सही अनुदान मिलना चाहिये वह निम्न प्रकार से होता चाहिए —

80 प्रतिशत अनुदान 5000 रुपये पर	4000 रुपये
50 प्रतिशत अनुदान 1000 रुपये पर	500 रुपये
कुल योग	4500 रुपये

इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि कुल अनुदान सस्था को ऐसी स्थिति में 3000 रुपये के बजाय 4500 रुपये मिलना चाहिए।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि क्रमोन्नत होने के पश्चात् जो खर्चा सस्था का होता है और जो क्रमान्त होने के अगर भी होता उस पर पुरानी दर से ही मिलना चाहिये और जो अतिरिक्त खर्चा क्रमोन्नत होने से हुआ उस पर 50%

★जीवन का आधार सदाचार है।

कमोन्नत सस्था को पहले साल या उस पर जा अनुदान की दर सरकार मुकरर करती है, उस पर भिन्ना चाहिए। साधारणतया कमोन्नत होने के पश्चात जो नया सर्वा होता है वह सरीद पर हो सकता है या पदोन्नति पर हो सकता है या नय अध्यापक की नियुक्ति पर हो सकता है। यदि कोई पद खाली हो जाता है और उस पर नई नियुक्ति की जाती है तो भी सस्था को ऐसे मामले पर निम्नानुसार अनुदान देय होना चाहिए —

द्वितीय बतन श्रु खला का न्यूनतम 160/- रुपये

अनुदान मिनेमा 80 प्रतिशत के हिसाब से 128 00

वरिष्ठ अध्यापक के बतन श्रु खला का न्यूनतम 225/-

हाता है इसलिए वरिष्ठ अध्यापक के बतन के अंतर

(225-160) 65 रुपये पर 50 प्रतिशत के हिसाब से 32 50

योग— 160 50

इसी प्रकार अध्यापक के वार्षिक बतन वृद्धि पर भी अनुदान निम्न प्रकार होना चाहिए, माना कि अध्यापक को वरिष्ठ अध्यापक की बतन श्रु खला में अपय वार्षिक बतन वृद्धि देय है, पून में द्वितीय बतन श्रु खला में बतन वृद्धि की 10 रुपये है

ता उस पर अनुदान 80 प्रतिशत के हिसाब से 8-00

और नेप बतन वृद्धि की राशि (15-10) 5/- 2-50

पर 50 प्रतिशत के हिसाब से

योग— 10-50

इन प्रकार सस्था को बतन वृद्धि पर 10-50 रुपये देय होना चाहिये।

बतन के अनुसार ही अन्य व्यय पर भी 80 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत इनका अनुदान स्वीकृत किया जाना चाहिए।

अतः राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित किया है कि इस प्रकार सस्था कमोन्नत स्तर पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है और उसके वर्गीकरण में अन्तर्गत उस सस्था को कमोन्नत के पूर्व के समय पर पूर्वानुसार ही अनुदान देय होगा कमोन्नत स्तर पर वह एवं व्यय पर कमोन्नत पर निश्चित किये गये प्रतिशत के हिसाब से अनुदान देय होगा।

यह आदेश वित्तीय वर्ष 1976-77 से प्रभावशील होगा।

कापालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा रायस्थान, बीकानेर

बिज्ञप्ति

इस वित्तीय वर्ष (79-80) के लिए विभिन्न स्तर वाली रजिस्टर्ड गरीबों की निजी शिक्षण सस्थाओं को अनुदान सूची में लेन के लिए आवेदन पत्र भेज दिये जाते हैं। वे छात्र/छात्रा सस्थाएं जिन्हें मान्यता प्राप्त है उनका असाधारण ही मानव को जानवर से भेद होता है।



अतः हुए अथवा नवीन विषय प्रारम्भ किये हुए 5 वष/3 वष की अवधि जुलाई 78 में पूरी हो गई है, विभागीय नीति के अनुसार आवेदन की पात्रता होगी। निम्न थ ली में आनेवाली समस्याओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर ही अनुदान सूची में लिया जा सकेगा —

(घ) छात्र विद्यालय जुलाई 73 से मायता प्राप्त है/स्तर में अमान्य न/नये विषय चाले गये हैं।

(ब) छात्रा विद्यालय जो जुलाई 75 से मायता प्राप्त है/स्तर में अमान्य न/नये विषय चाले गये हैं।

इस थ ली में आनेवाली समस्याओं को ही आवेदन पत्र देन चाहिए। जो सीधे न्त कार्यालय में 30 सितम्बर, 79 तक प्राप्त हो जाने चाहिये निर्धारित विधि के बाद प्राप्त होन वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा।

आवेदकों से निवेदन है कि आवेदन पत्र भेजने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें—

(1) केवल व ही समस्याएं आवेदन कर सकेगी जो उन्नत नीति में आती है। ऐसी समस्याओं का विभागीय रजिस्ट्रेशन किया जावेगा।

(2) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में जिसकी नकल माफ में सलग्न है, दाख किये हुए साफ कागज में अथवा माफ मगारा में हाथ में लिख हुए भी स्वीकार किया जा सके हैं। गलत सूचना देने अथवा अस्पष्ट मगारा में लिखे आनेवालों को प्रत्योकार किया जा सकेगा है।

(3) आवेदकता आवेदन पत्र देने के बाद विभाग से इस प्रसंग पर कोई पत्र व्यवहार नहीं करेंगे क्योंकि अम्य आवेदन पत्रों को निरीक्षण प्रतिवेदन सहित अनुदान समिति के विचाराय प्रस्तुत किया जा कर प्रस्ताव राज्य सरकार का भेजे जायेंगे।

(4) समस्याओं को अनुदान सूची पर नैन अथवा नहीं लेन की संपूर्ण परि स्थिति विभाग के पास उपलब्ध बजट प्रावधान पर ही निर्भर करेगी।

(5) अनुदान केवल उ ही समस्याओं का दिया जावेगा जो अनुदान नियम (1963) का पालन करेगी तथा विभागीय प्रादेश के अनुरूप कार्य करेगी। इस प्रकार सूची में ली गई समस्याओं को यथा समय सूचित कर दिया जावेगा तथा ज सूची में नहीं ला जा सकेगी उनकी कोई सूचना नहीं दी जायेगी।

(6) जो छात्र समस्याएं जुलाई 72 तक तथा छात्रा समस्याएं जुलाई 74 मा इससे पूर्व मायता प्राप्त/अमान्य/नये विषय की स्वकृति प्राप्त किये हुए हैं उनका मामले पर गत वष की नीति के अनुसार 5 व 6 अक्टूबर 78 की अनुदान समिति की विगत बैठक में विचार किया जा चुका है, अतः ऐसी समस्याओं का रजिस्टर्ड नहीं किया जावेगा। इसके मामले राज्य सरकार को भेजे जा चुके हैं अतः ऐसी समस्याओं को अब आग्रह करना वाछनीय नहीं है।

[क्रमांक-शिविरा/अनु।ए।17/02/69/178-79]

दिनांक 6.9.79,

\*कायर बार बार भरता है किन्तु बार एक ही बार भरता है।

—चन्द्र शेखर आजाद

रजिस्टर्ड गैर सरकारी निजी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान सूची पर लेने हेतु आवेदन पत्र

- (1) संस्था का नाम व डाक का पता
- (2) रजिस्ट्रेशन संख्या (प्रति सहित)
- (3) (घ) संस्था का स्तर प्रा वि उ प्रा वि मा वि उ मा वि  
(ब) सन जिससे मायता दी गई (मायता का सन)
- (4) स्तर जिस हेतु वनमान में अनुदान मिलता है
- (5) स्तर जिस हेतु अनुदान मांगा जा रहा है
- (6) मायता की स्वीकृति की प्रति भय देनेवाले अधिकारी का नाम
- (7) मायता यदि जून 79 तक मिली हुई हो तो  
(प्रथम मायता से लगातार वृद्धि की अनुमति की प्रति मलग्न हो)
- (8) कक्षावार ध्यान स — प्रा वि उ प्रा वि मा वि उ मा वि
- (9) मा वि तथा उ मा वि के लिए बढ़ाये जाने वाले विषय  
(ए) नियोजित कमचारियों की संख्या—  
प्रधानाध्यापक  
वरिष्ठ अध्यापक  
द्वितीय वेतनमान  
तृतीय वेतनमान  
लार्डब्रेरियन  
वरिष्ठ लिपिक  
कनिष्ठ लिपिक  
चतुर्थश्रेणी कमचारा  
(बी) अनुमानित वार्षिक व्यय  
(अ) वेतन व भत्ते  
(ब) अन्य व्यय
- (10) भवन (निजी) या किराये पर

हस्ताक्षर

मंत्री/अध्यक्ष संस्था

मोहर

पुस्तकें जीते जायते देयता हैं जिनकी सेवा करके तुरन्त वरदान प्राप्त किया जा सकता है।

—अज्ञात

# अध्याय--14

## निजी संस्थाओं को मान्यता

[शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर का पत्राक-गिविरा 1 प्राथमिकाडी: 19626।स्पेशल।73 दिनांक 16 4 74]

1 मायता हेतु अधिकारों का विवरण—

निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा निम्न प्रकार से निजी संस्थाओं का मायता दी जाएगी

क्र.सं.	सक्षम अधिकारी	प्रवृत्ति।संस्था प्रकार
(1)	निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा	(i) मोटेसरी (ii) शोध संस्थान (iii) मूल बधिर विद्यालय (iv) प्रतापशु विद्यालय (v) संगीत सम्पाएँ (vi) एस टी सी तथा गि क प्रशिक्षण विद्यालय (vii) अन्य
(2)	उपनिदेशक समाज शिक्षा	(i) प्रौढ शिक्षा (ii) पुस्तकालय एवं वाचनालय
(3)	समुक्त निदेशक और उप निदेशक (मण्डल)	(i) उच्च प्राथमिक विद्यालय
(4)	निरीक्षक, शारीरिक शिक्षा (निदेशालय)	(i) बन्धु (ii) व्यायाम शाला तथा अन्य शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी प्रवृत्तियों ।

सबसे उत्तम बदला दामा कर देना है ।

—रबीन्द्राथ टगोर

- (5) जिला शिक्षा अधिकारी (1) प्राथमिक विद्यालय  
(महिला सहित) । वरिष्ठ (11) बालवाडी  
उप जिला शिक्षाधिकारी ।  
उपजिला शिक्षा अधिकारी  
(महिला)

2 निजी सस्थाओं के मायता निरीक्षण हेतु सुझाव—

- (1) सस्थाओं से जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में 28 फरवरी तक मायता हेतु पायना पत्र पट्टा जान चाहिए ।
- (2) उनकी जांच जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 31 मार्च तक पूरी हो जानी चाहिए और निरीक्षण के लिए समिति गठित की जानी चाहिये ।
- (3) 30 अप्रैल से पूर्व सस्थाओं का निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए । सम्बन्धित सस्थाओं को निम्न की सूचना 30 अप्रैल तक रजिस्टर्ड होनी चाहिए ।
- (4) मायता शर्तों की वसूली की पूर्ति हेतु निजी सस्थाओं को दो माह का समय दिया जाय जिससे कि पूर्ति होने व पश्चात अनुपालना प्रतिवेदन 30 जून तक आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाय ।
- (5) नवीन सस्थाओं के निरीक्षण हेतु जो समिति गठित की जाय उसमें एक लेखाकार को प्रतिवाद्य रूप में सम्मिलित किया जाए ।
- (6) प्रथम निरीक्षण के समय ही सस्था से सम्बन्धित सभी शर्तों को सम्मिलित कर लिया जाए और किसी भी स्थिति में हर समय नई नई शर्तें नहीं लगाई जाए ।
- (7) निजी सस्थाओं से मायता हेतु जो आवेदन पत्र आय उनमें टाफ के नाम और योग्यता सम्बन्धी सूचना स्पष्ट हो जाय ।
- (8) शर्तों के सम्बन्ध में विवरण से विचार करत हेतु एक पृथक् समिति बनाई जाए ताकि पूरी समीक्षा की जा सके ।
- (9) निजी सस्थाओं को समय पर मायता हेतु जो समय मांगणी और विधियाँ नवीन सस्थाओं के लिए प्रस्तावित की गई हैं वे नवीनीकरण के लिए भी रखा जाय ।

- (10) सस्थावार परिवारों सक्षम अधिकारों के कार्यालय में खाली जाये

नम्रता ही सच्ची मानवता है ।

— गांधीजी

जिनमें सस्था का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अन्य आवश्यक पत्र रखे जायें ।

- (11) समय-समय पर विजिट तथा अचानक निरीक्षण किया जाए एवं उसका अभिलेख रखा जाय ।

3 अस्थाई मायता सम्बन्धी रजिस्टर—

- (1) अस्थाई मायता हेतु निम्न प्राण्य में एक रजिस्टर सप्तम अधिकारी के कार्यालय में संचालित किया जाए और उसमें वषवार स्थिति निदिष्ट की जाए

सस्था का नाम व स्तर	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि	दल निरीक्षण तिथि	मायता प्राप्त करने की तिथि एवं अवधि	मायता स्थाई/ अस्थाई
------------------------	-----------------------------------	---------------------	---	---------------------------

- (2) स्थायी मायता प्राप्त सस्थाओं के लिए हिंदी बखुमाला के क्रम में सक्षम अधिकारी के कार्यालय में एक रजिस्टर रखा जाए ।

- (3) कमिया की पूर्ति हेतु सस्था के लिए समय निर्धारित कर दिया जाए । कमियों की पूर्ति हेतु सस्था से लिखित में आश्वासन प्राप्त किया जाए । परंतु किसी भी दशा में अस्थाई मायता की अवधि 3 वर्ष से अधिक न बढ़ाई जाए । इस अवधि में स्थाई मायता प्राप्त न करने अथवा कमी पूर्ति न करने पर सस्था की अस्थाई मायता समाप्त मानी जायगी ।

- (4) किसी भी सस्था को भूतलकी मायता प्रदान नहीं की जाएगी ।

- (5) किसी सस्था की मायता निम्न कारणों से समाप्त की जा सकती है —

- (क) कोई मायता प्राप्त सस्था या उसका अनुभाग बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए बंद किया जा चुका हो ।
- (ख) सस्था को दूसरे भवन या क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए स्थानान्तरित किया गया हो ।
- (ग) सस्था को बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए अन्य दूसरी प्रवर्ध कारिणी समिति को स्थानांतरित किया गया हो ।
- (घ) अस्थाई मायता प्राप्त सस्था द्वारा अस्थाई मायता समाप्त होने तक विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न किया गया हो या स्थाई मायता का आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी को,

निर्धारित प्रपत्र में, मायता समाप्ति की तिथि के चार (4) माह पूर्व प्रस्तुत न किया गया हो।

(ट) किसी शिक्षा संस्था को मायता शिक्षा सत्र के अंत होने पर ही समाप्त की जा सकती है।

टिप्पणी—(1) उपरोक्त प्रावधान के अंतर्गत किसी संस्था की मायता समाप्त किये जाने के बाद पुन मायता हेतु विचार के समय वह संस्था नई संस्था मानी जाएगी।

(11) संस्था द्वारा नय स्थान पर संस्था की शाखा कायम (प्रारंभ) किए जाने पर मायता हेतु ऐसी शाखा को नई संस्था माना जाएगा।

4 मायता सम्बंधी सामान्य शर्तें—

(1) संस्था एक प्रबंध समिति द्वारा संचालित हो जिसका विधान विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो। प्रबंध समिति के सक्षम विभागीय अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के बाद ही मायता दी जाएगी, प्रयथा जारी रखी जाएगी।

5 अनुदान प्राप्त तथा अनुदान लेने हेतु इच्छुक संस्थाओं के लिए—

(1) प्रबंध समिति में 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे तथा उसके दो तिहाई से अधिक सदस्य किसी विशिष्ट समुदाय, जाति अथवा वर्ग के भी नहीं होंगे।

(2) इस समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे —

(क) सदस्यों में एक तिहाई दानदाताओं तथा नियमित रूप से चंदा देने वालों में से होंगे —

(ख) सदस्यों में कम से कम एक सदस्य अध्यापकों में से प्रतिनिधि होगा।

(ग) एक सदस्य छात्रों के अभिभावकों में से होगा।

(घ) शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि होगा।

(ङ) छात्रों का भी एक प्रतिनिधि लिया जाए। छात्र संसद का प्रधानमंत्री कार्यकारिणी समिति का पदेन सदस्य होगा।

(3) प्रबंध समिति के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे —

(i) अध्यक्ष एक

(ii) उपाध्यक्ष दो (इनमें से एक व्यवस्थापक का कार्य करेगा।

(iii) कोषाध्यक्ष एक

(iv) सचिव एक (प्रधानाध्यापक)

(v) सचिव के अनिवार्य अन्य पदाधिकारी दानदाताओं में से होंगे।

(4) अनुदान न लेने वाली संस्थाओं के लिए प्रबंध समिति में 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। उनमें शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि है

6 अथ शर्तें —

181

- (1) (i) सस्था की प्रत्येक शाखा के समिति का गठन सभ्य अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा बाद में उसकी स्वीकृति के बिना उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा ।
- (ii) यदि सभ्य अधिकारी की सम्मति में स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उस मामले को उपनिदेशक के पास भेजेगे । उपनिदेशक यदि सम्बंधित सस्था से जवाब चाहे तो उसके प्रतिनिधि को सुनने के बाद उस मामले पर अपना आदेश देगा ।
- (2) प्रत्येक समिति के सदस्यों में किया गया प्रत्येक परिवर्तन विभाग को सूचित किया जाएगा ।
- (3) आंतरिक व बाह्य गतिविधियों के लिए उपयुक्त भवन व क्रीडागम बने हुए हों और उनका उपयोग केवल शैक्षणिक उद्देश्यों तक ही सीमित हो ।
- (4) सस्था भवन किसी भी दशा में सांप्रदायिक तथा राजनैतिक गतिविधियों के लिए प्रयुक्त नहीं होगा ।
- (5) सस्था व्यवस्थापक के लिए आवश्यक होगा कि वह सेवा के निर्धारित नियम, अवकाश, भविष्य निधि आदि के बारे में विभागीय शर्तों की अनुपालना करेगा तथा सस्था अपने कर्मचारियों के लिए वे ही हितों में निर्धारित करेंगी जो उसी योग्यता वाले कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत हैं ।
- (6) अनुदान प्राप्त तथा अनुदान लेने हेतु इच्छुक सस्थाओं के लिए सस्था के समस्त कर्मचारियों के भविष्य निधि के जुगलान दिए जाने का प्रावधान भी होगा । सम्बंधित कर्मचारी अपने मासिक वेतन की सेवा छह प्रतिशत तक राशि सस्था में जमा कराएँ जिसके बराबर का अनुदान सस्था द्वारा जमा कराया जाएगा । यह राशि हानि होने से कर्मचारी के व्यक्तिगत गति में जमा की जायेगी । प्रति वर्ष भविष्य निधि का लेखा विवरण सम्बंधित कर्मचारी को दिखलाया जाना चाहिए ।
- (7) विभाग द्वारा चाही गई सूचना तुरंत तथा निश्चित रूप से भेजी जानी ।
- (8) सस्था एवं उसने समस्त अभिलेख लेखा आदि का विभाग द्वारा निरीक्षण कर लिया जा सकता है तथा निष्कर्ष द्वारा अधिकृत विधि भी व्यक्ति के सामने सस्था का अपने अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे ।
- (9) सस्था किसी व्यक्ति अथवा समुदाय के लाभार्थ संचालित नहीं की जाएगी ।
- (10) विभाग द्वारा निर्धारित अभिलेख सस्था द्वारा रख जाएंगे ।
- (11) सस्था की आर्थिक स्थिति अच्छी हो तथा विभाग द्वारा निर्धारित सुरक्षित निधि आरक्षण या वर में जमा हो ।
- (12) प्रत्येक सस्था का रिजर्व फंड होना चाहिए । रिजर्व फंड की राशि का निर्धारण मासिक व वार्षिक व्यय के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा ।







